



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 2019/चैत्र 4, 1941

No. 98]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 2019/CHAITRA 4, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2019

अंतिम जाँच परिणाम

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के 'बसों या लारियों के लिए न्यू न्यूमेटिक टायरों' के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/सब्सिडी रोधी जाँच।

फा.सं. 6/8/2018-डीजीएडी—क. मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

- यतः आटोमोटिव टायर मेन्युफैक्चरर्स एसोशिएशन (जिसे आगे याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता एसोसिएशन या एटीएमए कहा गया है) ने घरेलू उत्पादकों अर्थात् अपोलो टायर्स लि., जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लि., एमआरएफ लि. और सिएट लि. (जिन्हें समग्र रूप से घरेलू उद्योग कहा गया है) की ओर से समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडीप्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है)

के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) से बसों या लारियों के लिए न्यू न्यूमेटिक टायरों के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्यास साक्ष्यों के आधार पर, अधिसूचना संख्या 6/8/2018 - डीजीएडी दिनांक 27 मार्च, 2018 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें नियम 6 के अनुसार संबद्ध जॉन्च की शुरूआत की गई ताकि कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और सिब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'धन्ति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

क) प्राधिकारी के संबंधित नियम 6 के उप-नियम (5) के अनुसार जॉन्च की शुरूआत करने से पहले वर्तमान सब्सिडीरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में चीन जन. गण. के दूतावास को सूचित किया।

ख) प्राधिकारी ने स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से चीन सरकार के जन. गण. को आमंत्रित किया और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समझौते के अनुच्छेद 13 के अनुसार एक पारस्परिक रूप से सहमत समाधान पर पहुंचने के लिए विचार-विमर्श किया। यह विचार-विमर्श 20 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें चीन सरकार (आगे इसे जीओसी भी कहा गया है) के निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया:

- (i) श्री लियांग हाओ, परामर्शदाता
- (ii) श्री गुओ फांग, उप निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय, चीन जन. गण.
- (iii) श्री मा ज़िन, वाणिज्य मंत्रालय, चीन जन. गण.

ग) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/सब्सिडीरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक प्रकाशित 27 मार्च, 2018 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

घ) प्राधिकारी ने 27 मार्च, 2018 की जॉन्च शुरूआत संबंधी अधिसूचना चीन जन. गण. के दूतावास, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार चीन जन. गण. के ज्ञात उत्पादक/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को जॉन्च शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भेजी और उनसे विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

इ) प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 7(3) के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में चीन जन. गण के दूतावास को उपलब्ध कराई थी।

च) भारत में चीन जन. गण. के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी चीन जन. गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ भेजी गई थी।

छ) प्राधिकारी ने ऐसी विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों जिनसे प्रतिसंतुलनकारी लाभ चीन सरकार (जीओसी) द्वारा दिया गया हो के संबंध में संगत तथ्य/सूचना मांगने के लिए चीन सरकार (जीओसी) को प्रश्नावलियां भेजीं। जीओसी ने प्रश्नावली का उत्तर दिया जिसपर विचार किया गया है।

च) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7 (4) के अनुसार चीन जन. गण. के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली भेजी:-

क्र. सं.	निर्यातक का नाम	क्र. सं.	निर्यातक का नाम
1.	शेडोंग यिनवाओ टायर ग्रुप कंपनी लिमिटेड, टियांग औद्योगिक क्षेत्र, शोगुआंग सिटी, शेडोंग	2.	शेडोंग हेंगफेंग रबर एंड प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड, दावांग इकानामिक जोन

	प्रांत, चीन - 262735		गवांगराव काउंटी शेडोंग चीन- 257335
3.	एओलस टायर कंपनी लिमिटेड नंबर 48, जियाओदोंग साउथ रोड, जिआझू, हेनान, चीन- 454003	4.	ओयुआन रबर प्राइटेक्ट कं, लिमिटेड नं. 777, जिल्लोंग रोड, झोयुआन यंताई, शेडोंग, चीन -265400
5.	किंगदाओ डबलस्टार टायर औद्योगिक कं, लिमिटेड 95 किंगदाओ रोड, जियाओन डेवलपमेंट जोन, किंगदाओ, चीन- 266400	6.	हांगझू झोंगसी रबड कं, लिमिटेड, नंबर 2, 10वां एवेन्यू, इकानामिक डेवलपमेंट जोन, जेजियांग प्रांत, चीन -310008
7.	हाओयू टायर कं, लिमिटेड मिडिल सेक्शन आफ फेंग्सू रोड इंडस्ट्रियल पार्क, बो ई, जियाझू हेनान प्रांत, चीन -454450	8.	द्रायंगल टायर कंपनी लिमिटेड 56 मिडिल किंगदाओ रोड, विहाई, शेडोंग प्रांत, चीन-264200
9.	शेडोंग वांडा बोतो टायर कं, लिमिटेड 68 योगशेन रोड, डोंगयिंग सिटी, शेडोंग प्रांत, चीन-257506	10.	शंघाई टायर एंड रबर कं, लिमिटेड शंघाई म्यूनिसिपेलिटी नंबर 63, सिचुआन सेंट्रल रोड ।, शंघाई, शंघाई, चीन-200002
11.	जिआंगसू जनरल साइंस टेक्नालाजी कं, लिमिटेड होंग्डू औद्योगिक क्षेत्र, गंगकिसया टाउन, वूशी सिटी, जिआंगसू प्रांत चीन -214199	12.	डबलस्टर-डोंगफेंग टायर कं, लि नंबर 221, हंजियांग रोड, शियान, हुबेई, चीन -442053
13.	गीति रेडियल टायर (अनहुई) कंपनी लिमिटेड नंबर 18, शिक्सन रोड, हेफेई इकोटेक डेवलपमेंट ज़ोन, हेफेई अनहुई, चीन- 230601	14.	शेनज़ेन युआन्युनझी ट्रेडिंग कं, लि. 202 हाईटेज, हैलोंगहुआयुआन, फेन्गुआंग रोड, लुओहु डिस्ट्रिक्ट, शेनज़ेन, गुआंगडोंग प्रांत, चीन-518002
15.	किंगदाओ येलो सी रबर कंपनी लिमिटेड नंबर 1 कंगन रोड, किंगदाओ, शेडोंग प्रांत, चीन -266041	16.	केंडा रबर (चीन) कं, लिमिटेड नंबर 2, कुंजिया रोड ।, पेनलंग टाउन, कुशान, सूज़ौ, जिआंगसु, जिआंगसु प्रांत, चीन 215333

17.	शेंगताई ग्रुप कं. लिमिटेड शिंसुई इंडस्ट्रियल पार्क आफ गुंदगराओ कंट्री शेडोंग प्रांत, चीन -257336	18.	पिरेली टायर कं. लिमिटेड यिनहे इंडस्ट्रियल पार्क, यनज्होऊ, जीनिंग, शेडोंग प्रांत, चीन -272100
19.	गुआंग राव इकानामिक एंड टेक्नालाजी डेवलपमेंट जोन, डोंगयिंग, शेडोंग प्रांत, चीन -257300	20.	डिंगयिंग झोंग यि रवड कं. लिमिटेड गुआंग आर्थिक विकास क्षेत्र, गुआंगराव डोंगिंग शेडोंग प्रांत, चीन -257335
21.	कुपो चेंगशान (शेडोंग) टायर कं. लिमिटेड नंबर 98, नानशान एन रोड रांगचेंग, वीहाई	22.	शेन जेन सिटी हांग यू काई ट्रेड कं. लिमिटेड नंबर 12 एच यिनवोगे, हहुई हवेली, नान्यौ एवेन्यू, शेन्जेन, गुआंगडोंग प्रांत, चीन - 518000
23.	शेन्जेन डिस्ट्रोलन व्यापार कं. लिमिटेड नंबर 4, लेन 5, ज़िनसेंकू, जेनपुलिंग रोड, ननलियन जियांग, लॉन्गगैंग टाउन, लांगगांग डिस्ट्रिक्ट शेन्जेन गुआंगडोंग प्रांत, चीन - 518116	24.	गुआंगज्जौ पर्ल रिवर रबर टायर लिमिटेड तनु टाउन, हुदू जिला, गुआंगज्जौ शहर, गुआंगडोंग प्रांत, चीन -510828
25.	मिशेल (श्यांग) टायर कं. लिमिटेड नंबर 15 शेनक्सिन रोड इकानामिक - तकनीकी डेवलपमेंट, शेनयांग लिओनिंग प्रांत, चीन -110141	26.	पिरेली टायर कं. लिमिटेड यिनहे औद्योगिक पार्क, यनज्होऊ, जीनिंग, शेडोंग प्रांत, चीन -272100
27.	किंगदाओ डबलस्टार टायर इंडस्ट्रियल कं. लिमिटेड 95 ब्लॉक रोड, जियाओन विकास क्षेत्र किंगदाओ, चीन - 266400	28.	किंगदाओ पीला सागर रबर कंपनी लिमिटेड, नंबर 1 कंगन रोड, किंगदाओ, शेडोंग प्रांत, चीन -266041
29.	शेडोंग शिंगयुआन इंटरनेशनल ट्रेडिंग शिन्शुई इंडस्ट्रियल गुआंगराव काउंटी डांगयिंग सिटी, शेडोंग प्रांत चीन -257336		

अ) प्रत्युत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्धारित प्रारूप में निर्यातिक प्रश्नावली का उत्तर दिया:

- i. मै. शेडोंग हाओहुआ टायर कंपनी लिमिटेड
- ii. मै. गुआंगज्जौ एक्सिड इंडस्ट्रियल टेक्नालाजी कं लिमिटेड
- iii. मै. एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लिमिटेड
- iv. मै. एलोस टायर कंपनी लिमिटेड
- v. मै. किंगदाओ यलो शी रबड कं लिमिटेड
- vi. मै. शेडोंग योगफेंग टायर कंपनी लिमिटेड
- vii. मै. झोंगसी रबड ग्रपु कंपनी लिमिटेड
- viii. मै. शेडोंग वांडा बोटो टायर कंपनी लिमिटेड
- ix. मै. ट्रायंगल टायर कंपनी लिमिटेड

ज) जाँच शुरूआत अधिसूचना के अनुपालन में, संबद्ध देश से उपरोक्त उत्पादकों/निर्यातकों के अलावा चीन जन. गण. सरकार ने भी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।

ट) नियमावली के नियम 7 (4) के अनुसार प्राधिकारी ने आयातक प्रश्नावली को भारत में निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/संबद्ध वस्तु के प्रयोक्ताओं को आवश्यक जानकारी के लिए भेजा:

क्र.सं	आयातक का नाम	क्र.सं	आयातक का नाम
1.	ए.जी इंडस्ट्रीज पेट्रोल पंप के पास, बस स्टैंड के सामने, सिरसा रोड, हिसार / हरियाणा पिन -110065	2.	ए.एस. एंड कंपनी 2343, तिलक बाजार खारी बावली, दिल्ली पिन-110006
3.	आदित्य सेल्स कॉर्पोरेशन, 333, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली – 110065	4.	ए.जी.के डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, 703 कृष्णा एप्रा विजनेस स्क्वायर, प्लॉट नंबर डी -4 / 5/6, नेताजी सुभाष एलेस, दिल्ली -110034
5.	अड्डखिल इंपेक्स विलिंग आर.के. समाज, सहदेव मार्केट जालंधर, पिन -144001	6.	एलायंस ट्रेडर्स, दूसरी मंजिल, टी-770 डीसीएम रोड किशन गंज दिल्ली
7.	अमित एंटरप्राइजेज, परफेक्ट मैरिज पैलेस के पास, अंबाला बाय पास रोड, समरला चौक के पास, लुधियाना- 141009	8.	अरोड़ा एंटरप्राइजेज, 51/45 वाजोरिया मार्केट, नयागंज कानपुर, उत्तर प्रदेश, पिन -208001
9.	असिस एंटरप्राइजेज 2, गुरुनानक निवास, डोंगरी पाडा, किंग कांग नगर, जी.वी.रोड,	10.	भगवती इम्पेक्स केबिन नंबर -6, 294, बेसमेंट, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली -110065

	ठाणे पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र		
11.	कैपटाउन ओवरसीज सी 244, मिंटो रोड कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	12.	सेलाइट टायर कॉर्पोरेशन बी / 16, विहारी अपार्टमेंट, एनआर। वेलकम होटल, आर.सी.दत्त रोड, बडौदा-390007
13.	चड्डा टायर ट्रेडर्स 69, परिवहन केंद्र, रोहतक रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली -110035	14.	च्याबडा सेल्स कॉर्पोरेशन 122/235, सरोजनी नगर, नई दिल्ली
15.	दशमेश ट्रेडिंग कंपनी 804 / बी, ओडिसी भक्ति पार्क, वडाला एन.आर. इमेक्स सिनेमा, मुंबई महाराष्ट्र-400037	16.	डीप इंटरप्राइजेज लालडिगमी गणेश गंज, मिर्जापुर, यूपी -231001
17.	दिल्ली टायर शाप F-7, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली -110065	18.	एकनूर टायर्स प्राइवेट लिमिटेड। एम. एच. विल्डिंग नं. 1 आर.सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई
19.	इलेक्ट्रो लिंक 5/356 बी, सी और डी, इस्वरमंगलम, पोन्नानी, मालापुरम, केरल, इंडिया पिन-679573	20.	एस् इंफ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड विलियम कंपाउंड, आफ. मारवे रोड, मिठ चौली, मलाड (डब्ल्यू) मुंबई
21.	फाइन ट्रेडर्स जी -12 / 334, गली नंबर -12 ब्लॉक-जी संगम, विहार, दिल्ली	22.	फिश एक्स्प्रेस होम एच -16, विकास मार्ग लक्ष्मी नगर, दिल्ली
23.	गणपति ओवरसीज़ आरजेडए-72, ए ब्लॉक द्वारका, नई दिल्ली	24.	जेनेटिक सेल्स कॉर्पोरेशन 7 ए / 28, पहली मंजिल डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग नई दिल्ली, पिन -110005
25.	ग्लोबस कॉर्पोरेशन ए-301, प्राइम एप्स। पी.पी. मार्ग, विराट नगर, विराट, पश्चिम, मुंबई	26.	गुसा टायर हाउस 328, ऑटो मार्केट, हिसार / हरियाणा
27.	एच. डी. इंटरनेशनल एस धी मंडी अमृतसर पंजाब	28.	एच.एस. अरोरा एंड कंपनी, एफ -5 / 1 ए, भगत सिंह मार्केट, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110015
29.	एच. एस. इंटरनेशनल	30.	हरप्रीत इंटरनेशनल

	सी -192, वेसमेंट दुकान नंबर -2, पुष्पांजलि एन्क्लेव, पीतमपुरा दिल्ली -110034		वी -5 करमपुरा, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली पिन - 110015
31.	हायर ट्रेडिंग कं. लि. दुकान नंबर 2, द हायर प्रीमियम ओप्स शिशु विहार, मराठी स्कूल, रामवाग लेन नंबर 6, कल्याण-पश्चिम -421301	32.	हिंद ट्रेडर्स, सी विंग नंबर 234, स्टील चैंबर, प्लॉट नंबर 514, कालांबोली स्टील मार्केट, नवी मुंबई, महाराष्ट्र
33.	हिंद ट्रेडर्स बसरा नं .9 संगम विहार गली नंबर 10, ग्राम वज़ीरावाद, दिल्ली	34.	भारतीय रबड़ निर्माता अनुसंधान संघ, प्लॉट नंबर 254/1 वी, रोड नंबर 16 वी, वागले इंड. एस्टेट, थाणे वेस्ट, मुंबई महाराष्ट्र पिन- 400604
35.	इंडो चाइना इम्पेक्स 149-परिवहन केंद्र रोहतक रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली पिन -110035	36.	इंडो सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स पी. लिमिटेड 3/7, ब्लॉक-सी, अशोक विहार, फेज।।। नई दिल्ली, पिन -110052
37.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह 1238/5 नंददीप, पहली मंजिल, आप्टे रोड, दक्कन जिमखाना, पुणे / महाराष्ट्र	38.	जे.एम.शाम डिजाइन 494, मेलेग्रिना, लिंकिंग रोड, ऑफ वांदरा वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र पिन -400050
39.	जैपेक्स 1-15, संहिता इंडल। एस्टेट, ओर्काय मिल्स, साकीनाका के पीछे अंथरी (ई) मुंबई, महाराष्ट्र पिन -400059	40.	जितेंदर ओवरसीज डी-149 भू तल, एनआर। मिलन सिनेमा करमपुरा नई दिल्ली पिन -110015
41.	जुनेजा एजेंसियां 267, ट्रांसपोर्ट नगर, सरब मल्टीप्लेक्स के सामने, जालंधर, पंजाब	42.	के.सी. इमपेक्स सी -64, ग्राउंड फ्लोर, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली पिन -110059
43.	कबीर कंपोनेंट्स प्रा. लिमिटेड सी-208 मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज -2, नई दिल्ली पिन -110064	44.	काक्स एंड विल्स प्राइवेट लिमिटेड एन -5 कैलाश कॉलोनी नई दिल्ली पिन -110048
45.	किंगस्टन एंटरप्राइजेज 7/8, गणेश नगर पांडव नगर	46.	लोकेश इमेक्स प्लॉट नंबर 3 नवलगढ़ हाउस एस सी

	कॉम्प्लेक्स, गली नंबर 1 बी, दिल्ली		रोड, जालूपुरा, जयपुर, राजस्थान
47.	एम एस इंटरनेशनल एच। सं।-174, स्वामा अपार्टमेंट के पास गांव - पीतमपुरा, दिल्ली	48.	मंकेश ट्रेडिंग कंपनी गू -74 टाव फ्लोर तिरुपति परिसर, शकरपुर दिल्ली
49.	मीनाक्षी इंपोर्ट्स 2 अमृत भवन 65 डी लिंकिंग रोड, सांता कूज़ बॉम्बे, महाराष्ट्र पिन -400054	50.	मोहन एंटरप्राइजेज डी-262 करमपुरा नई दिल्ली
51.	नंद रबड़ प्रा.लि. धनी पंडित किशन दत्त, XII क्वार्टर रोड, हिंसार / हरियाणा पिन 125001	52.	नेशनल ट्रेडिंग कंपनी 14, सी-ब्लॉक, डीडीए मार्केट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली पिन -110095
53.	न्यू विकास टायर 92, एमएम रोड, बारा हिंदू राव दिल्ली पिन -110006	54.	पाहवा डिस्ट्रीब्यूटर्स 81/20-ए, शिवपुरी जी.वी.रोड लखनऊ, यूपी - 226018
55.	पारस ऑटो पार्ट्स शॉप नंबर 4, प्लॉट नं .70, पीजेपी चैंबर, सेक्टर - 9 सी, गांधीधाम (कन्द्र) पिन 370201	56.	परदीप इंपोर्ट एक्सपोर्ट दुकान नंबर 2/3, साईनाथ बिल्डिंग, अजीज बाजार, चेंबूर, मुंबई, महाराष्ट्र -400074
57.	पायनियर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 178 चड्डा हाउस, एस.वी.पी.नगर, म्हाडा लेआउट, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई, महाराष्ट्र - 400053	58.	प्रेम ट्रेडिंग कंपनी 57, हर्ष नगर, सुभाश नगर, संस्कार सेंटरी स्कूल के पास, जवलपुर म.प्र. पिन -482002
59.	प्रिकॉन इंजीनियरिंग सर्विसेज 90, नेशनल पार्क लाजपत नगर- IV नई दिल्ली पिन -110024	60.	आर सी इंटरनेशनल सी -33, मारुति धाम, आनंद नगर, वसई पश्चिम, ठाणे महाराष्ट्र पिन -401202
61.	आर एस एंटरप्राइजेज 122/235, सरोजिनी नगर -2, कमरा नं 61, सेक -20 जोर्ड, नवी मुंबई - 400705	62.	राधे किशन एंटरप्राइजेज 2263/68 भूतल शॉप न .3 गली।।-लिंगा वेग फाटक हब्स खान खारी बावली दिल्ली
63.	राजपाल रोडलाइंस प्राइवेट लिमिटेड 23, सेवरी परिसर सोसायटी, 2 मंज़िल,	64.	रामेश्वर दास एंड कंपनी वी -584, नेहरू ग्राउंड एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा

	सेवरी फोर्ट रोड, सेवरी (ई), मुंबई, महाराष्ट्र		
65.	रंगी रोड कैरियर दुकान नंबर 3, कावले कॉम्प्लेक्स दत्ता नगर, हिंगोली रोड, रेलवे ओवर ब्रिज के पास, नांदेड / महाराष्ट्र	66.	रेणु राज ट्रेडिंग डी -303, मोटा नगर, चकला , अंधेरी- पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र, पिन -400099
67.	रोडलियन इंटरनेशनल लेन नंबर 7, बरारी रोड खसरा नंबर 5/5, 5/6, स्वरूप नगर समयपुर, दिल्ली पिन -110042	68.	रॉयल ट्रेडर्स शॉप नं .2, पहली मंजिल मां घोरी परिसर, डब्ल्यूजे-97 पंजाबी बाग, दिल्ली पिन 110063
69.	रायना ओवरसीज (भारत) 540/1, गीतांजलि, 13 वां रोड, टीपीएस एलआईआई, खार (डब्ल्यू), मुंबई	70.	एस आर एंटरप्राइजेज ई-109, पहली मंजिल, करमपुरा, दिल्ली
71.	एस.एस. एंड संस 2343, पहली मंजिल, तिएक बाजार चांदनी चौक दिल्ली	72.	एस.के. अंतरराष्ट्रीय बी -3 / 13, जनकपुरी, नई दिल्ली पिन -110058
73.	सरवन एंटरप्राइजेज 219, दूसरा तल विशाल टॉवर जिला केंद्र, जनक पुरी, नई दिल्ली	74.	सभरवाल ट्रेडिंग कंपनी 3099, संख्या 36 शॉप नं. 4, बीडोनपुरा करोल बाग दिल्ली
75.	सचिन प्रसाद यादव, 20 ए / एच / 2, पॉटरी रोड, कोलकाता, प.बं. पिन -700015	76.	समर ट्रेडर्स 6528, मेन रोड बारा हिंदू राव दिल्ली पिन -110006
77.	संजोग इंपेक्स 6/2, दक्षिण तुकोगंज, मधुमुखी चौक, इंदौर, म.प्र. पिन - 452001	78.	सनमताल पोर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड वाई-434/7 आदर्श एन्कलेव प्रेम नगर
79.	सत गुरु ट्रेडर्स 148 प्रथम तल सिविल लाइंस सदर आजमगढ़ उ.प्र. पिन -276001	80.	सवीर इंटरनेशनल 703, कृष्णा एप्रा बिजनेस स्कायर प्लॉट नंबर- 4/5/6, नेताजी सुभाष जगह, जिला।

			वजीरपुर, नई दिल्ली पिन -110034
81.	शिव शक्ति एंटरप्राइजेज 10 राम पार्क, किशन गांज, दिल्ली	82.	शिवालिक एकिजम एससीओ 21-25, केविन नंबर 20, सेक्टर 70, विवेक हाई स्कूल के सामने, मोहाली। (पंजाब)
83.	सिमरन इंडिया इंक, D-139, करमपुरा, नई दिल्ली पिन -110015	84.	सिमरन ट्रेडर्स हाउस नंबर 160 ग्राउंड फ्लोर चंद नगर, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली
85.	सोम प्रोजेक्ट्स एंड एसोसिएट्स दुकान नंबर 5, प्लॉट नंबर, ए 2 ब्लॉक, कंवर सिंह नागर, नांगलोई दिल्ली पिन -110041	86.	श्री एंड कं., नं. 16/2, एल.बी.एफ.रोड, बैंगलोर, कर्नाटक
87.	श्री कुमारन ट्रेडर्स नंबर 5, 6, 7, 4/1, ग्राउंड फ्लोर, दूसरा क्रॉस, रुद्रप्पा कम्पाउंड, एच। सिद्धजाह रोड, बैंगलोर	88.	श्री टायर्स नं. 22/4 कर्नाटक परिसर लालबाग किला रोड बैंगलोर पिन -560004
89.	सुमंत बच्छावत 189, बांगुर एवेन्यू, ब्लॉक-बी, कोलकाता, पं. ब., पिन -700055	90.	सन ट्रेडर्स 7 ए / 28, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, दिल्ली
91.	सुप्रीम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 104 शिवलोक हाउस-एल करमपुरा कं., नई दिल्ली पिन -110015	92.	सुरोध्या सेल्स जी -1990, पुष्कर एन्कलेव पश्चिम विहार, नई दिल्ली पिन -110063
93.	ट्रांस टायर्स (भारत) प्रा.लि. 193, चकला स्ट्रीट, मुंबई, महाराष्ट्र पिन -400003	94.	यूनिग्लोरी इंटरनेशनल के -1 प्रथम तल कैलाश कॉलोनी नई दिल्ली पिन -110048
95.	वान सेल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड टी-770, डीसीएम रोड, वाडा हिंदू राव, दिल्ली - 110006	96.	विकास रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, एजी 103, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, नई दिल्ली -110042
97.	वोरटेक्स रबड इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड 98-ए, पॉकेट डी, ग्राउंड फ्लोर अशोक विहार, फेज -2 दिल्ली -110052	98.	वृदा ओवरसीज फ्लैट नंबर -27, एफ / एफ, कोडली घरोली, मयूर विहार, पहसे-एलएल, नई दिल्ली
99.	ज़ाफको इंडिया प्रा. लिमिटेड		

	1 ए वंधना, 11, टॉल्स्टॉय मार्ग नई दिल्ली -110001		
--	---	--	--

ठ) किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने उत्तर नहीं दिया और आयातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं प्रस्तुत किया।

ड) ऊपर उल्लिखित प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों के अलावा, इस जाँच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित पक्षों की ओर से कुछ विधिक अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं।

- भारत में चीन जन. गण. का दूतावास
- आल इंडिया टायर डीलर्स एसोसिएशन

ढ) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों और किए गए अनुरोधों को हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया था।

ण) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से जाँच अवधि समेत विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार ब्योरे की जानकारी देने का अनुरोध किया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए। प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जाँच के बाद आयातों की मात्रा और अपेक्षित विश्लेषण की गणना के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

त) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-॥। के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) जात की गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि सब्सिडी मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

थ) आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन वास्तविक सत्यापन के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा किया गया था। वर्तमान प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ जहां आवश्यक हो वहां आवश्यक सुधार सहित केवल इस तरह की सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया गया है।

द) उत्पादकों/निर्यातकों और चीन सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना का आवश्यक सीमा तक सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया था और वर्तमान प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा किया गया है।

ध) वर्तमान सब्सिडीरोधी जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) अक्टूबर, 2016 से सितम्बर, 2017 (12 महीने) है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017 की अवधि तथा जाँच की अवधि पर विचार किया गया है।

न) नियमावली के नियम 7 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने 28 अगस्त, 2018 को हुई मौखिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। पक्षों से विरोधी पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां लेने और अपने खंडन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

प) हितबद्ध पक्षों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/खंडनों में दिए गए तर्कों पर वर्तमान अंतिम जाँच परिणाम में विचार किया गया है।

फ) इस जाँच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए अनुरोधों पर अंतिम जाँच परिणाम में ध्यान दिया गया है।

ब) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जाँच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।

भ) जहां भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया अथवा उसे अन्यथा

उपलब्ध नहीं कराया या जांच में अत्यधिक बाधा डाली तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षों को असहयोगी माना है और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अंतिम जांच परिणाम को दर्ज किया है।

य) संबंधित नियमावली के नियम 18 के अनुसार प्राधिकारी ने 6 मार्च, 2019 को जारी प्रकटन विवरण द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जांच के अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया और उनसे 13 मार्च, 2019 तक प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत करने को कहा। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों पर संगत समझी गई सीमा तक वर्तमान जांच परिणाम में ध्यान दिया गया है।

र) पीओआई के लिए विनियम दर प्राधिकारी द्वारा 1 अमरीकी डॉलर = 66.70 रुपये के रूप में लिया गया है।

ल) इस अधिसूचना में ***** चिन्ह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अधीन प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरूआत के समय, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है : वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद " बसों या लारियों के लिए न्यू न्यूमेटिक टायर" हैं, जो सीमाशुल्क उपशीर्ष 4011.20 के तहत वर्गीकृत हैं।

5. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु, चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अश्वा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु हैं। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "बसों या लारियों में उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के रबर का न्यू न्यूमेटिक टायर, चाहे छूब के साथ या बिना रेडियल या बायस और/या फ्लैप के बिना, है, जिसे 4011.20 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।"

ख) टायर, छूब और फ्लैप अलग-अलग उत्पादित होते हैं। तथापि, वे आटोमोटिव मोटर वाहन अनुप्रयोगों में विशेष रूप से एक साथ उपयोग किए जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद को अध्याय 40 में सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 4011.20 के तहत वर्गीकृत किया गया है और छूब और फ्लैप को क्रमशः 4013.1010 / 4013.1020 और 4012.9049 के तहत वर्गीकृत किया गया है।

ग) यद्यपि बसों और लारियों के लिए रेडियल टायरों के उत्पादन की लागत बसों और लारियों के लिए बायस टायरों की तुलना में अधिक है और भले ही घरेलू उद्योग बायस टायरों को रेडियल वन (प्रति किलोग्राम आधार पर) से मापूली कम कीमत पर बेच रहा है, फिर भी रेडियल टायरों के आयात की पंहुच कीमत न केवल रेडियल टायरों से कम है, बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले बायस टायर से भी कम हैं।

घ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान हैं। दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें नियमों के तहत समान वस्तु माना जाना चाहिए।

इ) टीबीबी टायर्स का समावेश वर्तमान जांच में आवश्यक है क्योंकि टीबीबी और टीबीआर दो अलग-अलग तकनीकों में से प्रतिस्थापन योग्य उत्पाद हैं और इनका उपयोग परस्पर किया जा रहा है। इसके अलावा, जिन कीमतों पर टीबीआर का आयात किया जा रहा है, वे घरेलू उद्योग के टीबीबी मूल्य से भी कम हैं। जहां तक इस तर्के संबंध है कि टीबीबी को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि कोई आयात नहीं हुए है, यह अनुरोध किया जाता है कि सी बी डी जांच विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है, जिसमें बायस और रेडियल टायर दोनों शामिल हैं। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क सभी प्रकार के विचाराधीन उत्पाद पर लगाया जा सकता है, बशर्ते कि यह समान वस्तु के साथ वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा करता हो और इसका आयात क्षति का कारण बन सकता हो। याचिकाकर्ता प्राधिकारियों का ध्यान हुवेई टैक्नालोजीज कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर आकर्षित करना चाहता है, जिसमें सेस्टेट ने निम्नलिखित माना था :

एसटीएम 256 के संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि यह उत्पाद न तो भारत में उत्पादित किया गया था और न ही जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारत में आयात किया गया था। यह हमारे विचार में महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जांच उत्पाद के संबंध में है, न कि उत्पाद के प्रकार के संबंध में। हम घरेलू उद्योग के वकील से सहमत हैं कि जब तक उत्पाद आयात किया जाता है, तब तक सभी प्रकार के उत्पाद पर शुल्क लगाया जा सकता है, बशर्ते कि इस तरह का उत्पाद भारत में बनी वस्तु के साथ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में हो और इसके आयात से क्षति हो सकती हो। एसटीएम 256 एसटीएम 64 का एक उच्च संस्करण है। एसटीएम 256 यदि कम कीमत पर दिया जाए तो वह एसटीएम 64 को प्रतिस्थापित कर सकता है और भारत में एसटीएम 64 के लिए बाजार के लिए क्षतिकारी हो सकता है।

च) वर्तमान मामले में टीबीआर का आयात ऐसी कीमत पर किया जा रहा है, जो घरेलू उद्योग द्वारा बेचे जाने वाले टीबीबी की कीमत से भी कम है, यह अधिक संभावना है कि यह टीबीआर बाजार के अलावा, घरेलू उद्योग के टीबीबी बाजार पर कब्जा करेगा। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हुवेर्इ मामले में, यहां तक कि जब घरेलू उद्योग एक विशेष उत्पाद प्रकार की आपूर्ति नहीं कर रहा था और उत्पाद प्रकार के शून्य आयात थे ऐसे उत्पाद प्रकार को केवल इस आधार पर शामिल किया गया था कि उत्पाद प्रकार अन्य उत्पाद प्रकार के साथ प्रतिस्थापनीय है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद प्रकार की क्षति का कारण बन सकता है। वर्तमान मामले में, भारत में एक बड़ा टीबीबी बाजार है, जहां कई भारतीय निर्माता टीबीबी की आपूर्ति कर रहे हैं, इसलिए टीबीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन से अलग करना अनावश्यक और जांच के लिए हानिकारक होगा।

छ) इस तथ्य कि चीन जन. गण. से आयातित टीबीआर टायर, टीबीबी टायरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, को चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'बसों और लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त न्यू/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों, ट्यूब सहित या रहित और/या रवड के फ्लेप (ट्यूबलैस टायर सहित) जिनका सामान्य रिम व्यास कोड 16 से अधिक हो' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के संबंध में अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था, प्रासंगिक भाग नीचे उद्धरित है:

तथापि, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चीनी टीबीआर के आयात से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टीबीबी और टीबीआर पर क्षति हो रही है। हितबद्ध पक्षों ने यह भी माना है कि देश भर में टायर उद्योग में रेडियलिसाइजेशन बढ़ रहा है। रेडियलाइजेशन का अर्थ है कि बायस टायर निरंतर बढ़ते हुए रेडियल टायर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। हालांकि यह सच हो सकता है कि टीबीआर और टीबीबी तकनीकी रूप से अलग-अलग उत्पाद हैं, लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं है कि टीबीआर तेजी से टीबीबी को प्रतिस्थापित कर रहा है। वास्तव में, हितबद्ध पक्षों ने खुद ही इसका विरोध किया है। घरेलू उद्योग का इस तर्क कि टीबीआर और टीबीबी का उपयोग एक ही लाई में भी हो रहा है, पर हितबद्ध पक्षों द्वारा खंडन नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि इस तरह का प्रतिस्थापन ओईएम (अर्थात् कोई नया ट्रक या बस बेचते समय) के स्तर पर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा तब हुआ है जब उपभोक्ताओं द्वारा टायर बदले जाते हैं।

ज) कजरिया सिरेमिक्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में यह माना गया कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक आकार या आयाम की टाइलें भारत में आयात शुल्क के लिए आयात की जाती हैं। कई प्रकार/आकार/आयाम हो सकते हैं, जिन्हें चीन में निर्मित किया जा सकता है और भारत को निर्यात नहीं किया जाता है। जब तक ऐसी किसी पीयूसी का हिस्सा हैं और समान वस्तु से वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में हैं और घरेलू उत्पादक को क्षति पहुंचा सकते हैं, तब तक उन्हें लेवी के दायरे में कवर किया जा सकता है।

झ) किसी विशेष प्रकार के आयात की अनुपस्थिति और पीयूसी के दायरे में उसी को शामिल किए जाने के तथ्य पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कोरिया से एनबीआर के मामले में विचार किया था।

ज) आंध्र प्रदेश केमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में निर्णय जिस पर हितबद्ध पक्षों द्वारा भरोसा किया गया है, पूरी तरह से अलग है और वर्तमान मामले पर लागू नहीं है। उस मामले में, सीसैट ने पाया कि विचाराधीन उत्पाद या वस्तु को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया था, और यह कि प्रत्येक एसाइक्लिक ऑक्सो-अल्कोहल एक अलग वस्तु थी, जिसके लिए अलग पाटन और क्षति की जांच की आवश्यकता थी। यह इस संदर्भ में है कि सेस्टेट ने यह माना कि कोई वस्तु, जिसे आयात नहीं किया गया है, शुल्क लगाए जाने के अधीन नहीं हो सकती है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किए जाने की मांग करने वाले उत्पाद को भारत में आयात किया गया था, लेकिन घरेलू उद्योग ने इस तरह की वस्तु की

आपूर्ति नहीं की और इसलिए इसका समावेश अनुचित पाया गया। वर्तमान मामले में, चीन और भारत में टीबीबी का उत्पादन किया जा रहा है। इसे पीओआई के दौरान आयात नहीं किया गया है, लेकिन चीन और भारत दोनों में इसका उत्पादन जारी है।

ट) माननीय सेस्टेट ने इसी सिद्धांत पर आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी को हुवेर्इ टेक्नालाजीज कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में बदल दिया था।

ठ) आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टेट का निर्णय वर्तमान मामले में यहाँ लागू नहीं है क्योंकि टीबीबी टायर एक भिन्न या पृथक उत्पाद नहीं है, बल्कि बस और लॉरियों के लिए एक प्रकार का न्यू न्यूमेटिक टायर है, जो कि पीयूसी है। बायस और रेडियल टायर दोनों विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा हैं।

ड) यूएस अथॉरिटी ने चीन जनवादी गणराज्य से कुछ पैसेंजर ब्हीकल और लाइट ट्रक टायर्स के लिए अपनी जांच के दायरे में कहा कि पैसेंजर ब्हीकल या लाइट ट्रक साइज के साथ पैसेंजर ब्हीकल और लाइट ट्रक टायर रबर के न्यू न्यूमेटिक टायर हैं। उस जांच द्वारा कवर किए गए टायरों में घूब-प्रकार, घूबलेस, रेडियल या गैर-रेडियल शामिल थे, जिसका उद्देश्य मूल उपकरण निर्माताओं या प्रतिस्थापन बाजार में विक्री के लिए हो सकते हैं। यूएस अथॉरिटी ने अपने आदेश में माना कि दायरे में शामिल ओटीआर टायर या तो घूब-टाइप या घूबलेस, रेडियल या नॉन-रेडियल हो सकते हैं और इसलिए या तो मूल उपकरण निर्माताओं या प्रतिस्थापन बाजार में अभीष्ट विक्री के लिए हो सकते हैं।

ढ) इस प्रकार, बायस टायरों और रेडियल टायरों को अमेरिकी प्राधिकारी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से कुछ पैसेंजर ब्हीकल और लाइट ट्रक टायरों और चीनी जनवादी गणराज्य से कुछ न्यू न्यूमेटिक ऑफ-द-रोड टायरों को विचाराधीन उत्पाद माना गया है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद में दो प्रकार के टायर शामिल हैं—ट्रक और बस बायस टायर (टीबीबी) और ट्रक और बस रेडियल टायर (टीबीआर) और दोनों उत्पादों को अलग-अलग पाटनरोधी शुल्क के अधीन रखा गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया कि दोनों तकनीकी रूप से अलग-अलग उत्पाद हैं और टीबीआर तेजी से टीबीबी को प्रतिस्थापित कर रहा है। इसके आलोक में, यह स्पष्ट है कि दोनों उत्पादों को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि उन्हें नियम 2 (ग) के तहत समान वस्तु नहीं कहा जा सकता है।

ख) इसके अलावा, प्राधिकारी ने टीबीबी तक शुल्कों का विस्तार नहीं किया, क्योंकि घरेलू उद्योग यह सावित करने में विफल रहा कि टीबीबी के कारण किसी भी तरह की क्षति हुई या क्षति होने की संभावना है। अतः इन दोनों को जोड़ा जाना केवल टीबीबी पर शुल्क लगवाये जाने का एक प्रयास है। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि टीबीबी को इस जांच के दायरे से बाहर रखा जाए।

ग) न्यू न्यूमेटिक टायरों के डीजीसीआईएंडएस आयात आकड़ों से पता चलता है कि पीओआई के दौरान सभी आयात न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायरों के हैं।

आयात चीन जन. गण.	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
रेडियल टायर	एमटी	30,665	69,982	81,896	61,203
बायस टायर	नग	0	0	0	1

घ) पाटनरोधी शुल्क जांच उत्पाद पर शुरू नहीं की जा सकती है जब जांचकर्ता देश में ऐसे उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ हो। यह आंध्र पेट्रोकेमिकल्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माना गया था। इसलिए, बसों और लॉरी के लिए न्यू न्यूमेटिक बायस टायर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना आवश्यक है।

इ) प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 2 (ब) के साथ पढ़े जाने वाले सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 वी (1) (ख) (ii) के लिए आवश्यक है कि आयातित उत्पाद को समान वस्तु के विनिर्माण में शामिल घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण होना चाहिए। समान वस्तु एक ऐसी वस्तु है जो जांच के अधीन उत्पाद के सभी तरह से एक जैसी या समान है। इसलिए, बस और लॉरी के लिए केवल न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर को शामिल करने के लिए घरेलू समान उत्पाद को सीमित किया जाना चाहिए। यह बात चीन जन. गण. से न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर्स संबंधी पाटनरोधी जांच में देखी गई थी।

च) विचाराधीन उत्पाद को हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर इस्तेमाल किए जाने वाले 17.5 इंच छूबलेस के सामान्य रिम व्यास वाले टायर को बाहर रखा जाना चाहिए और हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर 16 इंच और उससे नीचे के नामिनल रिम व्यास वाले टायर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भारत में बस और लारी या ट्रक छूब टाइप टायर के लिए रिम व्यास कोड 20 इंच और छूबलेस टायर के लिए केवल 22.5 टायर का उपयोग करते हैं।

छ) घरेलू उद्योग का दावा है कि बसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक रेडियल टायर आयात किए गए हैं, जिनका उपयोग घरेलू स्तर पर उत्पादित रेडियल टायर के साथ-साथ बायस के टायर के साथ किया जाता है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग यह दर्शाता है कि दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें नियमों के तहत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले में विचाराधीन (पीयूसी) उत्पाद बसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक टायर हैं। इस प्रकार, पीयूसी में नए न्यूमेटिक रेडियल टायर और नए न्यूमेटिक बायस टायर दोनों शामिल हैं। नए न्यूमेटिक टायरों के डीजीसीआईएंडएस आयात आकड़ों से पता चलता है कि क्षति की जांच अवधि में चीन जन. गण. से नए न्यूमेटिक बायस टायरों का कोई आयात नहीं हुआ है। बायस टायर के आयात केवल एक नमूना लेनदेन है। जब जांचकर्ता देश में इस तरह के उत्पाद का कोई आयात नहीं होता है तो उत्पाद पर पाटनरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच शुरू नहीं की जा सकती है। आंध्र प्रेट्रोकेमिकल्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (2011) ई.एल.टी. 481, के मामले में माननीय सेस्टेट ने निर्णय दिया कि:

"इसके अलावा, यह धारा 9 क (1) के प्रावधानों से स्पष्ट है कि न केवल वस्तु को आयात के उद्देश्य के लिए पहचाना जाना चाहिए, बल्कि यह एक वस्तु होनी चाहिए जिसे किसी भी देश या क्षेत्र से भारत को निर्यात किया जाता है। इसलिए, निर्यात देश से पहचानी गई वस्तु लेवी का आधार होती है जब इसे अपने सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया जाता है और आयात पर पाटन के मार्जिन से अधिक नहीं होने के कारण उस पर पाटन रोधी शुल्क लगाया जा सकता है। **किसी वस्तु जिसका भारत को निर्यात नहीं किया गया है को इसलिए, अधिनियम की धारा 9 क (1) जो आयात का आधार निर्धारित करती है, के तहत पाटन रोधी शुल्क के अधीन नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, अब तक के अंतिम जांच परिणाम में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि भारत में आयात नहीं की गई वस्तुओं पर शुल्क नहीं लगाया गया है। इसी कारण से जिन वस्तुओं का आयात नहीं हुआ है उन पर पाटन रोधी शुल्क लगाना उचित नहीं था।" (इस पर जोर दिया)**

ज) यदि बसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक बायस टायर भारत में आयात नहीं किए जाते हैं, तो बसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक टायर के व्यापक दायरे में इसे शामिल करके ऐसे उत्पादों के खिलाफ जांच शुरू नहीं की जा सकती है। बसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक बायस टायर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किए जाने की आवश्यकता है।

झ) समान वस्तु कोई ऐसी वस्तु है जो जांच के तहत उत्पाद के लिए सभी तरह से एक जैसी या समान है। जैसा कि कहा गया है, चीन जन. गण. से भारत में सभी आयात बसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक रेडियल टायर हैं। तदनुसार, बस और लॉरियों के लिए केवल नए न्यूमेटिक रेडियल टायर शामिल करने के लिए घरेलू समान उत्पाद को भी सीमित किया जाना चाहिए। चीन जन. गण. से न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर्स पर पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी पहले ही यह मान चुके हैं कि वास्तविक क्षति का आकलन समान वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग के लिए किया जाना चाहिए और घरेलू रेडियल टायर को आयातित रेडियल टायर की समान वस्तु माना जाए। प्राधिकारी ने यह समुक्ति की कि:

"घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ट्रक और बस रेडियल (टीबीआर) टायर आयातित टीबीआर टायर के लिए तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टीबीआर चीन से आयातित टीबीआर के समान वस्तु हैं।"

ज) इस प्रकार, घरेलू उद्योग वर्तमान जांच में इस मुद्दे को फिर से नहीं उठा सकता है और दावा नहीं कर सकता है कि घरेलू रूप से उत्पादित बायस टायर को आयातित रेडियल टायर के समान वस्तु माना जाना चाहिए।

ग.३ प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में और घरेलू उद्योग की समान वस्तु संबंधी अनुरोधों को नोट किया है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं:

क) जांच में पहला कदम विचाराधीन उत्पाद की पहचान करना है। विचाराधीन उत्पाद आयातित उत्पाद है जो कथित रूप से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि वसों और लॉरियों के लिए केवल नए न्यूमेटिक रेडियल टायर भारत में आयात किए जा रहे हैं और बसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक बायस टायर का कोई आयात नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग का दावा यह भी है कि भारत में आयात किए जा रहे वसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक रेडियल टायर रेडियल टायरों के निर्माताओं के साथ-साथ उनके द्वारा निर्मित बायस टायर के लिए क्षति का कारण बन रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि वसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक बायस टायर भारत में आयात किए जा रहे हैं, इसलिए, विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों और घरेलू उद्योग के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, प्राधिकारी नए न्यूमेटिक को जांच से बाहर करने का प्रस्ताव करता है। बायस वसों और लॉरी के लिए उत्पाद के दायरे से विचाराधीन है। तदनुसार, वर्तमान जांच में जांचाधीन उत्पाद वसों और लॉरियों/ट्रकों में उपयोग किए जाने वाले "नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर के ट्यूब सहित या रहित और/या रवड़ के फ्लैप (ट्यूबलेस टायर सहित) जिनका 16 से नाममात्र अधिक रिम ब्यास कोड हो" हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में ट्यूब किस्म और ट्यूबलेस टायर दोनों शामिल हैं। ट्यूब वाले टायर में, टायर का उपयोग वाहन में एक ट्यूब और एक फ्लैप के साथ किया जाता है। एक टायर, एक ट्यूब और एक फ्लैप को एक साथ "टायर" के रूप में बेचा जाता है। सेट "और" टीटीएफ के रूप में वर्णित किया जाता है। "टायर सेट" को दर्शाने के लिए "टीटीएफ" शब्द उद्योग में प्रचलित है। टायर, ट्यूब और फ्लैप संयुक्त रूप से एक वाहन में "टायर" के रूप में कार्य करते हैं। टायर, ट्यूब और फ्लैप की विक्री मुख्य रूप से "टीटीएफ" या "टायर सेट" आधार पर होती है। ट्यूबलेस रेडियल टायर, जहां ट्यूब और फ्लैप की आवश्यकता नहीं है, इस भी जांच के दायरे में शामिल हैं।

ख) आयातित उत्पाद के दायरे में वसों और लॉरियों/ट्रकों में उपयोग किए जाने वाले रेडियल टायर शामिल हैं। टायर का इस्तेमाल आम तौर पर विभिन्न प्रकार के वाहनों जैसे ट्रक, बस, लॉरी, हल्के वाणिज्यिक वाहन, यात्री कार, जीप, ट्रैक्टर, दोपहिया, तिपहिया वाहन, पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहन, अर्थमूवर, औद्योगिक टायर, हवाई जहाज आदि में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद केवल उस प्रकार का टायर है जिसका उपयोग वसों और लॉरियों/ट्रकों में किया जाता है। अन्य सभी प्रकार के टायर वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

ग) विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 40 के तहत वर्गीकृत किया गया है, टायर को सीमा शुल्क उप-शीर्ष 40112010 के तहत वर्गीकृत किया गया है जबकि ट्यूब और फ्लैप क्रमशः 40131020 और 40129049 के तहत वर्गीकृत किए गए हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

घ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर चीन जन. गण. से आयात किए गए नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर के समान वस्तु हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन जन. गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं और चीन जन. गण. से आयातित वस्तु उत्पाद विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के मामले में सामूहिक और संचयी रूप से तुलनीय हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि सब्सिडीरोधी नियमों के अनुसार आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.१. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

9. घरेलू उद्योग के दायरे के संबंध में जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

क) चीन द्वारा संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडीप्राप्त आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने के लिए ऑटोमोटिव टायर निर्माता एसोसिएशन द्वारा आवेदन दायर किया गया था। एटीएमए के चार सदस्य, अर्थात अपोलो टायर्स लि., मेसर्स सिएट लिमिटेड, मेसर्स जे. के. टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एमआरएफ लि., ने सभी संगत जानकारी प्रदान करके वर्तमान जांच में भाग लिया है। याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। याचिकाकर्ता कंपनियां भारत से बाहर संबद्ध उत्पाद के किसी भी विनिर्माता-निर्यातिक से संबंधित नहीं हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता कंपनियां,

सभिसिडीरोधी नियमों के तहत प्रदान किए गए निर्धारित मानदंडों के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करती हैं और योग्यता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करती हैं।

घ.2. अन्य हितबद्ध पक्षों के अनुरोध

10. घरेलू उद्योग के दायरे और योग्यता के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

क) जैसा बताया गया है, वस और लॉरी के लिए केवल नए न्यूमेटिक रेडियल टायर शामिल करने के लिए घरेलू समान उत्पाद को संकुचित किया जाना चाहिए। प्रतिवादी ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह घरेलू उद्योग की स्थिति की ओर घरेलू उद्योग के इस दावे की भी पुनः जांच करे कि वह नए उत्पादन के लिए नए न्यूमेटिक बायस टायर को समान वस्तु दायरे से बाहर करने के बाद कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा निर्धारित करे।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. नियमावली का नियम 2(ख) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है तथा उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाइत वस्तु के नियर्तिकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

12. यह आवेदन ऑटोमोटिव टायर मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा अपोलो टायर्स लिमिटेड, जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड और सीएट लिमिटेड की ओर से दायर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियों ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या नियर्तिक से संबंधित हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियों का भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। तदनुसार, इस जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता कंपनियां नियमावली के नियम 2 (घ) और नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।

इ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

इ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

13. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) प्रतिवादी नियर्तिकों ने उनके द्वारा दायर प्रश्नावली में अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है। नियर्तिकों ने अधिकांश जानकारी के उचित अगोपनीय सारांश प्रदान किए बिना, गोपनीय रूप में होने का दावा किया है। इसके अलावा, नियर्तिकों ने सीमित संख्या में योजनाओं के लिए प्रतिक्रिया दी है, जो कि अधूरा उत्तर है। ये कार्रवाई सीवीडी नियमों के नियम 8 के उल्लंघन के साथ-साथ प्रकट करने की सूचना की प्रकृति बताने वाली व्यापार सूचना का उल्लंघन है।

ख) नियर्तिकों ने निम्नलिखित के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को भी दबा दिया है -

- अन्य संबंधित और संबद्ध उद्यमों के साथ संबंध
- क्षमता, उत्पादन, स्टॉक और विक्री
- नमूना नियर्त विक्री दस्तावेज
- नमूना घरेलू विक्री दस्तावेज
- भारत को नियर्त से संबंधित जानकारी
- अतिरिक्त अनुदान

ग) सभिसिडियों और प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी समझौते के अनुच्छेद 12.4 भी इस तरह की जांच में गोपनीयता की सीमाओं को स्पष्ट करता है।

घ) ग्वाटेमाला - सीमेंट // में, पैनल ने इस दावे की जांच की कि ग्वाटेमाला के प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादक से किसी अनुरोध को उत्पादन द्वारा कोई उचित कारण बताए बिना स्वयं की पहल पर गोपनीय व्यवहार प्रदान करके अनुच्छेद 6.5, 6.5.1 और 6.5.2 का उल्लंघन किया है। मेक्सिको ने दावा किया कि इस अपेक्षा की पूर्ति करने में विफल रहने के कारण प्राधिकारी ने 6.5.2 का उल्लंघन किया है कि घरेलू उत्पादक इस बात के कारण बताए कि क्यों कुछ जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।

इ) अर्जेंटीना में - सिरेमिक टाइलें, पैनल ने इस बात की जांच करते समय कि क्या प्राधिकारियों को अपने निर्धारण में गोपनीय जानकारी पर स्वयं को आधार बनाने की अनुमति दी गई है कि अगोपनीय (एनसीबी) सारांश का उद्देश्य हितबद्ध पक्षों को सूचित करना है ताकि वे अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हो सकें।

च) भारत में, सेस्टेट द्वारा एस्सार स्टील बनाम यूओआई और एचआर जॉनसन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में फैसले में मुख्य रूप से बताया गया है कि डीए को केवल पक्ष के अनुरोध पर गोपनीय रूप से किसी पार्टी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से गोपनीय व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, नियम किसी पक्ष द्वारा किए गए गोपनीयता के अनुरोध पर विचार करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेक भी प्रदान करते हैं और यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

छ) घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा अनुचित है क्योंकि घरेलू उद्योग ने सभी प्रासंगिक आकड़ों को सूचीबद्ध रूप में दिया है क्योंकि वास्तविक आकड़ों, जो व्यापार संवेदनशील जानकारी हैं, का प्रकटीकरण घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक होगा।

ज) इसके अलावा, हितबद्ध पक्षों से अत्यधिक गोपनीयता का दावा आश्वर्यजनक है क्योंकि हितबद्ध पक्षों ने न केवल अपने आकड़ों के गोपनीय होने का दावा किया है, बल्कि उन्होंने योजनाओं और ऐसी योजनाओं की मौजूदगी और बंद होने को दर्शने वाले दस्तावेजों के गोपनीय होने का दावा किया है। समाज के कुछ वर्गों के लाभ के लिए एक सरकारी नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी और इस तरह की जानकारी के गोपनीय होने का दावा करना गोपनीयता का नून का घोर दुरुपयोग है।

इ.2. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

14. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) आवेदक उद्योग ने ऐसा करने के लिए पर्याप्त तर्क दिए बिना कई प्रमुख आर्थिक मापदंडों को गोपनीय रखा है। इसने प्रतिवादियों को आवेदक उद्योग की क्षति के मापदंडों की एक सार्थक जांच करने से रोक दिया है और अपने स्वयं के हितों की रक्षा की है। उन्होंने याचिका के मामले की उचित समझ के लिए उक्त मापदंडों का एक उचित अगोपनीय संस्करण भी नहीं दिया है, जैसा कि सबिडीरोधी नियमों के नियम 8 के तहत आवश्यक है। निम्नलिखित कारकों के संबंध में आवेदकों द्वारा मांगी गई गोपनीयता अत्यधिक है:

- क्षमता, उत्पादन, विक्री से संबंधित बुनियादी जानकारी।
- मांग के आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं। उनके बिना प्रतिवादी बाजार हिस्से के महत्वपूर्ण मुद्दे पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- इस बारे में तथ्य कि आवेदक के पास समर्पित क्षमता है या साझी क्षमता है।
- उपरोक्त के अलावा अन्य प्रमुख कारकों को भी गोपनीय रखा गया है।

ख) इसके अलावा, टीबीआर पाटनरोधी मामले के अंतिम जांच परिणामों में स्वयं मात्रा संबंधी जानकारी के गोपनीय रूप में खुलासा करने के बाद, प्राधिकारी को वर्तमान मामले में आवेदकों को ऐसी जानकारी को गोपनीय नहीं रखने देना चाहिए। ऐसा करना केवल आवेदकों द्वारा हितबद्ध दलों को उनके द्वारा दायर याचिका पर प्रभावी टिप्पणी करने से वंचित करने का एक प्रयास है। यह अनुरोध किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी बिना उचित जांच के आवेदकों को ऐसी जानकारी को गोपनीय न रखने दें। इसके लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने, स्टेराइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में, यह प्रतिपादित किया है कि गोपनीयता की अपने आप से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यह पूरी तरह से जांच के आधार पर होनी चाहिए।

ग) यदि गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाला पक्ष इस विश्वास के तहत कार्य कर रहा है कि दी गई जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो सबिसडीरोधी नियमों के नियम 8 के लिए आवश्यक है कि इस तरह की राय प्रस्तुत करने के लिए कारण बताया जाए। वर्तमान मामले में, प्रासंगिक जानकारी के गहन मूल्यांकन के बिना गोपनीयता के लिए दावा प्रदान किया गया है, जो स्थापित कानूनी मानकों के विरुद्ध है।

घ) माननीय सेस्टेट ने एच एंड आर जॉन्सन लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में स्पष्ट किया है कि प्राधिकारी को किसी पार्टी द्वारा प्रदान की गई जानकारी को यांत्रिक रूप से केवल इसलिए गोपनीय नहीं मानना है क्योंकि वह पक्ष ऐसा चाहता है। उन्हें सूचना की प्रकृति जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर गोपनीयता और यदि ऐसी कोई जानकारी कानून या परम्परा या उपयोग के अनुसार गोपनीय है, से संतुष्ट होना होगा। जानकारी को गोपनीय मानने का कोई भी दावा, दावा करने वाले पक्ष के अधिकारों और वैध हितों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए।

ङ) इसके अलावा, अपीलीय निकाय ने यूरोपीय समुदायों- फास्टनरों में यह राय व्यक्त की है कि गोपनीयता का दावा करने वाले पक्ष का दायित्व है कि वह उचित कारण बताए और प्राधिकारी को इसका निष्पक्ष मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या दावा पर्याप्त रूप से प्रमाणित किया गया है। यह उस पक्षपातपूर्ण प्रभाव के साथ संतुलित होना चाहिए कि गैर-प्रकटीकरण से पारदर्शिता और नियत प्रक्रिया में शामिल अन्य दलों के हितों पर प्रभाव पड़ सकता है। उपरोक्त के आलोक में, यह अनिवार्य है कि आवेदक उद्योग कानून के प्रावधानों के अनुसार मात्रा संबंधी जानकारी और उनके मापदंडों के उचित अगोपनीय अंश का खुलासा करें।

च) याचिकार्ता ने विक्री की मात्रा, खपत, भारतीय उत्पादन, क्षमता, घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सेदारी और मांग के वास्तविक आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। इन मापदंडों से संबंधित जानकारी व्यावसायिक रूप से संवेदनशील प्रकृति की नहीं है और यह याचिकार्ता के प्रतियोगियों को कोई भी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान नहीं करेगी।

छ) इसके अलावा, इन मापदंडों संबंधी जानकारी 1 अगस्त 2017 को अंतिम जॉच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा दी गई है और इसलिए, घरेलू उद्योग के लिए गोपनीयता का दावा करने का कोई कारण नहीं है। चीन जन. गण. की सरकार ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह याचिकार्ता को हितवद्ध पक्षों के लिए उक्त मापदंडों के वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करने का निर्देश दे।

इ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. सूचना की गोपनीयता के संबंध में सबिसडी-रोधी नियमावली के नियम-8 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

गोपनीय सूचना. (1) नियम 7 के उपनियमों (1), (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 14 के उपनियम (2) और नियम 17 के उपनियम (4) और नियम 19 के उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 6 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्रास आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

16. प्राधिकारी ने विभिन्न हितवद्ध पक्षों द्वारा सार्वजनिक फाइल के माध्यम से विभिन्न हितवद्ध पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अगोपनीय संस्करण को निरीक्षण के लिए विभिन्न हितवद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय संस्करण वाले अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराए।

17. घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितवद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध को संगत समझी गई सीमा तक गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार उन पर ध्यान दिया गया। गोपनीय आधार पर हितवद्ध पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता दावों को

स्वीकार कर लिया है, जहां भी वांछित है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षों को इसका खुलासा नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी के पर्याप्त अगोपनीय संस्करण प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराया। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि सभी हितबद्ध पक्षों ने अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीय माना है।

विविध अनुरोध

अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

18. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क) 18 सितंबर 2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना द्वारा चीन जन. गण. से आयात किए गए न्यू न्यूमैटिक रेडियल टायरों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और यह पांच साल तक अर्थात् 17 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा।

ख) घरेलू उद्योग ने प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियम और एससीसी करार के अधीन आयात पर दोहरे उपाय लागू करवाने के लिए दो अलग-अलग कानूनी आवश्यकताओं को स्वीकार किया है। घरेलू उद्योग इस बात से इनकार नहीं करता है कि यदि निर्यात सब्सिडी की मिल्द हो जाती है, तो उसे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 ख (1) (क) के अधीन स्पष्ट नियेथ के कारण प्रतिसंतुलित नहीं किया जा सकता है।

ग) निर्यात सब्सिडी और पाटन के परिणामस्वरूप संबंधित उत्पाद का निर्यात मूल्य कम हो जाता है। इसलिए, गैट 1994 के अनुच्छेद VI:5 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 ख (1) (क) में प्रावधान है कि पाटन या निर्यात सब्सिडी की एक ही स्थिति की भरपाई के लिए एक उत्पाद को पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क दोनों के अधीन नहीं रखा जाएगा।

घ) संयुक्त राज्य अमेरिका में अपीलीय निकाय - चीन के कुछ उत्पादों पर निश्चित पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क ने समुक्ति की कि दोहरे उपचार लागू किया जाना एससीएम करार के अनुच्छेद 19.3, जो उचित मात्रा में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का प्रावधान करता है, के विपरीत है।

इ) गैट 1994 के अनुच्छेद VI:5 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 ख (1) (क) के अनुसार पाटन या निर्यात सब्सिडी की एक ही स्थिति की भरपाई के लिए एक उत्पाद को पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क दोनों के अधीन नहीं रखा जाएगा। इसलिए, पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन होने वाले आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से निर्यात सब्सिडी की भरपाई के लिए अतिरिक्त शुल्क लग जाएंगे और उक्त प्रावधानों का प्रत्यक्ष उल्लंघन होगा।

च) वर्तमान मामले में, पाटन रोधी जांच के अधीन, चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया है जहां चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया था और सामान्य मूल्य चीनी कंपनियों की वास्तविक लागत पर आधारित नहीं था। इसलिए, उत्पादकों/निर्यातकों के उत्पादन की लागत में ऐसे उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्राप्त किसी भी सब्सिडी के लाभ के कारण होने वाली विकृति सहित किसी भी विकृति को पाटन रोधी शुल्क लगाने से निवारित कर दिया गया। इसके अलावा, अन्य घरेलू सब्सिडी की भरपाई करने के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से दोहरे उपाय हो जाएंगे।

झ) अमेरिका - निश्चयात्मक एडीवी और सीवीडी (चीन) (डीएस 379) विवाद में, अपीलीय निकाय ने कहा कि दोनों शुल्कों के समवर्ती कार्यान्वयन द्वारा दो बार एक ही सब्सिडी की भरपाई करना, एससीएम करार के अनुच्छेद 19.3 के साथ असंगत है।

ज) जे.के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में, यह कहा गया था कि दोनों शुल्कों को एक साथ लागू नहीं करने के पीछे कारण यह है क्योंकि यह केंद्र सरकार के लिए यह विकल्प है कि वह निर्यात की मात्रा मात्रा और इसके घरेलू उत्पाद पर प्रभाव के अलावा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए इनमें से किसी उपाय को अपनाये।

झ) सनसिटी शीट्स बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सेस्टेट का निर्णय एक अलग वास्तविक स्थिति पर आधारित था: चीन जन. गण. से आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में पाटन मार्जिन की तुलना में क्षति मार्जिन कम था, पाटन मार्जिन की पूर्ण सीमा तक नहीं था। इस प्रकार, सब्सिडी को के प्रभाव को दूर करने के लिए और गुंजाइश थी क्योंकि यह संभावना थी कि सब्सिडी के समस्त प्रभाव की पाटन रोधी शुल्क से भरपाई नहीं हुई थी, माननीय सेस्टेट ने समुक्ति की कि प्रतिसंतुलनकारी और पाटनरोधी दोनों शुल्क लगाने में कोई समस्या नहीं है।

ज) चीन जन. गण. में तथाकथित घरेलू सब्सिडी की भरपाई करने के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने से दोहरे उपाय हो जाएंगे क्योंकि पाटनरोधी शुल्क पहले से मौजूद है और यह चीन जन. गण. की बाजार अर्थव्यवस्था के उपचार के आधार पर अपने पूर्ण मार्जिन पर लगाया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 ख (1) (क) और गैट 1994 के अनुच्छेद VI:5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाटन और निर्यात सब्सिडी के एक ही आधार की भरपाई करने के लिए पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी दोनों शुल्क नहीं लगाए जा सकते हैं।

ट) निर्यात सब्सिडी, भले ही वर्तमान जांच में इन कथित कार्यक्रमों के अनुसार मौजूद निर्धारित की गई हो, परंतु उत्पाद पर पहले से मौजूद पाटनरोधी शुल्क के कारण इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह गैट के अनुच्छेद VI: 5 के असंगत होगा।

ठ) प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के लागू होने से इसकी भरपाई दो बार हो जाएगी और एससीआर समझौते के अनुच्छेद 19.3 के अनुसार यह असंगत होगा। इसलिए, हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान मामले में कोई दोहरा उपाय नहीं है।

ड) चीन से निर्यात होने वाली संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क पहले से मौजूद है, याचिका में टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार, 1994 के सिद्धांतों के अनुच्छेद VI के पैराग्राफ 5 का उल्लंघन किया गया है क्योंकि किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा पाटनरोधी शुल्क और सब्सिडीरोधी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क दोनों एक साथ लगाया नहीं जा सकता। यह स्पष्ट है कि यह अनुच्छेद एक ही स्थिति के लिए दोहरे उपाय या मुआवजे की स्थिति का निवारण करता है। निर्यात सब्सिडी और समवर्ती शुल्कों के लिए पहले से ही पाटन मार्जिन दोगुना जोखिम उत्पन्न करेगा और भारत में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 ख (1) (क) दोहरे बतारे का निवारण करेगा। जैसा कि जे.के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में निर्धारित किया गया है, प्राधिकारी के पास पाटनरोधी शुल्क या प्रतिसंतुलनकारी/सब्सिडीरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने की स्वतंत्रता है, लेकिन दोनों शुल्कों को लागू करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसके अलावा, चीन जन. गण. को एक गैर-आर्थिक बाजार के रूप में माना जाता है और सामान्य मूल्य पर गणना की जाती है, जिसके कारण, यदि चीन द्वारा कथित सब्सिडी के कारण कोई लाभ उठाया जाता है, तो पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लगाने से उसका प्रतिकार किया गया है। यह निर्धारण कमतर शुल्क नियम को लागू करके क्षति के मार्जिन के आधार पर किया गया था, और इसलिए, यदि आयात से घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है तो आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के दौरान प्राधिकारी द्वारा पहले ही उस पर विचार और समाधान किया गया है।

ड) याचिकाकर्ता ने वर्तमान जांच में निर्यात सब्सिडी का आरोप लगाया है और चीन की सरकार द्वारा अपने टायर उत्पादकों/निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली निर्यात सब्सिडी के रूप में निम्नलिखित कार्यक्रमों का दावा किया है कि:

- i. कार्यक्रम 11: निर्यात सहायता अनुदान
- ii. कार्यक्रम 15: हेफेई नगरपालिका निर्यात संवर्धन नीतियां
- iii. कार्यक्रम 19: गुआंगडोंग और झेजियांग प्रांतों में स्थित उद्यमों के लिए निर्यात व्याज सब्सिडी निधि
- iv. कार्यक्रम 55: निर्यात विक्रेता क्रहण
- v. कार्यक्रम 56: निर्यात खरीदार क्रहण
- vi. कार्यक्रम 57: राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य निर्यात वित्तीय सेवाएँ
- vii. कार्यक्रम 58: निर्यात क्रहण वीमा सब्सिडी
- viii. कार्यक्रम 59: निर्यात क्रहण गारंटी

इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि सब्सिडी मार्जिन की गणना करते समय, प्राधिकारी द्वारा निर्यात सब्सिडियों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

ड) जांच अवधि घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती है।

- बसों या लॉरियों पर इस्तेमाल होने वाले नए न्यूमेटिक रेडियल टायरों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क 10% से बढ़कर 15% कर दिया गया, परिणामस्वरूप, चीन जन. गण. के लिए सीमा शुल्क की प्रभावी दर 8.6% से बढ़कर 12.9% हो गई।

- वर्तमान मामले में जांच की अवधि अक्टूबर 2016 से सितंबर 2017 है। एचएस कोड 40112010 के तहत आने वाली वसों या लॉरियों पर इस्तेमाल होने वाले नए न्यूमेटिक रेडियल टायरों के आयात पर मूल सीमा शुल्क प्रभावी रूप से भारत सरकार द्वारा 2 फरवरी 2018 से 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। परिणामस्वरूप, चीन के लिए सीमा शुल्क की प्रभावी दर 8.6% से बढ़कर 12.9% हो गई। 18 सितंबर 2017 से चीन जन. गण. से नए न्यूमेटिकरेडियल टायरों पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था जो 245 अमरीकी डालर/मीट्रिक टन से 452 अमरीकी डालर/मीट्रिक टन तक था।
- प्राधिकारी पाटन रोधी शुल्क के प्रभाव और संबद्ध वस्तु के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि और घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार का आकलन करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि ये बातें जांच अवधि की समाप्ति के बाद हुई हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक क्षति का आकलन घरेलू उद्योग के आयात और प्रदर्शन के बारे में वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधि नहीं होगा।

ण) प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता उद्योग द्वारा दायर लिखित अनुरोध पर आपत्ति जताई है जो 172 से अधिक पृष्ठों की हैं। अनुवंध 700 से अधिक पृष्ठों के हैं। इस संदर्भ में, यह अनुरोध किया जाता है कि लिखित अनुरोध माननीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई बातों का सारांश होना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता उद्योग द्वारा किए गए लिखित अनुरोधों का मौखिक सुनवाई के दौरान किए गए अनुरोधों से कोई संबंध नहीं है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि इस पहलू पर गौर करें और ऐसे सभी लिखित अनुरोधों पर ध्यान न दें जिन पर मौखिक सुनवाई के दौरान तर्क नहीं दिया गया था।

त) यह अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता उद्योग ने सीबीडी जांच में रक्षोपायों की धारा 8 (3) पर निर्भरता रखकर दोहरे उपाय के संबंध में माननीय प्राधिकारी को फिर से गुमराह करने की कोशिश की है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि सीमा शुल्क की धारा 8 रक्षोपाय जांच के लिए लागू होती है, न कि प्रतिसंतुलनकारी जांच के लिए। इसके अलावा, याचिकाकर्ता उद्योग ने फिर से धारा 9 ख (1) का हवाला देकर प्राधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की है, जो पाटन और निर्यात सभिसडी की एक ही स्थिति के लिए एडीडी और सीबीडी दोनों को लागू करने पर रोक लगाता है। अपने पूर्ण लिखित अनुरोध वे अपनी बात को सही ठहराने में विफल रहे हैं कि धारा 9 खी (1) के संदर्भ में, एडीडी और सीबीडी दोनों शुल्कों को वर्तमान जांच में क्यों सही ठहराया गया है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

19. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क) यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से, चीन को गैर-वाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया था और उस जांच में प्राधिकारी द्वारा कमतर शुल्क नियम लागू किया गया था। यूएस-चीन में विश्व व्यापार संगठन अपीलीय निकाय ने कहा कि ऐसे मामलों, जहां एनएमई कार्य प्रणाली कार्यरत है, में दोहरे उपचार की संभावना है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि डब्ल्यूटीओ का निर्णय भारतीय संदर्भ में अनुचित है, क्योंकि भारत कमतर शुल्क नियमों को लागू करता है और याचिकाकर्ता की सहमति के अनुसार सभिसडी शुल्क केवल उस सीमा तक लगाया जा सकता है जहां तक सभिसडी शुल्क की मात्रा एडीडी की राशि से अधिक हो। विश्व व्यापार संगठन के मामले में, अमेरिका ने दूसरे में एक शुल्क की भरपाई किए बिना सभिसडी शुल्क और पाटन शुल्क लागू किया था।

ख) याचिकाकर्ता सहमत है कि (क) प्राधिकारी कृपया सभिसडी मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करें, (ख) सभिसडी शुल्क देयता की राशि निर्धारित करें, (ग) प्राधिकारी सभिसडी शुल्क की मात्रा को उस मामले में कम कर सकते हैं जब सभिसडी शुल्क की राशि पाटन शुल्क की राशि से अधिक हो और अंतर की उस राशि की सिफारिश उन उत्पाद प्रकारों के संबंध में कर सकते हैं जिन पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है, (घ) यदि मौजूदा पाटन शुल्क की राशि सभिसडी शुल्क की राशि से अधिक है तो उन उत्पाद प्रकारों के संबंध में शुल्क की एक शून्य दर निर्दिष्ट की जा सकती है। स्टेनलेस स्टील के आयात के संबंध में अंतिम जांच परिणाम का उल्लेख किया गया है जिसमें निर्दिष्ट पराधिकारी या वित्त मंत्रालय द्वारा घरेलू उद्योग को दोहरी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी।

ग) याचिकाकर्ता यह दावा करते हैं कि हितवद्ध पक्ष इस बात पर विश्वास या विचार करने में निर्दिष्ट प्राधिकारी को गुमराह कर रहे हैं कि पहले से पाटनरोधी शुल्क के अधीन किसी उत्पाद के संबंध में सभिसडी जांच शुरू करना निषिद्ध है। इसके अलावा, हितवद्ध पक्ष यह मानते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी को गुमराह कर रहे हैं कि यह कानून उन उत्पादों पर सभिसडी शुल्क लगाने पर रोक लगाता है जिनपर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लागू है। यह देखा जाएगा कि डब्ल्यूटीओ ने स्पष्ट रूप से माना है कि दोहरे शुल्क को लागू करने पर एकमात्र प्रतिवंध है - एक बार पाटनरोधी के रूप में और एक बार पाटन और निर्यात सभिसडी के रूप में एक ही स्थिति के लिए सभिसडीरोधी शुल्क के रूप में। किसी मामला विशेष के तथ्य समान स्थिति के अर्थ में आते हैं अथवा नहीं एक

तथ्य का उचित प्रश्न है और इसके लिए हितबद्ध पक्षों द्वारा अपनी दलील को सिद्ध करने से पहले स्थापित करने की आवश्यकता है।

घ) हितबद्ध पक्षों को उनके आयात प्रवृत्ति विक्षेपण में चयनात्मक रहे हैं, आधार वर्ष के बाद से देखी गई जबरदस्त वृद्धि के आयात को अनदेखा कर 2016-17 से पीओआई के आयात के रुक्कानों की तुलना करना अनुचित है। आधार वर्ष से पीओआई तक आयात लगभग दोगुना हो गया है। इसके अलावा, आयात में गिरावट आंशिक रूप से मांग में गिरावट के कारण हुई है और आंशिक रूप से मई 2016 में टीबीआर के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के कारण हुई है।

ङ) यह नोट करना संगत है कि पाटनरोधी जांच की पीओआई जुलाई 2014- दिसंबर 2015 थी। प्राधिकारी ने उस अवधि में जब कीमत संबंधी मापदंड बेहतर स्थिति में थे जो वर्तमान पीओआई में प्रचलित हैं, आयात में वृद्धि का निष्कर्ष निकाला था और साथ ही वास्तविक क्षति का भी निष्कर्ष निकाला था। यह देखा जाएगा कि यद्यपि आयात में गिरावट आई है लेकिन लागत में वृद्धि के बावजूद आयात की कीमतों में और गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में और गिरावट आई है जो इस प्रकार चीन से सब्सिडी प्राप्त आयातों के संदर्भ में जारी रहने वाली वास्तविक क्षति का साक्ष्य दर्शाती है।

च) इस तर्क के संबंध में कि पीओआई के बाद के आयात में भारी गिरावट आई है, यह पाटन कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि पीओआई क्षति विक्षेपण के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक अवधि है। इसके अलावा, जबकि इस बात को माना जाता है कि एडीडी लगाए जाने के परिणामस्वरूप पीओआई के बाद के आयात में गिरावट आई है, जिसमें यह भी देखने योग्य है कि पीओआई की तुलना में आयात शुल्क में काफी गिरावट आई है, यहां तक कि सीमाशुल्क और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद स्पष्ट रूप से चीनी निर्यातकों की कीमतों को कम करने की प्रवृत्ति को इंगित करती है कि उनके पास अनेक सब्सिडियां उपलब्ध हैं। पीओआई के पश्चात से संबंधित जानकारी पर निर्दिष्ट प्राधिकारी का पिछला निर्णय सऊदी अरब के एनबीए के आयात के मामले में संदर्भित और निर्भर है।

छ) विरोधी दलों द्वारा दोहरे उपाय के संबंध में किए गए विरोध के संबंध में, चूंकि पाटनरोधी शुल्क पहले से ही कुछ प्रकार के विचाराधीन उत्पाद पर लगाया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि केवल ट्रक और बस रेडियल टायर टीबीआर पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। शुरुआत में, याचिकाकर्ता को एक ही उत्पाद और एक ही समय में दोनों उपायों की मांग करने से प्रतिवंधित करने वाला कानून में कुछ भी नहीं है। याचिकाकर्ता सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 (ख) (3) पर भरोसा करते हैं, जो निम्नानुसार है-

(3) इस धारा के अधीन प्रभारित किया जाने वाला शुल्क इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य कानून के अधीन लगाए गए किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा।

इसके अलावा, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 (5) में निम्नानुसार है-

(5) इस धारा के अधीन प्रभारित किया जाने वाला प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के अधीन लागू किए जाने वाले किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा।

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 ख (1) में कहा गया है कि-

9 ख. (1) धारा 9 या धारा 9 क में दी गई किसी बात के होते हुए भी -

(क) पाटन या निर्यात सब्सिडी की एक ही स्थिति की भरपाई के लिए किसी भी वस्तु को प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और पाटनरोधी शुल्क दोनों के अधीन नहीं रखा जाएगा;

ज) हितबद्ध पक्षों द्वारा प्राधिकारी से अनुरोध किया गया कि किसी ऐसे उत्पाद पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की जांच शुरू करना और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना जो पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन है, कानून के तहत निषिद्ध है, भामक है। विश्व व्यापार संगठन अपीलीय निकाय के फैसले के अनुसार, प्राधिकारी पर एकमात्र प्रतिवंध सब्सिडी राशि तय करने के संबंध में है, और ऐसा करने पर उस राहत पर विचार करना चाहिए जो पहले से ही घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क के माध्यम से दी गई है।

झ) एनएमई देशों में भी घरेलू सब्सिडी की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि शुल्कों को लागू नहीं किया जा सकता है। पाटन रोधी शुल्क लागू होने पर भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने पर कोई रोक नहीं है। चूंकि भारत कमतर शुल्क नियम का पालन

करता है, इसलिए प्राधिकारी को प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित करने के लिए धृति मार्जिन के साथ सब्सिडी मार्जिन की तुलना करनी चाहिए। यदि निर्धारित किया गया प्रतिसंतुलनकारी शुल्क मौजूदा पाटन रोधी शुल्क से अधिक है, तो मौजूदा पाटन शुल्क को समायोजित करने के बाद प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने पर कोई रोक नहीं है।

ज) याचिकाकर्ता का कहना है कि "चीन से कतिपय हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पाद" के संबंध में सेस्टेट के आदेश और डीजीटीआर के निष्कर्ष से स्पष्ट रूप से एक साथ शुल्कों को लागू करने की स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

ट) जहां तक डब्ल्यूटीओ के फैसले का संबंध है, याचिकाकर्ता ने कहा कि इस बात पर विचार करते हुए यह भारतीय संदर्भ में यह पूरी तरह से अनुचित है कि (क) भारत कमतर शुल्क नियम लागू करता है और (ख) याचिकाकर्ता सहमति देता है कि सब्सिडी शुल्क के बजाए उस सीमा तक प्रभारित किया जा सकता है जिस तक सब्सिडी शुल्क की राशि पाटनरोधी शुल्क की राशि से अधिक है। डब्ल्यूटीओ डीएस 379 के मामले में, अमेरिका ने एक शुल्क की भरपाई किए विना, सब्सिडी शुल्क और पाटन शुल्क लागू किया है।

ठ) तदनुसार, याचिकाकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करता है -

- वह सिफारिश करें कि घरेलू उद्योग को दोहरे उपाय पर ध्यान देने के लिए आयात पर देय पाटनरोधी शुल्क की राशि को कम करने के बाद सब्सिडी शुल्क की राशि निर्धारित की जाएगी। केवल अंतर की राशि सब्सिडी शुल्क के रूप में ली जाएगी। इसके अलावा, यदि अंतर की राशि नकारात्मक है, तो कोई सीवीडी एकत्र नहीं किया जाएगा।
- वैकल्पिक रूप से, प्राधिकारी कृपया आयात की पहुंच कीमत में देय एडीडी को जोड़ने के बाद देय सब्सिडी शुल्क की राशि निर्धारित कर सकते हैं और शेष राशि को देय सब्सिडी शुल्क की राशि के रूप में अनुशंसित कर सकते हैं।
- वैकल्पिक रूप से, प्राधिकारी देय सब्सिडी शुल्क की राशि निर्धारित कर सकते हैं और सीवीडी मार्जिन और एडीडी के बीच के अंतर की देय शुल्क की राशि के रूप में अनुशंसा कर सकते हैं।

च. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच :

विविध मामलों के संबंध में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा विविध मामलों के संबंध में किए गए विविध अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए अनुरोधों की जांच की जा रही है और उन पर इस प्रकार कार्रवाई की गई है :

20. जहां तक संबद्ध वस्तुओं पर पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क के दोहरे उपचार का संबंध है, प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर देय पाटनरोधी शुल्क की मात्रा का विधिवत समायोजन करने के बाद प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की मात्रा की सिफारिश की जाएगी। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के रूप में केवल अंतर की राशि वसूल की जाएगी। इसके अलावा, यदि अंतर की राशि नकारात्मक है तो कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

21. यह नीति पूर्ववर्ती जांचों में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई संगत परिपाटी के अनुक्रम में है जिसका अनुसर्व अनुसर्व माननीय सेस्टेट ने भी किया है।

च. सब्सिडी का अन्तर और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण :

22. घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई याचिका में जांच को शुरू करने से पूर्व तत्काल जांच करने के लिए संबद्ध देश में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी की मौजूदगी के प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए गए हैं। चीन सरकार को चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था, जो दिनांक 20 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में हुई थी। चीन जन. गण. से उत्पादकों तथा नियांतकों को प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने के लिए सलाह दी गई थी और उन्हें कथित सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव के संबंध में प्रमाणित करने योग्य साक्ष्य प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था ताकि ऐसी सब्सिडी, यदि कोई हो, की मौजूदगी की मात्रा का उपयुक्त निर्धारण किया जा सके।

23. चीन सरकार सहित चीन जन. गण. से निम्नलिखित उत्पादकों/ नियांतकों ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए गए हैं :

- मै. शेडोंग हाओहुआ टायर कंपनी लिमिटेड
- मै. गुआंगज़ौ एक्सिड इंडस्ट्रियल टेक्नालोजी कं लिमिटेड
- मै. एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लिमिटेड

- iv. मै. एलोस टायर कंपनी लिमिटेड
- v. मै. किंगदाओ यलो शी रबड कं लिमिटेड
- vi. मै. शेडोंग योगफेंग टायर कंपनी लिमिटेड
- vii. मै. झोंगसी रबड ग्रपु कंपनी लिमिटेड
- viii. मै. शेडोंग वांडा बोटो टायर कंपनी लिमिटेड
- ix. मै. ट्रायंगल टायर कंपनी लिमिटेड

कथित सब्सिडी कार्यक्रमों का सामान्य अवलोकन :

छ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध :

24. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चीन जन. गण. सरकार ('जी ओ सी) संबद्ध वस्तुओं के अपने उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी प्रदान कर रहा है और विधिक तथा नीतिगत दस्तावेजों के अनुसार ऐसी सब्सिडी योजनाओं की मौजूदगी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने ए एस सी एम और भारतीय नियमों के तात्पर्य से चीन जन. गण. में कुछ भागों में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी योजनाएं मौजूद होने की पहचान की है और यह तर्क दिया है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को ऐसी सब्सिडी से लाभ हुआ है।
- ii. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी चीन की सरकार और निर्यात संबंधी डाटा पर भरोसा किया जा सकता है, वर्ते कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना पूर्ण, सही और पर्याप्त हो। प्रतिवादी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा केवल यह "दिखावा" करने के लिए प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए गए थे कि उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है। प्रश्नावली के उत्तर पूरी तरह से अधूरे और अपर्याप्त हैं। चीन की सरकार और निर्यातकों को इस जांच में असहयोगी माना जाना चाहिए। इन निर्यातकों द्वारा दाखिल की गई बहुत ही सीमित सी सूचना में भी विरोधी दावे दर्शाए गए हैं। सरकार ने कतिपय योजनाओं की मौजूदगी से इंकार किया गया है। तथापि, निर्यातकों ने कतिपय योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने को स्वीकार किया है। इसके अलावा, निर्यातकों ने उनके द्वारा प्राप्त अतिरिक्त सब्सिडी योजनाओं के लाभ की सूचना प्रदान की है, जिसे चीन की सरकार द्वारा प्रकट नहीं किया गया है। इस प्रकार से चूंकि चीन की सरकार और निर्यातकों ने तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं।
- iii. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को सब्सिडी से लाभ हुआ है। चीन की सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों का अनुरक्षण किया है। याचिकाकर्ताओं ने संगत चीनी कानूनों और विनियमों जैसे दस्तावेजों, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्टों, मीडिया स्रोतों, सरकारी रिपोर्टों, स्वतंत्र रिपोर्ट विश्लेषणों और अध्ययनों, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच विश्लेषण और चीन जन. गण. में सब्सिडी कार्यक्रमों संबंधी अन्य प्राधिकारियों के जांच परिणामों पर विचार किया है। याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में व्यापक सूचना प्रदान की है।
- iv. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी वर्तमान मामले में नमूने के तौर पर चयन कर प्रयोग कर सकते हैं। चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के काफी संख्या में निर्यातक हैं, जो भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि कृपया चीन के उत्पादकों का नमूने के तौर पर चयन करके विचार करें और विस्तृत जांच को केवल टॉप तीन उत्पादकों तक ही सीमित रखें, जो कि शांडोंग यिनवाओ टायर ग्रुप कं. लिमि., किंगदाओ येलो सी रबर कं. लिमि., और शांडोंग वांडा बोटो टायर कं. लिमि., हैं।

क्योंकि सभी प्रतिवादी उत्पादकों की विस्तृत जांच व्यर्थ होगी। कुछ प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा बहुत ही कम है और व्यापक जांच करने का कोई औचित्य नहीं है।

v. चीन की सरकार और चीन जन. गण. में अन्य सार्वजनिक निकायों के कार्यक्रमों में निम्नलिखित कारणों से सब्सिडी होती है :

- सरकारी अथवा किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा एक वित्तीय योगदान, जहां पर सरकारी प्रक्रिया में धनराशि का सीधा अंतरण होता है (अर्थात् अनुदान, ऋण और इंक्रिटी योगदान), सरकारी राजस्व, जो अन्यथा देय है, समाप्त हो चुका है अथवा वसूली नहीं की गई है (अर्थात् वित्तीय प्रोत्साहन जैसे कर छूट), सरकार सामान्य अवसंरचना के अलावा वस्तुएं अथवा सेवाएं प्रदान करती है अथवा वस्तुएं खरीदती है;
- उसके द्वारा चीन के विचाराधीन उत्पादकों/ निर्यातकों को लाभ प्रदान किए गए हैं, और
- यह कार्यक्रम भारतीय नियमों और ए एस सी एम के तात्पर्य से विशिष्ट है।

vi. संगत चीनी कानून और विनियम, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट, विभिन्न सरकारी रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट और स्वतंत्र अध्ययन एवं विश्लेषण, उनके सब्सिडी विरोधी जांचों में अन्य जांच एंजेसियों के जांच परिणाम स्पष्ट तौर पर चीन जन. गण. में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रमों की मौजूदगी के पर्याप्त साक्ष्य हैं। ये साक्ष्य याचिकाकर्ताओं द्वारा सभी हितवद्ध पक्षकारों, चीन की सरकार और चीन जन. गण. में सभी जात उत्पादकों और निर्यातकों को उपलब्ध करा दिए गए थे।

vii. इस जांच के प्रयोजन से “चीन जनतांत्रिक गणतंत्र की सरकार” में सरकार के सभी स्तर शामिल हैं, अर्थात् संघीय, केंद्रीय, 27 प्रांतीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय सरकार जैसे नगरपालिका अथवा नगर अथवा टाउनशिप सरकार; ग्राम अथवा स्थानीय विधायिका, प्रशासनिक अथवा न्यायिक एंजेसियां/ निकाय; और राज्य के स्वामित्वाधीन उद्यम, जो चीन की सरकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा प्रभाव में संचालित हो रहे हैं, जो ए एस सी एम में यथा परिभाषित इसके तात्पर्य से “सार्वजनिक निकाय” के रूप में संचालित होते हैं।

viii. याचिका के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं के लिए चीन के उत्पादकों/ निर्यातकों को सरकार के विभिन्न स्तरों के निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी प्राप्त हुई है और उन्हें 6 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों के तहत वर्गीकृत विभिन्न कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं -

- I. अनुदान
- II. कर छूट
- III. अधिमान्य ऋण
- IV. निर्यात वित्त देयता और निर्यात ऋण
- V. इंक्रिटी सहायता
- VI. वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान

छ. 2. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध :

25. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. निर्यातकों के लिए कोई भी प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है। चीन सरकार द्वारा कोई भी अधिमान्य ऋण, इंक्रिटी योगदान और सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा पर्याप्त पारिश्रमिक से कम का किसी वस्तु अथवा सेवा का प्रावधान, सरकार द्वारा राजस्व वकाया की माफी अथवा कर प्रोत्साहन प्रदान नहीं किए जाते। भारत को संबद्ध वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए आवश्यक निवेश की तुलना में राशि नगण्य है।
- ii. यदि जांच जारी रहती है तो सब्सिडी का निर्धारण, निर्यातकों और चीन जन. गण. की सरकार द्वारा दाखिल उत्तर के आधार पर होना चाहिए। चूंकि यह याचिका संबद्ध वस्तुओं के चीन जन. गण. से निर्यातकों/ आयातकों को वास्तविक

लाभ प्रदान किए जाने के कोई साक्ष्य प्रदान नहीं करती, प्राधिकारी से अनुरोध हैं कि वह प्रश्नावली उत्तर के आधार पर चीन जन. गण. से सभी निर्यातकों के लिए सब्सिडी की मात्रा निर्धारित करें।

iii. याचिकार्ताओं द्वारा अभिज्ञात 72 सब्सिडी कार्यक्रमों में से 22 समाप्त हो चुके हैं। तदनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए जांच को समाप्त करें :

क्र. सं. (याचिका)	कार्यक्रम
4	राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना कोष
7	विदेशी निवेश के साथ मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान
17	ऑटोमोबाइल और टायर उद्योगों के लिए वेहाई नगरपालिका सब्सिडी
18	रोंगचेंग आर्थिक विकास जोन में स्थित कंपनियों के लिए सब्सिडी
19	गुआंगडोंग और जियांग प्रांतों में स्थित उद्यमों के लिए निर्यात व्याज सब्सिडी कोष
28	एफ आई ई के अनुसंधान और विकास के लिए अधिमान्य कर नीतियां
29	एफ आई ई द्वारा अनुसंधान और विकास के लिए कर ऑफसेट
30	घरेलू रूप से उत्पादित और निर्मित उत्पादन उपकरण की खरीद के लिए आय कर छूट
34	चीन निर्मित उपकरण की खरीद करने वाली घरेलू स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए आय कर छूट
36	चीन निर्मित उपकरण की खरीद पर घरेलू फर्मों के लिए वेट की वापसी
37	केंद्रीय क्षेत्र के लिए वेट की छूट और कटौतियां
38	कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रचालन हेतु निर्धारित उत्पादनकारी एफ आई ई के लिए कर की कम दर
39	विदेशी निवेश वाले निर्यात उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां
40	गहन प्रौद्योगिकी प्रधान और गहन ज्ञान प्रधान एफ आई ई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
41	चीन में स्थापित किए गए अथवा वहां पर स्थित एफ आई ई और विदेशी उद्यमों और जो घरेलू उत्पादित उपकरण के उत्पादन अथवा कारोबारी प्रचालनों में लगे हुए हैं, उनके लिए अधिमान्य कर नीतियां
42	विदेशी निवेशकों द्वारा एफ आई ई लाभों के पुनः निवेश के लिए आय कर वापसी
44	विशेष आर्थिक जोनों (शंघाई पुडोंग क्षेत्र को छोड़कर) में स्थापित विदेशी निवेश (एफ आई ई) के साथ उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां
45	तटवर्ती आर्थिक खुले क्षेत्रों और आर्थिक व प्रौद्योगिकीय विकास जोनों में स्थापित एफ आई ई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
46	विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड) और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय आय कर छूट और/ अथवा कटौती
47	विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जैड) में और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में कारपोरेट आय कर छूट और/ अथवा कटौती
52	एस ओ ई के लिए अधिमान्य ऋण
65	औद्योगिक और अन्य विशेष आर्थिक जोनों में भू उपयोग अधिकार

iv. याचिकाकर्ताओं ने चीन जन. गण. में उत्पादकों/ निर्यातकों के लाभ के लिए अथवा उनके समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए विना कई सब्सिडी मौजूद होने का आरोप लगाया है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि चीन की सरकार

और चीन जन. गण. से उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तरों के आधार पर सब्सिडी की मात्रा का निर्धारण करें।

v. लागत और उत्पादन से संबद्ध सब्सिडी के संबंध में यह अनुरोध है कि चीन जन. गण. की संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते समय प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य और चीन में लागत को ध्यान में रखा है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्माण किया है और ऐसा करते समय, प्राधिकारी ने निम्नलिखित क्रियाविधि को अपनाया है :

- प्राकृतिक रबड़, सिथेटिक रबड़, कार्बन ब्लैक, नाइलोन कॉर्ड फैब्रिक, स्टील कॉर्ड फैब्रिक तथा बीड वायर जैसी कच्ची सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत (विश्व बैंक व्यापार एटलस के तहत चीन जन. गण. से/ में निर्यात/ आयात कीमत अपनाई गई है);
- घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर रसायनों और रीक्लेम्ड रबड़ की कीमतों पर विचार किया गया है;
- घरेलू उद्योग के सबसे अधिक घटक आधारित खपत मानक;
- घरेलू उद्योग के सबसे अधिक उचित घटक आधारित परिवर्तन लागत;
- घरेलू उद्योग के सबसे अधिक उचित घटक आधारित विक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय; और
- 5 प्रतिशत की दर से काल्पनिक (नोशनल) लाभ पर विचार किया गया है।

उपरोक्त क्रियाविधि से यह स्पष्ट है कि निर्मित सामान्य मूल्य की गणना करते समय, प्राधिकारी ने निर्मित सामान्य मूल्य के सभी घटकों मुख्यतः, कच्ची सामग्री, ऊर्जा खपत, परिवर्तन कारकों, विक्री और सामान्य प्रशासनिक व्यय के साथ साथ लाभ को भी अपनाया गया है, जो कि चीन की कंपनियों से संबंधित भी नहीं था। अतः विना बताए यह स्पष्ट है कि सब्सिडी, यदि कोई हो, चाहे इसमें गुप्त तरीके से शामिल है अथवा नहीं, खपत निर्धारित करने के लिए निर्मित सामान्य मूल्य की गणना करते समय इसे पहले ही ध्यान में रखा गया है।

vi. निर्यात निष्पादन से संबंधित सब्सिडी के संबंध में यह कहना है सी आई एफ कीमत निर्यात सब्सिडी के कारण कम है। यह मानते हुए कि प्रतिवादियों को निर्यात सब्सिडी प्राप्त हो रही है (उदाहरण के लिए 10 प्रतिशत), उनकी निवल निर्यात कीमत 10 प्रतिशत तक कम होगी। यह कम सी आई एफ/ निर्यात कीमत पाटनरोधी शुल्कों में समुचित रूप से ध्यान में रखी गई है।

vii. टॉप तीन उत्पादकों/ निर्यातकों तक ही जांच को सीमित रखने और नमूने के तौर पर चयन के संबंध में याचिकार्ता उद्योग के अनुरोध के संबंध में, प्रतिवादी विनम्रता के साथ यह अनुरोध करते हैं कि याचिकार्ता उद्योग का अनुरोध जांच की इस अवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नमूना चयन करने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अध्यधीन जांच शुरू करने से पूर्व दी जाती है। यह न्याय पर आधार होगा यदि पूर्ण रूप से सहयोग करने वाले निर्यातकों के उत्तरों को जांच की इस अवस्था में नमूना आधार पर चयन करने की अनुमति देकर अस्वीकार किया जाता है। प्राधिकारी को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि प्रतिवादियों ने कार्यवाही में पूरा सहयोग दिया है और उन्होंने अपने डाटा तथा संख्या के आधार पर व्यक्तिगत मार्जिन की प्रत्याशा में प्राधिकारी को प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं। यह भी कहा जाता है कि इस में कोई भी नमूना आधार पर चयन करने से प्रतिवादियों के कानूनी और वाणिज्यिक हितों के प्रति घोर अन्याय होगा। बहरहाल, हम आश्चर्यचकित हैं कि याचिकार्ता उद्योग एक ऐसे मामले पर राय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जो कि माननीय प्राधिकारी का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है।

viii. चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादों/ निर्यातकों के लिए उपलब्ध अनुदानों की पहचान के संबंध में, यह कहना है कि प्रतिवादियों ने उनके द्वारा लाभ प्राप्त योजनाओं का पूर्ण व्यौरा पहले ही प्रदान कर दिया था। प्रतिवादी निर्दिष्ट प्राधिकारी से उनके द्वारा प्रदान किए गए डाटा/ सूचना के पूर्ण सत्यापन की मांग करते हैं। अन्य सभी योजनाएं प्रतिवादियों के लिए लागू नहीं हैं और इसीलिए ऐसी योजनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

ix. अन्य प्राधिकारियों द्वारा संस्तुत किए गए सब्सिडी मार्जिन की मात्रा पर निर्भरता गलत होगी और गलत निष्कर्षों की ओर प्रेरित करेगा। चूंकि सब्सिडी मार्जिन निर्यातिक विशेष द्वारा प्राप्त सब्सिडी और जांच की अवधि के दौरान किए

गए निर्यातों की मात्रा पर आधारित होते हैं, इसलिए मार्जिन पर कोई सामान्य सी निर्भरता भी न केवल अतार्किक होगी बल्कि लागू कानून के विपरीत होगी।

x. यदि प्राधिकारी जांच के अनुसार आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो सबिसडी का निर्धारण निर्यातकों और चीन जन. गण. सरकार द्वारा दाखिल किए गए उत्तर के आधार पर होना चाहिए क्योंकि याचिका में चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/ उत्पादकों को वास्तविक लाभ के साक्ष्य नहीं दिए गए हैं।

xi. घरेलू उद्योग का यह दावा है कि सभी संगत संस्थाओं द्वारा उत्तर दाखिल किया जाना गलत है, एस सी एम करार और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के तहत अपेक्षा के विरुद्ध है और निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व प्रथा के भी विरुद्ध है। एयोलस टायर कंपनी लिमि. और किंगदाओ येलो सी रवड़ कंपनी लिमि. की संगत संस्थाओं को निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल करना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने आवश्यक सूचना की पहचान नहीं की है, जो यदि ऐसी संगत संस्थाएं प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं करती हैं तो उपलब्ध नहीं होगी। येलो सी और एयोलस ने याचिका में उल्लिखित सबिसडी कार्यक्रमों के तहत उसके द्वारा प्राप्त लाभों और याचिका में उल्लेख न किए गए सबिसडी कार्यक्रम के बारे में सभी सूचना प्रदान की है।

xii. याचिका में उल्लिखित 72 कार्यक्रमों में से निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तरों में ऐसे कार्यक्रमों की स्पष्ट पहचान हो गई है, जिनके लिए उन्होंने लाभ प्राप्त किया है। निर्यातकों द्वारा दाखिल की गई निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में याचिका में उल्लेख न किए गए सबिसडी कार्यक्रमों के बारे में भी सूचना प्रदान की गई है।

xiii. याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित कार्यक्रम और प्रतिवादी निर्यातक द्वारा पहचाने गए कार्यक्रम में अंतर घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली उत्तर में उल्लिखित लाभ के लिए कानूनी आधार में अंतर से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीन की सरकार ने कोई गलत सूचना प्रदान नहीं की है और चीन की सरकार तथा निर्यातक द्वारा दाखिल किए गए उत्तर में कोई विरोध नहीं है।

xiv. राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना कोष के लिए चीन की सरकार ने यह उल्लेख किया है कि कार्यक्रम को 22 फरवरी, 2008 को बंद कर दिया गया था। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि इस कार्यक्रम के भिन्न नाम हो सकते हैं लेकिन ऐसे दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं।

xv. परिसंपत्तियों की औसतन उपयोगी आयु 18 वर्ष नहीं है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है और इसीलिए यह कहना गलत है कि इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त लाभों की ऐसी अवधि के लिए जांच की जानी आवश्यक है। घरेलू उद्योग ने अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य भी प्रदान हीं किए हैं। निर्यातक द्वारा अपनाई गई वार्षिक मूल्यहास दर, मूल्यहास नीति, विभिन्न परिसंपत्तियों की औसतन लाभकारी आयु के संबंध में सूचना के लिए प्राधिकारी द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर में अनुरोध किया गया है। प्राधिकारी संबंधित निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त औसतन लाभकारी आयु की अवधि तय कर सकते हैं।

xvi. एक आई ई के लिए अधिमान्य आय कर कानून के लिए चीन की सरकार का उत्तर यह है कि घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित ऐसे कार्यक्रम बंद हो चुके हैं।

xvii. चीन की सरकार ने अपने प्रश्नावली उत्तर में स्वयं ही यह माना है कि विदेशी निवेश वाले उद्यम के लिए आय कर संबंधी पूर्व कानून के समाप्त होने के बाद वर्ष 2008 में नया उद्यम आय कर कानून लागू किया गया था। चीन की सरकार ने प्रश्नावली उत्तर में यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित कार्यक्रम के लिए कोई भी रियायत की अवधि लागू नहीं थी। चीन की सरकार ने कार्यक्रम के समाप्त होने और रियायत की अवधि के लागू न होने के संबंध में प्रश्नावली उत्तर में साक्ष्य भी प्रदान किए हैं। 'पी आर सी स्टेट काउंसिल द्वारा पी आर सी उद्यम आय कर कानून डिक्री सं. [2007] 39' के तहत अधिमान्य नीतियों में रियायत के कार्यान्वयन के संबंध में 'नोटिस' यह दर्शाता है कि इस नोटिस में स्पष्ट रूप से सचीबद्ध कार्यक्रमों को ही रियायती अवधि प्रदान की गई थी।

xviii. विशिष्ट कंपनियों को प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल याचिका में कथित कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत विवरण, कानूनी आधार, पात्रता मानदंड, प्रदानकर्ता प्राधिकारी का नाम, इत्यादि प्रदान नहीं किए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई याचिका में सामान्यता प्रत्यक्ष अनुदान कार्यक्रमों की मौजूदगी का उल्लेख

किया गया है। अतः चीन की सरकार ने स्पष्ट रूप से यह उत्तर दिया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रत्यक्ष अनुदान कार्यक्रम नहीं हैं।

xix. यदि घरेलू उद्योग कथित सब्सिडी के बारे में कोई विशिष्ट सूचना दाखिल नहीं करता है अथवा स्पष्टीकरण और साक्ष्य प्रदान नहीं करता है तो वह चीन जन. गण. की सरकार द्वारा कुछ अनुदान कार्यक्रमों की मौजूदगी का दावा नहीं कर सकता।

xx. बैंकों द्वारा कोई भी अधिमान्य क्रृष्ण प्रदान नहीं किया जाता। “चीन के वाणिज्यिक बैंक कानून” के अनुच्छेद 4 में वाणिज्यिक बैंकों को सुरक्षा, लिक्विडिटी और दक्षता के सिद्धांत का अनुसरण करने की अपेक्षा की गई है। वाणिज्यिक बैंक कानून के अनुसार और किसी संस्था अथवा व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बिना अपने कारोबारी प्रचालनों के संबंध में अपने स्वयं के निर्णय लेते हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (पी बी ओ सी) वाणिज्यिक बैंकों के क्रृष्ण कारोबार में दखल नहीं देता। पुनर्गठन के अनुसार, प्रमुख राज्य स्वामित्वाधीन वाणिज्यिक बैंक (एस ओ सी बी) तथा निजी बैंक की अब सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जो बाजार के सिद्धांतों पर ही संचालित हो रही हैं। किसी भी विशिष्ट उद्योग क्षेत्र के अनुसार कोई विशिष्ट क्रृष्ण की नीति निर्मित और प्रयुक्त नहीं की गई है।

xxi. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के लिए चीन सरकार ने वस्तुओं/ सेवाओं के प्रावधान में प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित प्रश्नों के उत्तरों में वस्तुओं के कथित प्रत्येक प्रावधान के लिए चीन जन. गण. में लागू तंत्र के संबंध में पूरी सूचना प्रदान की गई है।

xxii. घरेलू उद्योग ने कतिपय यात्री वाहन और हल्के ट्रक टायरों के मामले में यह दावा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, वाणिज्य विभाग के जांच परिणामों पर भरोसा किया है कि चीन जन. गण. में टायर निर्माताओं को इन कार्यक्रमों के तहत लाभ मिला है। चीन सरकार ने यह नोट किया है कि द्वितीयक सूचना का सहारा लेने का कोई कारण नहीं है, जबकि प्रतिवादी निर्यातिकों ने स्पष्ट रूप से उनके द्वारा लाभ प्राप्त कार्यक्रमों के उपयोग के संबंध में सूचना प्रदान कर दी है। प्रश्नावली उत्तर में उनके द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों व सूचना के आधार पर प्रतिवादी निर्यातिकों के लिए सब्सिडी का निर्धारण किया जाना अपेक्षित होता है।

xxiii. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में, जांच की अवधि 1 जनवरी, 2013 से 31 दिसंबर, 2013 निर्धारित की गई थी। वर्तमान जांच में जांच की अवधि अक्टूबर, 2016 से मित्रिंवर, 2017 तक की है। चीन जन. गण. में ऐसे निर्यातिकों के लिए, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कर रहे थे, जांच की अवधि के लिए सब्सिडी का निर्धारण वर्तमान सब्सिडी रोधी जांच के लिए अप्रतिनिधिक है। बसों और लॉरी के लिए नए न्यूमेटिक टायरों के ऐसे उत्पादकों के लिए जांच की अवधि के निर्धारण के लिए सब्सिडी आवश्यक है, जो भारत को निर्यात कर रहे हैं। इसके अलावा, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “बसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक टायर” हैं, जो संयुक्त राज्य द्वारा प्रतिसंतुलनकारी जांच में विचाराधीन उत्पाद से भिन्न हैं अर्थात् “कतिपय यात्री वाहन और हल्के ट्रक टायर” हैं।

xxiv. साथ ही, घरेलू उद्योग द्वारा जिस निर्धारण पर भरोसा किया गया है वह वर्ष 2015 के संबंध में हैं, जो अप्रचलित हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य ने ही इसकी प्रशासनिक समीक्षा की है।

xxv. घरेलू उद्योग ने यह गलत दावा किया है कि कतिपय कार्यक्रमों को संयुक्त राज्य द्वारा प्रतिसंतुलनकारी किया गया था। उदाहरण के लिए घरेलू उद्योग का कहना है कि संयुक्त राज्य प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष दिया है कि “ऑटोमोबाइल्स और टायर उद्योगों के लिए वेहाई म्युनिसिपलिटी सब्सिडी” का प्रयोग किया गया था और चीन जन. गण. से निर्यातिकों को समीक्षा की अवधि के दौरान लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार, घरेलू उद्योग ने यह गलत उल्लेख किया है कि यू एस प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि निर्यातक शांडोंग योंगफेंग टायर्स कं. लिमि. ने “उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए आय कर कटौती” के तहत लाभ प्राप्त किया है। संयुक्त राज्य ने प्रशासनिक समीक्षा के विशेष तौर पर यह निष्कर्ष दिया है कि “उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए आय कर कटौती” के लिए निर्यातिकों को कोई लाभ प्रदान नहीं किया था।

xxvi. यदि कथित सब्सिडी के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई तो चीन की सरकार को विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। एस सी एम करार के अनुच्छेद 11.2 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल आवेदन में सब्सिडी की मौजूदगी के पर्याप्त साक्ष्य होंगे। अतः आवेदन में (i) वित्तीय अंशदान (ii) विशिष्टता और (iii) लाभ के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य शामिल होंगे।

xxvii. घरेलू उद्योग की पूर्व सी वी डी जांचों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलनकारिता के संबंध में गलत सूचना प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा कथित निम्नलिखित अनुदान कार्यक्रम, जिसमें पवन संचालित विद्युत जनरेटर के लिए कास्टिंग के मामले में प्रतिसंतुलनकारिता पाई गई है, उनकी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच भी नहीं की गई थी :

- ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार के लिए विशेष कोष
- स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी कोष
- निर्धारित परिसंपत्ति निवेश सब्सिडी और
- निर्यात सहायता अनुदान

xxviii. इसी प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा कथित निम्नलिखित अधिमान्य कर कार्यक्रमों, जिनमें पवन संचालित विद्युत जनरेटर के लिए कास्टिंग के मामले में प्रतिसंतुलनकारिता पाई गई है, उनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच भी नहीं की गई थी :

- कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित संचालन हेतु उत्पादनकारी एफ आई ई के लिए घटाई गई कर दर
- विदेशी निवेश वाले निर्यात उद्यम के लिए अधिमान्य कर नीतियां
- विदेशी निवेशकों द्वारा एफ आई ई लाभों के पुनर्निवेश के लिए आय कर रिफंड
- उन्नत प्रौद्योगिकी एफ आई ई के लिए आय कर कटौती
- विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित विदेशी निवेश वाले उद्यम के लिए अधिमान्य कर नीतियां
- तटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों में और आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्रों में स्थापित विदेशी निवेश वाले उद्यम के लिए अधिमान्य कर नीतियां
- सेज और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों आदि में कारपोरेट आय कर छूट और कटौती

xxix. घरेलू उद्योग ने भी सब्सिडी कार्यक्रमों की अन्य श्रेणियों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व जांच परिणाम के आधार पर कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलनकारिता के बारे में इसी प्रकार के गलत दावे किए हैं।

xxx. कपितय होट एंड कोल्ड स्टेनलेस स्टील उत्पादों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन सरकार को असहयोगी माना है और उसके बाद उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कथित कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलनकारिता निर्धारित की है। तथापि, वर्तमान मामले में, चीन की सरकार ने पूर्ण प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है और सभी संगत सूचना प्रदान की है। निर्दिष्ट प्राधिकारी चाहे तो चीन की सरकार से ऐसी और भी सूचना की मांग कर सकते हैं, जो उसे आवश्यक लगे और कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलनकारिता निर्धारित करने के लिए स्टेनलेस स्टील उत्पादों के मामले में अपने पूर्व जांच परिणाम पर भरोसा न करें।

xxxi. स्टील उत्पादों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांचों में अन्य देशों में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर निर्भरता न्यायोचित नहीं है। एस सी एम करार के अनुच्छेद 12.8 तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 7(8) में स्पष्ट प्रावधान है कि केवल जब हितवद्ध पक्षकार (अर्थात् चीन सरकार अथवा अन्य निर्यातक) सूचना प्रदान करने से मना करते हैं, अथवा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करते हैं, तो ही प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों का सहारा ले सकते हैं। ऐसे मामलों में विचाराधीन उत्पाद 'आर्गेनिक कोटेड स्टील', 'कार्बन और अलॉय स्टील', 'नान-ओरिएंटेड स्टील' आदि थे। इन मामलों में विचाराधीन सभी उत्पाद स्टील क्षेत्र के हैं। चीन जन. गण. में स्टील उत्पादकों को लाभ प्राप्त हो चुके हैं, उनका ऐसे लाभ से कोई संबंध नहीं है, जो चीन जन. गण. में बसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक टायरों के उत्पादकों को प्राप्त हुए होंगे। ऐसे मामलों में जांच की अवधि पुरानी है और अप्रतिनिधिक है तथा ऐसे

मामलों में जांच प्राधिकारियों ने अनेक कार्यक्रमों के संबंध में सब्सिडी का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है न कि सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर अथवा चीन सरकार अथवा चीन जन. गण. के निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर।

xxxii. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 12 (1) में यह प्रावधान है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की राशि प्राप्तकर्ता पर प्रदत्त लाभ के संबंध में गिनी जाएगी, जो सब्सिडी के लिए जांच अवधि के दौरान मौजूद पाई गई है।

xxxiii. चीन की सरकार ने अपने प्रश्नावली उत्तर में कथित सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए सह्योगी निर्यातकों को प्राप्त लाभ के बारे में सूचना प्रदान की है। विचाराधीन उत्पाद के ऐसे उत्पादकों को प्राप्त लाभ के संबंध में कोई सूचना अपेक्षित नहीं है, जो या तो विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं कर रहे हैं अथवा जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया था। ऐसे उत्पादकों को जिन्होंने तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया था, प्राप्त लाभ का इस प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में प्राधिकारी विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान जांच का दायरा ऐसे उत्पादकों तक सीमित है, जिन्होंने भारत को बसों और लॉरियों के लिए नए न्यूमेटिक टायरों का निर्यात किया है।

xxxiv. प्रतिवादी निर्यातकों ने जांच की अवधि के दौरान आवृत्ति सब्सिडी के लिए और गैर आवृत्ति सब्सिडी के लिए उन्हें प्राप्त लाभ के बारे में सूचना प्रदान की है, जिसके लिए जांच की अवधि में लाभ प्राप्त हुआ है।

xxxv. घरेलू उद्योग ने यह माना है कि ए यू एल की अवधि 18 वर्षों की है। वास्तव में, घरेलू उद्योग ने लिखित अनुरोध में यह भी दावा किया है कि वर्तमान जांच में ए यू एल की अवधि 25 वर्षों की है। घरेलू उद्योग ने ऐसी दीर्घ ए यू एल अवधि को मानने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है। प्राधिकारी को चीन जन. गण. में टायर क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास की दरों के आधार पर गैर-आवृत्ति सब्सिडी के मामले में लाभ के आवंटन के लिए उपयुक्त ए यू एल अवधि निर्धारित करनी अपेक्षित है। निर्यातकों ने ऐसे मूल्यहास की दरों और ऐसे मूल्यहास की दरों के आधार पर प्रस्तावित ए यू एल अवधि के बारे में अपने प्रश्नावली उत्तर में सूचना प्रदान की है।

xxxvi. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि निर्यातक को जांच की अवधि के दौरान कथित सब्सिडी कार्यक्रम के लिए लाभ प्राप्त हुआ है। निर्यातकों ने निम्नलिखित की स्पष्ट पहचान करते हुए विस्तृत उत्तर प्रदान किए हैं :

- ऐसे आवृत्ति सब्सिडी कार्यक्रम, जो याचिका में उल्लिखित हैं और जिनके तहत उन्हें जांच की अवधि में लाभ प्राप्त हुआ है।
- ऐसे गैर-आवृत्ति सब्सिडी कार्यक्रम, जो याचिका में उल्लिखित हैं और जिनके तहत उन्हें जांच की अवधि में लाभ प्राप्त हुआ है।
- ऐसे आवृत्ति सब्सिडी कार्यक्रम जो याचिका में उल्लिखित नहीं हैं लेकिन जिनके तहत उन्हें जांच की अवधि में लाभ प्राप्त हुआ है।
- ऐसे गैर आवृत्ति सब्सिडी कार्यक्रम, जो याचिका में उल्लिखित नहीं हैं, लेकिन जिनके तहत उन्हें जांच की अवधि में लाभ प्राप्त हुआ है।

xxxvii. घरेलू उद्योग का यह दावा है कि प्रतिवादी निर्यातक ऐसे सकारात्मक साक्ष्य प्रदर्शित करे कि उन्हें कथित सब्सिडी के तहत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, यह तर्कसंगत नहीं है।

xxxviii. निर्यातकों ने यह दर्शाते हुए सकारात्मक साक्ष्य प्रदर्शित किए हैं कि उन्हें कथित सब्सिडी कार्यक्रम के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। लाभ प्राप्त न होना एक नकारात्मक तथ्य है, जो सकारात्मक साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

छ. 3. याचिकाकर्ताओं द्वारा सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच :

26. चीन जन. गण. से टायर के 6 समूहों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। उनमें से 5 समूहों ने पी ओ आई के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है। मै. शेनडोंग हाओहुआ टायर कं. लि., मै. गुआनझोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कं. लि. और

मैं, एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लि, ने भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। ऐसे टायर उत्पादकों के लिए अलग सब्सिडी माजिन निर्धारित नहीं किया जा सकता जिन्होंने पी औ आई के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से इन उत्पादकों के लिए अलग प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

I. अनुदान :

(i) कार्यक्रम सं. 1 : प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम :

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध :

27. याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि ऐसे उद्यम जिनके ब्रांड “चीन के विश्वव्यापी प्रसिद्ध ब्रांड” के लिए योग्य हैं, चीन की सरकार से प्रत्यक्ष निश्चिय अंतरण के लिए पात्र हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट प्रकृति का है, क्योंकि यह निर्यातों के संबंध में प्रासंगिक है। कार्यक्रम के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं जो उनके पास ताकिक तौर पर उपलब्ध थे :

- i. आदेश सं. 124 – चीन के प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों के प्रशासन के लिए उपाय (दिसंबर, 2009)
- ii. चीन के प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों के प्रशासन के लिए उपाय (दिसंबर, 2006)
- iii. “राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के प्रशासन के लिए उपाय” के प्रख्यापन और परिचालन के संबंध में नोटिस (पैरा 4 और 7)
- iv. राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के लिए ट्रेजरी बांड विशेष कोष के प्रशासन के लिए उपाय पैरा 6-9 गुओ जिंग माओ टोऊ जी (1999) सं. 886 (10 सितंबर, 1999)
- v. स्टेट काउंसिल ऑन प्रोमोटिंग इंटरप्राइज टेक्नोलोजिकल रिनावेशन की मार्गदर्शी राय (गुओ फा (2012) सं. 44)
- vi. 2015 के लिए औद्योगिक पुनरुद्धार और प्रौद्योगिकीय नवीकरण विशेष कार्य योजना
- vii. गुआंगडोंग प्रांत के ऐसे उद्यमों, जिनके उत्पाद “चीन विश्वव्यापी प्रसिद्ध ब्रांड”, “चीन प्रसिद्ध ब्रांड” अथवा “चीन विख्यात ब्रांड” शीर्षक के लिए पात्र हैं, उनकी सराहना करने और/ अथवा पुरस्कृत करने के संबंध में निर्णय।
- viii. स्व- निर्यात ब्रांड के विकास के लिए 2008 में विशेष अवार्ड फंड वजट के संबंध में शानडोंग प्रांत का नोटिस (लु काई की झी (2008) सं. 75)।

क. चीन सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध :

28. चीन सरकार ने यह कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए सभी कानूनी आधारों में कानूनी पाठ केवल आदेश सं. 124 – चीन के प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों के प्रशासन के लिए उपाय (दिसंबर, 2009) के लिए प्रदान किया गया था। आदेश सं. 124 – चीन के प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों के प्रशासन के लिए उपाय (दिसंबर, 2009) दिनांक 6 मार्च, 2008 को समाप्त कर दिया गया था। शेष दस्तावेजों के लिए कोई भी कानूनी पाठ संलग्न नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई ‘चीन के प्रसिद्ध ब्रांड रणनीति विकास रिपोर्ट’ कानूनी पाठ नहीं है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

29. “राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के प्रशासन के लिए उपाय” के प्रख्यापन और परिचालन के संबंध में नोटिस (पैरा 4 और 7) तथा राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के लिए ट्रेजरी बांड स्पेशल फंड के प्रशासन के लिए उपाय – पैरा 6-9, गुओ जिंग माओ टोऊ जी (1999) सं. 886 (10 सितंबर, 1999) राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना कोष के संदर्भ में थे और दोनों ही वैध नहीं पाए गए।

30. उद्यम प्रौद्योगिकीय नवीकरण को बढ़ावा देने के संबंध में स्टेट काउंसिल की मार्गदर्शी राय (गुओ फा (2012) सं. 44) तथा 2015 के लिए औद्योगिक पुनरुद्धार और प्रौद्योगिकीय नवीकरण विशेष कार्य योजना प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम के लिए संगत नहीं

पाए गए थे। प्राधिकारी स्वयं निर्यात ब्रांड के विकास के लिए 2008 में विशेष पुरस्कार कोष बजट के संबंध में शानडोंग प्रांत के नोटिस (लु काई की सी (2008) सं. 75) की सामग्री की पहचान करने और यह मूल्यांकन करने में असमर्थ थे कि क्या यह विधान कार्यक्रम से संबंधित है अथवा नहीं।

31. प्राधिकारी ने गुआंगडोंग प्रोविंस की जनतिंत्रक सरकार की वेबसाइट पर भी यह नोटिस किया कि उसने गुआंगडोंग प्रांत के ऐसे उद्यमों, जिनके उत्पाद 2005, 2006 और 2007 में “चीन विश्वव्यापी प्रसिद्ध ब्रांड”, चीन प्रसिद्ध ब्रांड, “चीन विख्यात ब्रांड” शीर्षक के लिए योग्य थे, उनकी सराहना करने और/ अथवा पुरस्कृत करने के संबंध में निर्णय जारी किया था। तथापि, यह जात नहीं है कि क्या ये कार्यक्रम अभी भी सक्रिय हैं अथवा नहीं।
32. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम दिनांक 29 दिसंबर, 2001 के चीन के ब्रांड नाम वाले उत्पादों के लिए प्रशासनिक उपायो (गुणवत्ता, पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध के सामान्य प्रशासन के आदेश सं. 12) के तहत शासित था। इसे दिनांक 18 दिसंबर, 2009 को “चीन के ब्रांड नाम वाले उत्पादों के लिए प्रशासनिक उपायों” को संशोधित करने के संबंध में गुणवत्ता, पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध के सामान्य प्रशासन के निर्णय (गुणवत्ता, पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध के सामान्य प्रशासन का आदेश सं. 124, वर्ष 2009) द्वारा संशोधित किया गया था।
33. गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध के सामान्य प्रशासन के कुछ विनियमों (2018) को समाप्त करने और संशोधित करने के संबंध में निर्णय (गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध के सामान्य प्रशासन के 2018 के आदेश सं. 196) के अनुसार यह कार्यक्रम जांच की अवधि के दौरान भी वैध था।
34. कार्यक्रम में धनराशि के अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है और उसका लाभ को प्राप्तकर्ता को प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है, क्योंकि यह केवल ऐसे कतिपय उद्यम तक ही लागू है, जो प्रसिद्ध ब्रांडों के लिए उत्पाद मानदंड को पूरा करता है। चीन जन. गण. से किसी भी भागीदार उत्पादक और निर्यातक को इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं होते हैं।
35. याचिकाकर्ता ने यह दर्शने के लिए कोई साक्ष्य भी प्रदान नहीं किया है कि यह कार्यक्रम चीन जन. गण. में टायर उत्पादों द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया था।
36. जांच के दौरान प्राधिकारी ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके जिससे कि यह पता चले कि चीन जन. गण. में ऐसे टायर उत्पादकों, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया था, को इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, चीन सरकार ने यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रदर्शित किए हैं कि यह कार्यक्रम दिनांक 6 मार्च, 2018 को समाप्त कर दिया गया था। अतः प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(ii) कार्यक्रम सं. 2 : ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार के लिए विशेष कोष :

क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध :

37. याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि कार्यक्रम के तहत ऐसे उद्यमों की सहायता करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई थी, जो चीन में उच्च दक्षता और ऊर्जा खपत वाले उत्पादों का निर्माण करते हैं। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाओं अथवा योजनाओं के दस्तावेज प्रदान किए हैं, जो उनके पास तर्कसंगत रूप से उपलब्ध थे :

 - i. ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार पुरस्कार वित्तीय कोष के प्रशासन के संबंध में मुद्रण और वितरण अंतरिम उपायों पर वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग का परिपत्र (कोई जियान (2007) सं. 371)
 - ii. शानडोंग वित्तीय विभाग और शांडोंग, आर्थिक और व्यापार आयोग के परिपत्र के तहत ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी के लिए अनंतिम उपाय विशेष कोष।
 - iii. टायर उद्योग नीति जारी करने के संबंध में उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अनुवादित नोटिस (गोंग चान ये झेंग के (2010) सं., अनुच्छेद 6.

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध :

38. चीन सरकार ने यह कहा कि याचिकाकर्ताओं ने शांडोंग वित्त विभाग और शांडोंग आर्थिक तथा व्यापार आयोग के परिपत्र के तहत ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी के लिए अनंतिम उपाय विशेष कोष के संबंध में कानूनी पाठ प्रदान नहीं किया।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

39. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कार्यक्रम को काई जियान (2007) सं. 371 के तहत संचालित किया गया था। इस विनियम के स्थान पर ऊर्जा संरक्षण प्रौद्योगिकी सुधार के लिए वित्तीय प्रोत्साहन कोष के लिए प्रशासनिक उपाय जारी करने के संबंध में वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग का नोटिस (काई जियान (2011) सं. 367) दिनांक 21 जून, 2011 जारी किया गया। इस नोटिस के बाद उसकी जगह पर ऊर्जा संरक्षण और उत्सर्जन कटौती के लिए प्रशासनिक सबिसडी हेतु अंतरिम उपायों को जारी करने पर वित्त मंत्रालय का नोटिस (काई जियान (2015) सं. 161) दिनांक 12 मई, 2015 जारी किया गया। काई जियान (2015) सं. 161 अब तक लागू है।

40. शांडोंग वित्त विभाग और शांडोंग आर्थिक एवं व्यापार आयोग के परिपत्र (लु काई जियान (2006) सं. 61 के तहत ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी के लिए विशेष कोष के संबंध में अनंतिम उपायों के संबंध में, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि विनियम के स्थान पर लु काई जियान (2007) सं. 14) दिनांक 12 जून, 2007 जारी किया गया और उसके बाद उसके स्थान पर दिनांक 27 दिसंबर, 2017 का लु काई गोंग (2017) सं. 52 जारी किया गया और लु काई गोंग (2017) सं. 52 अभी लागू है।

41. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कार्यक्रम की पहले भी अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा चुकी है, जिसमें भी इसकी मौजूदगी सावित हो चुकी है। उदाहरण के लिए इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील में यू एस प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित की जा चुकी है।

42. कार्यक्रम में धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है और उसके बाद ऐसे वित्तीय योगदान की प्राप्ति के लाभ प्रदान किए गए हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह ऐसे उद्यम तक सीमित है, जिसमें ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार किए गए हैं।

43. चीन जन. गण. से किसी भी भागीदार उत्पादकों/ निर्यातकों ने इस सबिसडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने यह दर्शने के लिए कोई साक्ष्य भी प्रदान नहीं किया है कि इस कार्यक्रम के तहत चीन जन. गण. में टायर उत्पादकों द्वारा लाभ प्राप्त किए गए थे, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, उन्हें इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है।

44. जांच के दौरान प्राधिकारी कोई भी ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके कि चीन जन. गण. में टायर उत्पादकों, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, उन्हें इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है।

45. अतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(iii) कार्यक्रम सं. 3 : स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी कोष :

क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध :

46. याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के तहत सबिसडी फंड पर्यावरणीय निरीक्षण करने वाले उत्पादकों और निर्माताओं को प्रदान किए गए आर्थिक पुरस्कारों सहित प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रदूषण कम करने के प्रयोजन से प्रदान किया गया था। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज, प्रदान किए हैं, जो उनके पास तार्किक तौर पर उपलब्ध थे।

- स्वच्छ उत्पादन निरीक्षण के संबंध में अनंतिम उपाय, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पर्यावरणीय संरक्षण मंत्रालय की डिक्री सं. 16 (अगस्त, 2004), अनुदित अंश।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

47. प्राधिकारी ने यह नोट किया कि कार्यक्रम को 'स्वच्छता उत्पादन समीक्षा' के लिए अंतरिम उपाय (राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग तथा पूर्व राज्य पर्यावरणीय संरक्षण प्रशासन का आदेश सं. 16) के तहत संचालित किया गया था। विनियम के स्थान पर स्वच्छता उत्पादन समीक्षा (2016 संशोधन) दिनांक 16 मई, 2016 लाया गया। यह 2016 का संशोधन अभी भी लागू है।

48. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कार्यक्रम की जांच पूर्व में भी अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा की जा चुकी है। उदाहरण के लिए इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता की मौजूदगी नॉन ओरिएटेड इलेक्ट्रिकल स्टील में यू एस प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित की जा चुकी है।

49. कार्यक्रम में धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है और उसके बाद ऐसे वित्तीय योगदान की प्राप्ति के लाभ प्रदान किए गए हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह ऐसे उद्यम तक सीमित है जिसमें पर्यावरणीय निरीक्षण शामिल है।

50. किसी भी सहभागी कंपनी ने इस समिडी के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रदान नहीं किया है, जिससे चीन जन. गण. में ऐसी किसी टायर उत्पादकों द्वारा इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किए जाने को दर्शाया जो सके, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात किया है।

51. जांच के दौरान, प्राधिकारी ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, जिससे यह पता चले कि चीन जन. गण. में ऐसे टायर उत्पादकों, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है, को इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है।

52. अतः प्राधिकारी यह प्रस्ताव करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(iv) कार्यक्रम सं. 4 : राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण :

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुरोध :

53. पात्र उद्यमों को तकनीकी उन्नयन और नवोन्मेष के लिए अनुदान प्रदान किया गया है और यह अन्य के साथ-साथ प्रमुख उद्योगों, उद्योगों और उत्पादों में प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित ऐसी अधिसूचना अथवा सूचना दस्तावेज प्रदान किए हैं, जो उनके पास तर्कसंगत रूप से उपलब्ध थे -

- i. "राष्ट्रीय प्रभाव प्रौद्योगिकीय नवीकरणीय परियोजनाओं के प्रशासन के लिए उपायों" और "राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के लिए ट्रेजरी बांड विशेष कोष के प्रशासन के लिए उपायों" के प्रख्यापन और परिचालन के संबंध में नोटिस (गुओ जिंग माओ ताऊ जी [1999] सं. 886);
- ii. गुओ जिंग माओ ताऊ जी सं. 122 (1999);
- iii. "राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के पर्यवेक्षण और प्रशासन के लिए उपाय" के राज्य आर्थिक और व्यापार आयोग से प्रख्यापन और परिचालन के लिए नोटिस (गुओ जिंग माओ तोऊ जी (1999) सं. 1038);
- iv. "राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के प्रशासन के लिए उपाय" और "राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के लिए ट्रेजरी बांड विशेष कोष के प्रशासन के लिए अन्य" में संशोधनों के लिए नोटिस (गुओ जिंग माओ तोऊ जी [2000] सं. 82)
- v. 15 टायर ब्रांड/ उत्पादकों सहित संकेंद्रित प्रोत्साहन और विकास के लिए शांडोंग प्रोविंस इंटरनेशनल ब्रांड शांडोंज प्रांत की 2012-13 की सूची
- vi. चीन के प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों के प्रशासन, गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध के सामान्य प्रशासन के लिए उपाय, आदेश सं. 124 (18 दिसंबर, 2009)

vii. संकेंद्रित प्रोत्साहन और विकास के लिए शांडोंग प्रोविंस इंटरनेशनल ब्रांड नामों की 2011-13 की सूची की घोषणा करने के संबंध में वाणिज्य विभाग, शांडोंग प्रांत का नोटिस (7 जनवरी, 2012)।

54. कार्यक्रम में नकदी अनुदान के रूप में धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण और प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान करने के लिए प्रावधान है। इस कार्यक्रम में अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा प्रतिसंतुलनकारिता पाइ गई है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि चीन में ऐसे प्रमुख टायर उत्पादक, जो इन कार्यक्रमों के हित पात्र हैं, शंघाई टायर एंड रबड कं. लिमि. जैसी संस्थाएं हैं। (डबल क्वाइन का एक उत्तराधिकारी) गुइज्जोऊ टायर कं. लिमि. किंगदाओ डाबल स्टार।

ख. **चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :**

55. यह कार्यक्रम काफी समय पहले 22 फरवरी, 2008 को समाप्त कर दिया गया था। इस कार्यक्रम के तहत लाभ की निरंतर मौजूदगी नहीं है। इस कार्यक्रम के तहत कोई प्रतिस्थापन और रियायती अवधि नहीं थी। अतः जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के तहत किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने लाभ के लिए अनुरोध नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

ग. **प्राधिकारी द्वारा जांच :**

56. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम 10 सितंबर, 1999 को निम्नलिखित दस्तावेज के माध्यम से लागू किया गया था :

- “राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के प्रशासन के लिए उपाय” तथा
- राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के लिए ट्रेजरी बांड विशेष कोष के प्रशासन के लिए आय” (गुओ जिंग टोऊ जी [1999] सं. 886), जिसे दिनांक 28 अगस्त, 2000 को प्रतिस्थापित किया गया था (गुओ जिंग माओ टोऊ जी [2000] सं. 822)
- इसके अलावा, राज्य अर्थिक और व्यापार आयोग द्वारा जारी “राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के पर्यवेक्षण और प्रशासन के लिए उपाय” (गुओ जिंग माओ टोऊ जी (1999) सं. 1038) वह माध्यम था, जिसे तहत कार्यक्रम का पर्यवेक्षण किया गया था।

57. दिनांक 22 फरवरी, 2008 को राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एन डी आर सी) ने अपनी डिक्री सं. 59 जारी की थी, जिसके द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम को बंद किया गया था।

58. प्राधिकारी ने कानूनी आधार वाले शेष तीन दस्तावेजों की जांच की है :

- संकेंद्रित प्रोत्साहन और विकास के लिए शांडोंग प्रोविंस इंटरनेशनल ब्रांड की वर्ष 2012-13 की शांडोंग प्रोविंस की सूची (जिसमें 15 टायर ब्रांडों/ उत्पादकों के नाम शामिल हैं);
- चीन के प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों के प्रशासन, गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध के सामान्य प्रशासन के लिए उपाय, आदेश सं. 124 (18 दिसंबर, 2009); और
- संकेंद्रित प्रोत्साहन और विकास के लिए शांडोंग प्रोविंस इंटरनेशनल ब्रांड नामों की 2011-13 की सूची की घोषणा के संबंध में शांडोंग प्रोविंस, वाणिज्य विभाग का नोटिस (7 जनवरी, 2012)।

तथापि, प्राधिकारी ने यह पाया कि ये दस्तावेज इस कार्यक्रम के कानूनी आधार के लिए संगत नहीं थे।

59. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि कुछ दस्तावेज उपरोक्त कार्यक्रम के लिए संगत नहीं थे और अन्य दस्तावेज अब आगे लागू नहीं हैं। इस प्रकार चीन जन. गण. में कोई भी ऐसा उत्पादक, जिसने संबद्ध उत्पाद का भारत को निर्यात किया है, उसे जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के तहत अवश्य लाभ प्राप्त हुए होंगे। इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(v) कार्यक्रम सं. 5, निर्धारित परिसंपत्ति निवेश समिक्षा :

क. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध :

60. याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि उपरोक्त कार्यक्रम के तहत हेफेर्ड सरकार द्वारा एक समिक्षा प्रदान की जाती है। यह ऐसी समिक्षा है जो 'द हेफेर्ड म्युनिसिपल इकोनोमी एंड इंफोर्मेशन कमीशन' की रिपोर्ट के तहत निर्यात संवर्धन के तहत प्रदान की जाती है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं, जो उनके पास तर्कसंगत रूप से उपलब्ध थे।

i. हेफेर्ड म्युनिसिपल इकोनोमी एंड इंफोर्मेशन कमीशन, टिप्पणियों के लिए नोटिस; स्थानांतरित उद्योग और त्वरित नए औद्योगिकीकरण के लिए अनेक नीतियां (15 मई, 2013)

ii. जी आई टी आई फुजियन तिमाही रिपोर्ट (2014)

याचिकाकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि केवल गीती अनहुई पैसेंजर रेडियल टायर कं. लिमि. गीती टायर (अनहुई) कं. लिमि. इस कार्यक्रम के तहत पात्र थे।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

61. गीती फुजियन प्रारंभिक तिमाही रिपोर्ट कानूनी आधार नहीं हैं। अतः प्राधिकारी को ऐसी सूचना को अस्वीकार कर देना चाहिए। हेफेर्ड शहर में स्थित संबद्ध वस्तुओं का केवल एक ही उत्पादक है अर्थात् गीती टायर (अनहुई) कं. लिमि।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विनियम के तहत हेफेर्ड म्युनिसिपल इकोनोमी एंड इंफोर्मेशन कमीशन निर्धारित परिसंपत्ति निवेश मूल्य के 5 प्रतिशत के समान वित्तीय अंशदान प्रदान करता है। कार्यक्रम में धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है, जिससे प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया जाता है। समिक्षा भी निश्चित है, क्योंकि यह निर्धारित परिसंपत्ति निवेश वाले उद्यम के लिए है और वह ऐसे लाभ के लिए योग्य है।

63. किसी भी भागीदार कंपनी ने इस समिक्षा कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने कोई भी ऐसे साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं, जो यह दर्शाएं कि चीन जन. गण. में ऐसे टायर उत्पादकों द्वारा इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किए हैं, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है।

64. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हेफेर्ड शहर में स्थित गीती टायर (अनहुई) कं. लिमि. ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र था। गीती टायर (अनहुई) कं. लिमि. ने भाग नहीं लिया है अथवा प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है और इसीलिए प्राधिकारी यह अनुमान नहीं लगा सकते कि गीती टायर (अनहुई) कं. लिमि. ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है। इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(vi) कार्यक्रम सं. 6, हाईटेक उद्योग का उद्यम निवेश कोष :

क. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध :

65. याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि उपरोक्त कार्यक्रम के तहत हाईटेक जोन अथवा हाईटेक पार्क (वीजिंग, शंघाई, तियांजिन, चोंगकिंग, चीन के उत्तरी जिले) में स्थित "हाईटेक उत्पाद" का उत्पादन करने वाले उद्यम वित्तीय अनुदान के लिए पात्र हैं। कर्ज की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं, जो उनके पास तार्किक रूप से उपलब्ध थे।

i. चोंगकिंग में हाईटेक उद्योग के उद्यम निवेश कोष के संबंध में अस्थायी प्रशासन उपायों में चोंगकिंग पीपल्स गवर्नर्मेंट ऑफिस का परिपत्र – 2005

66. याचिकाकर्ताओं ने केवल शंघाई टायर एंड रबड कं. लिमि., शंघाई गुआंग जेंग रबड कं. लिमि., शंघाई इंटरनेशनल ट्रेड कं. लिमि., फिच बम्बू, चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लिमि., शंघाई जिंग यू ट्रेडिंग कं. लिमि. चांगकिंग अनुंग डोव ट्रेड

कं. लिमि., अपलोड चिंग ट्रेड कं. लिमि., चॉंगकिंग यान इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमि., चॉंगकिंग जुयानन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं. लिमि. इस कार्यक्रम के तहत पात्र थी।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

67. चीन सरकार ने यह बताया है कि विनियम केवल चॉंगकिंग म्युनिसिपलिटी के लिए लागू थे। चिंग किंग में कोई भी संबद्ध उत्पाद का उत्पादक नहीं था।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

68. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विनियम के तहत चिंगकिंग म्युनिसिपल सरकार ने चिंगकिंग में महत्वपूर्ण हाई-टेक उद्योगों को सब्सिडी प्रदान की गई है।

69. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कार्यक्रम की कुछ अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई है, जो इसकी मौजूदगी को भी सिद्ध करता है। उदाहरण के लिए, इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता क्तिपय एल्युमिनियम एक्ट्रजन में कनाडाई जांच प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित की गई है।

70. कार्यक्रम में धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है और इसके प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम में सब्सिडी भी निश्चित है, क्योंकि यह हाई-टेक उद्योगों के लिए प्रासंगिक है।

71. तथापि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चॉंगकिंग में कोई भी टायर उत्पादक स्थित नहीं था। अतः किसी टायर उत्पादक, जिसने भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है, को इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। अतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(vii) कार्यक्रम सं. 7, विदेशी निवेश के साथ मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान :

क. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध :

72. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना था। निवेश की लागत की दृष्टि से एफ आई ई को अनुदान प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं, जो उन्हें तर्कसंगत रूप से उपलब्ध कराए गए थे।

- i. मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने के लिए विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन देने के संबंध में गुआंगज़ोऊ म्युनिसिपलिटी का प्रावधान
- ii. मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना करने के लिए विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के संबंध में गुआंगज़ोऊ म्युनिसिपलिटी के प्रावधान जारी करने के बारे में गुआंगज़ोऊ म्युनिसिपल पीपल्स गवर्नर्मेंट के सामान्य कार्यालय का नोटिस (सं. 34 (2006))
- iii. मुख्यालय की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रेषित विचारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए गुआंगज़ोऊ म्युनिसिपल पीपल्स गवर्नर्मेंट का नोटिस सुई (2010) सं. 2)

73. याचिकाकर्ताओं ने यह उल्लेख किया है कि केवल झाओयूवान लायो रवड प्रोडक्ट्स कं. लिमि., हंगज़ोऊ झोंगुजी रवड कं. लिमि., हाआयू टायर कं. लिमि., गुआंगज़ोऊ पर्ल रिवर रवड टायर लिमि. माइकेलिन (शेनयांग) टायर कं. लिमि., जियामेन झोंगजिन रवड इंडस्ट्री कं. लिमि., केन्डा रवड (चीन) कं. लिमि. इस कार्यक्रम के तहत पात्र थे।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

74. कानूनी आधार (i) और (ii) समान थे, जो कानूनी आधार (iii) के तहत समाप्त कर दिए गए थे। कानूनी आधार (iii) को भी मुख्यालय की अर्थव्यवस्था के विकास को त्वरित करने के संबंध में गुआंगज़ोऊ म्युनिसिपलिटी की जन. सरकार के नोटिस के तहत समाप्त कर दिया गया था (सुई फू (2013) सं. 14, दिनांक 15 जून, 2013).

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

75. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मुख्यालय क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना के लिए विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के संबंध में गुआंगज़ोऊ म्युनिसिपल्स की जन. सरकार के सामान्य कार्यालय की सूचना (सुई फु वान (2006) सं. 34) के स्थान पर मुख्यालय की अर्थव्यवस्था के विकास के नोटिस पर प्रेषित विचारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए गुआंगज़ोऊ म्युनिसिपलिटी की जन. सरकार का दिनांक 16 जनवरी, 2010 का नोटिस जारी किया गया था (सुई फु (2010) सं. 2 तथापि यह कानूनी आधार भी मुख्यालय की अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के सबध में गुआंगज़ोऊ म्युनिसिपलिटी की जन. सरकार के नोटिस के तहत समाप्त कर दिया गया था। (सुई फु (2013) सं. 14; दिनांक 15 जून, 2013.

76. चीन जन. गण. में किसी भी टायर उत्पादक को कथित सन्सिडी कार्यक्रमों के तहत कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि यह लागू नहीं था।

77. अतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(vii) कार्यक्रम सं. 8 : नवोन्मेषी लघु और मध्यम उद्यम अनुदान :

क. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध :

78. एस एम ई के लिए नए उत्पाद विकास के लिए पूंजी और सन्सिडी शुरू करने के लिए अनुदान प्रदान किए गए थे। प्रत्येक परियोजना के लिए उपयुक्त राशि सामान्यतः 1 मिलियन आर एम बी से अधिक नहीं होगी, जो प्रमुख परियोजनाओं के मामले में 2 मिलियन आर एम बी से अधिक नहीं होगी। कार्यक्रम की मौजूदगी के साध्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं:

- एस एम ई के संवर्धन के संबंध में पी आर सी के कानून का अनुच्छेद 12, 13, 36;
- लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकास कोष के प्रशासन के लिए उपाय;
- लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकास कोष के प्रशासन के लिए उपायों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम (1 जुलाई, 2001)
- लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकास कोष के प्रशासन के लिए उपाय जारी करने के लिए परिपत्र सहयोग (2010)
- विदेशी व्यापार विकास कोष और प्रबंधन संकल्पना, काई की (2014)
- “एस एम ई के विकास के लिए विशेष कोष के प्रशासन के संबंध में उपाय” जारी करने के संबंध में वित्त मंत्रालय और उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नोटिस (सं. 96 (2012), वित्त मंत्रालय)
- एस एम ई के विकास के लिए विशेष कोष अंतरिम उपाय जारी करने के संबंध में उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय का नोटिस (काई की (2014) सं. 38)
- एस एम ई के विकास के लिए विशेष कोष के प्रबंधन के संबंध में अंतरिम उपाय “जारी करने के संबंध में वित्त मंत्रालय का नोटिस (काई जियान (2015) सं. 458”.

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

79. चीन जन. गण. से भागीदार उत्पादकों/ नियांतिकों को इस कार्यक्रम के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कार्यक्रम को लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए विशेष कोष के प्रशासन के लिए उपायों के तहत शासित किया गया था (काई की (2004) सं. 185)। इस विनियम को कई बार बदला गया था। अंततः इसे काई जियान (2016) सं. 841 द्वारा बदला गया, जो अभी भी लागू है।

81. लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के प्रोत्साहन के संबंध में चीन जनतांत्रिक गणराज्य का कानून भी दिनांक 1 सितंबर, 2017 से संशोधन किया गया।

82. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकास कोष के प्रशासन के लिए उपायों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम को अंत में विदेशी व्यापार और आर्थिक विकास के लिए विशेष कोष के लिए उपायों को जारी करने के संबंध में वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय का नोटिस जारी करके बदला गया था (2014 संशोधन) (काई सी (2014) सं. 36), जो अभी भी लागू है।

83. कार्यक्रम के तहत धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया गया है और उसके लाभ प्राप्तकर्ता को प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम में सब्सिडी भी निश्चित है क्योंकि यह केवल छोटे और मध्यम अवधि के उद्यमों (एस एम ई) के लिए ही उपलब्ध है।

84. चीन जन. गण. से किसी भी भागीदार उत्पादक/ निर्यातक ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने भी ऐसा कोई साध्य प्रदान नहीं किया है, जिससे कि यह पता चल सके कि चीन जन. गण. में टायर उत्पादकों ने कथित सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है। जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी ऐसा कोई साध्य प्राप्त नहीं कर सके जिससे यह पता चल सके कि चीन जन. गण. में टायर उत्पादक, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है, इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है।

85. अतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए।

(ix) कार्यक्रम सं. 9 : स्थानीय सरकारों द्वारा पाटनरोधी और/ अथवा प्रतिसंतुलनकारी कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति :

ख. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध :

86. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि यह योजना ऐसे कतिपय उद्यमों के लिए सीमित है, जो विदेशी पाटनरोधी कार्यवाही के अध्यधीन है। ऐसी कंपनियां पाटनरोधी कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए किए गए 40 प्रतिशत कानूनी शुल्क की वापसी के लिए पात्र होती हैं। कार्यक्रम की मौजूदगी के साध्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं, जो उन्हें तर्कसंगत रूप से उपलब्ध थे।

i. पाटनरोधी, सब्सिडी रोधी, सुरक्षोपाय जांच के लिए सहायक नीति के कार्यान्वयन के लिए नियम

यह भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम को अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा प्रतिसंतुलनकारी पाया गया है।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच :

87. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने केवल एक समाचार का अंश प्रदान किया है जो कि कानूनी आधार नहीं है। तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि झेजियांग प्रांत ने झेजियांग प्रांत के निर्यात उत्पादों के बारे में पाटनरोधी के उपाय जारी किए हैं (पीपल्स गवर्नमेंट, झेजियांग प्रांत का दिनांक 1 अप्रैल, 2014 का आदेश सं. 319) और यह पाया गया था कि अनुच्छेद 5.1 में यह उल्लेख किया गया है कि वित्तीय प्रशासनिक प्राधिकारी पाटनरोधी बचाव के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

88. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की पहले ही कुछ अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा की जा चुकी है और इस कार्यक्रम की मौजूदगी और प्रतिसंतुलनकारिता प्रमाणित हो चुकी है। उदाहरण के लिए आर्गेनिक कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स और कोटेड फाइन प्रेपर में यूरोपीय संघ में प्राधिकारियों द्वारा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच और संयुक्त राज्य प्राधिकारियों ने कार्बन और कतिपय अलॉय स्टील वायर रोड में प्रमाणित की गई है।

89. कार्यक्रम से धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया गया है और उससे प्राप्त लाभ प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम में सब्सिडी भी निश्चित है क्योंकि पाटनरोधी जांच के अध्यधीन यह उद्यम प्रासंगिक है।

90. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से कतिपय सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा शुल्क की गई पाटनरोधी जांच में भाग लेने के लिए कानूनी शुल्क की बजाय जांच की अवधि के दौरान स्वच्छ व्यापार धन के लिए कानूनी

शुल्क के नाम से लाभ प्राप्त हुए हैं। अतः कुछ निर्यातकों द्वारा स्वच्छ व्यापार के लिए कानूनी शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रतिसंतुलनकारी की गई है।

(x) कार्यक्रम सं. 10 : सुपरस्टार उद्यम अनुदान :

क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध :

91. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि यह योजना ऐसे कर्तिपय उद्यमों तक सीमित है, जो वर्ष के दौरान बिक्री कीमत से अधिक हो गए हैं। अनुदान के रूप में वित्तीय योगदान वार्षिक बिक्रियों के लक्ष्य की प्राप्ति पर स्थानीय सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं, जो उन्हें पहले से उपलब्ध थे।

- i. सुपरस्टार उद्यमों और उत्कृष्ट उद्यमों के मूल्यांकन और प्रोत्साहन के उपाय
- ii. सुपरस्टार उद्यमों, उत्कृष्ट उद्यमों और बैक बोन उद्यमों के लिए मानदंड की घोषणा के संबंध में हुजोहू सरकारी कार्यालय का नोटिस

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

92. यह कार्यक्रम हुजोहू शहर विशिष्ट है। हुजोहू शहर में कोई टायर उत्पादक नहीं है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

93. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिका में याचिकाकर्ता ने अन्य परिणामों को ही प्रदान किया है। याचिका में उल्लिखित योजना दस्तावेजों का कोई कानूनी पाठ संलग्न नहीं किया गया है। प्राधिकारी सुपरस्टार उद्यमों और उत्कृष्ट उद्यमों के मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए उपायों का अंश पहचानने और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर कार्यक्रम की मौजूदगी का मूल्यांकन करने में विफल रहे हैं।

94. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सुपर स्टार उद्यमों, उत्कृष्ट उद्यमों और बैक बोन उद्यमों के लिए मानदंडों की घोषणा के संबंध में हुजोहू सरकार के कार्यालय का नोटिस (हु झेंग वेन फा (2008) सं. 20) के स्थान पर औद्योगिक परिवर्तन और उन्नयन को आगे बढ़ावा देने के संबंध में हुजोहू शहर की पील्स गवर्नमेंट की राय जारी की (हु झेंग फा (2011) सं. 6)। हु झेंग फा (2011) सं. 6 को भी प्रशासनिक दस्तावेजों का निरसन करने के संबंध में हुजोहू शहर की पील्स गवर्नमेंट के नोटिस के तह हटा दिया गया था (हु झेंग फा (2014) सं. 14)। यह कार्यक्रम हुजोहू शहर में मौजूद था।

95. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हुजोहू शहर में कोई टायर उत्पादक नहीं था और फिर भी यदि इस कार्यक्रम के कारण सब्सिडी आकर्षित होती थी और यह विशिष्ट प्रकृति का कार्यक्रम था, चीन जन. गण. में कोई भी टायर उत्पादक इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सका। अतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xi) कार्यक्रम सं. 11 : निर्यात सहायता अनुदान :

ख. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध :

96. एस एम ई को निम्नलिखित के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है (i) देश से बाहर की प्रदर्शनियों का आयोजन करना अथवा भाग लेना, (ii) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए; (iii) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संवर्धन; (iv) नए बाजार की तलाश करना; (v) प्रशिक्षण सेमिनार और सिम्पोजियम का आयोजना करना, और (vi) विदेशी बोली, कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं।

- i. विदेशी व्यापार विभाग, वित्त (200) सं. 270

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

97. न तो चीन की सरकार ने और न ही किसी प्रतिवादी निर्यातक ने कथित कार्यक्रम के संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणी प्रदान नहीं की है तथापि, शांडोंग वांडा बोटो टायर कं. लिमि. और शांडोंग हाओहुआ टायर कं. लिमि. ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किए हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

98. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम छोटे तथा मध्यम आकार के उद्योगों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकास कोष के प्रशासन के लिए उपाय जारी करने के संबंध में परिपत्र सहयोग (परीक्षण कार्यान्वयन के लिए) (काई की (2000) सं. 467) और छोटे तथा मध्यम आकार के उद्यमों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकास कोष के लिए उपाय के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियमों (अनंतिम कार्यान्वयन के लिए) वाई जिंग माओ जी काई का (2001) सं. 270) के तहत शासित था। तथापि, दोनों विनियमों के स्थान पर छोटे तथा मध्यम आकार के उद्यमों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकास कोष के लिए प्रशासनिक उपाय जारी करने के संबंध में वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय का नोटिस (काई की (2010) सं. 87) दिनांक 24 मई, 2010 जारी किया गया तथा उसके बाद उसे बदलकर 2014 (संशोधन) काई की (2014) सं. 36 दिनांक 9 अप्रैल, 2014 जारी किया गया। अभी भी काई की (2014) सं. 36 को मौजूद पाया गया।

99. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की कुछ अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा पहले भी की जा चुकी है और इस कार्यक्रम की मौजूदगी और प्रतिसंतुलनकारिता यू.एस प्राधिकारियों द्वारा सर्कुलर बेल्डेड कार्बन क्वालिटी स्टील पाइप में तथा कतिपय सीमलेस कार्बन और अलाय स्टील स्टेंडर्ड, लाइन और प्रेशर पाइप में, तथा (2) कनेडियाई प्राधिकारियों द्वारा कतिपय मेटल बार ग्रेटिंग ऑफ कार्बन, अलाय अथवा स्टेनलेस स्टील में प्रमाणित की जा चुकी है।

100. शांडोंग वांडा बोटो टायर कं. लिमि. और शांडोंग हाओहुआ टायर कं. लिमि., चीन से दो प्रतिवादी निर्यातकों, जिन्होंने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किया है, ने यह कहा है कि उन्होंने इस लाभ को प्राप्त किया है तथा जांच की अवधि के दौरान उन्हें प्राप्त सब्सिडी की राशि के संबंध में सूचना प्रदान की है।

101. इसके अलावा, कंपनियों ने योजना के प्रचालन के संबंध में भी संगत सूचना और योजना के तहत लाभ तथा कानूनी आधार के संबंध में सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि शांडोंग प्रांत के वाणिज्य विभाग ने सौ प्रदर्शनियों को बाजार की तलाश योजना के संबंध में वार्षिक रूप से नोटिस जारी किया है, जिसमें शांडोंग प्रांत की सरकार ऐसी प्रदर्शनियों में उनकी भागीदारी की लागत को कम करने के लिए कंपनियों को अनुदान प्रदान करेगी।

102. कार्यक्रम में धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया गया है और उसके लाभ प्रदान किए गए हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह एस एम ई तक सीमित है। यह तथ्य कि शांडोंग वांडा बोये टायर कं. लिमि. को कार्यक्रम से लाभ हुआ है, यह दर्शाता है कि कार्यक्रम वास्तव में चीन में ऐसे टायर उत्पादकों द्वारा प्रयोग किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(xii) कार्यक्रम सं. 12 : अनुसंधान और विकास सहायता अनुदान :

क. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध :

103. याचिकाकर्ताओं ने यह कहा है कि यह अनुदान ऐसे उद्यमों तक सीमित है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान करते हैं और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा चुने जाते हैं। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं:

- विदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी टाइप उद्यमों के अधिग्रहण और विदेशी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास टीम को शेनयांग आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी रोजगार के लिए सहायता के उपाय का कार्यान्वयन
- वुकिंसग जिले के तीन प्रकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व्यय के संबंध में प्रबंधन उपाय जारी करने और प्रकाशन के संबंध में वुकिंसग जिल की पीपल्स गवर्नरमेंट के कार्यालय का नोटिस

- iii. वुक्सिंग जिले के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तीन टाइप के कोषों के उपयोग के प्रशासनिक उपायों के मुद्रण और वितरण के संबंध में वुक्सिंग जिले की पीपल्स गवर्नर्मेंट के कार्यालय का परिपत्र
- iv. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में बुक्सी नगरपालिका ब्यूरो
- v. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2007 के संबंध में पी आर सी के कानून का अनुच्छेद 9, 34, 35, 37.

तथापि, याचिकाकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि केवल हांगझोऊ झोंगकी रबड़ कं. लिमि., यिंग जिन्यून कमोडिटीज परचेज कं. लिमि. इस कार्यक्रम के लिए पात्र थे।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

104. चीन सरकार ने यह कहा है कि याचिकाकर्ता विदेशी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टाइप उद्यमों के अधिग्रहण और शेनयांग आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी विदेशी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास दल के रोजगार में सहायता के लिए उपायों का कार्यान्वयन करने के लिए कानूनी पाठ प्रदान करने में विफल रहे हैं। वुक्सिंग जिले की की जन. सरकार के कार्यालय के नोटिस वुक्सिंग जिला, हुझोऊ, झेजियांग प्रांत में स्थित कंपनियों के लिए ही लागू थे। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का कोई उत्पादक क्षेत्र में स्थित नहीं था।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

105. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय प्रगति के संबंध में चीन जनतांत्रिक गणराज्य के कानून के तहत विनियमित किया गया था और विनियम अभी वैध है।

106. वुक्सिंग जिले के तीन प्रकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकीय व्ययों के संबंध में प्रबंधन जिले की जन. सरकार के कार्यालय का नोटिस (वु झेंग वान फा (2005) सं. 78) को 2017 में प्रशासनिक नियमों और विनियमों के लिए समीक्षा परिणामों के प्रकाशन के संबंध में वुक्सिंग जिले की जन. सरकार के नोटिस (वु झेंग फा (2017) के माध्यम से दिनांक 22 सितंबर, 2017 को समाप्त कर किया गया था और सह प्रकार जांच की अवधि के दौरान मौजूद है।

107. याचिकाकर्ताओं ने विदेशी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टाइप उद्यमों के अधिग्रहण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास टीम को शेनयांग आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी रोजगार के लिए सहायता के कार्यान्वयन संबंधी उपाय का कानूनी पाठ प्रदान नहीं किया।

108. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा पहले भी की जा चुकी है। उदाहरण के लिए, इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता कतिपय स्टेनलेस स्टील सिंक और कतिपय एल्यूमिनियम एक्स्ट्रसन में कनेडियन प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित की गई है।

109. कार्यक्रम में वुक्सिंग जिले द्वारा धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के द्वारा ऐसे उद्यमों को वित्तीय योगदान का प्रावधान है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान करते हैं। तथापि, वुक्सिंग जिले में कोई टायर निर्माता नहीं है और इसीलिए प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि चीन में टायर निर्माता, जिन्होंने भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है, को इस कार्यक्रम से लाभ हुआ होगा। अतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xiii) कार्यक्रम सं. 13 : हेफेई आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकास जोन में स्थित कंपनियों के लिए सब्सिडी :

क. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध :

110. हेफेई सरकार ने नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा नए उन्नयन के लिए समान धनराशि, सरकारी शुल्कों से छूट, अनुदान और छूट, क्रृष्ण व्याज कटौती तथा अधिमान्य वेट और नियर्ताओं के लिए आय कर छूट की सहायता के लिए धनराशि प्रदान की है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में प्रदान की है।

111. यह कार्यक्रम कतिपय निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उत्पादकों के लिए ही पात्र था। यह दर्शाया गया है कि गीति रेडियल टायर (अनुहृदई) कं. लिमि. जैसे उत्पादकों ने इस कार्यक्रम से लाभ उठाया है।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

112. चीन सरकार ने यह बताया है कि केवल एक ही टायर निर्माता था जो निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित था। तथापि, वार्षिक रिपोर्ट कानूनी आधार के रूप में नहीं है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

113. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने केवल के पी एम जी द्वारा सूचित 'हेफेई आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्र निवेश वातावरण अध्ययन 2008' और 'हेफेई आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्र की देव शुरुआत' उपलब्ध कराए हैं। दोनों की दस्तावेज कार्यक्रम के लिए कानूनी आधार नहीं थे।

114. तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कथित कार्यक्रम में धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया है और इसके लाभ प्राप्तकर्ता को प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम में सब्सिडी भी निश्चित है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष उन्नयन में लगे किंतु उद्यमों के लिए निश्चित है।

115. एक टायर निर्माता गीति रेडियल टायर (अनहुई) कं. लिमि. हेफेई आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास जोन में स्थित था। गीति रेडियल टायर (अनहुई) कं. लिमि. ने जांच में भाग नहीं लिया है अथवा प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। गीति रेडियल टायर (अनहुई) कं. लिमि. इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र था और प्राधिकारी यह अन्दाजा नहीं लगा सकते कि गीति टायर (अनहुई) कं. लिमि. ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। अतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(xiv) कार्यक्रम सं. 14 : विदेशी निवेश वाले उद्यमों के लिए अनहुई प्रांत सब्सिडी :

क. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध :

116. याचिकाकर्ता का यह दावा है कि अनहुई प्रांत में स्थित एफ आई ई किंतु प्रय छूटों और वेट कटौतियों के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं, जो उन्हें तर्कसंगत रूप से उपलब्ध थे।

i. विदेशी निवेश वाले उद्यमों के लिए अनहुई प्रांत की अधिमान्य कर नीतियां (13 मई, 2011)

ii. "अनहुई प्रांत के विकास जोनों में विदेशी वित्त पोषण वाले उद्यमों के लिए अधिमान्य व्यवहार" (13 मई, 2011)

याचिकाकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पादक जैसे गीति रेडियल टायर (अनहुई) कं., लिमि. ने इस कार्यक्रम में लाभ प्राप्त किया होगा।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

117. चीन सरकार ने यह कहा है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में केवल एक ही एफ आई ई टायर निर्माता स्थित था।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

118. याचिका में याचिकाकर्ताओं ने केवल अनहुई प्रांत में विदेशी निवेश वाले उद्यमों के लिए अधिमान्य नीतियों की देव न्यूज उपलब्ध कराई है। तथापि, कार्यक्रम की मौजूदगी के लिए दोनों ही दस्तावेजों का कानूनी आधार नहीं है। प्राधिकारी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को शासित करने संबंधी योजना दस्तावेज की पहचान करने में असमर्थ था।

119. गीति टायर (अनहुई) कं. लिमि. एक एफ आई ई है और अनहुई प्रांत में स्थित था। गीति टायर (अनहुई) कं. लिमि. अनहुई प्रांत में स्थित है और जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है और इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र था।

120. गीति टायर (अनहुई) कं. लिमि. ने भाग नहीं लिया है अथवा प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है और इसीलिए प्राधिकारी यह अन्दाजा नहीं लगा सकते कि गीति टायर (अनहुई) कं. लिमि. को इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

121. अतः प्राधिकारी यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(xv) कार्यक्रम सं. 15 : हेफेई म्युनिसिपल निर्यात संबंधी नीतियां :

क. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध :

122. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि यदि कंपनी एक निश्चित राशि से अधिक का निर्यात और आयात करती है तो उस कंपनी की ट्रेड वैल्यू के 1 प्रतिशत अथवा 1.5 प्रतिशत के समान अनुदान हेफेई की नगरपालिका को प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं, जो उन्हें तर्कसंगत रूप से उपलब्ध थे।

- i. हेफेई ने विदेशी व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतियां शुरू की थी (23 मई, 2012)
- ii. विदेशी व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतियां जारी करने के संबंध में हेफेई जनतांत्रित सरकार को नोटिस (30 सितंबर, 2013)

याचिकाकर्ता का यह भी उल्लेख किया है कि गीति टायर (अनहुई) कं. लिमि. जैसे उत्पादकों ने इस कार्यक्रम से लाभ अवश्य प्राप्त किया होगा।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

123. चीन सरकार ने यह कहा है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में केवल एक ही एफ आई ई टायर निर्माता था।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

124. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने विदेशी व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतियां जारी करने के संबंध में हेफेई जनतांत्रिक सरकार को नोटिस प्रदान किया है हे झेंग मी (2013) सं. 115), जिसमें स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख किया गया था कि जब भी उद्यम 50 मिलियन डालर से अधिक का आयात और निर्यात करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा और धीरे धीरे विकास प्राप्त कर लेगा तो उसके कुल आयात और निर्यात व्यापार मूल्य का 1 प्रतिशत पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाएगा।

125. इस दावे के संबंध में कि हेफेई ने विदेशी व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतियां शुरू की हैं (23 मई, 2012), प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिका में इन नीतियों को किसी का भी कानूनी पाठ प्रदान नहीं किया गया है। प्राधिकारी को यह भी पता चला है कि हेफेई जनतांत्रिक सरकार के कार्यालय ने नोटिस जारी किया था (हे झेंग बान (2012) सं. 25) लेकिन इसे दिनांक 8 अप्रैल, 2014 को प्रशासनिक दस्तावेज के निरसन संबंधी निर्णय के तहत निरस्त किया गया था (हे फेंग (2014) सं. 46)।

126. गीति टायर (अनहुई) कं. लिमि. एक एफ आई ई है और यह हेफेई शहर में स्थित थी। गीति टायर (अनहुई) कं. लिमि. हेफेई शहर में है और उसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है और इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।

127. गीति टायर (अनहुई) कं. लिमि. ने भाग नहीं लिया है अथवा प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है और इसीलिए प्राधिकारी यह अन्दाजा नहीं लगा सकते कि गीति टायर (अनहुई) कं. लिमि. ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ नहीं लिया था।

128. अतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(xvi) कार्यक्रम सं. 16 : कुन्शान आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास जोन में स्थित कंपनियों के लि सब्सिडी :

क. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध :

129. स्थानीय आय कर से छूट, निर्यात उन्मुखी उद्यमों के लिए आय कर में आधी छूट कम आय कर दरों जैसी छूट के विभिन्न लाभ कुन्शान आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास जोन में स्थित एफ आई ई के लिए उपलब्ध है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं:

- i. कराधान के राज्य प्रशासन के कुन्शान नगरपालिका कार्यालय “विदेशी निवेश वाले उद्यमों के लिए कर लाभों की शुरुआत”

ii. पुरने आय कर कानून के तहत विदेशी निवेश वाले उद्यमों के लिए अधिमान्य नीतियां

याचिकाकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि केन्द्र रबड़ (चीन) कं. लिमि. जैसे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को इस कार्यक्रम के तहत अवश्य लाभ मिला होगा।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

130. चीन सरकार ने यह सूचित किया है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में कोई टायर एफ आई ई निर्माता स्थित नहीं था।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

131. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित दस्तावेजों का कानूनी अधिकार नहीं था। याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि पुराने आय कर कानून के तहत सब्सिडी कार्यक्रम मौजूद था। इस संबंध में, प्राधिकारी 2008 में चीन जन. गण. में हुए कर सुधारों के विवरण नोट करते हैं। वर्ष 2008 से पूर्व चीन जन. गण. ने उद्यम आय कर के संबंध चीन जन. गण. के अनंतिम विनियमों का कार्यान्वयन किया था, जो कि चीन जन. गण. के भीतर विदेशी निवेश वाले उद्यमों ("एफ आई एफ") के अलावा अन्य सभी उद्यमों के लिए उपलब्ध थे। चीन जन. गण. में विदेशी निवेश वाले उद्यमों और विदेशी उद्यमों के लिए पी आर सी के आयकर कानून का अलग से कार्यान्वयन किया है, जिसमें एफ आई ई के लिए अनेक अधिमान्य कर नीतियां लागू थीं। दिनांक 16, 2007 को चीन सरकार ने पी आर सी का उद्यम आयकर कानून ("एफ आई टी एल") जारी किया है, जो कि एफ आई ई सहित चीन जन. गण. में सभी उद्यमों पर लागू है। यह कानून 1 जनवरी, 2008 से कार्यान्वित किया गया था। नए कर कानून में दो प्रमुख बदलाव किए गए थे – (1) एफ आई ई के लिए अधिमान्य आयकर नीतियां समाप्त कर दी गई हैं और एक एकीकृत कर दर घरेलू उद्यमों और एफ आई ई के लिए लागू की गई है; (2) स्थानीय विशेष आर्थिक जोनों के लिए अधिमान्य आय कर नीतियां समाप्त कर दी गई हैं। इसके अलावा, स्टेट काउंसिल ने यह विनिर्दिष्ट करते हुए उद्यम आय कर के संबंध में संक्रमणकालीन अधिमान्य नीतियों का कार्यान्वयन करने के संबंध में नोटिस जारी किए थे कि दिनांक 1 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार ऐसे उद्यमों, जिन्होंने कम कर दरों की अधिमान्य नीतियों का पहले लाभ उठाया है, उन्हें ई आई टी एल के कार्यान्वयन के बाद 5 वर्षों के भीतर धीरे-धीरे सांविधिक कर दर का लाभ उठाने के लिए बदलाव किया है। अतः ऐसे ही उद्यम, जिन्होंने पुराने आय कर कानून के तहत अधिमान्य कर नीतियों का लाभ लिया है, वे 2012 के अंत से उसका आगे लाभ नहीं ले पाएंगे।

133. याचिका में संलग्न दस्तावेज में ही यह उल्लेख किया गया है कि नए उद्यम आय कर कानून में 1 जनवरी, 2008 से पांच वर्ष की संक्रमणकालीन अवधि प्रदान की है। यह संक्रमण की अवधि जांच की अवधि अर्थात् 1 जनवरी, 2013 से पूर्व समाप्त हो गई थी। इसके अलावा, यह पाया गया कि कुंशान आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास जोन में स्थित विचाराधीन उत्पाद का कोई भी उत्पादक नहीं था।

133. चीन जन. गण. में किसी भी टायर निर्माण को कथित सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं हो सका है क्योंकि यह लागू नहीं था।

134. अतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए

(xvii) कार्यक्रम सं. 17 : ऑटोमोबाइल टायर उद्योगों के लिए वेहाई नगरपालिका सब्सिडी :

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुरोध :

135. वेहाई नगरपालिका प्राधिकारण क्रृष्ण सहायता, अधिमान्य नीति के लाभ उठाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट के रूप में परियोजनाओं के विस्तार के लिए धनराशि प्रदान की है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं:

i. वेहाई आर्थिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति, "ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल्स पुर्जे उद्योग के लिए वेहाई नगरपालिका 12वीं पंच वर्षीय विकास योजना" (3 अप्रैल, 2013)

ii. वेहाई वित्तीय ब्यूरो, "स्वावलंबी नवोन्मेष विशिष्टता कोष का शांडोंग प्रांत प्रतिस्पर्धी आवंटन योजना" (6 अगस्त, 2012)

यह दावा किया गया है कि कुपो चेंगशान (शांडोंग) टायर कं. लिमि. और ट्राइएंगल टायर कं. लिमि. जैसे उत्पादकों ने इस कार्यक्रम से आवश्यक लाभ मिला होगा।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

136. चीन सरकार ने यह कहा है कि वर्ष 2011-2015 तक की 12वीं पंचवर्षीय योजना और यह कि जब से कार्यक्रम समाप्त हुआ है, यह कार्यक्रम 2015 से वैध नहीं था।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

137. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शांडोंग प्रांत ने स्वतंत्र नवोन्मेष के लिए प्रतिस्पर्धी विशेष धन वितरण के संबंध में प्रांतीय सरकार के सामान्य कार्यालय की सूचना के माध्यम से रबड टायर उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए अनुदोनों, क्रह ब्याज सब्सिड्यों, इक्रीटी निवेश, प्रोत्साहनों और अन्य माध्यमों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की। (लु झेंग बान फा [2012] सं. 49)। इस वित्तीय अनुदोनों के प्राप्तकर्ता के संबंध में लाभ प्राप्त किए गए हैं। तथापि, जांच की अवधि के प्रारंभ से पूर्व लाभ की अवधि समाप्त हो गई है। कार्यक्रम समाप्त भी हो चुका है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उपरोक्त कार्यक्रम अनुदान पूँजीगत परिसंपत्तियों से संबद्ध नहीं थे और आवृत्ति प्रकृति के थे।

138. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि कुछ दस्तावेज उपरोक्त कार्यक्रम के लिए संगत नहीं थे, लेकिन अन्य दस्तावेज अब आगे लागू नहीं थे। इस प्रकार, चीन जन. गण. में ऐसे कोई भी टायर उत्पादक, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया था, उन्होंने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के तहत अवश्य लाभ प्राप्त किया होगा।

139. अतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xviii) कार्यक्रम सं. 18 : रोंगचेंग आर्थिक विकास जोन में स्थित कंपनियों के लिए सब्सिडी :

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुरोध :

140. रोंगचेंग नगरपालिका सरकार ने रोंगचेंग ई डी जेड में स्थित सी सी टी कंपनियों को सहायता प्रदान करने के लिए धनराशि प्रदान की है। कार्यक्रम के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाओं अथवा योजना दस्तावेजों को प्रदान किया है :

i. रोंगचेंग नगरपालिका जनतंत्र सरकार द्वारा रूपांतरण और विकास के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के संबंध में क्रियान्वयन नियम (28 फरवरी, 2012)

यह दावा किया गया है कि कुपो चेंगशान (शांडोंग) टायर कं. लिमि. और रोंगचेंग युक ट्रेडिंग कं. लिमि. जैसे टायर उत्पादकों ने इस कार्यक्रम से अवश्य लाभ उठाया होगा।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

141. चीन सरकार ने यह कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने कानूनी आधार तो प्रदान किए लेकिन गलत कानूनी पाठ संलग्न किया। चीन सरकार ने यह कहा कि यह कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

142. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम रोंगचेंग शहर की सरकार द्वारा उद्यमों के प्रोत्साहन और रूपांतरण के संबंध में विनियमों के तहत शासित होता था (रोंग झेंग फा (2012) सं. 7)। लेकिन इसे नगरपालिका सरकार के विनियामक दस्तावेजों के स्पष्ट परिणामों के प्रकाशन के संबंध में रोंगचेंग शहर की जन सरकार के नोटिस के तहत समाप्त कर दिया गया था (रोंग झेंग फा (2016) सं. 16)।

143. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संगत दस्तावेज जांच की अवधि के दौरान अब लागू नहीं था। चीन जन. गण. में ऐसा कोई भी टायर उत्पादक, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया था, कथित सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सका है क्योंकि यह लागू नहीं था।

144. इसलिए, प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xix) कार्यक्रम सं. 19 : गुआंगडोंग और झेजियांग प्रांतों में स्थित उद्यमों के लिए निर्यात व्याज सब्सिडी :

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुरोध :

145. गुआंगडोंग प्रांत और झेजियांग प्रांत में स्थित निर्यातकों को धनराशि प्रदान नहीं की गई थी। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के लिए याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए गए हैं:

- चीन जनतांत्रिक गणराज्य के विकास के संबंध में प्रोटोकोल की धारा 18 के अनुसरण में संक्रमणकालीन समीक्षा तंत्र, सब्सिडी प्रक्रियाओं पर चीन के संक्रमणकालीन समीक्षा तंत्र के संबंध में चीन के यूरोपीय समुदायों से प्रश्न, जी/एससीएम/ सीएचएन/ 24, 2, (20 अक्टूबर, 2006)
- शेनज़ेन उद्यमों के टी डी सी ट्रेड के लिए निर्यात व्याज सब्सिडी (1 मई, 2004)

146. यह पाया गया है कि झोंगसी, गुआंगझो पर्ल रीवर रबड़ टायर लिमि., केन्डा टायर (शेन्डोन) कं. लिमि. तथा साउथ चाइना टायर एंड रबड़ जैसे उत्पादकों ने इस कार्यक्रम से अवश्य लाभ लिया होगा।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

147. चीन सरकार ने यह कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने दो कानूनी आधार प्रदान किए हैं लेकिन कार्यक्रम की मौजूदगी के संबंध में दोनों ही कानूनी आधार नहीं हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

148. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने यह दर्शने के लिए केवल ऐसे साक्ष्य प्रदान किए हैं कि झेजियांग प्रांत और शेन्ज़ेन में निर्यातकों को 2014 में निर्यात व्याज सब्सिडी का लाभ अवश्य मिला होगा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डब्ल्यू टी ओ में यूरोपीय संघ से लेकर चीन जन. गण. तक शामिल होने का प्रश्न कानूनी आधार नहीं है और यह इस कार्यक्रम की मौजूदगी को प्रमाणित नहीं करता। चीन जनतांत्रिक गणराज्य के विकास के संबंध में प्रोटोकोल की धारा 18 के अनुसरण में संक्रमणकालीन समीक्षा तंत्र समाप्त हो चुका है।

149. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. में किसी भी टायर उत्पादक, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, ने कथित कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है क्योंकि यह लागू नहीं था। अतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xx) कार्यक्रम सं. 20 : गुआंगडोंग प्रांत में उद्यमों के 'बाह्य विस्तार' के लिए धनराशि :

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुरोध :

150. उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तलाश, निर्यात ऋण बीमा सहायता, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापार के विकास, निर्यात उत्पाद अनुसंधान एवं विकास, पाटनरोधी शुल्क के मामले में बचाव संबंधी व्ययों के लिए सहायता, विभिन्न निर्यात संबंधी ऋणों के लिए व्याज अनुदान और बाह्य उद्यमों के विकास के लिए धनराशि प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि सब्सिडी क्षेत्र से संबद्ध है और निर्यात निष्पादन के संबंध में प्रासंगिक है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं:

- बाह्य-उन्मुखी निजी उद्यमों के विकास में सहायता के संबंध में गुआंगडोंग प्रांत के उपायों का कार्यान्वयन (युए बान फा (2003) सं. 17)
- गुआंगडोंग की सहायता से निजी उद्यम आउटवार्ड, टी डी सी ट्रेड, 1 मार्च, 2014)

तथापि, याचिकाकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि केवल गुआंगडोंग पर्ल रीवर रवड़ टायर कं. लिमि., केन्डा टायर (शानडोन) कं. लिमि. साउथ चीन टायर एंड रबड़ ही इस कार्यक्रम के तहत पात्र थे।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

151. चीन सरकार ने यह कहा है कि विनियम युए बान फा (2003) सं. 17 वैध है लेकिन यह केवल गुआंगडोंग प्रांत के लिए ही लागू था। इसके अलावा, गुआंगडोंग प्रांत में स्थित विचाराधीन उत्पाद का केवल एक ही उत्पादक था। इसके अलावा, दूसरा दस्तावेज 'गुआंगडोंग की सहायता से निजी उद्यम आउटवार्ड' का कोई वैध कानूनी आधार नहीं है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

152. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि युए बान फा (2003) सं. 17 वैध था। इस विनियम के अनुसरण में, गुआंगडोंग ने कार्यक्रम के माध्यम से कंपनियों को अनुदान प्रदान किया है।

153. कार्यक्रम में धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया गया है और उससे प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किए गए हैं। सब्सिडी भी निश्चित है क्योंकि यह निर्यात निष्पादन के संबंध में प्रासंगिक है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा पहले भी की जा चुकी है, जिससे सब्सिडी के रूप में इसकी मौजूदगी प्रमाणित की गई है। उदाहरण के लिए इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता लाइट वेट थर्मल ऐपर में यू एस प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित भी गई है।

154. ऐसे टायर उत्पादकों, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात किया है, में से गुआंगझोऊ पर्ल रीवर इस स्थान में स्थित है। गुआंगझोऊ पर्ल रीवर इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र थी। गुआंगझोऊ पर्ल रीवर से किसी भी सूचना अथवा भागीदारी के अभाव में, प्राधिकारी यह अनुमान नहीं लगा सकते कि गुआंगझोऊ पर्ल रीवर को इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

155. अतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(xxi) कार्यक्रम सं. 21 : एयोलस के लिए प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान :

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुरोध :

156. याचिकाकर्ता का यह दावा है कि चीन सरकार द्वारा टायर उद्योग को निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न अनुदान प्रदान किए जाते हैं। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं:

i. एयोलस की वार्षिक रिपोर्ट

याचिकाकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि यह कार्यक्रम केवल एयोलस के लिए पात्र था।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

157. चीन सरकार ने यह कहा है कि कोई वार्षिक रिपोर्ट कानूनी आधार के रूप में नहीं हो सकती। प्राधिकारी एयोलस टायर कं. लिमि. द्वारा दाखिल किए गए निर्यात प्रश्नावली उत्तर से सत्यापित कर सकते हैं कि क्या इसे चीन सरकार से ऐसी सब्सिडी प्राप्त हुई है अथवा नहीं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

158. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने एक न्यूज रिपोर्ट प्रदान की है, जो कार्यक्रम की मौजूदगी को प्रभावित करने का कानूनी आधार नहीं है।

159. प्राधिकारी ने एयोलस द्वारा प्राप्त किए गए सभी सरकारी अनुदानों की मौजूदगी की पुष्टि की है और यह पाया गया था कि सूचित किए गए सभी डाटा का उसकी वार्षिक रिपोर्ट और उसके लेखा परीक्षित लेखों से मिलान किया गया था। एयोलस द्वारा प्राप्त किए गए अनुदानों के लिए सब्सिडी मार्जिन का प्रश्नावली उत्तर में प्रदान की गई सूचना के आधार पर अलग से निर्धारण किया गया है। चीन द्वारा एयोलस को प्रत्यक्ष अनुदानों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है।

160. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. में ऐसे कोई अन्य टायर उत्पादक नहीं हैं, जिन्होंने भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है और कथित कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त हो सका है, जो एयोलस के लिए ही उपलब्ध होने का उल्लेख किया गया है।

161. अतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xxii) कार्यक्रम सं. 22 से 26 : डबल कॉइन, गीति, गुईज़ोऊ टायर, किंगदाओ डबल स्टार, सैलून ग्रुप को प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान :

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुरोध :

162. याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि वार्षिक रिपोर्ट में विभिन्न अनुदानों का उल्लेख किया गया था जैसे विशिष्ट टायर उत्पादकों को नवोन्मेष और उद्योग उन्नयन विशेष मार्गदर्शी धनराशि कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं :

- i. डबल कॉइन होल्डिंग्स की वार्षिक रिपोर्ट 2013
- ii. गीति की वार्षिक रिपोर्ट 2016
- iii. गुईज़ोऊ टायर की वार्षिक रिपोर्ट
- iv. किंगदाओ डबल स्टार की वार्षिक रिपोर्ट
- v. सैलून ग्रुप की वार्षिक रिपोर्ट

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

163. चीन सरकार ने कह कहा है कि वार्षिक रिपोर्ट को कानूनी आधार के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने केवल डबल क्वाइन होल्डिंग्स तथा गीति की वर्ष 2013 की वार्षिक रिपोर्ट प्रदान की है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

164. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त कार्यक्रमों के संबंध में कोई कानूनी आधार प्रदान नहीं किया है। इसके अलावा, दो कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट के रूप में प्रदान किए गए साक्ष्य वर्ष 2013 के लिए हैं और इसीलिए यह तय करने के लिए यह संगत आधार नहीं है कि जांच की अवधि के दौरान इन टायर उत्पादकों द्वारा अनुदान प्राप्त किए गए थे।

165. बहरहाल, प्राधिकारी सभी सूचनाओं की समीक्षा करने के बाद यह नोट करते हैं कि 'प्रत्यक्ष अनुदानों' के नाम से कोई भी सबिसडी कार्यक्रम मौजूद नहीं था।

166. अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

I. क चीन जन. गण. से भागीदार उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा प्राप्त अनुदान कार्यक्रम :

167. चीन जन. गण. से टायर उत्पादकों के छ: समूहों ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं। इनमें से 5 समूहों ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है। मैसर्स शांडोंग हाओहुआ टायर कं. लिमि., मैसर्स गुआंगज़ोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कं. लिमि. और मैसर्स एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लिमि. ने भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। व्यक्तिगत सबिसडी मार्जिन को ऐसे टायर उत्पादकों के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिन्होंने भारत को जांच की अवधि के दौरान उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि अलग से प्रतिसंतुलनकारी शुल्क दर चीन जन. गण. के इन उत्पादकों के लिए निर्धारित नहीं की जा सकती।

(i) झोग्सी रबड़ ग्रुप कं. लिमि. :

168. झोग्सी रबड़ ग्रुप कं. लिमि. (झोग्सी रबड़) ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है और उनके द्वारा प्राप्त अनुदान कार्यक्रमों के संबंध में सूचना प्रदान की गई है।

169. झोंगसी के पास संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में शामिल तीन फैक्ट्रियां हैं। ये तीन फैक्ट्रियां नामतः (i) झोंगसी रबड़ (जियांडे) कं. लिमि., (ii) झोंगसी चाओयांग रबड़ कं. लिमि., (iii) झोंगसी रबड़ (फुयांग) कं. लिमि. झोंगसी रबड़ के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं। झोंगसी रबड़ ने इन सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त अनुदान कार्यक्रम के बारे में भी सूचना प्रदान की है।

170. प्राधिकारी ने झोंगसी रबड़ कं. ग्रुप लिमि. द्वारा प्रदान की गई सूचना की पुष्टि की है और ऐसे अनुदान कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है, जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किया गया था अथवा अर्जित किया गया था। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि सभी अनुदान कार्यक्रमों में धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है। परिणामस्वरूप झोंगसी रबड़ को इस अनुदान के प्राप्तकर्ता के रूप में लाभ प्रदान किया गया था। सब्सिडी कार्यक्रम भी निश्चित थे क्योंकि वे झोंगसी रबड़ सहित कुछ उद्यमों तक ही सीमित थे।

171. नीचे लिखी सारणी में अनुदान कार्यक्रमों के नाम और तदनुरूपी सब्सिडी मार्जिन के लिए प्रावधान हैं:

अनुदान कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण/ टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
2014 हांगझोऊ आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र (एच ई डी ए) में विदेशी आर्थिक और व्यापार विकास के संवर्धन के लिए विशेष कोष	निम्नलिखित पांच प्रमुख परियोजनाओं के लिए सहायता : (1) प्रदर्शनी सब्सिडी; (2) निर्यात ब्रांड नाम; (3) निर्यात ऋण बीमा; (4) आयात उन्नत उपकरण; (5) पाटनरोधी जांच में भागीदारी (6) सेवा आउटसोर्स उद्योग संबंधी क्रियाकलाप (7) विदेशी व्यापार प्रचालन सर्वे निगरानी विंदुओं की स्थापना	****	0 - 1%
2013 एच ई डी ए में स्थित उद्यमों के लिए निर्यात ऋण बीमा छूट	विगत वर्षों में कंपनी द्वारा किए गए निर्यात ऋण बीमा लागत की प्रतिपूर्ति	****	0 - 1%
2016 विदेशी आर्थिक और व्यापार विकास (एच ई डी ए) के लिए विशेष	विदेशी क्षेत्र में उद्यमों के निवेश के लिए सहायता झोंगसी को थाइलैंड में अपने निवेश के लिए अनुदान प्राप्त किया गया।	****	0 - 1%
कोयला आधारित बायलर स्वच्छ नवोन्मेष प्रथम चरण विशेष अनुदान (एच ई डी ए)	डस्ट, सल्फर डाई-आक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयोजन से थर्मो-इलैक्ट्रिक कोयला आधारित बॉयलर और औद्योगिक कोयला आधारित बॉयलर	****	0 - 1%
2016 वायु प्रदूषण संरक्षण विशेष अनुदान	पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयोजन से थर्मो-इलैक्ट्रिक कोयला आधारित बॉयलर और औद्योगिक कोयला आधारित बॉयलर	****	0 - 1%
2016 हांगझोऊ प्रदूषण स्रोत निगरानी उपकरण निधि (प्रथम बैच)	पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयोजन से थर्मो-इलैक्ट्रिक कोयला आधारित बॉयलर और औद्योगिक कोयला आधारित बॉयलर	****	0 - 1 %
2016 हांगझोऊ प्रदूषण स्रोत	पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयोजन से थर्मो-इलैक्ट्रिक कोयला आधारित बॉयलर और औद्योगिक कोयला आधारित बॉयलर	****	0 - 1%

निगरानी उपकरण निधि (प्रथम बैच)	औद्योगिक कोयला आधारित बॉयलर		
2014 झेजियांग प्रांत और हांगझोऊ शहर "निर्यात प्रसिद्ध ब्रांड" पुरस्कार	कार्यक्रम में ऐसे उद्यमों के लिए प्रावधान हैं, जिनके उत्पाद ब्रांड सी पहचान "हांगझोऊ निर्यात प्रसिद्ध ब्रांड" अथवा "झेजियांग निर्यात प्रसिद्ध ब्रांड" के रूप में की गई है।	****	0 - 1 %
हांगझोऊ शहर के रोजगार स्थिरीकरण के लिए अनुदान	ऐसे उद्यमों के लिए रोजगार स्थिरीकरण सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो छंटनी को कम करने और रोजगार को स्थिर रखने के लिए प्रभावी उपायों को अपनाते हैं।	****	0 - 1 %
2016 हांगझोऊ इंटरनेट ऑफ थिम्स और इंडस्ट्रियल इंटरनेट पायलट प्रोजेक्ट कंफिंग	वस्तुओं के उत्पादन और प्रवंधन के इंटरनेट के संबंध में उद्यम परीक्षण परियोजनाओं की सहायता	****	0 - 1 %
वित्तीय सब्सिडी (एच ई डी ए)	सामान्य वित्तीय सहायता	****	0 - 1 %
2015 एच ई डी ए में स्थित उद्यमों के लिए आर डी निवेश वित्तपोषण	आर एंड डी प्रयोजनों के लिए	****	0 - 1 %
2016 प्रौद्योगिकी मानक वित्तपोषण (एच ई डी ए)	प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए	****	0 - 1 %
2013 आयात और निर्यात व्यापार उचित वित्तपोषण	विपणन सहायता के लिए	****	0 - 1 %
पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधानकर्ता वित्तपोषण	आर एंड डी प्रयोजनों के लिए	****	0 - 1 %
पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधानकर्ता एक बारगी आर एंड डी वित्तपोषण	आर एंड डी प्रयोजनों के लिए	****	0 - 1 %
सरकारी सब्सिडी आस्थगित आय का गैर-प्रचालन आय में अंतरण	परिसंपत्तियों के लिए अधिग्रहण के लिए	****	0 - 1 %
पुनर्स्थापन मुआवजा	पुनर्स्थापन मुआवजा	****	0 - 1 %
जियान्डे			
2016 हांगझोऊ प्रदूषण स्रोत निगरानी उपकरण कोष (प्रथम बैच और द्वितीय बैच)	पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयोजन के लिए थर्मो इलैक्ट्रिक कोयला आधारित बॉयलर का सुधार करने के लिए	****	0 - 1 %
2016 प्रदूषण स्रोत निगरानी उपरांत कोष (प्रथम बैच)	पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयोजन के लिए थर्मो इलैक्ट्रिक कोयला आधारित बॉयलर का सुधार करने के लिए	****	0 - 1 %
2015 "115" निवेश सब्सिडी का	निवेश प्रारंभ करने के लिए कंपनी को पुरस्कृत	****	0 - 1 %

प्रारंभ	करना		
चायोयांग			
2016 हांगझोऊ प्रांत उन्नत औद्योगिक नवीन उत्पाद (प्रौद्योगिकी) सूची – आल स्टील इंडस्ट्रियल रेडियल टायर्स	नवीन औद्योगिक प्रौद्योगिकी और उत्पादन को प्रोत्साहन	****	0 - 1 %
2016 ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ट्रांजेक्शन अचीवमेंट कन्वर्सन प्रोजेक्ट को हांगझोऊ सब्सिडी (द्वितीय वैच)	टेक्नोलॉजी ट्रांजेक्शन अचीवमेंट कन्वर्सन को प्रोत्साहन	****	0 - 1 %
2016 ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ट्रांजेक्शन अचीवमेंट कन्वर्सन प्रोजेक्ट को हांगझोऊ सब्सिडी (द्वितीय वैच)	टेक्नोलॉजी ट्रांजेक्शन अचीवमेंट कन्वर्सन को प्रोत्साहन	****	0 - 1 %
2015 हांगझोऊ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट पायलेट प्रोजेक्ट फंडिंग – आल स्टील ऑफ रोड रेडियल टायर क्राफ्ट	वस्तुओं के उत्पादन और प्रबंधन के लिए इंटरनेट के संबंध में उद्यम परीक्षण परियोजनाओं के लिए सहायता	****	0 - 1 %
2015 हांगझोऊ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट पायलेट प्रोजेक्ट फंडिंग	वस्तुओं के उत्पादन और प्रबंधन के लिए इंटरनेट के संबंध में उद्यम परीक्षण परियोजनाओं के लिए सहायता	****	0 - 1 %
2015 एच ई डी ए में स्थित उद्यमों के लिए आर डी निवेश	आर एंड डी प्रयोजनों के लिए	****	0 - 1 %
2016 प्रांतीय और शहरी उद्योग तथा सूचना विकास वित्तीय विशेष कोष क्षेत्र केंद्रीय एयरकंडीशनर टेक्नोलॉजी नवोन्मेष का मिश्रण	वस्तुओं के उत्पादन और प्रबंधन के लिए इंटरनेट के संबंध में उद्यम परीक्षण परियोजनाओं के लिए सहायता	****	0 - 1 %
2016 प्रांतीय और शहरी उद्योग तथा सूचना विकास वित्तीय विशेष कोष चायोयांग आल स्टील रेडियल टायर इंडस्ट्रियल डिजाइन	वस्तुओं के उत्पादन और प्रबंधन के लिए इंटरनेट के संबंध में उद्यम परीक्षण परियोजनाओं के लिए सहायता	****	0 - 1 %
2015 हांगझोऊ विकास जोन ग्रेजुएट प्रशिक्षण एवं रोजगार अनुदान	ग्रेजुएट व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कराना	****	0 - 1 %
2016 हांगझोऊ प्रदूषण स्रोत निगरानी उपकरण कोष (प्रथम वैच)	पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयोजन से थर्मो इलैक्ट्रिकल कोयला आधारित बॉयलरों का सुधार	****	0 - 1 %
2016 हांगझोऊ प्रदूषण स्रोत निगरानी उपकरण कोष (द्वितीय वैच)	पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयोजन से थर्मो इलैक्ट्रिकल कोयला आधारित बॉयलरों का सुधार	****	0 - 1 %
“मायोरल कप” के लिए	बौद्धिक संपदा उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहन	****	0 - 1 %
2015 हांगझोऊ शहरी परिस्थितिकी सम्भारा प्रदर्शन परियोजना सब्सिडी	शहरी परिस्थितिकी वातावरण में सुधार	****	0 - 1 %

हांगझोऊ शहर के रोजगार स्थिरीकरण के लिए अनुदान	ऐसे उद्यमों के लिए रोजगार स्थिरीकरण सब्सिडी प्रदान की जाती है जो छंटनी में कम लाने और रोजगार को स्थिर रखने के लिए प्रभावी उपायों को अपनाते हैं।	****	0 - 1 %
परिसंपत्तियों के संबंध में विगत वर्ष में प्राप्त विविध सरकारी और इस वर्ष में चुकाई गई सब्सिडी	परिसंपत्तियों के संबंध में विगत वर्ष में प्राप्त विविध सरकारी और इस वर्ष में चुकाई गई सब्सिडी	****	0 - 1 %
कुल			
पुनर्स्थापन की प्रतिपूर्ति	पुनर्स्थापन की प्रतिपूर्ति	****	0 - 1 %
कुल		****	0 - 5%

(ii) शांडोंग वांडा बोटो टायर कं. लिमि. :

172. शांडोंग वांडा, बोटो टायर कं. लिमि. ("वांडा बोटो") ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया और उनके द्वारा प्राप्त अनुदान कार्यक्रमों के संबंध में सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी ने वांडा बोटो द्वारा प्रदान की सूचना का सत्यापन किया गया है और अनुदान कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया है जिसके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किया गया है और लाभ अर्जित किया गया है। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि सभी अनुदान कार्यक्रमों के कारण धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वांडा बोटो को इस अनुदान के एक प्राप्तकर्ता के रूप में लाभ प्रदान किया गया था। सब्सिडी कार्यक्रम भी निश्चित थे लेकिन वे वांडा बोटो सहित कुछ उद्यमों के लिए निश्चित थे।

173 नीचे दी गई सारणी में अनुदान कार्यक्रमों और तदनुरूपी सब्सिडी मार्जिन के लिए प्रावधान दिया गया है :

अनुदान का नाम	संक्षिप्त विवरण/ टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन की रेंज %
विदेश व्यापार विकास कोष	डोंगिंग शहर वित्त ब्यूरो के विदेश व्यापार विभाग के लिए विशेष कोष	****	0 - 5%
निर्यात सहायता अनुदान - विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए अनुदान	2016 फ्रैंकफर्ट मिडल ईस्ट (दुबई) इंटरनेशनल ऑटो पार्ट्स प्रदर्शनी विशेष कोष	****	0 - 1%
निर्यात सहायता अनुदान - विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए अनुदान	2016 जर्मनी ऐसन इंटरनेशनल टायर बूथ सब्सिडी	****	0 - 1%
निर्यात सहायता अनुदान - विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए अनुदान	प्रदर्शनियों के लिए सब्सिडी	****	0 - 1%
प्रतिभा परिचय कोष	डोंगिंग मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो का वित्तपोषण	****	0 - 1%
विदेशी व्यापार विकास कोष	डोंगिंग शहरी वित्त ब्यूरो के विदेशी व्यापार विकास के लिए विशेष कोष	****	0 - 5%
अनुसंधान रिपोर्ट लेखन व्यय	अनुसंधान रिपोर्ट लेखन व्यय	****	0 - 1%
विकास कोष	शेंगटुओ नगर सरकार की सहायता सब्सिडी	****	0 - 1%

सेवा उद्योग विकास कोष	2016 में केन्ली काउंटी वित्त व्यूरो के सेवा उद्योग विकास के लिए विशिष्ट कोष	****	0 - 1%
निर्यात सहायता अनुदान - विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए अनुदान	प्रदर्शनियों के लिए सब्सिडी	****	0 - 1%
कुल		****	0 - 5%

(iii) शांडोंग योगफेंग टायर कं. लिमि. :

174. शांडोंग योगफेंग टायर कं. लिमि. ("शांडोंग योगफेंग") ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है और उनके द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान कार्यक्रमों के संबंध में सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी ने शांडोंग योगफेंग द्वारा प्रदान की गई सूचना का सत्यापन किया है और अनुदान कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त हुए अथवा अर्जित किए। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि सभी अनुदान कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया है। परिणामस्वरूप इस अनुदान के प्राप्तकर्ता के रूप में शांडोंग योगफेंग को लाभ प्रदान किया गया। सब्सिडी कार्यक्रम भी निश्चित थे क्योंकि वे शांडोंग योगफेंग सहित कुछ उद्यमों के लिए निश्चित थे।

175. निम्नलिखित सारणी में अनुदान कार्यक्रमों के नाम और तदनुरूपी सब्सिडी मार्जिन दिया गया है :

अनुदान का नाम	संक्षिप्त विवरण/टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन की रेंज %
गैस प्रदूषण रोधी विशेष कोष	पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयोजन के लिए थर्मो इलैक्ट्रिक कोयला आधारित बॉयलर	****	0 - 1%
प्रांतीय प्रमुख स्व-स्वामित्व ब्रांड सब्सिडी	शांडोंग प्रांत में इंटरनेशनल स्व-स्वामित्व ब्रांड निर्माण को बढ़ावा देना	****	0 - 1%
स्व- स्वामित्व ब्रांड विकास पंजीरण शुल्क	शांडोंग प्रांत में इंटरनेशनल स्व- स्वामित्व ब्रांड निर्माण को बढ़ावा देना	****	0 - 1%
आयात उपकरण व्याज सब्सिडी 2015	प्रोत्साहित उपकरणों के आयात के लिए सहायता प्रदान करना	****	0 - 1%
आयात उपकरण व्याज सब्सिडी	प्रोत्साहित उपकरणों के आयात के लिए सहायता प्रदान करना	****	0 - 1%
निर्यात पुरस्कार	ऐसे उद्यमों को पुरस्कृत करना जिन्होंने निर्यात मूल्य का लक्ष्य प्राप्त किया है	****	0 - 1%
विदेशी व्यापार और आर्थिक विकास के लिए विशेष कोष (आयात उपकरण)	प्रोत्साहित उपकरणों के आयात के लिए सहायता प्रदान करना	****	0 - 1%
कुल		****	0 - 5%

(iv) ट्राइएंगल टायर कं. लिमि. :

176. ट्राइएंगल टायर कं. लिमि. ("ट्राइएंगल टायर") ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है और उनके द्वारा प्राप्त अनुदान कार्यक्रमों के संबंध में सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी ने ट्राइएंगल टायर द्वारा प्रदान की गई सूचना का सत्यापन किया है और अनुदान कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है, जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किए गए थे अथवा अर्जित किए गए थे। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि सभी कार्यक्रमों के कारण धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ट्राइएंगल टायर्स को इस अनुदान के प्राप्तकर्ता के रूप में लाभ प्रदान किया गया था। सब्सिडी कार्यक्रम भी निश्चित थे क्योंकि वे ट्राइएंगल टायर सहित कुछ उद्यमों के लिए निश्चित थे।

177. तनदनुरूपी सब्सिडी मार्जिन प्रदान किया गया है :

अनुदान का नाम	संक्षिप्त विवरण/टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन की रेंज %
पेटेंट सूजन सहायता कोष	यह वर्ष 2015 की समाप्ति से पूर्व कंपनी द्वारा पहले से प्राप्त किए गए पेटेंट के लिए एक सब्सिडी है	****	0 - 1%
प्रौद्योगिकी पुरस्कार	प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए संस्थाओं को प्रदान किए गए	****	0 - 1%
पेटेंट सूजन सहायता कोष	यह वर्ष 2015 की समाप्ति से पूर्व कंपनी द्वारा पहले से प्राप्त किए गए पेटेंट के लिए एक सब्सिडी है	****	0 - 1%
औद्योगिक डिजाइन पुरस्कार	प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए संस्थाओं को प्रदान किए गए	****	0 - 1%
निर्यात ऋण वीमा प्रीमियम सब्सिडी	निर्यात ऋण वीमा प्रीमियम सब्सिडी	****	0 - 1%
सूचीबद्ध शुल्क अनुदान	स्टॉक सूचीबद्ध कंपनियों को अनुदान	****	0 - 1%
पेटेंट सूजन सहायता कोष	यह वर्ष 2015 की समाप्ति से पूर्व कंपनी द्वारा पहले से प्राप्त किए गए पेटेंट के लिए एक सब्सिडी है। यह एक पेटेंट के लिए सब्सिडी नहीं है। यह वर्ष 2015 की समाप्ति से पूर्व कंपनी द्वारा पहले से प्राप्त किए गए पेटेंट के लिए एक सब्सिडी है	****	0 - 1%
निर्यात ऋण वीमा प्रीमियम सब्सिडी	निर्यात ऋण वीमा प्रीमियम सब्सिडी	****	0 - 1%
निर्यात ऋण वीमा प्रीमियम सब्सिडी	निर्यात ऋण वीमा प्रीमियम सब्सिडी	****	0 - 1%
विदेशी वुद्धिजीवियों को लोन के लिए अनुदान	विशेषज्ञ विदेशी राष्ट्रों को उनके वेतन घटक की सब्सिडी के लिए रोजगार हेतु प्रदान किया गया	****	0 - 1%

2016 नगर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना “आंतरिक स्व-मरम्मत और पंक्चर रोधी” अनुसंधान वित्तपोषण	प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए संस्थाओं को प्रदान किया गया	****	0 - 1%
पेटेंट पुरस्कार कोष	पेटेंट पुरस्कार कोष	****	0 - 1%
पर्यावरणीय निगरानी प्रणाली निगरानी उपकरण प्रचालन एवं रख-रखाव समिक्षा	सरकार (पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी) ने कंपनी में एक पर्यावरणीय निगरानी उपकरण स्थापित किया है, जिससे रख-रखाव और लागत व्यय में मदद मिलती है। सरकार द्वारा लागत के उस हिस्से का भुगतान किया जाता है।	****	0 - 1%
2016 प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उद्यम सहायता पुरस्कार	प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए संस्थाओं को प्रदान किए गए	****	0 - 1%
वर्ष 2016 में निर्यात ऋण	वर्ष 2016 में निर्यात ऋण	****	0 - 1%
सूचीबद्ध कंपनी सूचीबद्ध कंपनी समिक्षा 2016	स्टॉक सूचीबद्ध कंपनियों को प्रदान किया गया (शेष 50 प्रतिशत)	****	0 - 1%
2017 वेहाई पेटेंट सृजन वित्तपोषण कोष	यह वर्ष 2015 की समाप्ति से पूर्व कंपनी द्वारा पहले से प्राप्त किए गए पेटेंट के लिए एक समिक्षा है	****	0 - 1%
2017 वेहाई पेटेंट सृजन वित्तपोषण कोष	यह वर्ष 2015 की समाप्ति से पूर्व कंपनी द्वारा पहले से प्राप्त किए गए पेटेंट के लिए एक समिक्षा है	****	0 - 1%
अनुसंधान एवं विकास केंद्र औद्योगिक पार्क अवसंरचना निर्माण विशेष कोष	यह फैक्ट्री मूल रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित थी (जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है), फैक्ट्री के पुनर्स्थापन के लिए नया स्थान उप नगरीय है और अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है (जहां भूमि की कीमत बहुत कम है), सरकारी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।	****	0 - 1%
अवसंरचना कम	यह फैक्ट्री मूल रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित थी (जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है), फैक्ट्री के पुनर्स्थापन के लिए नया स्थान उप नगरीय है और अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है (जहां भूमि की कीमत बहुत कम है), सरकारी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।	****	0 - 1%
कम तापमान रबड़ शोधन प्रौद्योगिकी (रबड़ के शोधन की प्रौद्योगिकी के संबंध में) की परियोजनाओं का विकास और अनुप्रयोग	प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए अनुदान	****	0 - 1%
अनुसंधान एवं विकास केंद्र औद्योगिक पार्क अवसंरचना निर्माण विशेष कोष	यह फैक्ट्री मूल रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित थी (जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है), फैक्ट्री के पुनर्स्थापन के लिए नया स्थान उप नगरीय है और अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है (जहां भूमि की कीमत बहुत कम है), सरकारी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।	****	0 - 1%

भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन प्रतिपूर्ति व्यय के लिए कोष	यह फैक्ट्री मूल रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित थी (जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है), फैक्ट्री के पुनर्स्थापन के लिए नया स्थान उप नगरीय है और अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है (जहां भूमि की कीमत बहुत कम है), सरकारी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।	****	0 - 1%
औद्योगिक पार्क फेज II - विशेष कोष के भूमि आधार के दक्षिण की ओर निर्माण	यह फैक्ट्री मूल रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित थी (जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है), फैक्ट्री के पुनर्स्थापन के लिए नया स्थान उप नगरीय है और अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है (जहां भूमि की कीमत बहुत कम है), सरकारी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।	****	0 - 1%
अनुसंधान एवं विकास केंद्र औद्योगिक पार्क अवसंरचना निर्माण विशेष कोष	यह फैक्ट्री मूल रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित थी (जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है), फैक्ट्री के पुनर्स्थापन के लिए नया स्थान उप नगरीय है और अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है (जहां भूमि की कीमत बहुत कम है), सरकारी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।	****	0 - 1%
विशेष कोष के औद्योगिक पार्क भूमि आधार का निर्माण	यह फैक्ट्री मूल रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित थी (जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है), फैक्ट्री के पुनर्स्थापन के लिए नया स्थान उप नगरीय है और अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है (जहां भूमि की कीमत बहुत कम है), सरकारी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।	****	0 - 1%
प्रमुख प्रौद्योगिकीय रूपांतरण परियोजना उद्योग क्रहण वित्तीय छूट कोष, वर्ष 2015	प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए अनुदान	****	0 - 1%
अवसंरचना निर्माण व्यय	यह फैक्ट्री मूल रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित थी (जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है), फैक्ट्री के पुनर्स्थापन के लिए नया स्थान उप नगरीय है और अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है (जहां भूमि की कीमत बहुत कम है), सरकारी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।	****	0 - 1%
कम तापमान रबड़ शोधन प्रौद्योगिकी (रबड़ के शोधन की प्रौद्योगिकी के संबंध में) की परियोजनाओं का विकास और अनुप्रयोग	प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए अनुदान	****	0 - 1%
भूमि अधिग्रहण और तोड़ फोड़ क्षतिपूर्ति व्यय निधि	यह फैक्ट्री मूल रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित थी (जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है), फैक्ट्री के पुनर्स्थापन के लिए नया स्थान उप नगरीय है और अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है (जहां भूमि की कीमत बहुत कम है), सरकारी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।	****	0 - 1%
औद्योगिक पार्क के दूसरे चरण के दक्षिण की ओर भूमि पर आधारभूत निर्माण के लिए विशेष कोष	यह फैक्ट्री मूल रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित थी (जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है), फैक्ट्री के पुनर्स्थापन के लिए नया स्थान उप नगरीय है और अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है (जहां भूमि की कीमत	****	0 - 1%

	बहुत कम है), सरकारी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।		
औद्योगिक पार्क आर एंड डी सेंट मूलभूत निर्माण विशेष कोष	यह फैक्ट्री मूल रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित थी (जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है), फैक्ट्री के पुनर्स्थापन के लिए नया स्थान उप नगरीय है और अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है (जहां भूमि की कीमत बहुत कम है), सरकारी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।	****	0 - 1%
औद्योगिक पार्क आर एंड डी सेंट मूलभूत निर्माण विशेष कोष	यह फैक्ट्री मूल रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित थी (जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है), फैक्ट्री के पुनर्स्थापन के लिए नया स्थान उप नगरीय है और अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है (जहां भूमि की कीमत बहुत कम है), सरकारी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।	****	0 - 1%
शांडोंग प्रांत प्रमुख उद्योग तकनीकी सुधार परियोजना क्रृष्ण वित्तीय छूट व्याज कोष	प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए अनुदान	****	0 - 1%
नुन्हाई नव जिला औद्योगिक पार्क भूमि विशेष कोष	यह फैक्ट्री मूल रूप से शहरी क्षेत्र में स्थित थी (जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है), फैक्ट्री के पुनर्स्थापन के लिए नया स्थान उप नगरीय है और अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है (जहां भूमि की कीमत बहुत कम है), सरकारी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।	****	0 - 1%
बॉयलर डिसल्फ्यूरीकरण डिनाइट्रिफिकेशन और धूल निष्कासन प्रौद्योगिकी रूपांतरण कोष	प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए अनुदान	****	0 - 1%
कुल		****	0 - 5%

(v) एयोलस टायर कं. लिमि. :

178. एयोलस टायर कं. लिमि. ("एयोलस टायर") ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है और उनके द्वारा प्राप्त अनुदान कार्यक्रमों के संबंध में सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी ने एयोलस टायर द्वारा प्रदान की गई सूचना का सत्यापन किया है और अनुदान कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है, जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किए गए थे अथवा अर्जित किए गए थे। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि सभी कार्यक्रमों के कारण धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एयोलस टायर्स को इस अनुदान के प्राप्तकर्ता के रूप में लाभ प्रदान किया गया था। सब्सिडी कार्यक्रम भी निश्चित थे क्योंकि वे एयोलस टायर सहित कुछ उद्यमों के लिए निश्चित थे।

तदनुरूपी सब्सिडी मार्जिन प्रदान किया गया है :

अनुदान का नाम	संक्षिप्त विवरण/ टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन की रेंज %
जियोओजिओ 2015 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार	कंपनी को उसकी प्रौद्योगिकीय उपलब्धि के लिए पुरस्कृत करना	****	0 - 1%
2017 पर्यावरणीय संरक्षण के लिए विशेष कोष योजना - 5# रबड़ मिक्सिंग सेंटर 1# जीके 400 प्रोडक्शन लाइन ओडोर मेनेजमेंट प्रोजेक्ट	पर्यावरणीय प्रबंधन परियोजना के व्यय की पूर्ति के लिए	****	0 - 1%

रोजगार स्थिरीकरण के लिए सब्सिडी	कंपनी का रोजगार स्थिर करना	****	0 - 1%
नगरपालिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष का दूसरा बैच, 2016	कंपनी को उसके पेटेंट अधिकृत करने के लिए पुरस्कृत करना	****	0 - 1%
2016 हेनन प्रांत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार कोष	कंपनी को उसकी प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत करना	****	0 - 1%
व्यापार परियोजना प्रसंस्करण के लिए सब्सिडी	कंपनी को व्यापार प्रसंस्करण के आयोजन के लिए सब्सिडी प्रदान करना	****	0 - 1%
2016 निर्यात ऋण बीमा के लिए वार्षिक सब्सिडी	निर्यात ऋण बीमा के व्यय को पूरा करना	****	0 - 1%
जियोज़ुओ शहर उद्यमिता नवीकरण में अग्रणी प्रतिभा पुरस्कार	नवीकरण साहस के लिए पुरस्कार	****	0 - 1%
2017 औद्योगिक पुनर्गठन और उन्नयन कोष	औद्योगिक पुनर्गठन और उन्नयन के व्यय को पूरा करना	****	0 - 1%
बॉयलर कम उत्सर्जन नवोन्मेष कोष	पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयोजन के लिए उपचार की लागत को पूरा करना	****	0 - 1%
कुल		****	0 - 5%

(vi) येलो सी रबड़ कं. लिमि. :

179. एयोलस सी रबड़ कं. लिमि. ("एयोलस सी") ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है और उनके द्वारा प्राप्त अनुदान कार्यक्रमों के संबंध में सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी ने एयोलस सी द्वारा प्रदान की गई सूचना का सत्यापन किया है और अनुदान कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है, जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किए गए थे अथवा अर्जित किए गए थे। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि सभी कार्यक्रमों के कारण धनराशि के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एयोलस सी को इस अनुदान के प्राप्तकर्ता के रूप में लाभ प्रदान किया गया था। सब्सिडी कार्यक्रम भी निश्चित थे क्योंकि वे एयोलस सी सहित कुछ उद्यमों के लिए निश्चित थे।

अनुदान का नाम	संक्षिप्त विवरण/टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन की रेंज %
पोस्ट डॉक्टरल अनुदान	आर एंड डी प्रयोजनों के लिए	****	0 - 1%
वर्ष 2015 के हाई टैक उद्यमों के लिए विशेष सब्सिडी	आर एंड डी व्यय को पूरा करने के लिए	****	0 - 1%
वर्ष 2015 के निर्यात ऋण बीमा के लिए सब्सिडी	विगत वर्षों में कंपनी द्वारा निर्यात ऋण बीमा लागत के व्यय की प्रतिपूर्ति	****	0 - 1%
निर्यात ऋण बीमा के लिए सब्सिडी	विगत वर्षों में कंपनी द्वारा निर्यात ऋण बीमा लागत के व्यय की प्रतिपूर्ति	****	0 - 1%
कोयला आधारित वायू प्रदूषण नियंत्रण कोष	उपचार लागत को पूरा करने के लिए	****	0 - 1%
कुल		****	0 - 5%

I. ख. अनुदान कार्यक्रमों का सारांश :

180. प्राधिकारी ने सहयोगी पक्षकारों के लिए उच्चतम सब्सिडी मार्जिन के आधार पर सभी अन्य दरों निर्धारित की हैं। इसके अलावा, कार्यक्रम सं. 14, 15 और 20 के लिए सब्सिडी मार्जिन भी सभी अन्य दरों को निर्धारण करते समय शामिल किया गया है।

कंपनी का नाम	अनुदानों के लिए सब्सिडी मार्जिन %	रेज %
झोंगसी रबड़ ग्रुप कं. लिमि.	****	0 - 5%
शांडोंग वांडा बोटो टायर कं. लिमि.	****	0 - 5%
ट्राइएंगल टायर कं. लिमि.	****	0 - 5%
शांडोंग योंगफेंग टायर्स कं. लिमि.	****	0 - 5%
एलोयस टायर कं. लिमि.	****	0 - 5%
किंगदाओ येलो सी रबड़ कं. लिमि.	****	0 - 5%
सभी अन्य	****	5 - 15%

II. कर प्रोत्साहनों के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम :

(i) कार्यक्रम सं. 27 : अनुसंधान एवं विकास व्यय की कटौती के लिए कर नीतियां :

क. प्राधिकारी द्वारा जांच :

181. जो कंपनियां नई प्रौद्योगिकियां, उत्पाद अथवा तकनीकें अपने उत्पादन में शामिल करती हैं, उनके 50 प्रतिशत तक कारपोरेट आय कर में कमी हो सकती है। कार्यक्रम की मोजूदगी के साथ्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं :

- चीन राज्य कराधान प्रशासन (एस ट टी) गुओ शुई फा (2008) सं. 116
- आर एंड डी व्ययों की क्री टैक्स सुपर कटौती से संबंधित नीतिगत मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय और एस ए टी का नोटिस (परिपत्र 70, 2013)
- उद्यम अनुसंधान और विकास व्यय की कर पूर्व कटौती के लिए प्रशासनिक उपाय जारी करने के संबंध में एस ए के नोटिस का अनुच्छेद, 2008
- पी आर सी का कारपोरेट आय कर कानून (अनुच्छेद 30.1)
- पी आर सी के उद्यम आय कर के कार्यान्वयन के संबंध में विनियम का अनुच्छेद 95 (पी आर सी की स्टेट काउंसिल की डिक्री सं. 512) तथा प्रमुख क्षेत्रों के लिए गाइड (अधिसूचना सं. 6/2007)

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

182. न तो चीन की सरकार ने और न ही प्रतिवादी निर्यातकों ने कथित कार्यक्रम के संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणियां प्रदान की हैं। तथापि, झोंगसी रबड़ ग्रुप कं. लिमि. ने यह स्वीकार किया है कि उसने इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

183. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम पी आर सी के कारपोरेट आय कर कानून के अनुच्छेद 30.1 और पी आर सी के उद्यम आय कर कानून के कार्यान्वयन के संबंध में विनियमों के अनुच्छेद 95 के तहत शासित होता था। इसके अलावा, एस ए टी ने उद्यम अनुसंधान एवं विकास व्यय की कर पूर्व कटौती (परीक्षण कार्यान्वयन) के लिए प्रशासनिक उपायों को जारी करने के

संबंध में नोटिस जारी किया है (गुओ शुई फा (2008) सं. 116) ताकि भारित आधार पर कटौती किए जाने वाले आर एंड डी व्यय को स्पष्ट किया जा सके।

184. उपरोक्त कागजात में यह भी विनिर्दिष्ट है कि जहां किसी उद्यम द्वारा वास्तव में किए गए आर एंड डी व्यय वर्तमान हानि और लाभ में अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में शामिल नहीं किए गए हैं, वहां वर्ष के दौरान वास्तव में हुए आर एंड डी की 50 प्रतिशत राशि वास्तविक व्ययों के आधार की गई कटौती के अलावा, कर योग्य आय में से कटौती की जाएगी। जहां कोई अमूर्त परिसंपत्तियां पाई जाती हैं, अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत का 150 प्रतिशत कर भुगतान से पूर्व चुकता की जाएगी।

185. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गुओ शुई फा (2008) सं. 116 के स्थान पर अनुसंधान एवं विकास लागतों की भारित कर पूर्व कटौती के लिए नीतियों से संबंधित मामलों पर राज्य कराधान प्रशासन और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया था (काई शुई (2013) सं. 70 दिनांक 1 जनवरी, 2013) और उसके बाद इसके स्थान पर अनुसंधान एवं विकास व्ययों की भारित कर पूर्व कटौती के लिए नीतियों में सुधार करने के संबंध में राज्य कराधान प्रशासन, वित्त मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नोटिस जारी किया गया (काई शुई (2015) सं. 119) दिनांक 1 जनवरी, 2016। यह अभी लागू है।

186. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की पहले ही कुछ अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा की जा चुकी है, जिनमें इसकी मौजूदगी प्रमाणित हुई है। उदाहरण के लिए इस कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता आर्गेन्टिक कोटेड स्टील उत्पादों में यूरोपीय संघ के प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित की जा चुकी है।

187. झोंगसी रबड़ ग्रुप कं. लिमि., जो चीन जन. गण. से एक प्रतिवादी नियर्यातिक हैं, ने अपना प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किया है कि उसने इस सब्सिडी का लाभ उठाया है और उसने जांच की अवधि के दौरान सब्सिडी की राशि के संबंध में सूचना प्रदान की है।

188. कार्यक्रम में राजस्व त्यागने के रूप में एक वित्तीय योगदान के लिए प्रावधान है, जो कि अन्यथा देय है और इसका लाभ प्रदान किया गया है। सब्सिडी भी विशिष्ट है, क्योंकि यह ऐसे उद्यमों के लिए सीमित है, जो अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। यह तथ्य कि झोंगसी रबड़ को इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त हुआ है, यह दर्शाता है कि वास्तव में चीन जन. गण. के ऐसे टायर उत्पादकों ने कार्यक्रम का लाभ लिया है, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को 'संबंधित' उत्पाद का निर्यात किया। अतः प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(ii) कार्यक्रम सं. 28 और 29 : एफ ई आई द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए एफ ई और कर ऑफसेट के अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिमान्य कर नीतियां :

189. कथित वित्तीय योगदान और कार्यक्रम 28 और 29 के लाभ के कानूनी आधार वही हैं। इन दोनों कार्यक्रमों की एक साथ जांच की गई है।

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुरोध :

190. चीन सरकार अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिमान्य कर नीतियां रखती हैं। विशेष रूप से ऐसे समय में, जब अनुसंधान एवं विकास व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से भी अधिक तक की वृद्धि हुई है, उत्पादन कंपनियों को उस वर्ष की कर योग्य आय से 50 प्रतिशत तक ऐसे व्यय को आफसेट करने की अनुमति है। कार्यक्रम के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं:

- गुओ शुई हान (2001) सं. 405
- एस ए टी परिपत्र गुओ शुई फा सं. 173/1999

191. याचिकाकर्ताओं ने यह उल्लेख किया है कि झाओचान लासो रबड़ प्रोडक्ट्स कं. लिमि., हाओयू टायर कं. लिमि. गुआंगज़ोऊ पर्ल रीवर रबड़ टायर लिमि., गीती रेडियल टायर (अनहुई) कं. लिमि., मिसेलिन (थेयांग) टायर कं. लिमि., जियायेन झंगकिसन रबड़ इंडस्ट्री कं. लिमि., केन्डा रबड़ (चीन) कं. लिमि. ने इन कार्यक्रमों से अवश्य लाभ प्राप्त किया होगा।

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :

192. चीन की सरकार द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि दोनों कार्यक्रमों को काफी समय पूर्व 4 जनवरी, 2011 को समाप्त कर दिया गया था और इस कार्यक्रम के तहत कोई रियायती अवधि और इसके स्थान पर कोई अन्य कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया

था। अतः कोई भी विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक/ निर्यातक जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के तहत आवेदन नहीं कर सका अथवा लाभ प्राप्त नहीं कर सका।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच :

193. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कथित कार्यक्रम निम्नलिखित द्वारा शासित होते थे :

- i. “विदेशी निवेश उद्यमों के प्रौद्योगिकी विकास शुल्कों के संबंध में ऑफसेट आय से संबंधित मामलों पर परिपत्र” (गुओ शुई सं. 173/1999) दिनांक 19 सितंबर, 1999 और अनुपूरक परिपत्र (गुओ शुई हान (2001) सं. 405) दिनांक 8 जून, 2001

तथापि, दोनों ही विनियम राज्य कराधान प्रशासन के दिनांक 4 जनवरी, 2011 की घोषणा सं. 2 [2011] द्वारा समाप्त कर दिए गए थे।

194. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने यह पाया है कि ये कार्यक्रम अब लागू नहीं थे और चीन जन. गण. के टायर उत्पादक, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया, उन्हें इन दोनों कार्यक्रमों के तहत लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

195. अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) कार्यक्रम सं. 30 : घरेलू रूप से उत्पादित और निर्मित उत्पादन उपकरण की खरीद के लिए आय कर छूट :

(iv) कार्यक्रम सं. 34 : चीन में बने उपकरण को खरीदने वाली घरेलू स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए आय कर छूट :

196. उपरोक्त कार्यक्रमों में चीन जन. गण. के आय कर कानून के तहत घरेलू रूप में उत्पादित और निर्मित उत्पादन उपकरण की खरीद के लिए उद्यमों को कर छूट/ कटौती/ माफी प्रदान करने की है। अतः इन दोनों कार्यक्रमों की एक साथ जांच की गई थी।

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुरोध :

197. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि चीन सरकार घरेलू उपकरण की खरीद कीमत के 40 प्रतिशत तक कर छूट प्रदान करती है, जिसे पात्र उद्यमों के लिए कर बचत के रूप में माना गया है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचना अथवा योजना दस्तावेज प्रदान किए हैं :

- i. प्रौद्योगिकी नवोन्मेष परियोजना के लिए घरेलू रूप से उत्पादित उपकरण में निवेश के लिए उद्यम आय कर छूट के संबंध में अनंतिम उपाय, 1 जनवरी, 1999
- ii. घरेलू निर्मित उपकरण की खरीद में किसी उद्यम में निवेश की उपकरण आय कर कटौती और छूट नीति के कार्यान्वयन को बंद करने पर राज्य कराधान प्रशासन का नोटिस, सं. 52 (2008), कराधान प्रशासन विवरण, 1 जनवरी, 2008 से प्रभावी।
- iii. उद्यम आय कर के संबंध में पी आर सी कानून का अनुच्छेद 28 (संख्या 63 – दिनांक 16 मार्च, 2007 को प्रभ्यापित) तथा उच्च और नवीन प्रौद्योगिकी उद्यमों के निर्धारण के लिए प्रशासनिक उपाय
- iv. उद्यम आय कर के संबंध में संक्रमणकालीन अधिमान्य नीतियों से संबंधित मामलों के संबंध में स्टेट काउसिल का परिपत्र, गुओ फा (2007) सं. 39
- v. हाई-टैक उद्यमों के लिए अधिमान्य आय कर के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के संबंध में राज्य कराधान प्रशासन का परिपत्र, गुओ शुई हान (2009) सं. 203
- vi. विदेशी निवेश वाले उद्यमों और विदेशी उद्यमों द्वारा घरेलू उपकरण की खरीद के लिए उद्यम आय कर छूट के संबंध में राज्य कराधान प्रशासन और वित्त मंत्रालय का परिपत्र (काई शुई जी (2000) सं. 49)
- vii. एफ आई ई और विदेशी उद्यमों द्वारा घरेलू उपकरण की खरीद के लिए उद्यम आय कर छूट के संबंध में प्रशासनिक उपाय

viii. प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष के लिए उद्यम आय कर की कटौती और छूट के संबंध में अंतरिम उपायों के विवरण के संबंध में चीन जन. गण. के राज्य कराधान प्रशासन तथा वित्त मंत्रालय का परिपत्र (काई शुई जी (1999) सं. 209)

198. याचिकाकर्ताओं ने यह उल्लेख किया है कि ज्ञाओजियान लायो रबड़ प्रोडक्ट कं. लिमि. होयायू टायर कं. लिमि., गुआंगज़ोऊ पर्ल रीवर रबड़ टायर लिमि. गीती रेडियल टायर (अनहुई) कं. लिमि. मिसेलिन (शेंयांग) टायर कं. लिमि., जियामेन झेंजिंग रबड़ इंडस्ट्री कं. लिमि., केन्डा रबड. (चीन) कं. लिमि. जैसे उत्पादकों को इन कार्यक्रमों के तहत लाभ अवश्य प्राप्त हुआ होगा।

ख. **चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध :**

199. उद्यम आय कर के संबंध में पी आर सी कानून का अनुच्छेद 28 (सं. 63 दिनांक 16 मार्च, 2007 को प्रख्यापित), हाई और न्यू प्रौद्योगिकी उद्यमों के निर्धारण के लिए प्रशासनिक उपाय तथा हाई टैक उद्यमों के लिए अधिमान्य आय कर के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य कराधान प्रशासन का परिपत्र गुओ शुई हान (2009) सं. 203 उपरोक्त कार्यक्रमों से संबंधित नहीं थे लेकिन इसकी बजाय हाई टेक्नोलॉजी उद्यमों से संबंधित थे।

200. दोनों ही कार्यक्रम काफी समय पहले 16 मई, 2008 को समाप्त कर दिए गए थे। इनके स्थान पर कोई भी कार्यक्रम नहीं लाया गया अथवा रियायती अवधि प्रदान नहीं की गई। अतः कोई भी निरंतर मौजूद नहीं है। अतः किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के तहत आवेदन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किया है।

ग. **प्राधिकारी द्वारा जांच :**

201. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ये कार्यक्रम प्रौद्योगिकी नवोन्मेष परियोजनाओं के लिए घरेलू उत्पादित उपकरण में निवेश के लिए उद्यम आय कर छूट के संबंध में अनंतिम उपायों के माध्यम से 1999 में शुरू किए गए थे। (काई शुई जी (1999) सं. 290)

202. दिनांक 14 जनवरी, 2000 को चीन सरकार ने विदेशी वित्तपोषित उद्यमों द्वारा घरेलू उपकरण खरीद के लिए उद्यम आय कर के लिए कर छूट जारी करने के संबंध में राज्य कराधान प्रशासन तथा वित्त मंत्रालय का नोटिस जारी किया (काई शुई जी (2000) सं. 49), जिसमें विदेशी वित्तपोषित उद्यमों के उद्योगों को निर्देशित श्रेणी में सूचीबद्ध प्रोत्साहित श्रेणी और प्रतिनिधि बी श्रेणी के तहत आने वाले एफ आई ई को पिछले वर्षों में खरीद वर्ष के उद्यम आय कर के बढ़ हुए भाग से घरेलू उपकरण खरीदने के लिए निवेश का 40 प्रतिशत काटने की अनुमति है।

203. तथापि, दोनों ही विनियमों को समाप्त और अशक्त किए गए वित्त प्रावधानों ओर विनियामक दस्तावेजों की सूची की घोषणा के संबंध में वित्त मंत्रालय के निर्णय के माध्यम से समाप्त किया गया था। (11वां सेट), दिनांक 21 फरवरी, 2011

204. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि राज्य कराधान प्रशासन ने घरेलू उत्पादों की खरीद के माध्यम से विदेशी वित्त पोषित उद्यमों और विदेशी उद्यमों के निवेश के संबंध में औद्योगिक आय कर छूट के संबंध में उपायों के प्रतिवंध और विवरण के संबंध में राज्य कराधान प्रशासन का नोटिस भी जारी किया (गुओ शुई फा (2000) सं. 90)। लेकिन दिनांक 4 जनवरी, 2011 को राज्य कराधान प्रशासन की घोषणा सं. 2 (2011) के माध्यम से विनियम को समाप्त भी कर दिया गया था।

205. घरेलू निर्मित उपकरण की खरीद में किसी उद्यम के निवेश की उद्यम आय कर कटौती की छूट नीति के कार्यान्वयन को बंद करने के संबंध में राज्य कराधान प्रशासन के नोटिस के संबंध में (राज्य कराधान प्रशासन का नोटिस सं. 52 (2008)), यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि दिनांक 1 जनवरी, 2008 से घरेलू रूप से निर्मित उपकरण की खरीद के जरिए उद्यम आय कर के ऑफ सेट की नीति का कार्यान्वयन समाप्त किया जाएगा। अतः दोनों ही कार्यक्रमों को पी आर सी के नए उद्यम आय कर कानून के कार्यान्वयन के बाद समाप्त कर दिया गया था।

206. उद्यम आय कर के संबंध में संक्रमणकालीन अधिमान्य नीतियों से संबंधित मामलों पर स्टेट काउंसिल का परिपत्र, गुओ फा (2007) सं. 39 में पुराने कानून के तहत संक्रमणकालीन अवधि का प्रावधान है लेकिन कार्यक्रम सं. 30 और 34 के साथ कोई भी संबंध नहीं पाया गया।

207. प्राधिकारी ने उद्यम आय कर के संबंध में पी आर सी कानून के अनुच्छेद 28 (16 मार्च 2016 को प्रख्यापित सं 63) और हाई एवं न्यू टैक्नोलॉजी उद्यमों के निर्धारण के लिए प्रशासनिक उपायों तथा हाई टैक उद्यमों के लिए अधिमान्य आय कर के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर राज्य कराधान प्रशासन के परिपत्र (गुओ शुई हान (2009) सं. 203) की भी जांच की है लेकिन यह पाया गया कि इन कार्यक्रमों का संबंध कार्यक्रम सं 31 से है न कि ये कार्यक्रम सं 30 और 34 से संबंधित हैं।

208. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कुछ कागजात तो उपरोक्त कार्यक्रमों से संबंधित ही नहीं थे, जबकि अन्य दस्तावेज अब आगे लागू नहीं थे। अतः चीन जन. गण. से किसी भी ऐसे टायर निर्माता को, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया था, इन कार्यक्रमों से लाभ नहीं मिला था।

209. अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इन कार्यक्रमों के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(v) कार्यक्रम संख्या 31: उन कंपनियों के लिये अधिमान्य कर नीतियां/आयकर कटौतियां जो उच्च एवं नवीन प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में पहचानी गई हैं।

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

210. उच्च एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्यम के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले उद्यम सामान्य तौर पर लागू 25 प्रतिशत की दर की तुलना में 15 प्रतिशत की घटी हुई आयकर दर का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम की विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं या योजना दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, जो यथोचित रूप से उनके पास उपलब्ध थे:-

- i. पीआरसी के निगमित आयकर कानून का अनुच्छेद 28 (16 मार्च, 2007 को लागू संख्या 63)
- ii. पीआरसी के उद्यम आयकर कानून के कार्यान्वयन संबंधी विनियम (पीआरसी की राज्य परिषद की डिक्री संख्या 512)
- iii. उच्च और नवीन प्रौद्योगिकी उद्यमों के निर्धारण के लिए प्रशासनिक उपाय।
- iv. उच्च और नवीन प्रौद्योगिकी के उद्यम आयकर अदायगी से संबंधित मुद्दों पर कराधान संबंधी राज्य प्रशासन नोटिस (गुओ शुई हान (2008) संख्या 985)
- v. 2003 का परिपत्र गुओ शुई फा संख्या 135
- vi. परिपत्र के शुई (2004) संख्या 59 और के शुई (2010) संख्या 65
- vii. 1995 का एसएटी परिपत्र गुओ शुई फा संख्या 139

ख. जीओसी/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

211. कथित कार्यक्रम के संबंध में न तो जीओसी न ही प्रत्युत्तरकारी निर्यातकों में से किसी ने कोई विशिष्ट टिप्पणियां उपलब्ध कराई हैं। हालांकि, आयोलस टायर कंपनी लि० और ट्राईएंगल टायर कंपनी लि० ने कहा है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहायता (सब्सिडी) प्राप्त की हैं और अपने प्रश्नावली उत्तर में उन्होंने इसको प्रकटन किया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

212. कार्यक्रम को पीआरसी के निगमित आयकर कानून के अनुच्छेद 28 और पीआरसी के उद्यम आयकर कानून के कार्यान्वयन पर विनियमों के अनुच्छेद 93 के तहत अधिशासित किया गया था। इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और एसएटी ने संयुक्त रूप से उच्च और नवीन प्रौद्योगिकी उद्यमों (गुओ की फा हुओ (2008) संख्या 172) के निर्धारण के लिए प्रशासनिक उपाय जारी किये, साथ ही, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कराधान के राज्य प्रशासन ने उच्च एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्यमों की पहचान को स्पष्ट करने के लिए हाइटेक उद्यमों (गुओ शुई हान) (2009) संख्या 203) के मुद्रण और उन्हें जारी करने संबंधी परिपत्र को जारी किया। एसएटी में हाइटेक उद्यमों (गुओ शुई हान) (2009) संख्या 203) के लिए अधिमान्य आयकर के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर परिपत्र जारी किया जो अभी तक प्रवृत्त है।

213. तथापि, गुओ के फा हुआ (2008) संख्या 172 और गुओ की फा हुओ (2008) संख्या 362 को हाइटेक उद्यमों (गुओ के फा हुओ (2016) संख्या 32) के प्रमाणीकरण के प्रबंध के लिए उपायों में संशोधन और जारी किए जाने पर एसएटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के नोटिस तथा हाइटेक उद्यमों (2010) (गुओ के फा हुओ) (2016) संख्या 195 के प्रमाणीकरण के प्रबंध के लिए मार्ग निर्देशों के संशोधन एवं जारी किए जाने पर एसएटी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के नोटिस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। एसएटी ने हाइटेक उद्यमों (घोषणा संख्या 24 (2017) कराधान का राज्य प्रशासन) के संबंध में अधिमान्य आयकर नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर आख्यापन जारी किया।

214. प्राधिकारी ने यह भी निटिस किया कि उच्च एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्यमों (गुओ शुई हान (2008) संख्या 985) द्वारा उद्यम आयकर अदायगी से संबंधित मुद्दों पर एसएटी का नोटिस केवल 2008 के वित्तीय वर्ष से संबंधित था और इसे कर विनियामक दस्तावेजों के सूचीपत्र को अमान्य किए जाने और पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त किए जाने के आख्यापन द्वारा निरस्त किया गया। (दिनांक 29 मई, 2016 की कराधान के राज्य प्रशासन की घोषणा संख्या 34 (2016))

215. इसके अतिरिक्त, साई शुई (2010) संख्या 65 और कै शुई (2016) संख्या 59 उन्नत प्रौद्योगिकी सेवा उद्यमों से संबंधित थे। 2003 की गुओ शुई फा संख्या 135 और 1995 की गुओ शुई फा संख्या 139 को एसएटी की आख्यापन संख्या 2 (2011) द्वारा निरस्त किया गया।

216. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की विगत में कुछ अन्य जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा पहले भी जांच की गई है और इस कार्यक्रम की विद्यमानता और प्रतिकारिता की स्थापना की गई है। उदाहरण के लिए (क) आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों तथा कोटेड फाइन पेपर में ईयू प्राधिकारियों द्वारा।

217. आयोलस टायर कंपनी लि० और ट्राईएंगल टायर कंपनी लि०, चीन जन. गण. से उत्तर देने वाले निर्यातकों में से दो ने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किया है और कहा है कि उन्होंने इस लाभ को प्राप्त किया है और पीओआई के दौरान उनके द्वारा प्राप्त की गई सबिसडी की राशि के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है।

218. कार्यक्रम में पूर्वानुमानित राजस्व और उसके द्वारा प्रदत्त लाभ के रूप में वित्तीय अंशदान की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम इसलिए भी विशिष्ट है, क्योंकि यह कुछ विशेष उद्यमों तक सीमित है। यह तथ्य कि आयोलस टायर कंपनी लि० और ट्राइएंगल टायर कंपनी लि० ने कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है, दर्शाता है कि वास्तव में कार्यक्रम को चीन जन. गण. में ऐसे टायर उत्पादों द्वारा प्रयुक्त किया गया था जिन्होंने पीओआई के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात किया था। इसलिए, प्राधिकारी ने प्रस्ताव किया है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(vi) कार्यक्रम संख्या 32: विस्तृत संसाधन उपयोग (विशेष कच्ची सामग्रियां) में संलग्न उद्यमों के लिए आयकर रियायत

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

219. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि कार्यक्रम के अंतर्गत, जिन कंपनियों ने सामग्रियों का प्रयोग किया है और विस्तृत संसाधन उपयोग में संलग्न उद्यमों के लिए आयकर रियायतों के सूचीपत्र में सूचीबद्ध उत्पादों का विनियमण कर रही हैं, पांच वर्षों के लिए आयकर पर 10 प्रतिशत छूट के लिए पात्र है। कार्यक्रम की विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं, जो यथोचित रूप से उनके पास उपलब्ध थे।

- 2007 के उद्यम आयकर आदेश 63 पर पीआरसी कानून का अनुच्छेद 33
- राज्य परिषद द्वारा उद्यम आयकर पर पीआरसी कानून के कार्यान्वयन पर विनियम 2008 का अनुच्छेद 99 आदेश 115,
- विस्तृत संसाधन उपयोग में संलग्न उद्यमों के लिए आयकर रियायत का सूचीपत्र (कै शुई) (2008) संख्या 117)
- ईयू- विशेष आर्गेनिक स्टील उत्पाद, 2013
- ईयू- कोटेड फाइन पेपर, 2011

ख. जीओसी / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

220. जीओसी ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित कार्यक्रम का नाम गलत था और पद “विशेष कच्ची सामग्रियां” को शामिल किया जाना त्रुटिपूर्ण था। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम टायर उद्योग के लिए प्रासंगिक नहीं था।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

221. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम ईआईटीएल के तहत अभिशासित था और 2008 के आदेश 115 के अनुच्छेद 99 में भी निर्धारित किया गया है कि कोई उद्यम जो विस्तृत उपयोग के लिए संसाधनों के कैटालॉग में सूचीबद्ध सामग्रियों में से किसी का प्रयोग करता है। अधिमान्य आयकर उपचार के लिए हकदार है। उद्यमों द्वारा इसकी प्रमुख कच्ची सामग्रियों के रूप में उन

उत्पादों, जो राज्य द्वारा प्रतिवंधित अथवा निषिद्ध नहीं हैं और जो संबद्ध उद्योग अथवा राज्य के संगत मानकों को पूरा करते हैं, के उत्पादन से प्राप्त आयकर देयता से 10 प्रतिशत रियायत के लिए पात्र होंगे।

222. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कैटलॉग में पुराने टायरों को नया टायर बनाने के लिए केवल जंक टायर के प्रयोग को सूचीबद्ध किया गया था। इसलिए यह संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रत्युत्तरकारी उत्पादकों/निर्यातकों ने इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि चीन जनगण में किसी टायर उत्पादक ने, जिसने भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया हो, कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है। इसलिए, प्राधिकारी ने प्रस्ताव किया है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(vii) कार्यक्रम संख्या 33: विशेष उपकरण के क्रय के संबंध में कर क्रेडिट

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

223. क्रय के वर्ष में अदायगी योग्य निगमित आयकर के विरुद्ध पर्यावरणीय सुरक्षा, ऊर्जा और जल बचत एवं उत्पादन सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विशेष उपकरण की क्रय लागत पर 10 प्रतिशत की कटौती प्रदान की गयी है जिसे पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कार्यक्रम की विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में, निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं।

- आरपीसी का उद्यम आयकर कानून, चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति का आदेश संख्या 63
- पीआरसी के उद्यम आयकर कानून के कार्यान्वयन पर विनियमों का अनुच्छेद 100 (पीआरसी की राज्य परिषद की डिक्री संख्या 512)

ख. जीओसी / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निवेदन

224. न तो जीओसी और न ही किसी प्रत्युत्तरकारी निर्यातकों ने कथित कार्यक्रम के संबंध में कोई विशेष टिप्पणियां उपलब्ध कराई हैं। हालांकि, शेनडांग योगफेंग टायर कंपनी लि० ने स्वीकार किया है कि इसने इस कार्यक्रम से लाभ भी प्राप्त किया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

225. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम पीआरसी के उद्यम आयकर कानून के अनुच्छेद 34 और पीआरसी के उद्यम आयकर कानून के कार्यान्वयन पर विनियमों के अनुच्छेद 100 के तहत अभिशासित था। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, कराधान राज्य प्रशासन, राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग और अन्य विभागों ने ऊर्जा और जल संरक्षण और उद्यम आयकर प्राथमिकताओं के लिए विशेष उपकरण सूचीपत्र जारी किया (के शुई (2008) संख्या 115), जिसे 2017 के पाठ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था (के शुई (2017) संख्या 71)

226. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की विगत में कुछ अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा पहले भी जांच की गई है और इस कार्यक्रम की विद्यमानता और प्रतिकारिता की स्थापना की गई है। उदाहरण के लिए ईयू प्राधिकारियों द्वारा आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पाद।

227. चीन जनगण से प्रत्युत्तरकारी निर्यातकों में से एक शेनडांग योगफेंग टायर कंपनी लि० जिसने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किया है, कहा है कि उसने यह लाभ प्राप्त किया है और पीओआई के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त समिक्षा की मात्रा के संबंध में सूचना उपलब्ध करायी है।

228. कार्यक्रम में पूर्वानुमानित राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान की व्यवस्था की गई है और उसके द्वारा प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया गया है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि, यह कुछ विशिष्ट उद्यमों तक सीमित है जो विशेष उपकरणों का क्रय करते हैं। यह तथ्य कि शेनडांग योगफेंग को कार्यक्रम से लाभ प्राप्त हुआ है, दर्शाता है कि कार्यक्रम का वास्तव में चीन जनगण में टायर उत्पादकों द्वारा प्रयोग किया गया था, जिन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया था। इसलिए, प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लागू किया जाना चाहिए।

(vii) कार्यक्रम संख्या 35: आयातित प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के लिए टैरिफ एवं वैट छूट

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

229. यदि कोई एफआईई विदेशी निवेश का मार्गदर्शन (2004) करने के लिए उद्योगों के कैटालॉग में “प्रोत्साहित” या “प्रतिबंधित” श्रेणियों में अथवा विदेशी निवेश के मार्गदर्शन के लिए (2007) उद्योगों के सूचीपत्र में आता है तो यह उपकरण के लिए टैरिफ और आयात वैट से छूट के लिए पात्र है। कार्यक्रम की विद्यमानता के साथ्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसचूनाएं अथवा योजना दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं जो उनके पास यथोचित रूप से उपलब्ध थे-

- i. आयातित उपकरणों के लिए कराधान नीतियों के समायोजन के संबंध में राज्य परिषद के नोटिस का अनुच्छेद 1 और 2
- ii. वित्त मंत्रालय, सीमा शुल्क को सामान्य प्रशासन और कराधान के राज्य प्रशासन का आख्यापन (2008) संख्या 43
- iii. राज्य द्वारा विकास के लिए प्रोत्साहित घरेलू या विदेशी वित्त पोषित परियोजनाओं पर पुष्टि पत्र की कार्रवाई के संबंध में संगत मुद्दों पर एनडीआरसी का 22 फरवरी, 2006 का नोटिस संख्या 316 2006
- iv. या तो एफआईई या घरेलू उद्योग के लिए गैर-शुल्क छूट योग्य वस्तुओं के आयात पर सूचीपत्र, 2008
- v. विदेशी निवेश के मार्गदर्शन के लिए उद्योगों का कैटालॉग
- vi. इस समय राज्य द्वारा समर्थित उद्योग, उत्पाद और प्रौद्योगिकी प्रमुखों का सूचीपत्र (2004)
- vii. राज्य परिषद की आयात वस्तुएं विदेशी निवेश परियोजना कैटालॉग के लिए कराधान से छूट प्राप्त नहीं हैं।
- viii. आयात वस्तुएं घरेलू निवेश परियोजना सूचीपत्र के लिए कराधान से छूट प्राप्त नहीं है।

230. याचिकाकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. में प्रमुख टायर उत्पादक जो संभवतः इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो सकते हैं वे इस प्रकार हैं-

याओयुआन लियाओ रवड़ प्रोडक्ट्स कंपनी लि०, हाओयू टायर कंपनी लि०, गुआनझाऊ पर्ल रिवर रवड़ टायर लि०, गिती रेडियल टायर (अनहृदई) कंपनी लि०, मिशेलीन (शेनयांग) टायर कंपनी लि०, थियामेन झेंगजिन रवडू इंडस्ट्रीज कंपनी लि०, केंडा रवड़ (चीन) कंपनी लि०।

ख. जीओसी / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

231. इस कार्यक्रम को बहुत पहले 22 फरवरी, 2008 को समाप्त कर दिया गया था और इस कार्यक्रम के लिए कोई प्रतिस्थापन और रियायत अवधि प्रदान नहीं की गई। इस प्रकार लगातार लाभ की कोई विद्यमानता नहीं है। इसलिए, पीओआई के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी पीयूसी उत्पादक / नियांतक पीओआई के दौरान लाभों के लिए आवेदन अथवा लाभ प्राप्त नहीं कर सकता था।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

232. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने (i) के शूर्ई (2007) संख्या 75, (ii) के शूर्ई (2008) संख्या 170 (iii) के शूर्ई (2014) संख्या 36, (iv) के शूर्ई (2014) संख्या 38, (v) के शूर्ई (2014) संख्या 37, (vi) के क्यूआन शूर्ई (2014) संख्या 24, (v) फा गाई वान वाई जी (2014) संख्या 1329, (vi) फा गाई वान वाई जी (2014) संख्या 1454, (vii) फा गाई वान वाई जी (2014) संख्या 1386, (viii) पीबीओसी आदेश (2014) संख्या 2, (ix) राज्य परिषद (1993) संख्या 134, (x) साई फा (1993) संख्या 38, (xi) गुओ शूर्ई फा (2000) संख्या.84। हालांकि, ये 11 कानूनी पाठ कार्यक्रम से संबंधित नहीं थे।

233. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम 35 वास्तव में आयातित उपकरण कराधान नीतियों (गुओ फा (1997) संख्या 37) के समायोजन पर राज्य परिषद के परिपत्र के अंतर्गत अभिशासित किया गया था। इसके अलावा, सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन ने यह स्पष्ट करने के लिए विदेशी निवेश को और प्रोत्साहित करने (शूर्ई शूर्ई (1999) संख्या 791) से संबंधित आयात कराधान नीतियों पर सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन का नोटिस जारी किया कि एफआईई द्वारा आयातित कौन सी वस्तुएं वैट और सीमा शुल्क से छूट प्राप्त हैं।

234. इसी बीच, गुओ फा (1997)संख्या 37, भी स्पष्ट करता है कि उपकरण-

- क) जो विदेशी निवेश परियोजनाओं के, जिसमें प्रौद्योगिकी स्थानांतरण शामिल है, निवेश की कुल राशि के भीतर स्वयं के प्रयोग के लिए आयातित किए गए हैं और
- ख) जो विदेशी निवेश के लिए औद्योगिकी मार्गदर्शन कैटालॉग की सीमित श्रेणी के समूह 'ख' अथवा प्रोत्साहन श्रेणी में शामिल है और
- ग) ऐसे उपकरण विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं के लिए टैरिफ छूट के लिए हकदार नहीं मानी गई आयातित वस्तुओं के सूचीपत्र में सूचीबद्ध में शामिल नहीं है। ये टैरिफ और आयात स्तर पर मूल्य वर्धित कर से छूट प्राप्त कर सकते हैं वशर्ते कि- "उच्च निष्पादन रेडियल (विज्यीय) टायर" उद्योग पुर्नसंरचना संबंधी मार्ग निर्देश संबंधी कैटालॉग की प्रोत्साहन श्रेणी में सूचीबद्ध था (2011 पाठ) (2011 संशोधन)

235. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की विगत में कुछ अन्य जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा पहले जांच की गई थी और इस कार्यक्रम की विद्यमानता और प्रतिकारिता की स्थापना की गई है। उदाहरण के लिए, सोनर गिलास, आर्गेनिक कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स तथा कोटेड फाइन पेपर में ईयू प्राधिकारी।

236. कार्यक्रम में राजस्व पूर्वानुमान के रूप में वित्तीय योगदान की व्यवस्था की गई है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया गया है। कार्यक्रम इसलिए भी विशिष्ट है, क्योंकि यह विदेशी निवेश वाले उद्यम तक सीमित है। पीओआई के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत किसी भी प्रतिभागी टायर उत्पादकों ने लाभ प्राप्त नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया है कि चीन जन. गण. में टायर उत्पादकों, जिन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है, इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है। जांच की अवधि के दौरान, प्राधिकारी उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य की पहचान नहीं कर सके कि चीन जन. गण. में टायर उत्पादकों जिन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया था, इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है।

237. प्राधिकारी ने प्रस्ताव किया है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(viii) **कार्यक्रम संख्या 36: चीन द्वारा बनाये गये उपकरणों की क्रय पर घरेलू फर्मों के लिए वैट प्रतिदाय।**

(ix) **कार्यक्रम संख्या 41: एफआई और विदेशी उद्यमों के लिए जिनकी चीन में संस्थापनाएं हैं, अधिमान्य कर नीतियां और जो घरेलू रूप से उत्पादित उपकरणों की खरीद के व्यापार प्रचालनों में संलग्न हैं।**

238. कार्यक्रम संख्या 36 और 41 घरेलू रूप से उत्पादित और विनिर्मित उत्पादन उपकरणों के क्रय के लिए उद्यमों को सामान्य वैट लाभ प्रदान करने का आरोप लगाया गया है। इसलिए, इन कार्यक्रमों की एक साथ जांच की गई है।

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

239. वैट एफआई सहित उद्यमों के लिए घरेलू उपकरण की खरीद पर प्रतिदाय देय है। कार्यक्रम की विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाएं या योजना दस्तावेजों को उपलब्ध कराया है जो यथोचित रूप से उनके पास उपलब्ध थे।

- i. "मूल्य वर्धित कर पर चीन जनवादी गणराज्य के अंतरिम विनियमों" का अनुच्छेद 3 और 27 (राज्य परिषद की डिक्री (1993) संख्या 134)
- ii. "आयातित उपकरणों की कराधान नीतियों के समायोजन के संबंध में राज्य परिषद के परिपत्र में निर्धारित विदेशी वित्त पोषित उद्योगों की निर्देशात्मक श्रेणी"
- iii. एफआई के साथ उद्यम का कर प्रतिदाय के संचालन के लिए अंतरिम उपायों को अंतरित करने के संबंध में कराधान के राज्य संचालन का परिपत्र (गुओ शूई फा) (1997) संख्या 171, 20 सितंबर, 1999)
- iv. आयातित उपकरण की कर नीतियों के समायोजन पर राज्य परिषद का परिपत्र (गुओ फा (1997) संख्या 37)
- v. चीन में विकास के लिए प्रोत्साहित प्रमुख उद्योगों, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का कैटलॉग (1998)

- vi. ईयू कोटेड फाइन पेपर
- vii. ईयू- आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पाद
- viii. प्रमुख प्रौद्योगिकीय उपकरण और मशीनरी से संबंधित आयात – स्तर की कर नीतियों के समायोजन से संबंधित नोटिस (साई गुयाओ शूई (2014) संख्या 2)

240. इन कार्यक्रमों से टायर उत्पादकों जैसे ज्ञायोयान लियाओ रबड़ प्रोडक्ट्स कंपनी लि०, हाओयू टायर कंपनी लि०, गुआन ज्ञाओ पर्ल रिवर रबड़ टायर लि०, गिरी रेडियल टायर (अनहुई) कंपनी लि०, मिशोलिन (शेनयांग) टायर कंपनी लि०, थियामन ज्ञेनजिन रबड़ इंडस्ट्री कंपनी लि०, केंडा रबड़ (चीन) कंपनी लि० ने संभवतः लाभ प्राप्त किया है।

ख. जीओसी/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

241. “मूल्य वर्धित कर पर चीन जनवादी गणराज्य के अंतरिम विनियम” (राज्य परिषद की डिक्री (1993) संख्या 134) अमान्य है, क्योंकि इसे “मूल्य वर्धित कर पर चीन जनवादी गणराज्य के अंतरिम विनियमों” (2008 संशोधन) से प्रतिस्थापित किया गया था।

242. इसके अतिरिक्त, ईयू कोटेड फाइन पेपर और ईयू आर्गेनिक कोटेड स्टील में यूरोपीय आयोग के सीवीडी निष्कर्ष कानूनी आधार का निर्माण नहीं करते।

243. आयातित उपकरण की कर नीतियों के समायोजन (गुओ फा (1997) संख्या 37) और प्रमुख प्रौद्योगिकीय उपकरण और मशीनरी से संबंधित आयात स्तर पर नीतियों के समायोजन से संबंधित नोटिस (कै गुआन शूई (2014) संख्या 2) कार्यक्रम 35 से संबंधित विनियम हैं न कि कार्यक्रम 36 या कार्यक्रम 41 से।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

244. प्राधिकारी नोट करते हैं कि-

- i. उक्त कार्यक्रमों को मुख्यतः कर प्रतिदाय के लिए प्रस्तावित प्रबंध पद्धतियों से संबंधित राज्य कराधान प्रशासन के तहत अभियासित किया जाता है (गुओ शूई फा (1997) संख्या 171)।
- ii. 10 मई, 2006 को वित्त मंत्रालय और कराधान के राज्य प्रशासन ने संयुक्त रूप से विदेशी वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए गृह निर्मित उपकरण के क्रय के लिए कर प्रतिदाय नीतियों के कार्यक्षेत्र के समायोजन पर संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया (कै शूई (2006) संख्या 61)।
- iii. राज्य कराधान प्रशासन और एनडीआरसी ने भी 1 जुलाई, 2006 संयुक्त रूप से “विदेशी वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए स्वदेश निर्मित उपकरण के क्रय के लिए कर प्रतिदाय संचालन पर परीक्षण कार्यान्वयन उपाय” (गुओ शूई फा (2006) संख्या 111)

245. तथापि, उपर्युक्त सभी विनियमों को स्वदेश निर्मित उपकरण (कै शूई (2008) संख्या 176 की खरीद के लिए विदेशी वित्त पोषित उद्यमों की कर प्रतिदाय की नीति के कार्यान्वयन को रोकने पर कराधान के राज्य प्रशासन और वित्त मंत्रालय के नोटिस के अंतर्गत उन्मूलित कर दिया गया। इस प्रपत्र के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 1 जनवरी, 2009 से उन विदेशी वित्त पोषित उद्यमों को वैट के प्रतिदाय, जो निवेश की कुल राशि के भीतर स्वदेश निर्मित उपकरण क्रय करते हैं, आगे से क्रियान्वित नहीं किये जाएंगे।

246. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि “आयातित उपकरणों की कराधान नीतियों के समायोजन के संबंध में राज्य परिषदों के परिषद में निर्धारित विदेशी वित्त पोषित उद्योगों की निदेशात्मक श्रेणी” और “चीन में विकास के लिए प्रोत्साहित प्रमुख उद्योगों, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के सूचीपत्र” का उक्त कार्यक्रमों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है।

247. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां कुछ प्रपत्र उल्लिखित कार्यक्रम के संगत नहीं हैं, वहीं अन्य प्रपत्र प्रवृत्त नहीं थे। चीन जनगण में कोई भी टायर उत्पादन, जिन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया हो, कार्यक्रम से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

248. इसलिए, प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(x) कार्यक्रम संख्या 37: केंद्रीय क्षेत्रों के लिए वैट छूट और कटौतियां

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

249. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केंद्रीय क्षेत्र के पुराने औद्योगिकी आधारों के 26 शहरों में स्थित वैट अदाकर्ता, जिन्होंने कुछ विशेष अचल परिसंपत्तियों में निवेश किए हैं, अपनी कुल वैट देयताओं में से अचल परिसंपत्तियों पर अदा किए गए वैट की राशि काट सकते हैं। कार्यक्रम की विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं या योजना दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं—

- i. एसएटी – चीन जनगण के वैट पर अनंतिम विनियम- आदेश संख्या 134 (1993)
- ii. एसएटी - चीन जनगण के वैट पर अनंतिम विनियम के क्रियान्वयन के लिए नियमावली आदेश संख्या 38 (1993)
- iii. एसएटी - चीन जनगण से कर पूर्व कटौतियों के लिए उपाय – आदेश संख्या 84
- iv. केंद्रीय क्षेत्र संख्या 75 (2007) में वैट के लिए कटौती का क्षेत्र में विस्तार के लिए अंतरिम उपाय
- v. वित्त मंत्रालय के वैट कर सुधार संख्या 170 (2008) के राष्ट्रीय कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर वित्त मंत्रालय और एसएटी का नोटिस।
- vi. मूल्य वर्धित कर (वैट) संग्रहण दरों के सरलीकरण और समानीकरण से संबंधित मुद्दों से संबंधित नोटिस (एसएटी आख्यापन (2014) संख्या 36)
- vii. वेब अनुसंधान- चीन व्यापार पुस्तिका
- viii. वेब अनुसंधान- चीन जनगण में निवेश
- ix. वेब अनुसंधान- चीन का वैट अनुमान- जू यान द्वारा

तथापि, याचिकाकर्ताओं ने यह भी इंगित किया है कि यह कार्यक्रम केवल उन उत्पादकों के लिए पात्र था जो कुछ विशेष नामोदृष्टि क्षेत्रों में स्थित थे। यह दावा किया गया है कि उत्पाद जैसे केंडा रबड़, (चीन) कंपनी लिं०, गिरी रेडियल टायर (अनहुई) कंपनी लिं० और थियामन जेन जिन रबड़ इंडस्ट्री कंपनी लिं० ने संभवतः इन कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त हो सकता है।

ख. जीओसी / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

250. याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में नोट की गई अधिसूचना का कोई कानूनी पाठ उपलब्ध नहीं कराया गया था। वेब अनुसंधान और मामला निष्कर्ष एससीएम के अनुच्छेद 11.2 के तहत कोई कानूनी आधार नहीं हैं। पूर्णतः सहयोग करने के लिए, जीओसी ने कानूनी पाठ और समाप्ति अधिसूचना भी उपलब्ध कराई है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

251. जीओसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी प्रासंगिक विनियमों की पहचान कर सकते थे। उक्त कार्यक्रम केंद्रीय क्षेत्र में वैट के प्रतिसंतुलन के क्षेत्र के विस्तार के लिए अंतरिम उपायों के अंतर्गत अभिशासित था (कै शूई (2007) संख्या 75)। तथापि, विनियम को मूल्य वर्धित कर सुधार के राष्ट्रीय क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर कराधान के राज्य प्रशासन और वित्त मंत्रालय के नोटिस के अंतर्गत समाप्त किया गया था (कै शूई (2008) संख्या 170), तथापि, कै शूई (2008) संख्या 170 तब भी प्रवृत्त था और वैट दर को मूल्य वर्धित कर उद्धरण दरों को धाराप्रवाह और संयोजित बनाने की नीति पर वित्त मंत्रालय और कराधान पर राज्य प्रशासन के नोटिस के अंतर्गत सरलीकरण किया गया (कै शूई (2014) संख्या 57)। दोनों प्रावधान चीन जनगण के केवल सामान्य उपबंध हैं और इनका कार्यक्रम 37 के साथ कोई संबंध नहीं है।
252. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल्य वर्धित कर पर (राज्य परिषद की संख्या 134) चीन जनवादी गणराज्य के अंतरिम विनियम को 2008, 2016 और 2017 में संशोधित किया गया। दिनांक 25 दिसंबर, 1993 के मूल्य वर्धित कर पर चीन जनवादी गणराज्य के अंतरिम विनियमों के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत नियमों को 2008 और 2011 में भी संशोधित किया गया था। तथापि, दोनों विनियम केवल चीन जनगण में वैट के सामान्य उपबंध हैं और इनका कार्यक्रम 37 के साथ कोई संबंध नहीं है।

253. उद्यमों के लिए आयकर से कर पूर्व कटौतियों के लिए साधन उपाय (गुओ शूई फा (2000) संख्या 84) उद्यम आयकर की कटौती से संबंधित था और इसे दिनांक 29 नवंबर, 2010 के कराधान विभागों के वर्तमान प्रभावी, अमान्य और निरस्त नियमों की सूचीपत्र द्वारा समाप्त किया गया।

254. मूल्य वर्धित कर (वैट) संग्रहण दर (एसएटी आख्यापन (2014) संख्या 36) के सरलीकरण और समानीकरण से संबंधित मुद्रों से संबंधित लिखित नोटिस सरलीकृत पद्धति द्वारा संग्रहण किए जाने के लिए वैट का स्पष्टीकरण था। यह प्रपत्र कार्यक्रम 37 के संगत नहीं था।

255. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां कुछ प्रपत्र ऊपर उल्लिखित कार्यक्रम के प्रासंगिक थे, अन्य प्रपत्र प्रवृत्त नहीं थे। चीन जन. गण. में कोई भी टायर उत्पादक, जिसने संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया था, इस कथित कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सकता था। प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि याचिका में आरोपित किए गए इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए।

(xi) **कार्यक्रम संख्या 38: अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रचालन हेतु अनुसूचित उत्पादकारी एफआई के लिए घटी हुई कर दर।**

(xii) **कार्यक्रम संख्या 39: विदेशी निवेशित निर्यात उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां।**

(xiii) **कार्यक्रम संख्या 40: ऐसे एफआई के लिए अधिमान्य कर नीतियां जो प्रौद्योगिकी गहन और सूचना गहन हैं।**

(xiv) **कार्यक्रम संख्या 42: विदेशी निवेशकों द्वारा एफआई लाभों के पूर्ण निवेश के लिए आयकर प्रतिदाय।**

(xv) **कार्यक्रम संख्या 44: विशेष आर्थिक जोनों (शंघाई पुडोंग क्षेत्र को शामिल किए बिना) में स्थापित विदेशी निवेश के साथ उद्यम के लिए अधिमान्य कर नीतियां।**

(xvi) **कार्यक्रम संख्या 45: तटीय आर्थिक खुला क्षेत्रों और आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास जोनों में स्थापित एफआई के लिए अधिमान्य कर नीतियां।**

(xvii) **कार्यक्रम संख्या 46: सेज और अन्य नामोदृष्टि क्षेत्रों में स्थानीय आयकर छूट और / या कटौती।**

(xviii) **कार्यक्रम संख्या 47: सेज और अन्य नामोदृष्टि क्षेत्रों निगमित आयकर छूट और / या कटौती।**

256. याचिकाकर्ताओं ने कर कार्यक्रमों की शृंखला की मौजूदगी का दावा किया है जो उनके उद्यम के स्थान अथवा स्वरूप अथवा प्रौद्योगिकीय नवीकरण पर आधारित उद्यमों की कुछ विशेष श्रेणियों को आयकर में छूट / कटौती / माफी उपलब्ध कराता है। यह नोट किया जाता है कि कार्यक्रम संख्या 38,39,40,42,44,45,46 और 47 जैसा कि ऊपर सूचीबद्ध किया गया है, एफआई उद्यमों को समान आयकर लाभों की विद्यमानता का दावा करते हैं। इसलिए, इन सभी कार्यक्रमों की एक साथ जांच की गई है।

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

257. कार्यक्रम संख्या 38 को एमओएफ, एमओएफसीओएम, एसएटी और इसके स्थानीय कर ब्यूरो द्वारा संचालित किया जाता है। उस वर्ष से जब से एफआई ने लाभ प्राप्त करना आरंभ किया, यह पहले दो वर्षों के लिए पूर्ण आयकर छूट और अगले तीन वर्षों के लिए 50 प्रतिशत छूट प्राप्त कर रहा है। पात्र होने के लिए उद्यम को एक एफआई होना चाहिए, जो कम से कम 10 वर्षों के पूर्वानुमानित प्रचालन के साथ उत्पादोन्मुख है और जिसका एक ऐसा वित्तीय वर्ष रहा है, जिसमें उसने लाभ प्राप्त किया है।

258. कार्यक्रम संख्या 39 के तहत, विदेशी कारोबारों द्वारा प्रचालित और निवेशित निर्यातोन्मुखी उद्यमों, जिसके लिए किसी वर्ष में सभी निर्यात उत्पादों का आउटपुट मूल्य उस विशेष वर्ष के लिए 70 प्रतिशत या उससे अधिक रहा है, ऊपर उल्लिखित स्थितियों के अंतर्गत अर्हता के अनुसार आधा या 15 प्रतिशत अदा कर सकता है अथवा 10 प्रतिशत की कर दर पर उद्यम आयकर अदा करेगा।

259. कार्यक्रम 40 के अंतर्गत एफआई जो प्रौद्योगिकी गहन अथवा जानकारी गहन के रूप में अर्हता प्राप्त है और चीन के उच्च और नवीन प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूचीपत्र में सूचीबद्ध प्रमुख उत्पादों का उत्पादन करते हैं, उक्त कार्यक्रम के लिए पात्र है।

260. कार्यक्रम 42 के अंतर्गत, एफआईई आयकर पर 40 प्रतिशत (यदि लाभों को पुनः निवेशित किया जाता है) या 100 प्रतिशत (यदि लाभों को एक नियर्तोन्मुख अथवा प्रौद्योगिकीय रूप से अग्रिम उद्यम में पुनः निवेशित किया जाता है) प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए हकदार है।

261. कार्यक्रम 44 के अंतर्गत, पुडोंग क्षेत्र (शंघाई) में स्थापित विदेशी निवेशित उत्पादक उद्यम 15 प्रतिशत की घटी हुई दर पर आयकर के अध्याधीन है।

262. कार्यक्रम 45 के अंतर्गत, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकास जोन या तटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों में स्थित एफआईई उत्पादन स्थान की स्थिति आधार पर 15 प्रतिशत या 24 की घटी हुई आयकर दर के लिए पात्र है।

263. कार्यक्रम 46 के अंतर्गत, घरेलू उद्यम और एफआईई दोनों अथवा “गुआंगडांग क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोनों पर विनियम” और “विकासशील हयनान आईलैंड में निवेश के प्रोत्साहन के संबंध में राज्य परिषद के प्रावधान” के तहत 15 प्रतिशत अथवा 24 प्रतिशत की निम्न दरों अथवा 3 प्रतिशत छूट पर आयकर के लिए पात्र है।

264. कार्यक्रम 47 के अंतर्गत, जो एफआईई आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकास जोन में स्थापित है, 15 प्रतिशत की घटी हुई निगमित आयकर दर के अध्याधीन है।

265. कार्यक्रम की विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं या योजना दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं-

कार्यक्रम 39: विदेशी निवेशित नियर्त उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां

- विदेशी निवेश वाले उद्यमों और विदेशी उद्यमों के लिए चीन जनवादी गणराज्य का आयकर कानून
- विदेशी निवेश वाले उद्यम और विदेशी उद्यमों के लिए चीन जनवादी गणराज्य के आयकर कानून के कार्यान्वयन के लिए नियम
- वित्त मंत्रालय और उद्यम आयकर अधिमान्य नीतियों पर राज्य कराधान प्रशासन का परिपत्र के शूर्ई (2009) संख्या 69
- परिपत्र 115 – अक्टूबर, 2009
- एसएटी परिपत्र गुओ सूर्ई फा संख्या 1995 का 139
- एसएटी परिपत्र गुओ सूर्ई फा संख्या 2003 का ।
- परिपत्र के शूर्ई (2014) संख्या 59 और 65

कार्यक्रम 40: एफआईई जो प्रौद्योगिकी गहन और जानकारी गहन के लिए अधिमान्य कर नीतियां हैं।

- उद्यम आयकर के संबंध में परिवर्ती अधिमान्य नीतियों को पूरा करने पर राज्य परिषद की अधिसूचना (गुओ फा 2007 संख्या 39)
- स्वाभाविक व्यक्ति से धन उधार ऋण लेने वाले उद्यम के लिए ब्याज व्यय पर उद्यम आयकर से कर पूर्व कटौती से संबंधित मुद्रों पर राज्य कराधान प्रशासन का नोटिस (पत्र संख्या 777,2009)
- विदेशी निवेश वाले उद्यमों के चीन जनवादी गणराज्य आयकर कानून के क्रियान्वयन नियमों का अनुच्छेद 73
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ("एमओएसटी") द्वारा प्रब्याप्ति चीन के उच्च और नवीन प्रौद्योगिकी उत्पादों का सूचीपत्र

विदेशी निवेशकों द्वारा एफआईई लाभों के पुनः निवेश के लिए आयकर प्रतिदाय -

- विदेशी निवेशित उद्यम और विदेशी उद्यम आयकर कानून 1991 का अनुच्छेद 10 (एफआईई कानून)
- विदेशी निवेशित उद्यम और विदेशी उद्यम आयकर कानून के कार्यान्वयन नियमों का अनुच्छेद 80 (एफआईई विनियम)

xiv. विदेशी निवेश के साथ उद्यम के विदेशी निवेशकों द्वारा किये गए पुनः निवेश के लिए कर प्रतिपूर्ति से संबंधित कुछ मुद्दों पर राज्य कराधान प्रशासन का परिपत्र (गुओ शूई फा (1993) संख्या 9) के शूई (2009) संख्या 69

xv. कार्यक्रम 44 विशेष आर्थिक जोन (शंघाई पुडोंग क्षेत्र शामिल नहीं है) में स्थापित विदेशी निवेश वाले उद्यमों (एफआईई) के लिए अधिमान्य कर नीतियां

xvi. राज्य परिषद की डिक्री (1991) संख्या 85 (30 जून, 1991)

xvii. चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति का आदेश संख्या (1991) 45 (9 अप्रैल, 91)

xviii. 2000 का राज्य परिषद परिपत्र गुओ फा संख्या 37

xix. उद्यम आयकर गुआ फा 2007 संख्या की 39 के संबंध में पारगमन अधिमान्य नीतियों को लागू करने पर राज्य परिषद की अधिसूचना

xx. विदेशी निवेश वाले उद्यमों और विदेशी उद्यमों के लिए चीन जनवादी गणराज्य के पर कानून, 1991 का अनुच्छेद 19

xxi. चीन जनवादी गणराज्य के उद्यम आयकर कानून, 2008 का अनुच्छेद 4, 28 और 36

xxii. उद्यम आयकर, 2008 के क्रियान्वयन पर चीन जनवादी गणराज्य के विनियमों का अनुच्छेद 91

कार्यक्रम 45 - तटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों और आर्थिक तथा प्रौद्यागिकीय विकास जोनों में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां

xxiii. विदेशी निवेश वाले उद्यमों और विदेशी उद्यमों के लिए चीन जनवादी गणराज्य का आयकर कानून (कर कानून)

xxiv. उद्यम आयकर कानून 2008

xxv. विदेशी निवेश वाले और विदेशी उद्यमों के लिए चीन जनवादी गणराज्य के आयकर कानून के क्रियान्वयन के लिए नियम ।

कार्यक्रम 46: सेज और अन्य नामोदृष्टि क्षेत्रों में स्थानीय आयकर छूट और / या कमी

xxvi. 1991 की डिक्री 85 का अनुच्छेद 82

xxvii. विदेशी निवेश वाले उद्यमों और विदेशी उद्यमों के लिए चीन जनवादी गणराज्य का आयकर कानून (कर कानून)

xxviii. विदेश निवेश वाले उद्यमों और विदेशी उद्यमों के लिए चीन जनवादी गणराज्य के आयकर कानून के क्रियान्वयन पर विनियम अनुच्छेद 5

xxix. गुआंगडांग प्रोविंस में विशेष आर्थिक जोनों पर विनियम

xxx. विकासशील ह्यनान आईलैंड में निवेश के प्रोत्साहन के संबंध में राज्य परिषद के उपबंध

कार्यक्रम 47: सेज और अन्य नामोदृष्टि क्षेत्रों में निगमित आयकर छूट और / या कमी-

xxxi. चीन जनवादी गणराज्य के उद्यम आयकर कानून 2008 का अनुच्छेद 28.2

xxxii. राज्य परिषद द्वारा चीन जनवादी गणराज्य के उद्यम आयकर कानून के क्रियान्वयन पर विनियमों का अनुच्छेद 93

xxxiii. वित्त मंत्रालय, राज्य कराधान प्रशासन, संसाधनों के विस्तृत उपयोग पर राज्य विकास और सुधार आयोग ने निगमित आयकर सूचीपत्र (2008 संस्करण) की घोषणा की नोटिस (कै शूई (2008) संख्या 116) और (कै शूई 2008 संख्या 117) (2008)।

xxxiv. विदेशी निवेश वाले उद्यमों और विदेशी उद्यमों के लिए चीन जनवादी गणराज्य का आयकर कानून (कर कानून)

xxxv. राज्य परिषद ने परिपत्र गुओ फा (2014) संख्या 14 (2014) जारी किया

xxxvi. राज्य परिषद निगमित आयकर का अनुच्छेद 57 नोटिस 40

xxxvii. चीन जन. गण. के अध्यक्ष की 2007 की डिक्री संख्या 516

xxxviii. चीन जन. गण. की राज्य परिषद की 2007 की डिक्री संख्या 516

xxxix. राज्य परिषद ने परिषद गुओ फा (2014) संख्या 14 (2014) जारी किया

ख. जीओसी / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

266. प्रपत्र जी/एससीएम/एन/235/सीएएन-2012, यूएस- कार्बन और कुच्छ विशेष अलॉय स्टील वायर रॉड, यूएस- सोडियम नाइट्रोट में, चीन जनगण जांच शुरूआत जांच सूची और जी/एससीएम/एन/123/सीएचएन-2006 कानूनी आधार का निर्माण नहीं करते।

267. द्वितीय, जीओसी ने कर सुधार आरंभ किया, जिसे 2008 में चीन जन. गण. में लागू किया गया। 2008 से पूर्व चीन जनगण कानून में एफआईई को प्रयोज्य/अधिमान्य कर नीतियों की व्यवस्था की गई है।

268. 16 मार्च, 2007 को, जीओसी ने पीआरसी का उद्यम आयकर कानून ("ईआईटीएल") जारी किया, जो एफआईई सहित चीन जनगण में सभी उद्यमों पर लागू है। यह कानून 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया था।

269. नए कर कानून में दो प्रमुख परिवर्तन किए गए: (1) एफआईई के लिए अधिमान्य आयकर नीतियों को समाप्त किया गया और घेरेलू उद्यमों और एफआईई के लिए एक समान कर दर लागू की गई; (2) स्थानीय विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अधिमान्य आयकर नीतियों समाप्त कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य परिषद ने यह निर्धारित करते हुए उद्यम आयकर के संबंध में ट्रांसजीशनल अधिमान्य नीतियों के क्रियान्वयन पर नोटिस जारी किया कि 1 जनवरी, 2008 को, जो उद्यम पहले निम्न कर दरों की अधिमान्य नीतियों का लाभ उठा रहे थे, वे ईआईटीएल के क्रियान्वयन के पश्चात 5 वर्षों के भीतर सांविधिक कर दर का लाभ उठाने के अध्यधीन क्रमशः पारगमन करेंगे। इस प्रकार, यहां तक कि वे उद्यम जो पिछले आयकर कानून के तहत अधिमान्य कर नीतियों का लाभ उठा रहे थे, अब 2012 के अंत से इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

270. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रेसीडेंट के आदेश संख्या 45, दिनांक 9 अप्रैल, 1991 को 1 जनवरी, 2008 के बाद से चीन जनवादी गणराज्य के उद्यम आयकर कानून (प्रेसीडेंट आदेश संख्या 63, दिनांक 16 मार्च, 2007) के तहत समाप्त किया गया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि राज्य परिषद के आदेश संख्या 85 दिनांक 30 जून, 1991 को राज्य परिषद द्वारा चीन जनवादी गणराज्य के उद्यम आयकर कानून के क्रियान्वयन पर विनियमों के अंतर्गत समाप्त किया गया था (राज्य परिषद आदेश संख्या 512)।

271. इसी समय, राज्य परिषद में "उद्यम आयकर (गुओ फा (2007) संख्या 39 के संबंध में परिवर्ती अधिमान्य नीतियों के क्रियान्वयन पर राज्य परिषद का नोटिस" भी जारी किया जिसके अनुसार पूर्ववर्ती कर कानून प्रशासनिक विनियम और दस्तावेजों के तहत उद्यम आयकर के संबंध में अधिमान्य नीतियों का लाभ उठाने वाले उद्यमों को छूट अवधि प्रदान की गई है; कार्यक्रम 47 (क्रम संख्या 1), 45 (क्रम संख्या 2 और 14), 40 (क्रम संख्या 3) 44, (क्रम संख्या 5) 46, (क्रम संख्या 11 और 13), 38 (क्रम संख्या 19) उद्यम आयकर परिवर्ती अधिमान्य नीति के क्रियान्वयन के लिए सारणी में सूचीबद्ध थे।

272. वित्त मंत्रालय और कराधान के राज्य प्रशासन का उद्यम आयकर अधिमान्य नीतियों (साई शूई (2009) संख्या 69) संबंधी परिपत्र गुओ फा (2007) संख्या 39 से संबंधित बहुत से मुद्रों को और स्पष्ट करता है। तथापि, उल्लिखित कार्यक्रमों से कोई मुद्रा संबंधित नहीं था।

273. गुओ शूई फा (1995) संख्या 139 को प्रौद्योगिकी गहन और जानकारी गहन परियोजनाओं (गुओ शूई फा (2003) संख्या 135) दिनांक 7 नवंबर, 2003 के संबंध में विदेशी निवेश वाले उद्यमों पर लागू कर अधिमान्य नीति के संबंध में कराधान राज्य प्रशासन के परिपत्र से प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे बदले में कराधान के राज्य प्रशासन के आछ्यापन संख्या 2(2011) द्वारा निरस्त किया गया।

274. इसी प्रकार, गुओ शूई फा (1993) संख्या 9 और गुओ फा (2000) संख्या 37 ने प्रेसीडेंट आदेश संख्या 45 और राज्य परिषद ओदेश संख्या 85 के उपबंधों को क्रियान्वित किया। तथापि, चूंकि प्रेसीडेंट आदेश संख्या 45 और राज्य परिषद आदेश संख्या 85 को 1 जनवरी, 2008 को समाप्त कर दिया गया, गुओ शूई फा (1993) संख्या 9 और गुओ फा (2000) संख्या 37 अमान्य बने रहे।

275. अपनी जांच के दौरान प्राधिकारी ने पाया कि कै शूई (2010) संख्या 65 और कै शूई (2014) संख्या 59 ऊपर उल्लिखित कार्यक्रमों से संबंधित नहीं थे।

276. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने विधि आधारित परिपत्र 115- अक्टूबर, 2009 का कानून पाठ उपलब्ध नहीं कराया। इसलिए, प्राधिकारी इस प्रपत्र के संबंध में कोई निर्धारण करने की स्थिति में नहीं है।

277. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि 2008 के पूर्व, चीन जनगण ने उद्यम आयकर पर चीन जनवादी गणराज्य के अनंतिम विनियमों को क्रियान्वित किया है, जो चीन जन. गण. के भीतर विदेशी निवेशित उद्यमों ("एफआईई") के अतिरिक्त सभी उद्यमों पर लागू थे। चीन जन. गण. ने पृथक रूप से विदेशी निवेश वाले उद्यमों और विदेशी उद्यमों के लिए पीआरसी के आयकर कानून को क्रियान्वित किया, जिसमें एफआईई पर बहुत सी अधिमान्य कर नीतियां लागू थीं। 16 मार्च, 2007 को, जीओसी ने पीआरसी का उद्यम आयकर कानून जारी किया ("ईआईटीएल") जो एफआईई सहित चीन जन. गण. में सभी उद्यमों पर प्रयोज्य था। यह कानून 1 जनवरी, 2008 से क्रियान्वित किया गया। नए कर कानून में दो प्रमुख परिवर्तन थे; (i) एफआईई के लिए अधिमान्य आयकर नीतियों को समाप्त कर दिया गया है और एक समान कर दर घरेलू उद्यमों और एफआईई के लिए लागू की गई है; (ii) स्थानीय विशेष आर्थिक जोनों के लिए अधिमान्य आयकर नीतियों को समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य परिषद ने यह निर्धारित करते हुए उद्यम आयकर के संबंध में परिवर्ती अधिमान्य नीतियों के क्रियान्वयन पर नोटिस जारी किया कि 1 जनवरी, 2008 को वे उद्यम जो पहले निम्न कर दरों की अधिमान्य नीतियों का लाभ उठा रहे थे, क्रमशः ईआईटीएल के क्रियान्वयन के पश्चात 5 वर्षों के भीतर सांविधिक कर दर का लाभ उठाने के लिए ट्रांसजिट करेंगे। इसलिए, वे उद्यम भी जो पुराने आयकर कानून के तहत अधिमान्य कर नीतियों का लाभ उठा रहे थे, 2012 के अंत से अब इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

278. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां कुछ प्रपत्र ऊपर उल्लिखित कार्यक्रम के संगत नहीं थे, वहीं अन्य प्रपत्र भी अब प्रवृत्त नहीं रहे थे। इस प्रकार, किसी भी टायर उत्पादक / निर्यातक जिसने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया था, इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

279. इसलिए, प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।

(xix) कार्यक्रम संख्या: 43 अग्रिम प्रौद्योगिकी वाले एफआईई के लिए आयकर कटौती

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा निवेदन

280. अग्रिम प्रौद्योगिकी वाले एफआईई छूट और कटौती के समाप्त हो जाने के पश्चात की अवधि में 50 प्रतिशत आयकर छूट का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं। कार्यक्रम की विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं या योजना दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं –

- उद्यम आयकर अधिमान्य नीतियों पर वित्त मंत्रालय और कराधान के राज्य प्रशासन का परिपत्र (कै शूई (2009) संख्या 69)
- कै शूई (2015) संख्या 37)
- सूचीपत्र – उद्यम आयकर अधिमान्य नीतियों, 2015 पर वित्त मंत्रालय और कराधान के राज्य प्रशासन के परिपत्र। याचिकाकर्ता ने यह भी इंगित किया है कि पीयूसी उत्पादक जैसे केंडा रवड़ (चीन) कंपनी लि० ने संभवतः इस कार्यक्रम से लाभ उठाया हो।

ख. जीओसी / अन्य हिबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

281. याचिकाकर्ता ने याचिका में उल्लिखित अधिसूचना का कानूनी पाठ उपलब्ध नहीं कराया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

282. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कै शूई (2009) संख्या 69 का कानूनी आधार इस कार्यक्रम के संगत नहीं हैं।

283. कै शूई (2015) संख्या 37 उद्यमों और सरकारी संस्थानों के परिवर्तन और पुर्नसंरचना का और समर्थन करने से संबंधित था और न कि कार्यक्रम 43 को। याचिकाकर्ताओं ने उद्यम आयकर अधिमान्य नीतियों, 2015 पर वित्त मंत्रालय और कराधान के राज्य

प्रशासन के परिपत्र का कानूनी पाठ उपलब्ध नहीं कराया। जांच की अवधि के दौरान, प्राधिकारी भी कथित कार्यक्रम के लिए संगत कानूनी आधार को पहचान करने में असफल रहे हैं।

284. चीन जनगण से प्रतिभागी उत्पादकों में से किसी ने भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने यह दर्शने के लिए भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं कि चीन जनगण में टायर उत्पादकों, जिन्होंने भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है।

285. इसलिए, यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि कथित कार्यक्रम विद्यमान है।

286. इसलिए, प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि कथित समिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए।

(xx) कार्यक्रम संख्या: 48 सेज और अन्य नामोदिष्ट क्षेत्रों में आयातित सामग्री और उपकरणों पर टैरिफ और मूल्य वर्धित कर दूटे

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

287. एफआईआई और कुछ विशेष घरेलू उद्यम दोनों तब तक अपने उत्पादन में प्रयुक्त आयातित उपकरणों पर वैट और टैरिफ से छूट प्राप्त हैं जब तक कि उक्त उपकरण अपात्र मदों की निर्धारित सूची में नहीं आता। प्रोविशियल शाखा उन उद्यमों को प्रमाण पत्र प्रदान करती है, जो छूट प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है और इसका उद्देश्य विदेशी अग्रिम प्रौद्योगिकी वाले उपकरणों को आंतर्भ करना और उद्योग प्रौद्योगिकी वाले उपकरणों को प्रस्तुत करना और उद्योग प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना है। कार्यक्रम की विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं या योजना दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं –

- आयात उपकरणों पर कर नीतियों के समायोजन पर राज्य परिषद का परिपत्र (गुओ फा संख्या 37)
- वेब अनुसंधान- कर छूट और कमी
- वेब अनुसंधान- व्यापार विनियम, सीमा शुल्क और मानक
- चीन जन. गण. के कर कानून

ख. जीओसी / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

288. जीओसी ने कहा है कि गुओ फा संख्या 37 के अतिरिक्त, बाकी दस्तावेज कानूनी आधार स्थापित नहीं करते।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

289. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुओ फा (1997) संख्या 37 आयातित सामग्रियों और उपकरणों के लिए टैरिफ और आयात स्तरीय मूल्य वर्धित कर पर छूट से संबंधित है। आयातित सामग्री पर कर लाभ का पहले ही कार्यक्रम 35 में मूल्यांकन किया गया है।

290. किसी अन्य कानूनी आधार की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी यह आकलन करने में असमर्थ है, क्या कार्यक्रम में राजस्व पूर्वानुमान के रूप में वित्तीय योगदान के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, पीओआई के दौरान इस कार्यक्रम के तहत प्रतिभागी टायर उत्पादकों में से किसी ने भी लाभ प्राप्त नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने यह दर्शने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि चीन जन. गण. में टायर उत्पादक, जिन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है, ने इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है। जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी भी इस तथ्य के समर्थन में साक्ष्य की पहचान नहीं कर सके कि चीन जन. गण. में टायर उत्पादकों, जिन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया था, इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है।

291. अतः प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लागू किया जाना चाहिए।

(xxi) कार्यक्रम संख्या 49 पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमान्य आयकर नीति

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा निवेदन

292. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उक्त कार्यक्रम के तहत, चीन जन. गण. के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित उद्यम अचल परिसंपत्तियों की खरीद से जुड़े त्वरित मूल्य ह्रास और परिशोधन व्ययों की कटौती के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम की विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं या योजना दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं—

- उत्तर पूर्व के पुराने औद्योगिक ठिकानों में परिसंपत्ति मूल्य ह्रास और परिशोधन नीति की क्रियान्वयन क्षमता पर वित्त मंत्रालय और कराधान के राज्य प्रशासन का नोटिस (कै शूई (2005) संख्या 17)।
- उत्तर पूर्व चीन में पुराने औद्योगिक ठिकानों को खोलने की प्रोन्नति को क्रियान्वित करने पर राज्य परिषद के सामान्य कार्यालय की राय। (गुओ वान फा (2005) संख्या 36)
- उत्तर पूर्व चीन सहित पुराने औद्योगिक ठिकानों का पुनरुद्धार करने की कार्य नीति को और क्रियान्वित करने पर राज्य परिषद की राय (गुओ फा (2009) संख्या 33)
- उत्तर पूर्व चीन के पुराने औद्योगिक ठिकानों में उद्यमों के कर बकाया पर छूट देने पर वित्त मंत्रालय और कराधान पर राज्य प्रशासन का नोटिस (कै शूई (2006) संख्या 167)

तथापि, याचिकाकर्ताओं ने यह भी इंगित किया है कि केवल उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित टायर कंपनियां ही इस कार्यक्रम के लिए पात्र थीं।

ख. जीओसी / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

293. जीओसी ने स्पष्ट किया है कि मद (1) को समाप्त और अमान्य वित्त प्रावधानों और विनियामक दस्तावेजों (11वां सेट) दिनांक 21 जनवरी, 2011 की सूची के आध्यापन पर वित्त मंत्रालय के निर्णय के तहत समाप्त किया गया था। मद (2) और (3) कार्यक्रम के संगत नहीं थे। इसके अतिरिक्त, याचिका में कोई कानूनी पाठ संलग्न नहीं था। पूरी तरह सहयोग करने के लिए, जीओसी ने इस कार्यक्रम के लिए कानूनी पाठ की पहचान की और इसे जांच पड़ताल दल को उपलब्ध कराया और इसे सत्यापन प्रदर्शन का भाग बनाया गया।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

294. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कै शूई (2005) संख्या 17 को 21 फरवरी, 2011 को समाप्त और अमान्य वित्त प्रावधानों ओर विनियामक दस्तावेजों (11वां सेट) की सूची के आध्यापन पर वित्त मंत्रालय के निर्णय के द्वारा समाप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, गुओ वान फा (2005) संख्या 36, कै शूई (2006) संख्या 167 और गुओ फा (2009) संख्या 33 कार्यक्रम से संबंधित नहीं था।

295. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कार्यक्रम को वास्तव में उत्तर पूर्व चीन (गुओ शूई हान (2005) संख्या 823) में पुराने औद्योगिक ठिकाने को पुर्नजीवित करने के लिए उद्यम आयकर अधिमान्य नीतियों को लागू करने की संभावना के बारे में कराधान के राज्य प्रशासन के नोटिस के तहत अभिशासित किया गया था। तथापि, विनियमको दिनांक 4 जनवरी, 2011 के राज्य प्रशासन के आध्यापन संख्या 2 (2011) के तहत समाप्त किया गया था। प्राधिकारी किसी अन्य कानूनी आधार को चिन्हित करने में असफल रहे हैं, जिसमें इस कार्यक्रम की विद्यमानता के लिए व्यवस्था की गई है और जो अभी भी प्रवृत्त है।

296. इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रतिभागी टायर उत्पादक ने पीओआई के दौरान इस व्यथित कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने यह दर्शने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि चीन जन. गण. में टायर उत्पादकों, जिन्होंने जीओआई के दौरान संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया था, इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है। जांच की अवधि के दौरान, प्राधिकारी समर्थन में किसी साक्ष्य की पहचान भी नहीं कर सके हैं कि चीन जन. गण. में टायर उत्पादक जिन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है, इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है।

297. अतः प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए।

(xxii) कार्यक्रम संख्या 50: केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्र के लिए कर रियायत

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

298. चीन जन. गण. के केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों में कंपनियों को आमतौर पर प्रयोज्य 25 प्रतिशत की तुलना में 15 प्रतिशत की एक अधिमान्य आयकर दर उपलब्ध थी। कार्यक्रम की विद्यमानता के साक्ष के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं या योजना दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं जो उनके पास यथोचित रूप से उपलब्ध थे –

- i. गुओ फा (2000) संख्या 33
- ii. कै शूई (2001) संख्या 202
- i. कै शूई (2011) संख्या 58
- ii. एसएटी – सीआईटी पर पश्चिमी विकास कार्य नीति का गहन कार्यान्वयन
- iii. चीन द्वारा पश्चिमी क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित – 2012
- iv. केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश मार्ग निर्देश
- v. केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्र में निवेश - 2000
- vi. कराधान का राज्य प्रशासन – 2012
- vii. पश्चिमी चीन विकास कार्य नीति – 2013
- viii. चीन द्वारा पश्चिमी क्षेत्रों में कर प्रोत्साहनों का विस्तार
- ix. कराधान का राज्य प्रशासन – 2015 “पश्चिमी क्षेत्र में विकास के लिए प्रोत्साहित उद्योगों की सूचीपत्र” के क्रियान्वयन में संबंधित उद्यम आयकर से संबंधित मुद्दों पर आध्यात्मन” (कै शूई (2015) संख्या 14)।

299. याचिकाकर्ताओं ने पात्र सत्ताओं के रूप में निम्नलिखित नाम उपलब्ध कराए हैं – आयोलन टायर कंपनी लि०, हाओयू टायर कंपनी लि०, डबल स्टार – डांगफेंग टायर कंपनी लि०, एंशी जी लांग ट्रेडिंग कंपनी लि०, पश्चिमी चीन में टायर उत्पादक चांगकिंग किंगसू साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लि०, चांगकिंग लानपो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लि०, चांगकिंग लानपो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लि०, चांगकिंग जुनडांग ट्रेड कंपनी लि०, चेंग वाओलिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लि०, कुनमिंग संगदुओ ट्रेड कंपनी लि०, कुनमिंग मिंगवेन ट्रेडिंग कंपनी लि०, बाईवीजुआन ट्रेडिंग कंपनी लि०, काशी जिन शेंग सानली इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लि०।

ख. जीओसी / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निवेदन

300. याचिका में भारतीय घरेलू ने उद्योग इस कार्यक्रम के प्रति 12 कानूनी आधारों का उल्लेख किए हैं। जीओसी ने स्पष्ट किया है कि 3 कानूनी आधारों को समाप्त किया गया था, 5 कानूनी आधारों का कोई पाठ अथवा संगत दस्तावेज नहीं है। बकाया 4 कानूनी आधारों का संगत कानूनी पाठ है, लेकिन ये सभी पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित थे। पश्चिमी क्षेत्र में कुल 12 प्रोविंस शामिल थे। अर्थात् शाकसी, सिशुआन, युनान, गुर्जर, गुआनझी, गांसू, किंधाई, निंगजिया, जियान, जिनजियांग इनर मंगोलिया और चानकिंग। यह स्पष्ट किया गया है कि इन स्थानों पर कोई टायर विनिर्माता स्थित नहीं हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

301. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम को वास्तव में गुओ फा (2000) संख्या 33 के तहत अभिशासित किया गया था, जो अभी भी मान्य है। क्षेत्र, जिनमें पश्चिमी क्षेत्र के विकास पर नीतियां प्रयोज्य हैं, में शांगकिंग म्युनिसिपेलिटी, सिशुआन प्राविंस, गुर्जर आओ प्राविंस, युनान प्रोविंस, तिब्बत स्वयत्त क्षेत्र, शंगझी प्रोविंस, गंसू प्रोविंस, दिजियांग युईगुर स्वायत्त क्षेत्र, आंतरिक मंगोलिया इस स्वायत्त क्षेत्र और गुआनझी शुआंग, स्वायत्त क्षेत्र शामिल हैं।
302. कै शूई (2015) संख्या 14 द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में प्रोत्साहित उद्योगों के प्रति निगमित आयकर को और विनियमित किया गया और व्यवस्था की गई कि वे 15 प्रतिशत की अधिमान्य आयकर दर को जारी रखेंगे।
303. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम की विगत में अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा पहले भी जांच की गई है और इस कार्यक्रम का विद्यमानता और प्रतिकारिता की स्थापना की गई है। उदाहरण के लिए आर्गेनिक कोटेड पेपर की ईयू प्राधिकारियों द्वारा।

304. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी टायर विनिर्माता, जिन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया था, पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित नहीं था। जांच की अवधि के दौरान, प्राधिकारी भी यह पहचान नहीं कर सके कि कोई टायर उत्पादक, जिसने जीओआई के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया था, इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है।

305. इसलिए, प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि इस कार्यक्रम के प्रति प्रतिकारी शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए।

II.क. चीन जन. गण. से प्रतिशागी उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्राप्त कर कार्यक्रम

(i) झोंगसी रबड़ गृप कंपनी लि०

306. प्राधिकारी ने झोंगसी रबड़ गृप कंपनी लि० द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन किया और कर प्रोग्रामों के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया, जिसके लिए पीओआई के दौरान लाभ प्राप्त किया गया अथवा प्रोद्भूत किया गया था। प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि सभी कर कार्यक्रमों का परिणाम राजस्व पूर्वानुमान के रूप में वित्तीय अंशदान के प्रावधान के रूप में हुआ। सिब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी थे, क्योंकि उन्होंने झोंगसी रबड़ सहित कुछ विशिष्ट उद्यमों को लाभ प्रदान किया।

307. नीचे दी गई सारणी में कर कार्यक्रमों और तदनुरूपी सब्सिडी मार्जिन के नामों की व्यवस्था की गई है –

अनुदान कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण / टिप्पणियां	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेज %
कार्यक्रम संख्या 27: याचिका के अनुसार-अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्ययों की कटौती के लिए कर नीतियां	जहां किसी उद्यम ने नये प्रौद्योगिकियों, नये उत्पादों और नई प्रक्रियाओं के विकास में अनुसंधान विकास व्यय उपगत किया है। किंतु अमूर्त संपत्तियों का भी गठन किया जाना और वर्तमान अविधि के लिए लाभ और हानि में शामिल किया जाना है, अनुसंधान और विकास व्ययों के 50 प्रतिशत की वास्तविक कटौती के आधार पर कटौती की जाएगी, जहां अमूर्त परिसंपत्तियों का गठन किया गया है, अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत के 150 प्रतिशत को परिशोधित किया जाएगा।	****	0-5%

(ii) शानडांग वांडा बोटो टायर कंपनी लि०

308. वांडा बोटो ने पीओआई के दौरान कर कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

(iii) शानडांग योंगफेंग टायर्स कंपनी लि०

309. शानडांग योंगफेंग टायर्स कंपनी लि० द्वारा प्राप्त कर कार्यक्रमों को नीचे दी गई सारणी में नोट किया गया है-

अनुदान कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण / टिप्पणियां	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेज %
कार्यक्रम 33: विशेष उपकरण के क्रय के संबंध में कर क्रेडिट	ईआईटीएल के अनुच्छेद 34 में निर्धारित किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा और जल बचत, कार्य सुरक्षा, आदि की खरीद में किसी उद्यम के निवेश की राशि को एक विशिष्ट दर पर कर राशि से घटाया जा सकता है।	****	0-5%

(iv) द्राईएंगल टायर कंपनी लि०

310. द्राईएंगल टायर द्वारा प्राप्त कर कार्यक्रम नीचे सारणी में नोट किया गया है –

अनुदान कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण / टिप्पणियां	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
कार्यक्रम 31: अधिमान्य आयकर दर	उच्च और नई प्रौद्योगिकी उद्यम के लिए अधिमान्य आयकर दर	****	0-5%

(v) आयोलस टायर कंपनी लि०

311. नीचे सारणी में कर कार्यक्रम और तदनुरूपी सब्सिडी मार्जिन उपलब्ध कराए गए हैं-

कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त तथ्य	सब्सिडी मार्जिन	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
कार्यक्रम 31: उन कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां / आयकर कटौतियां जिन्हें उच्च और नवीन प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के रूप में पहचाना गया है।	कंपनी को सरकारी तौर पर एक नए हाई-टेक उद्यम के रूप में पहचाना गया है।	****	0-5%

(vi) येलो सी रबड़ कंपनी लि०

312. येलो सी रबड़ कंपनी लि० ने पीओआई के दौरान कर कार्यक्रमों के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

II. ख. कर कार्यक्रमों का सार

313. प्राधिकारी ने सहयोगी पक्षकारों के लिए उच्चतम सब्सिडी मार्जिनों पर आधारित सभी अन्य दरों को निर्धारित किया है -

कंपनी का नाम	अनुदान के लिए सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
जोंगसी रबड़ ग्रुप कंपनी लि०	****	0-5%
ट्राइएंगल टायर कंपनी लि०	****	0-5%
शानडांग योंगफेंग टायर्स कंपनी लि०	****	0-5%
आयोलास टायर कंपनी लि०	****	0-5%
सभी अन्य	****	0-5%

III. अधिमान्य ऋण के रूप में चिह्नित कार्यक्रम

(i) कार्यक्रम संख्या 51 ऋण संबंधी सरकारी नीति लैंडिंग

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

314. स्टील उत्पादकों ने चीनी स्टील उद्योग के विस्तार को समर्थन और विकास करने के लिए जीओसी नीति के अनुसरण में राज्य स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंक और सरकारी बैंकों से निम्न (सब्सिडाइज्ड) व्याज दरों से लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम की विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं या योजना दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं जो उनके पास यथोचित रूप से उपलब्ध थे -

- i. “औद्योगिक संरचना समायोजन को प्रोन्ति करने पर अस्थायी प्रावधान” के प्रख्यापन और कार्यान्वयन पर राज्य परिषद का निर्णय (गुआंग फा (2005) संख्या 40)

- ii. वाणिज्यिक बैंकिंग कानून के अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 38
- iii. आदेश संख्या 35 के अनुच्छेद 16,24 और 25 – लौह और स्टील उद्योग के विकास के लिए नीतियां।
- iv. उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 2012 के उद्योग स्थानांतरण मार्गदर्शन सूचीपत्र मुख्य और अग्रिम उद्योगों जैसे स्टील उद्योग का अधिमान्य ऋण के जरिए समर्थन करता है।
- v. औद्योगिक संरचना (निर्देशिका सूचीपत्र) के पुर्णसमायोजन पर निर्देशिका सूचीपत्र – 2005 और 2011
- vi. राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मार्ग निर्देश (2006-2010) (11वीं पंचवर्षीय योजना)
- vii. यिन फा (2003) संख्या 50
- viii. यिन फा (2004) संख्या 251
- ix. “प्रमुख आधारभूत उद्यमों के लिए वित्तीय समर्थन में वृद्धि” करते के लिए स्टील उद्योग (2009) के समायोजन और पुनरोद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराया गया ब्लू प्रिंट –

टायर उत्पादकों जैसे आयोलस, डबल कॉयन, सेलुन और गुर्दा झाओ टायर ने संभवतः इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है।

ख. जीओसी / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- 315. जीओसी ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने केवल गुओ फा (2005) संख्या 40 का कानूनी पाठ उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, “टायर इंडस्ट्री एक्सेस कंडीशन्स” को प्रकाशित करने के लिए अनुच्छेद एमआईटीटी और वार्षिक रिपोर्ट कानूनी आधार को स्थापित नहीं करते।
- 316. याचिका में उपलब्ध कराए गए कानूनी आधार की सूची के आधार पर, यह स्पष्ट है कि कार्यक्रम केवल स्टील उद्योग पर लागू है। याचिकाकर्ता स्वयं नोट करते हैं कि स्टील उद्योग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 317. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका में उपलब्ध कराए गए सभी कानूनी आधार स्टील उद्योग से संबंधित हैं। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
- 318. तथापि, जांच की अवधि के दौरान, प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि चीन जन. गण. से कुछ विशिष्ट प्रतिभागी निर्यातकों ने राज्य स्वामित्व वाले बैंकों से अधिमान्य ऋण के रूप में लाभ प्राप्त किया है। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि ऐसे अधिमान्य ऋण का परिणाम निधियों के सीधे स्थानांतरण के रूप में वित्तीय योगदान में हुआ है। प्राधिकारी ने पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना) द्वारा दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण पर निर्धारित वाणिज्यिक बैंचमार्क ब्याज दर की ऋण प्राप्त करने वाले निर्यातक से राज्य स्वामित्व वाले बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दर की तुलना द्वारा ऐसे अधिमान्य ऋण के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क निर्धारित किया है। लाभ को इन दोनों राशियों के बीच के अंतर के आधार पर परिकलित किया गया था।

(ii) कार्यक्रम संख्या 52: एसओई के अधिमान्य ऋण

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

- 319. यह दावा किया गया कि इस कार्यक्रम के तहत एसओई ने राज्य स्वामित्व वाले वाणिज्यिक या नीति निर्धारक बैंकों के जरिए अधिमान्य ऋण प्राप्त किए। कार्यक्रम की विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं या योजना दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं-
 - i. विदेशी मुद्रा के नियांत संग्रहणों की जांच में अनंतिम विनियमों के संबंध में पुरस्कार और दंड पर विस्तृत नियमों के मुद्रण और वितरण के संबंध के चाइना जन. गण. बैंक ऑफ चाइना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इकानॉमिक सहयोग और कराधान का राज्य प्रशासन के परिपत्र- यिन फा (2000) संख्या 58
- 320. यह दर्शाया गया है कि पीयूसी उत्पादकों जैसे जियामन पेनाविको लाजिस्टिक कंपनी लिं०, डबल स्टार डांगफेंग टायर कंपनी लिं०, जूझाओ जूगांग टायर कंपनी लिं०, आयोलस टायर कंपनी लिं०, किंगडाओ डबल स्टार टायर इंडस्ट्रीयल कंपनी लिं०,

द्राइंगल टायर कंपनी लि०, शिफेंग डबल स्टार टायर कंपनी लि०, शानडांग टाइशान आयर कंपनी लि०, चीन शिपविलिंग ट्रेडिंग (शंघाई) कंपनी लि०, शंघाई टायर एंड रबड कंपनी लि० ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है।

ख. जीओसी / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

321. जीओसी ने कहा है कि कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया था।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

322. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम को विदेशी मुद्रा के निर्यात संग्रहणों की जांच की तुलना में अनंतिम विनियमों के संबंध में पुरस्कार और दंडों पर विस्तृत नियमों के तहत अभिशासित किया गया था (यिन फा (2000) संख्या 58) इसे विदेशी मुद्रा के संग्रहण की जांच पर अनंतिम विनियमों के पुरस्कार और दंड पर संवितरण के परिपत्र को निरस्त करते हुए पीपल्स बैंक आफ चाइना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फारेन एक्सचेंज, वाणिज्य मंत्रालय और कराधान के राज्य प्रशासन के आख्यापन के जरिए समाप्त किया गया था।

323. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संगत दस्तावेज अब लागू नहीं था। तथापि, जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि चीन जन.गण. से कतिपय भागीदार निर्यातिकों को राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अधिमानी ऋण के रूप में लाभ मिला। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि ऐसे अधिमानी ऋण के परिणामस्वरूप निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में वित्तीय योगदान मिला। प्राधिकारी ने निर्यातिकों से राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज दर की तुलना पीपल बैंक ऑफ चाइना (चीन का केन्द्रीय बैंक) द्वारा दीर्घावधिक और अलावाधिक ऋण पर विहित वाणिज्यिक बैंच मार्क, ब्याज दर के साथ करके ऐसे अधिमानी ऋण के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित किया है। इसका लाभ इन दो राशियों के बीच अंतर के आधार पर परिकलित किया गया था।

(iii) कार्यक्रम संख्या 53: निर्यातोन्मुख उद्यमों के लिए क्षृत प्राप्त ऋण और निर्यात ऋण ब्याज पर समिडीज

(iv) कार्यक्रम संख्या 54: टायर उद्योग को अधिमान्य ऋण और ब्याज दर

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

324. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि राज्य स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों ने निर्यातों के लिए अधिमान्य ऋण उपलब्ध कराए हैं।

- i. फुजीयन प्रोविंस लौह एवं स्टील इंडस्ट्री और अलौह धातु उद्योग समायोजन और पुनरुद्धार कार्यान्वयन योजना (2009-2011)
- ii. शांकसी ताइगांग स्टेनलेस स्टील कंपनी लि० की 2012 की वार्षिक रिपोर्ट
- iii. 2013 – दि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, निंगबो शाखा का भर्ती नोटिस
- iv. लौह और स्टील उद्योग का 12वीं पंचवर्षीय विकास योजना के मुद्रण और संवितरण पर उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी का परिपत्र (गांग जिन गुई (2011) संख्या 480)
- v. उच्च गुणवत्ता वाले विशेषतः स्टील विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास 12वीं पंचवर्षीय विशेष योजना के मुद्रण और संवितरण पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिपत्र (2012)
- vi. सरकारी औद्योगिक नीतियों को पूरा करने के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों (2003) पर चीन जन. गण. के कानून का आदेश 47 – अनुच्छेद 34
- vii. वित्तीय संस्थानों के ऋण ब्याज दर नीति के विस्तार के संबंध में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का परिपत्र (यिन फा (2003) संख्या 250)
- viii. चीनी बैंकों की वार्षिक रिपोर्टें, जो या तो जीओसी द्वारा प्रस्तुत की गई थी अथवा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी, चीन के बैंकिंग क्षेत्र पर 2006 ड्यूश बैंक द्वारा किए गए अनुसंधान से प्राप्त सूचना, चीन पर डब्ल्यूटीओ नीति पुनरीक्षा (2010 और 2012), चीन 2030 विश्व बैंक रिपोर्ट।
- ix. जमा राशि और ऋणों पर ब्याज दरों को समायोजित करने से संबंधित मुद्दों पर पीबीओसी का परिपत्र – (यिन फा (2004) संख्या 251)
- x. एनडीआरसी आदेश संख्या 35 – लौह और स्टील उद्योग के विकास के लिए नीतियां

xii. ओईसीडी 2010 इकोनॉमिक सर्वे ऑफ चाइना, फरवरी, 2010 (देखें अध्याय 3, पृष्ठ 71, 73-81,97)

xiii. ओईसीडी चीन का वित्तीय क्षेत्र सुधार, आर्थिक विभाग कार्य पत्र संख्या 747, इसीओ / डब्ल्यूकेपी (2010)3, 1 फरवरी, 2010 (देखें पृष्ठ 2,8-15,36)।

325. याचिकाकर्ताओं ने यह भी इंगित किया है कि उत्पादक जैसे वियामन पेनविको लाजिस्टिक कंपनी लि०, फुजियान प्रोविंस कंपनी लि०, जियांगसू प्रोविंस, आयोलस टायर कंपनी लि०, हेनान प्रोविंस, किंगडाओ डबल स्टार टायर इंडस्ट्रीयल कंपनी लि०, शानडांग प्रोविंस, ट्राइएंगल टायर कंपनी लि०, शानडांग प्रोविंस, चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग (शंघाई) कंपनी लि०, शंघाई म्युनिसिपेलिटी, शंघाई टाइप एंड रबड कंपनी लि०, शंघाई म्युनिसिपेलिटी, शिहुआन टायर एंड रबड कंपनी लि०, शिहुआन प्रोविंस ने संभवतः इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है।

घ. जीओसी / अन्य हिबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

326. जीओसी ने कहा है कि वार्षिक रिपोर्ट, 2013, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, निंगबो ब्रांच को भर्ती नोटिस और ओईसीडी रिपोर्ट कानूनी आधार को स्थापित नहीं करते।

327. फुजियान प्रोविंस लोह और स्टील उद्योग और अलोह धातु उद्योग समायोजन और पुनरुद्धार कार्यान्वयन योजना (2009-2011), लौह और स्टील उद्योग की 12वीं पंचवर्षीय विकास योजना के मुद्रण और वितरण पर उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिपत्र (गांग जिन गुई (2011) संख्या 480) मुद्रण पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का परिपत्र और उच्च गुणवत्ता वाले विशेष स्टील विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का 12वीं पंचवर्षीय विशेष योजना के मुद्रण और वितरण पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिपत्र (2012) केवल स्टील उद्योग से संबंधित थे।

ड. प्राधिकारी द्वारा जांच

328. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम 53 में याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए कानूनी प्रपत्र केवल स्टील उद्योग से संबंधित थे। जहां यिन फा (2003) संख्या 250 वाणिज्यिक बैंकों को प्रयोज्य चल कार्य क्षेत्र को निर्धारित करने वाला विनियमन था। यिन फा (2004) संख्या 251 पीबीओसी द्वारा प्रकाशित बैंचमार्क ऋण ब्याज दर को निर्धारित करता है। तथापि, ये दोनों ही कार्यक्रम के संगत नहीं थे। डिक्री संख्या 40 यह उल्लेख नहीं करता कि टायर इंडस्ट्री को अधिमान्य ऋण और ब्याज दरें उपलब्ध कराए जाएंगे।

329. तथापि, जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि चीन जन.गण. से कतिपय भागीदार निर्यातकों को राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अधिमानी ऋण के रूप में लाभ मिला। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि ऐसे अधिमानी ऋण के परिणामस्वरूप निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में वित्तीय योगदान मिला। प्राधिकारी ने निर्यातकों से राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज दर की तुलना पीपल बैंक ऑफ चाइना (चीन का केन्द्रीय बैंक) द्वारा दीर्घावधिक और अलावधिक ऋण पर विहित वाणिज्यिक बैंच मार्क, ब्याज दर के साथ करके ऐसे अधिमानी ऋण के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित किया है। इसका लाभ इन दो राशियों के बीच अंतर के आधार पर परिकलित किया गया था।

IV. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम

(i) कार्यक्रम संख्या 55: निर्यात विक्रेता का ऋण

(ii) कार्यक्रम संख्या 56: निर्यात क्रेता का ऋण

(iii) कार्यक्रम संख्या 57: राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य निर्यात वित्तपोषण

(क) याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

330. घरेलू कंपनियां अपने निर्यात कार्यक्रम के अनुसार कुछ उत्पादों के निर्यात के लिए सरकारी बैंकों से वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा योजना से संबंधित दस्तावेज प्रदान किये हैं जो कि उन्हें उपयुक्त रूप से उपलब्ध थे-

- उच्च एवं नए प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यातों का समर्थन करने के संबंध में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक ऑफ चाइना का प्रपत्र, 1999, संख्या 210
- एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, निर्यात विक्रेताओं का ऋण 2012 वार्षिक रिपोर्ट
- निर्यात क्रेता का ऋण, वेबसाइट विशेषज्ञ

- iv. एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना की वेबसाइट
- v. डब्ल्यूटीओ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमावली, 2014 का चीन का अनुपालन
- vi. चीनी सरकार द्वारा निर्यात वित्तपोषण क्रियाकलाप, 2011

यह भी अनुरोध किया गया है कि यह कार्यक्रम अन्य जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रतिकारी माना गया है।

ख. चीन सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

331. चीन सरकार ने उल्लेख किया कि एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना की वार्षिक रिपोर्ट, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना की संक्षिप्त प्रस्तावना की वेबलिंक, गिरी की वार्षिक रिपोर्ट और याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अन्य सभी दस्तावेज कानूनी आधार नहीं बनाते।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

332. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने उच्च नये प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात के समर्थन में परिपत्र जारी किया (जिन चूंयन जी फा {1999} संख्या 210) जोकि अब भी प्रभावी है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 1 में उल्लेख है कि उच्च एवं नये प्रौद्योगिकी उत्पादों का क्षेत्र, जिसे समर्थन की आवश्यकता है, के संबंध में चीन के उच्च एवं नये प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात एवं आयातों की सूची के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि रेडियल टायर चीन के उच्च एवं नए प्रौद्योगिकी उत्पाद के रूप में सूचीबद्ध था।

333. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम 55 एवं 56 की जांच विगत में कुछ अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा पहले ही कर दी गई है और इस कार्यक्रम की मौजूदगी तथा प्रतिकारिता कुछ यात्री वाहनों और हल्के ट्रक टायरों तथा उपयोगी पैमाने के विंड टावरों में अमरीकी प्राधिकारी द्वारा सिद्ध की गई है।

334. जांच प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने नोट किया कि चीन जन. गण. के कुछ प्रतिभागी निर्यातकों ने राज्य स्वामित्व वाले बैंकों से अधिमान्य उधार के रूप में लाभ प्राप्त किया है। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि इस अधिमान्य उधार से निधियों के सीधे अंतरों के रूप में वित्तीय योगदान हुआ है। प्राधिकारी ने पीपिल्स बैंक ऑफ चाइना (सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना) द्वारा दीर्घावधि एवं अल्पावधि उधार के लिए निर्धारित वाणिज्यिक निर्धारण व्याज दर से ऋण प्राप्त करने वाले निर्यातक से सरकारी स्वामित्व वाले बैंक द्वारा लगाये जाने वाले व्याज दर की तुलना करके ऐसे अधिमान्य उधार के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क निर्धारित किया है। इन दोनों के दरों के बीच अंतर के आधार पर लाभ परिकलित किया गया था। प्राधिकारी ने अलग से यह पहचान नहीं कि है कि क्या सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा दिये गये ऋण निर्यात के लिए थे अथवा अन्य कारणों से थे।

(iv) कार्यक्रम संख्या 58 निर्यात ऋण बीमा समिस्डी

(v) कार्यक्रम संख्या 59 निर्यात ऋण गारंटी

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

335. याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया कि इस कार्यक्रम के तहत चीन सरकार ने चाइना एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अथवा सिनोश्योर को निर्यात के लिए चीनी उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची में सूचीबद्ध उत्पादों के निर्यात के लिए अपना समर्थन बढ़ाने हेतु निर्देश दिया। टायर उत्पादक निर्यात ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा स्कीम दस्तावेज प्रदान किए हैं।

- i. निर्यात ऋण बीमा का उपयोग करके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापार संबद्धन करने की कार्यनीति।
- ii. निर्यात के लिए चीनी उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची तथा अनुदित उद्धरण
- iii. चीन जन. गण. के वाणिज्य मंत्रालय, यांत्रिक, इलेक्ट्रानिक और उच्च प्रौद्योगिक विभाग (नेशनल मैकेनिक एंड इलेक्ट्रानिक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आफिस) की वेबसाइट और अनुदित उद्धरण
- iv. टायर उद्योग नीति जारी करने के संबद्ध में उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस (गोंग चान ये झेंग सी (2010) संख्या 2) तथा अनुदित उद्धरण
- v. औद्योगिक संरचना समायोजन के लिए मार्गदर्शी सूची के कुछ प्रावधानों में संशोधन के संबंध में चीन जन. गण. के एनडीआरसी और सुधार आयोग के आदेश (2011) की संख्या 21 (फरवरी 2013)
- vi. वाणिज्य मंत्रालय तथा चाइना एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस, सांग जी फा (2004) संख्या 368

ख. चीन सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

336. चीन सरकार ने उल्लेख किया कि व्यापार एवं वेबपेज का समर्थन करने की कार्यनीति कानूनी आधार नहीं था।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

337. प्राधिकारी नोट करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापार प्रोत्साहित करने की कार्यनीति कार्यान्वित करने हेतु निर्यात ऋण वीमा का उपयोग करने के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय तथा चाइना एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस का नोटिस (सांग जी फा (2004) संख्या 368 अभी लागू था।

338. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने उच्च नये प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात के समर्थन में परिपत्र जारी किया (जिन चू यिन जी फा 1999 संख्या 210) जोकि अब भी प्रभावी है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 1 में उल्लेख है कि उच्च एवं नये प्रौद्योगिकी उत्पादों का क्षेत्र, जिसे समर्थन की आवश्यकता है, के संबंध में चीन के उच्च एवं नये प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात एवं आयातों की सूची के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि रेडियल टायर चीन के उच्च एवं नए प्रौद्योगिकी उत्पाद के रूप में सूचीबद्ध था।

339. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम में सरकारी वित्तपोषित वीमा कंपनी सिनोश्योर द्वारा निर्यात गारंटी के प्रावधान की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में निधियों के संभावित सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है। कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक है। कार्यक्रम लाभ देने के लिए कहा जा सकता और इस प्रकार प्रतिकारी सब्सिडी है, यदि यह निर्धारित किया जाए कि सिनोश्योर द्वारा तुलनीय वाणिज्यिक प्रभारों अर्थात् तुलनीय वाणिज्यिक निर्यात गारंटी प्रावधान पर अन्य घेरेलू निजी वीमा कंपनी द्वारा शुल्क प्रभारों से कम निर्यात गारंटी दी जाती है। इस संबंध में याचिका में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

340. किसी भी स्थिति में याचिका ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि चीन जन. गण. में टायर उत्पादकों, जिन्होंने भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया, ने इस कार्यक्रम में लाभ प्राप्त किया। चीन जन. गण. से किसी भी प्रतिभागी निर्यात के लिए कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। जांच प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी यह भी अभिज्ञात नहीं कर पाये कि भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात करने वाले चीन जन. गण. के टायर उत्पादकों में इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है।

341. इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि इन आरोपित कार्यक्रमों के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

342. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कुछ प्रतिभागी उत्पादकों ने अनुदान के रूप में निर्यात ऋण वीमा प्रीमियम सब्सिडी के रूप में लाभ प्राप्त करने की सूचना दी है। (इस कार्यक्रम के तहत लाभ को छोड़कर) और उसे प्राधिकारी द्वारा पहले प्रतिकारी माना गया है।

iii/iv क. उत्तरदाता उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्राप्त अधिमान्य उधार / निर्यात वित्तपोषण एवं निर्यात ऋण का सार-

343. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के प्रतिभागी उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन किया है। जिस अधिमान्य ऋण के लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किया गया था वह निम्नलिखित तालिका में नोट किया जाता है-

344. प्राधिकारी ने सहयोगी पक्षकारों के लिए उच्चतम सब्सिडी मार्जिन के आधार पर सभी अन्य दर निर्धारित की है।

प्रतिभागी उत्पादकों / निर्यातकों के नाम	सब्सिडी मार्जिन%	सब्सिडी मार्जिन रेंज%
झोंगसी रवड़ ग्रुप कॉर्पोरेशन	****	0-5%
ट्रिएंगल टायर कं. लि०	****	0-5%
ऐलूस टायर कं. लि०	****	0-5%
अन्य सभी	****	0-5%

V. इक्कीटी के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम

(i) कार्यक्रम संख्या 60 इक्कीटी निवेश

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

345. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि चीन सरकार इस्पात कंपनियों में अतिरिक्त स्वामित्व के शेयर लेती है और साथ नकद सब्सिडी देती है। चीन सरकार आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में चीन जन. गण. में लगभग सभी इस्पात उत्पादकों में भारी दावेदारी रखती है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा स्कीम दस्तावेज प्रदान किये हैं।

i. चाइना इंटरनेशनल कैपिटल कारपोरेशन लि० ("सीआईसीसी") का वेब पेज

यह भी अनुरोध किया गया है कि यह कार्यक्रम अन्य जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रतिकारी माना गया है।

ख. चीन सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

346. चीन सरकार ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित दस्तावेज कानूनी आधार नहीं बनाते इसके अतिरिक्त, सीआईसीसी किसी भी टायर कंपनी का शेयरधारक नहीं है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

347. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका में स्वयं ही आरोप लगाया गया है कि इस्पात उद्योग के इंडिस्ट्री निवेश किया जाता है। अन्य तथा कथित कार्यक्रमों के असमान याचिका ने चीन जन. गण. के उन पात्र टायर उत्पादक की सूची नहीं दी गई है जिन्होंने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है।

348. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी उत्तरदाता निर्यातक ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। याचिका में यह दर्शाने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है कि भारत को संबद्ध उत्पाद को निर्यात करने वाले टायर उत्पादकों ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया। जांच प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी यह भी अभिज्ञात नहीं कर पाये कि भारत को संबद्ध उत्पाद करने वाले चीन जन. गण. के निर्यातकों ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया।

349. अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

ii. कार्यक्रम संख्या 61 अप्रदत्त लाभांश

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

350. सरकार टायर कंपनियों में अतिरिक्त स्वामित्व का हिस्सा लेती है। तथापि, चीन सरकार इन कंपनियों से कोई लाभांश नहीं लेती अथवा भूल जाती है, जिनमें से कुछ विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक हैं। कार्यक्रम के मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा स्कीम दस्तावेज प्रदान किये हैं जोकि उन्हें उपयुक्त रूप से उपलब्ध थे।

i. वित्त मंत्रालय राज्य सरकारी कराधान प्रशासन और चाइना सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन संयुक्त रूप से प्रकाशित काई सुई (2014) संख्या 79

ख. चीन सरकार द्वारा अनुरोध

351. याचिकाकर्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में विश्वास किये गये दस्तावेज प्रदर्श के रूप में नहीं दिए गए थे।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

352. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा नोट किया गया कानूनी दस्तावेज निर्धारित करता है कि चीन में स्टॉक के अंतरण अथवा अन्य किसी इंडिस्ट्री निवेश परिसंपत्ति के अंतरण से योग्य विदेशी संस्थागत निवेशक को ("क्यूएफआईआई") तथा आरएमबी योग्य विदेशी संस्थागत निवेशकों ("आरक्यूएफआईआई") द्वारा निकाली गई आय उद्यम आय कर से अस्थाई रूप से छूट प्राप्त होगी। तथापि, यह इस कार्यक्रम में संगति नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका में यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया कि संबद्ध उत्पाद का निर्यात करने वाली चीन जन. गण. की टायर कंपनियों ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया।

353. चीन जन. गण. के किसी भी प्रतिभागी उत्पादक/निर्यातक ने अप्रदत्त लाभांश के रूप में लाभ प्राप्त नहीं किया। याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं दिया कि भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात करने वाले चीन जन. गण. के टायर उत्पादकों ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया। जांच प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी यह भी अभिज्ञात नहीं कर पाये कि भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात करने वाले चीन जन. गण. के टायर उत्पादकों ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया।

354. अतः प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाये जाने चाहिए।

(iii). कार्यक्रम संख्या 62 योग्य आवासीय उद्यमों के बीच लाभांश छूट

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

355. उद्यमों को कुछ लाभांश, बोनस और अन्य इंडिस्ट्री लाभों पर कर छूट के रूप में अधिमान्य कर व्यवहार प्रदान किया जाता है। अन्य चीनी आवासीय उद्यमों में शेरयद्वारक चीनी उद्यम उपर्युक्त लाभ के पात्र हैं। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा स्कीम दस्तावेज प्रदान किये हैं, जोकि उन्हें उपयुक्त रूप से उपलब्ध थे।

i. अनुच्छेद 26 उद्यम आय कर कानून

ii. अनुच्छेद 83 उद्यम आय कर कानून के कार्यान्वयन संबंधित विनियम, स्टेट कॉसिल की डिक्री संख्या 512

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

356. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम उद्यम आय कर कानून के अनुच्छेद 26 तथा उद्यम आय कर कानून का कार्यान्वयन संबंधित विनियम के अनुच्छेद 83 के तहत शासित था।

357. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम की विगत में कुछ अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई थी और इस कार्यक्रम की मौजूदगी तथा प्रतिकारिता (क) कोटेड फाइन पेपर और (ख) कुछ आर्गनिक कोटेड स्टील उत्पादों में यूरोपीय संघ के प्राधिकारियों द्वारा सिद्ध की गई है।

358. चीन जन. गण. के किसी भी प्रतिभागी उत्पादक/निर्यातक ने अप्रदत्त लाभांश के रूप में लाभ प्राप्त नहीं किया। याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं दिया कि भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात करने वाले चीन जन. गण. के टायर उत्पादकों ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया। जांच प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी यह भी

अभिज्ञात नहीं कर पाये कि भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात करने वाले चीन जन. गण. के टायर उत्पादकों ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया।

359. अतः प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाये जाने चाहिए।

vi. वस्तु एवं सेवाओं के प्रावधान के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम

i. कार्यक्रम संख्या 63 पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए विजली का प्रावधान

ii. कार्यक्रम संख्या 64 पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए पानी का प्रावधान

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

360. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि टायर विनिर्माता पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए विजली अथवा पानी प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित कानूनी आधार पर विश्वास किया-

i. गुआ फा 2004 संख्या 20

ii. सूची – निर्णय संख्या 40 (2005) – (एनडीआरसी)

iii. एनडीआरसी का आदेश 35 – लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए नीतियां – 2005

iv. विजली कानूनों के अनुच्छेद 3,6,35,37,38,39,41 और 42 – 1995

v. चीन जन. गण. में पानी संवधी कानून – 2002

vi. वेब अनुसंधान – जियांग सू क्यूडोंग लूसियो विकास क्षेत्र में एफआईई के लिए अधिमान्य व्यवहार

ख. चीन सरकार द्वारा अनुरोध

361. याचिकाकर्ताओं ने याचिका में नोट किय गये किसी भी कानूनी आधार के लिए कानूनी पाठ प्रदान नहीं किया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

362. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चीन सरकार विजली और पानी क्रमशः अधिमानी दरों और मूल कीमत पर प्रदान करती है।

363. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं जो निष्कर्ष रूप में सिद्ध करते हैं कि चीन सरकार कतिपय उद्यमों को पर्याप्त कीमत से कम पर जल उपलब्ध करा रही है।

364. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन की सरकार कतिपय उद्यमों को पर्याप्त मूल्य से कम पर विजली दे रही है। पर्याप्त मूल्य से कम पर विजली देना सेवा प्रदान करने के रूप में वित्तीय अंशदान माना जाता है। प्राधिकारी समुक्ति करते हैं कि बाजार दर से कम पर विजली देना लाभ देना माना जाता है। यह सम्बिडी कार्यक्रम इसलिए स्पष्ट है क्योंकि चीन जन. गण. में यह कतिपय किस्म के उद्यमों तक सीमित है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन सरकार द्वारा विजली दिया जाना एक प्रतिसंतुलन योग्य सम्बिडी कार्यक्रम है।

365. चीन सरकार और भागीदार निर्यातकों/प्रतिवादियों ने प्राप्त लाभ की पहचान करने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं की है। अतः प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पर्याप्त से कम मूल्य के लिए विजली उपलब्ध कराने के तहत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित किया है।

(iii) कार्यक्रम संख्या 65 औद्योगिक एवं अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि के उपयोग के अधिकार

(iv) कार्यक्रम संख्या 66 एसओई के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

366. चीन में भूमि उपयोग अधिकार प्रावधान चीन जन. गण. के भूमि प्रशासन कानून ने दिये जाते हैं। चीन ने भूमि प्रावधान तथा अधिग्रहण अस्पष्ट और गैर पारदर्शी हैं और कीमतें प्रायः प्राधिकारियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक निर्धारित की जाती हैं। प्राधिकारी कीमतें शहरी भूमि मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार निर्धारित करते हैं, जो उन्हें अन्य मानदंडों के साथ विचार करने के लिए निर्देश देती है और औद्योगिक भूमि की कीमत निर्धारित करती है। चीन जन. गण. ने भूमि सामान्य बाजार दरों से कहीं कम कीमत पर दी जाती है।

367. भूमि प्रशासन कानून के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीनी संविधान तथा संगत कानूनी प्रावधानों के अनुसार पूरी भूमि सरकारी स्वामित्व में है, भूमि सामूहिक रूप से चीन जनवादी गणराज्य की है। कोई भी भूमि बेची नहीं जा सकती, परंतु कानून के अनुसार भूमि उपयोग के अधिकार दिये जा सकते हैं। राज्य प्राधिकारी उसे सार्वजनिक बोली, कोटेशन अथवा नीलामी के माध्यम से दे सकते हैं।

368. याचिकाकर्ताओं ने नोट किया है कि लाभ उच्च एवं नये औद्योगिकीय उन्नत एसओई को उपलब्ध हैं। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाएं एवं स्कीम दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं-

- i. हेनान प्रोविंस इंडस्ट्रियल ट्रांस्फारमेशन और अपग्रेडिंग 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रसारण के संबंध में हेनान प्रोविंस के गणराज्य सरकार के सामान्य कार्यालय का नोटिस, यू.झेंग बान (2012) संख्या 22 (25 फरवरी, 2012)
- ii. चीन गणराज्य का भूमि प्रशासन कानून, 2004
- iii. चीन गणराज्य का रेयल राइट कानून

ख. चीन सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

369. चीन सरकार ने उल्लेख किया कि 12 वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2011-15 से संबंधित है। चूंकि 12वीं योजना अवधि समाप्त हो गई है। अतः कार्यक्रम 2015 से अवैध था। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिये गये शेष प्रदर्श कानूनी आधार नहीं बनाते।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

370. प्राधिकारी नोट करते हैं याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया कानूनी आधार वर्ष 2011-15 के लिए था और यह कि अवधि समाप्त हो गई है।

371. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन सरकार पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कुछ उद्यमों को भूमि के उपयोग के अधिकार प्रदान कर रही है। पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि के उपयोग के अधिकार के प्रावधान से सेवाओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय योगदान होता है। प्राधिकारी यह देखते हैं कि बाजार दरों से कम पर दिये गये भूमि के उपयोग के अधिकार लाभ प्रदान करना बनाते हैं। यह सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है, क्योंकि यह चीन जन. गण. में कुछ खास प्रकार के उद्यमों के लिए सीमित है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन सरकार द्वारा भूमि के उपयोग के अधिकारों का प्रावधान एक प्रतिकारी सम्प्रिडी कार्यक्रम है।

372. चीन सरकार और भागीदार निर्यातकों/प्रतिवादियों ने भूमि उपयोग अधिकार के अधीन प्राप्त लाभ की पहचान करने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं की है। अतः प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पर्याप्त से कम मूल्य पर भूमि उपयोग अधिकार उपलब्ध कराने के तहत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित किया है।

व. कार्यक्रम संख्या 67 एफआईई के लिए भूमि उपयोग अधिकार

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

373. चीन की एसओआई के अलावा अधिमान्य आधार पर कुछ विदेशी निवेश के उद्यमों (एफआईई) को भूमि उपयोग अधिकार प्रदान करने की नीति है। विदेशी निवेश वाले उद्यम निर्यात उद्यम के रूप में भी योग्यता हासिल कर सकते हैं। साथ ही प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत उद्यम भूमि के प्रयोग के शुल्क पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा स्थानीय सरकारों सीमित अवधि के लिए ऐसे भुगतान के लिए प्राधिकृत हैं। कार्यक्रम की मौजूदगी के साथ्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा स्कीम दस्तावेज प्रदान किये हैं-

- i. विदेशी निवेश बढ़ाने के संबंध में स्टेट कॉसिल के प्रावधान, गुआ फा (1986) संख्या 95 अनुच्छेद 4 पर (11 अक्टूबर, 1986)
- ii. टायर उद्योग नीति जारी करने के संबंध में उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नोटिस (गोंग चान ये झेंग सी (2010) संख्या 2)
- iii. फुजोऊ आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र के प्रावधान (12 दिसंबर, 1986) अनुच्छेद 23 में
- iv. गुआनडोंग प्राविंस में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए प्रावधान कार्यान्वित करना (26 अप्रैल, 1987) अनुच्छेद 20 में
- v. हेलीजियांग प्राविंस में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए अनंतिम प्रावधान (18 दिसंबर, 1986) अनुच्छेद 24(1)-(2) में
- vi. विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए जियांगसू प्राविंशियल गणराज्य सरकार की विनियमावली (11 नवंबर, 1986) अनुच्छेद 2 में

ख. चीन सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

374. चीन सरकार ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ताओं ने जियांगडांग प्राविंस में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन प्रावधानों (26 अप्रैल, 1987) तथा विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए जियांगसू प्राविंशियल सरकार की कई विनियमावलियों के कानूनी पाठ उपलब्ध नहीं कराये (11 नवंबर, 1986)

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

375. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम गुआ फा (1986) संख्या 95 के तहत शासित था, जो तब भी लागू था।

376. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि फुजोऊ आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र की विनियमावली को 1993 के संशोधन और 2002 के संशोधन में रखा गया था। 2002 का संशोधन तब भी लागू था। तथापि, फुजोऊ आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र में कोई टायर उत्पादक नहीं था।

377. ग्रांगडांग प्राविंस में विदेश निवेश प्रणाली के लिए कार्यान्वयन प्रावधान (26 अप्रैल, 1987) को 14 अप्रैल, 1998 को निरस्त किया गया था। हेलियांग जियांग प्राविंस में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए प्राविंशियल प्रावधान (18 दिसंबर, 1986) 5 जनवरी, 2011 को रद्द किया गया था। विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए जियांगसू प्राविंशियल गणराज्य सरकार की विनियमावली (11 नवंबर, 1986) 24 जून, 2002 को रद्द की गई थी।

378. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन सरकार पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कुछ उद्यमों को भूमि के उपयोग के अधिकार प्रदान कर रही है। पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि के उपयोग के अधिकार के प्रावधान से सेवाओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय योगदान होता है। प्राधिकारी यह देखते हैं कि बाजार दरों से कम पर दिये गये भूमि के उपयोग के अधिकार लाभ प्रदान करना बनाते हैं। यह सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है, क्योंकि यह चीन जन. गण. में कुछ खास प्रकार के उद्यमों के लिए सीमित है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन सरकार द्वारा भूमि के उपयोग के अधिकारों का प्रावधान एक प्रतिकारी सब्सिडी कार्यक्रम है।

379. चीन सरकार और भागीदार निर्यातकों/प्रतिवादियों ने भूमि उपयोग अधिकार के अधीन प्राप्त लाभ की पहचान करने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं की है। अतः प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पर्याप्त से कम मूल्य पर भूमि उपयोग अधिकार उपलब्ध कराने के तहत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित किया है।

vi. कार्यक्रम संख्या 68 : पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए कार्बन ब्लैक का प्रावधान

vii. कार्यक्रम संख्या 69 : पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए नायलान कार्ड का प्रावधान

viii. कार्यक्रम संख्या 70 : पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए सिंथेटिक रबर तथा बूटाडीन का प्रावधान

ix. कार्यक्रम संख्या 71 : पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए प्राकृतिक रबर का प्रावधान

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

380. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि टायर उद्योग कार्बन ब्लैक, नायलान कार्ड, सिंथेटिक रबर और प्राकृतिक रबर जैसी कच्ची सामग्री का पूर्व प्रभावी प्रयोक्ता है। चीन सरकार एसओई के माध्यम से ये कच्ची सामग्रियां पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर प्रदान कर रही है। कार्यक्रम के मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा स्क्रीम दस्तावेज प्रदान नहीं किये हैं।

- टायर उद्योग नीति जारी करने के संबंध में उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस (गांग चान ए झेंग सी 2010) संख्या 2) अनुच्छेद 16-19 में।
- 30 अप्रैल, 2014 को यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में दायर सिनोपेक शंघाई पेट्रो केमिकल कंपनी लि० की वार्षिक रिपोर्ट का प्राप्त 20-एफ।
- विदेशी निवेश उद्योगों की मार्गदर्शन के लिए वाणिज्य मंत्रालय, चीन गणराज्य की सूची (2011 में संशोधित)
- दि डेलियान हाइटेक इंडस्ट्रीयल जोन “सिंथेटिक रबर” को अपनी “प्रोत्साहित विदेशी निवेश उद्योगों” में सूचीबद्ध करता है। “डेलियान हाइटेक इंडस्ट्रीयल जोन, “प्रोत्साहित विदेशी निवेश उद्योग” (16 मार्च, 2006)
- द ग्रांगझाऊ डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट “बूटाडीन” और “सिंथेटिक रबर” को “प्रोत्साहित उद्योग”, ग्रांगझाऊ डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट, “निवेश प्रोत्साहित उद्योग” में सूचीबद्ध करता है (2003)
- ग्रांगझाऊ “स्टेट इंडस्ट्रीयल कैटालॉग गाइडिंग फारने इनवेस्टमेंट” सिंथेटिक रबर को “द इंकरेज इंडस्ट्रीज फार फारेन इनवेस्टमेंट” में सूचीबद्ध करता है।
- “विदेशी निवेश के लिए प्रोत्साहित उद्योग” द स्टेट इंडस्ट्रीयल कैटालॉग गाइडिंग फारने इनवेस्टमेंट
- “ओद्योगिक संरचना समायोजन के लिए मार्गदर्शी सूची” के कुछ प्रावधानों में संशोधन के संबंध में चीन जन. गण. के राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग का आदेश (2011)

ख. चीन सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

381. चीन सरकार ने उल्लेख किया कि कि प्रपत्र 20-एफ वार्षिक रिपोर्ट, द डेलियान हाइटेक इंडस्ट्रीयल जोन सूची, द ग्रांगझाऊ डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट का कोई कानूनी अधिकारी नहीं बनता और इस प्रकार याचिकाकर्ता ने आरोपित कार्यक्रम के लिए कानूनी आधार / कानूनी पाठ प्रदान नहीं किया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

382. प्राधिकारी नोट करते हैं कि टायर उद्योग नीति जारी करने के संबंध में उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नोटिस (गांग चान ए झेंग सी(2010) संख्या 2) टायर उद्योग के विकास को विनिर्मित करने वाली प्रमुख औद्योगिक

नीति था। अनुच्छेद 16 से 19 में भी यह उल्लेख है कि टायर की गुणवत्ता अद्यतन करने के लिए सरकार ने प्राकृतिक रबर, कृतिपय सिंथेटिक रबर, संरचनात्मक स्टील कार्ड और विशेष कार्बन ब्लैक का विकास प्रोत्साहित किया।

383. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्ची सामग्री के लिए प्रावधान किया जाता है तो वित्तीय योगदान उठते हैं। ऐसी स्थिति में लाभ सामानों के प्राप्तकर्ताओं को दिये जाते हैं। यह सब्सिडी भी विशिष्ट होती है, क्योंकि उस उद्यम के लिए सीमित होती है, जो उस कच्ची सामग्री / सामानों का प्रयोग करता है।

384. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से भागीदार निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन किया। प्राधिकारी ने सबसे पहले इस बात की विस्तृत जांच की कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कौन सी कच्ची सामग्रियां खरीदी गईं। उसके बाद प्राधिकारी ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से खरीद कीमत की तुलना निजी उद्यमों की खरीद कीमत तथा आयात कीमत/अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्क के साथ की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा खरीदी गई तीन प्राथमिक कच्ची सामग्रियां प्राकृतिक रबड़, सिंथेटिक रबड़ और कार्बन ब्लैक हैं।

385. जहां तक प्राकृतिक रबड़ का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह प्राथमिक रूप से चीन में आयात होती है और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से घरेलू खरीद नगण्य है। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से खरीद कीमत की आयातित उत्पाद की कीमत से तुलना भी की गई है।

386. जहां तक सिंथेटिक रबड़ का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों तथा निजी कंपनियों से सिंथेटिक रबड़ की खरीद की है और उसका आयात भी किया है। प्राधिकारी ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम से खरीद कीमत की तुलना निजी कंपनी की खरीद कीमत और आयातित उत्पाद की कीमत के साथ भी की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम से खरीद कीमत निजी कंपनी से खरीद कीमत तथा आयातित उत्पाद की कीमत से तुलनीय है।

387. जहां तक कार्बन ब्लैक का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों तथा निजी कंपनियों से कार्बन ब्लैक की खरीद की है और उसका आयात भी किया है। किसी भी भागीदार उत्पादक/निर्यातक ने कार्बन ब्लैक का आयात नहीं किया है। तुलना के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय बैंच मार्क को भारत और कोरिया गणराज्य में कार्बन ब्लैक की आयात कीमत माना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ट्रेंगल टायर कंपनी लि. और झोंगसी रबड़ ग्रुप कंपनी लिमिटेड को छोड़कर राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम से खरीद कीमत निजी कंपनियों से खरीद कीमत और प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बैंच मार्क से तुलनीय है। तदनुसार प्राधिकारी ने ट्रेंगल टायर कंपनी लि. और झोंगसी रबड़ ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम को प्रदत्त कीमत तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्क के बीच अंतर के आधार पर लाभ को निर्धारित किया है।

388. इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि चीन जन गण से भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा ट्रेंगल टायर कंपनी लि. और झोंगसी रबड़ ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए कार्बन ब्लैक के प्रावधान को छोड़कर पर्याप्त मूल्य से कम पर कच्ची सामग्री प्रदान करने के रूप में कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

VII. क. पर्याप्त मूल्य से कम पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान का सारांश।

प्राधिकारी ने सहयोगी पक्षकारों के लिए उच्चतम सब्सिडी मार्जिन के आधार पर सभी अन्य दर निर्धारित की है।

कंपनी का नाम	पर्याप्त मूल्य से कम पर विद्युत के प्रावधान के लिए सब्सिडी मार्जिन %	पर्याप्त मूल्य से कम पर भूमि उपयोग अधिकार के प्रावधान के लिए सब्सिडी मार्जिन %	पर्याप्त मूल्य से कम पर कार्बन ब्लैक के प्रावधान के लिए सब्सिडी मार्जिन %	कुल	कुल रेंज
झोंगसी रबड़ ग्रुप कं. लि०	***	***	***	***	5-15%
शानडांग वांडा बोटो टायर कं. लि०	***	***	***	***	5-15%
टिंगल टायर कं. लि०	***	***	***	***	5-15%
शानडांग योगफेंग	***	***	***	***	5-15%

टायर कं. लि०					
एलूस टायर कारपोरेशन लि०	***	***	***	***	5-15%
किंगदाओ यलो सी रबर कं. लि०	***	***	***	***	5-15%
अन्य सभी	***	***	***	***	5-15%

x. कार्यक्रम संख्या 72 पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक के लिए सरकार द्वारा सामानों की खरीद
क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

389. सरकार उत्पादकों से उच्चतर कीमतों पर सामानों की खरीद करती है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं अथवा स्कीम दस्तावेज प्रदान किये हैं, जो उन्हें उपयुक्त रूप से उपलब्ध थे।

- डब्ल्यूटीओ कच्ची सामग्री इनपुट के संबंध में चीन के नियंत्रित प्रतिरोधों को चुनौती देता है
- चेन आइजू, जैसा कि विरोध उठता है, चीन पेट्रो केमिकल संयंत्रों के लिए योजनाओं की रक्षा करता है।
- सिनोपेक कार्प, केमिकल, वेबसाइट, उद्धरण
- सिथेटिक रबर इंडस्ट्री असेसमेंट (चीन), चाइना सिथेटिक रबर मोर्केट (सितंबर, 1998)
- चीन 16 महीनों में गैसोलीन, डीजल कीमतों में पहली कटौती करता है। इंग्लिश -न्यू-सीएन, 8 अक्टूबर, 2011 एक्जीविट एम 74 में संलग्न, चीन : सिनोपेक संयुक्त राज्य अमरीका के 1.7 बिलियन डॉलर की सब्सिडी की प्राप्ति की पुष्टि करता है, पेट्रो वर्ल्ड, 24 मार्च 2008
- वर्ल्ड एनर्जी, लोकल प्लेयर-सिनोपेक इकोनॉमिस्ट इंटेर्जीजेस यूनिट, 13 अगस्त 2007
- चीन जन. गण. से कुछ क्रिस्टलीन सिरीकॉन फोटोवोल्टेक उत्पाद

ख. चीन सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

390. चीन सरकार ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अभिज्ञात कोई भी दस्तावेज कर्तव्य कानूनी आधार नहीं बनाते। इसके अतिरिक्त, चीन सरकार विचाराधीन उत्पाद की खरीद नहीं करती।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

391. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने उपर्युक्त कार्यक्रम के संबंध में कोई कानूनी आधार तथा साक्ष्य प्रदान नहीं किया। किसी भी स्थिति में प्राधिकारी यह देखते हैं कि चीन सरकार टायरों / समग्र उत्पाद की खरीद नहीं करता और इसीलिए पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक पर सामानों की खरीद के कारण वित्तीय अंशदान का प्रश्न इस मामले में नहीं उठता।

392. अतः प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता।
चीन जन. गण. के प्रतिभागी उत्पादकों / नियंत्रितकों के लिए सब्सिडी मार्जिन का सार-

393. चीन जन. गण. के प्रतिभागी उत्पादकों / नियंत्रितकों के लिए कुल सब्सिडी मार्जिन के ब्यौरे और अन्य सभी दर निम्नलिखित हैं-

कंपनी का नाम	अनुदान के लिए सब्सिडी मार्जिन%	रेंज%
झोंगसी रवर्ड ग्रुप कं. लि०	***	5-15%

शानडांग वांडा बोटो टायर कं. लि०	***	5-15%
टिंगल टायर कं. लि०	***	5-15%
शानडांग योगफेंग टायर कं. लि०	***	5-15%
एलूस टायर कारपोरेशन लि०	***	5-15%
किंगडाओ यलो सी रबर कं. लि०	***	5-15%
एयूलस टायर कंपनी लि. और किंगडाओ यलो सी रबड कं. लि. के लिए भारित औसत	***	5-15%
अन्य सभी	***	10-20%

394. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के कुछ प्रतिभागी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।

ज. क्षति मूल्यांकन तथा कारणात्मक संपर्क
ज. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

395. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं-

क). विचाराधीन उत्पाद की मांग / स्पष्ट खपत भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्रियों की मात्रा तथा अन्य सभी देशों से आयातों की रूप में परिभाषित की जाती है। क्षति की अवधि में मांग में वृद्धि हुई है जबकि जांच की अवधि में कुछ गिरावट आयी।

ख) संबद्ध देश से सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में दुगनी हुई है। चूंकि आयात वस्तुतः केवल प्रतिस्थापन बाजार में ही है। अतः घरेलू उद्योग को क्षति प्रतिस्थापन बाजार में भी प्रमुख है। विचाराधीन आयात के उत्पाद 2016-17 में पूर्ण दृष्टि से काफी बढ़े, यहां तक कि जबकि मांग में आंशिक रूप से गिरावट आयी। उसके बाद जांच की अवधि में आयातों में आंशिक रूप से मांग में गिरावट के कारण तथा मई, 2016 में संबद्ध सामानों के आयातों (केवल टीबीआर) के आयातों पर पाठनरोधी शुल्क जांच की शुरूआत के कारण गिरावट आयी। टीबीबी के आयातों में काफी गिरावट आयी है, जिसका प्रमुख कारण यह तथ्य है कि चीनी टीबीआर बाजार में टीबीबी की कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध है। वस्तुतः वर्तमान स्थिति ऐसी है कि एक ट्रक टीबीबी तथा टीबीआर में विभिन्न एक्सल अथवा यहां तक कि समान एक्सलों पर देखा जा सकता है। इस संबंध में साक्ष्य इन अनुरोधों के साथ संलग्न हैं। तथापि, भारतीय बाजार में टीबीबी अब भी टीबीआर से अधिक हैं। चीनी आयात भारत में सभी आयातों का 85 प्रतिशत हैं। ओईएम क्षेत्र में विचाराधीन उत्पाद के कोई ज्ञात आयात नहीं हैं और चूंकि आयात वस्तुतः केवल प्रतिस्थापन बाजार में हैं। अतः प्रतिस्थापन बाजार में घरेलू उद्योग को भी क्षति दृश्यमान होगी।

ग) संबद्ध देश से आयात कीमतें काफी कम हैं और उनमें जांच की अवधि में उत्पादन लागत बढ़ने के बावजूद गिरावट आयी है।

घ) निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में सामान उत्पादों की कीमत के साथ तुलना करने पर सब्सिडीयुक्त आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का ह्रास करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए अन्यथा है, जोकि अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती है। वर्तमान मामले में संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से काफी कम है। इस प्रकार घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है।

ड.) उत्पादन लागत और विक्री कीमतों की तुलना यह दर्शाती है कि दोनों में गिरावट आयी है। तथापि, कीमतों में गिरावट लागतों में गिरावट की तुलना में कम थी। जिससे घरेलू उद्योग 2015-16 में अपनी लाभप्रदता में सुधार ला पाया। तथापि, उसके बाद 2016-17 में विक्री लागतों में गिरावट आयी और वर्तमान जांच की अवधि में पुनः वृद्धि हुई। विक्री कीमत 2016-17 में लागतों में गिरावट के बजाय और गिरावट आयी और

उसके बाद जांच की अवधि में विक्री कीमत में वृद्धि भी लागतों में तदनुरूपी वृद्धि की तुलना में कम थी। आयातों की पहुंच कीमत में लागतों में वृद्धि होने के बावजूद जांच की अवधि में गिरावट आयी है। पहुंच कीमत भी घरेलू उद्योग की विक्री कीमत और विक्री लागत दोनों के स्तर से कम है। इस प्रकार, आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण हुआ है। क्योंकि विक्री कीमत में वृद्धि लागतों में वृद्धि से कम है और सभिस्डीयुक्त आयात घरेलू उद्योग को अपनी विक्री कीमत बढ़ाने से रोक रहे हैं।

च) इस तथ्य कि टीबीआर आयात टीबीबी कीमत से वास्तविक रूप से कम कीमत पर हैं, का अभिप्राय है कि ग्राहक को लागत प्रति किलो, प्रति किलो ग्राम घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किये गये टीबीबी टायरों की तुलना में आयातित टीबीआर के लिए काफी कम है। यह चीनी निर्यातकों का न्यूनीकरण तथा हासमान व्यवहार दर्शाता है।

छ) घरेलू उद्योग ने उत्पादन एवं संभावित मांग के महेनजर क्षमता बढ़ायी। तथापि, इस वृद्धि के बावजूद उत्पादन, जो 2016-17 तक बढ़ा, विक्री सहित जांच की अवधि में गिर गया। परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग भी जांच की अवधि में कम हो गया। सभिस्डीयुक्त सामानों का प्रतिकूल प्रभाव प्रतिस्थापन बाजार में मात्रात्मक मानदंडों पर और स्पष्ट दिखाई देता है। चाहे इनपुट कीमतें बढ़ें / कम हों, उद्योग उसके साथ अपनी कीमतों को बराबर नहीं रखता।

ज) संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा पूरी क्षति अवधि में बढ़ा है और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भी बढ़ा। तथापि, भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में समनुरूप से गिरावट आयी है।

झ) आयातों के न्यूनीकरण प्रभाव से घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आयी है। व्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर आय, ने भी लाभ की तरह ही वही प्रवृत्ति दर्शायी। घरेलू उद्योग की निवेश पर आय भी भारत में विद्यमान बैंक दरों से कम है। लाभप्रदता समनुरूप से कंपनियों तथा विचाराधीन उत्पाद के लिये कम हुई है। विचाराधीन उत्पाद की लाभप्रदता में गिरावट गैर विचाराधीन उत्पाद की लाभप्रदता से कहीं अधिक है और यहां तक यदि विचाराधीन उत्पाद विक्री और नियोजित पूँजी का बराबर हिस्सा लेता है तो अर्जित लाभ बहुत ही कम है।

ट) घरेलू उद्योग में विचाराधीन उत्पाद की माल सूची जांच की अवधि में काफी बढ़ी है। मजदूरी में क्षति के अवधि में सुधार दर्शाया है जबकि कर्मचारियों की संख्या समान रही है। तथापि, ये पूर्णतः संबद्ध सामानों के निष्पादन पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि वे देश में कई कानूनी अपेक्षाओं और अन्य व्यापारिक मजबूरियों से शामिल होते हैं।

ठ) घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए एक मात्र जिम्मेदार कारक उत्पाद की आयात कीमतें और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत हैं। उत्पाद की आयात कीमत पर चीनी आयात ही ऐसे हैं, जो घरेलू उद्योग की चिंता बढ़ाते हैं। शेष विश्व से आयात कीमत घरेलू उद्योग को चिंतित नहीं करती है। क्योंकि या तो वह बहुत कीमतें हैं अथवा यह आयात एक टायर कंपनी द्वारा आयात किये जा रहे हैं और फिर बहुत अधिक कीमतों पर बाजार में पुनः बेचे जा रहे हैं। अतः घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक उत्पादन लागत और संबद्ध देशों की पहुंच कीमतें हैं।

ट) नये निवेश जुटाने की क्षमता उत्पाद की सभिस्डीकरण से प्रभावित नहीं हुई है, क्योंकि निवेश संबंधी निर्णय दीर्घावधि आधार पर लिये जाते हैं। तथापि, विचाराधीन उत्पाद की दीर्घावधि अर्थक्षमता सशक्त लाभदायी व्यापार पर निभ्र छोती है।

ण) क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि उत्पादन, विक्री, बाजार हिस्सा, लाभ पीबीआईटी, नकदलाभ तथा निवेश पर आय के मानदंडों के आधार पर घरेलू बाजार में सभिस्डीयुक्त आयातों की मौजूदगी में नकरात्मक थी।

त) संबद्ध देश से आयात पूर्ण दृष्टि से तथा क्षति की अवधि में तुलनात्मक संदर्भ में बढ़ा है। यद्यपि पूर्व वर्ष की तुलना में जांच अवधि में आयातों में कुछ गिरावट थी तथापि, इसका अर्थ यह नहीं है कि क्षति की अवधि में आयात बढ़े नहीं हैं, यह विचार करते हुए कि जांच की अवधि में आयात आधार वर्ष में मात्रा में दुगने थे। आयात कीमत क्षति की अवधि में बहुत तेजी से कम हुए हैं। आयातों से काफी मात्रा तक घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। आयातों से घरेलू उद्योग कीमतों का न्यूनीकरण हो रहा है और उनसे कीमत वृद्धि को रुक रही है, जोकि पाटन के अभाव में हुई होती। घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, घरेलू विक्री, क्षमता उपयोग, मालसूची, बाजार हिस्सा, लाभ, नकदप्रवाह और निवेश पर आय के संदर्भ में गिरावट आयी। घरेलू उद्योग पर सभिस्डीयुक्त आयातों का परिणामी प्रभाव काफी प्रतिकूल रहा है।

थ) चीनी उत्पादकों को चीन की सबिसडी काफी कम लागत पर उत्पाद करने देती हैं, जिससे उन्हें पूरे विश्व में संबद्ध सामानों के अन्य उत्पादकों में प्रतिस्पर्धी लाभ मिलता है। इस सबिसडीकरण से चीन द्वारा अन्य देशों का काफी निर्यात हुआ है। उपलब्ध सबिसडीयों की इस योजना से उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के निमित्त स्पष्ट बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमरीका ने चीन द्वारा संबद्ध सामानों के निर्यात पर पाटनरोधी शुल्क और सबिसडीरोधी जांच की शुरूआत की है।

द) संबद्ध देश से आयातों में घरेलू मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

ध) संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों की संबद्ध देश के बाजार में तुलनात्मक दृष्टि से संबद्ध सामानों के लिए मांग कम होने के बावजूद अधिक क्षमतायें हैं। जिससे क्षमतायें अधिक हो रही है।

न) आयातों का पहुंच मूल्य विक्री कीमत तथा घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम कीमत पर रखा जाता है। घरेलू बाजार संबद्ध देश के उत्पादकों के लिए आकर्षक है। आयात घरेलू कीमतों पर न्यूनीकरण / हासमान प्रभाव से बाजार में आ रहे हैं और अधिक आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि चीनी निर्यातक आक्रामक रूप से घरेलू बाजार को लक्ष्य बनाएंगे।

प) चीन से संबद्ध सामानों की आयात कीमत में जांच की अवधि में पूर्व वर्ष की तुलना में उसी अवधि में संबद्ध सामानों के उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद काफी गिरावट आयी है।

फ) चीन विश्व का सबसे बड़ा टायर उत्पादक एवं निर्यातक है जो वैश्विक उत्पादन का एक चौथाई है। विश्व तथा भारत को संबद्ध देश से निर्यात 2005 से बढ़ते रहे हैं। इस प्रकार चीनी निर्यातकों का विश्व तथा भारत में अत्यधिक निर्यात है। जो उन्हें अत्यधिक निर्यातोन्मुख बनाता है। घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच वर्तमान कीमत अंतर अत्यधिक है और इस प्रकार आयातित उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, उत्पादकों द्वारा क्षमताओं का विस्तार किया जा रहा है। चीन उद्योग टायर उद्योग के विरुद्ध कार्यरत व्यापारिक वाधाओं के बावजूद उन्हें थकाने के कोई संकेत नहीं दिखाई देते।

ब) ब्राजील, तुर्की, कोलंबिया, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरीका और यूरोपीय संघ जैसे अनेक अन्य देशों ने या तो संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाया है अथवा पाटनरोधी जांच शुरू की है।

भ) चीन ने 2014 में वैश्विक रूप से टायरों में प्रयुक्त प्राकृतिक रबड़ की 38 प्रतिशत की खपत की। 2015-16 में चीन ने 2,220,373 मीट्रिक टन प्राकृतिक रबड़ का आयात किया। कुल प्राकृतिक रबड़ के आयातों में से 263123 मीट्रिक टन आरएसए के रूप में था और 1957250 मीट्रिक टन ब्लॉक रबर (तकनीकी रूप से विशिष्ट प्राकृतिक रबर) के रूप में था। इस प्रकार आयातित लगभग 88 प्रतिशत प्राकृतिक रबर ब्लॉक रबर के रूप में है। प्रमुख रबर उत्पादक देशों में निवेश से भारत की तुलना में चीनी उत्पादकों का काफी लागत संबंधी लाभ प्राप्त हुये हैं। क्योंकि चीन में ब्लॉक रबड़ की आयात कीमत भारत में आयात कीमत से निरंतर कम है।

म) संबद्ध देश के उत्पादकों के पास मौजूद माल सूची का स्तर घरेलू उद्योग को मालूम नहीं है। तथापि, उनके पास उपलब्ध पर्याप्त क्षमता के तथ्य के मद्देनजर यह सिद्ध है कि विदेशी उत्पादक कम अवधि में ही अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

य) भारत चीनी टायर उत्पादकों के लिए 10 शीर्ष निर्यात लक्ष्यों में एक बन गया है। 2012 में निर्यात लक्ष्य में 43वें स्थान से भारत 2016 में छठे स्थान पर आ गया है। इस प्रकार सबिसडीयुक्त चीनी निर्यातों से भारतीय घरेलू उद्योग को गंभीर वास्तविक क्षति का खतरा बन रहा है।

(र) इस प्रकार, इस मामले में सबिसडीयुक्त विचाराधीन उत्पाद में काफी वृद्धि है, जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शा रहा है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क जांचों की शुरूआत तथा आयातकों के दिमाग में उसकी मात्रा की अनिश्चितता के कारण ये आयात केवल कुछ हद तक ही हैं। दोनों उत्पादकों के बीच कीमत का अंतर काफी है और आयातों के लिए मांग बढ़ सकती है। अंतिम रूप से संबद्ध देश में स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमताएं ही उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि संबद्ध देश में उत्पादक बहुत कम अवधि में उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

कक. घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति पूर्णतः घरेलू प्रचालनों के कारण है। उत्पादन प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्तर पर उद्योग में कोई खास प्रगति नहीं की गई है। याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है। कोई ऐसा व्यापार प्रतिबधात्मक परिपाठियां नहीं हैं जिनकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो और विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। इस आलोक में याचिकाकर्ता अनुभव करते हैं कि कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का प्रयोग किया जा सकता है:-

- आयातों से घरेलू उद्योग को कीमतों में कटौती हो रही है परिणामस्वरूप आयातों की मात्रा बढ़ी है।

- कीमत कटौती सम्बिंदीयुक्त आयातों के कारण हुई है परिणामस्वरूप आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में तेजी से गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, प्रतिस्थापन क्षेत्र में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में तेजी से गिरावट आई है।
- टीवीआर के आयातों की पहुंच कीमत टीवीबी की कीमतों से भी काफी कम है। आयातों से घरेलू उद्योग का काफी न्यूनीकरण हो रहा है।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में जांच की अवधि में गिरावट आई है। लाभ, व्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और नियोजित निवेश पर आय में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग की मालसूची काफी बढ़ी है।
- घरेलू उद्योग पर सम्बिंदीयुक्त आयातों का परिणामी प्रभाव काफी प्रतिकूल रहा है।

खब्ब. विभिन्न मानदंड सामूहिक रूप से और संचयी रूप से सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, चीनी आयातों में वृद्धि, चीनी उत्पादकों के पास उनकी अत्यधिक निर्यातोन्मुखता के साथ अतिरिक्त क्षमता और भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को और भी वास्तविक क्षति का खतरा है।

गग. तथ्य यह है कि चीन में उत्पादकों के पास उनकी मांग से कहीं अधिक काफी क्षमता पड़ी है और अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं जैसा कि वैश्विक बाजार में उनके हमेशा बढ़ते हुए निर्यातों से सिद्ध है।

घघ. इसके अतिरिक्त, यह दावा कि सीमाशुल्क में वृद्धि तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण जांच की अवधि की बाद की अवधि में कीमत कटौती में और गिरावट है, वास्तविकता से कोई संबंध न रखते हुए एक मानने वाली बात है। जांच की अवधि के बाद की अवधि में कीमत कटौती में वृद्धि हुई है क्योंकि जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों की कीमत में काफी गिरावट आई है।

डड. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, आयातों में गिरावट आंशिक रूप से मांग में गिरावट के कारण है और आंशिक रूप से मई, 2016 में संबद्ध सामानों (केवल टीवीआर) के आयातों पर पाटनरोधी जांच की शुरुआत के कारण है। इसके अतिरिक्त, प्रतिकारी जांच के लिए संगत अवधि जांच की अवधि है। संबद्ध देश से सम्बिंदीयुक्त आयातों की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में दुगुनी हुई है। यह नोट किया जाए कि चूंकि आयात केवल यथा तथ्यतः प्रतिस्थापन बाजार में हैं अतः घरेलू उद्योग को क्षति प्रतिस्थापन बाजार में भी है। उपर्युक्त के होते हुए यद्यपि यह सच है कि आयातों की मात्रा में संबद्ध देश से गिरावट आई है परंतु जिस कीमत पर वे आयात आ रहे हैं, उसमें भी जांच की अवधि के बाद काफी गिरावट आई है।

चच. यह देखा जा सकता है घरेलू उद्योग 2015-16 में अपना लाभ बढ़ाने में सक्षम था। तथापि, उसमें कम कीमतों पर आयातों में काफी वृद्धि से 2016-17 में काफी गिरावट आई। आयात कीमतों में जांच की अवधि में और भी गिरावट आई जब लागत वास्तविक रूप से बढ़ गई है। इस प्रकार, आयातों के न्यूनीकरण प्रभाव से घरेलू उद्योग के लाभ में और गिरावट आई है।

छछ. यह नोट करना भी संगत है कि घरेलू उद्योग के लिए इनपुट में प्रत्येक परिवर्तन के साथ अपनी कीमतें बसूलते रहना संभव नहीं है। यह अनुरोध है कि चाहे इनपुट कीमतें बढ़ें अथवा कम हों, उद्योग अपनी कीमतें तत्काल ही इनपुट लागतों में परिवर्तन के बराबर नहीं रखता। वस्तुतः उद्योग ने विगत में एक वर्ष में 2-4 कीमत परिवर्तन लिए थे जब प्राकृतिक रवड़ जैसे इनपुट में लगभग प्रतिदिन परिवर्तन हुए थे।

जज. हितबद्ध पक्षकारों की अवधारणा गलत है जैसा कि याचिका में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है, जो यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है। किसी भी व्यापार के लिए उस समय उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है जब वह कच्ची सामग्री की कमी का सामना कर रहा हो। कच्ची सामग्री की कमी के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया साध्य जांच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित है और इन इनपुट के उपभोक्ताओं की सहायता कर सलाहकारों के लिए प्राप्त करने योग्य एक सूचना है। इन पक्षकारों के लिए इन कच्ची सामग्रियों के संबंध में अन्य उपभोक्ताओं अथवा एटीएमए का प्रतिनिधित्व करना, इन पहलुओं पर चर्चाएं प्राप्त करना और अब निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे दावे प्रस्तुत करना जोकि वर्तमान मामले में जांच की अवधि से संबंधित नहीं हैं, पूर्णतः अनुचित है।

झझ. हितबद्ध पक्षकारों की अवधारणा गलत है जैसा कि याचिका में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है। बिक्री लागत में जांच की अवधि में थोड़ी सी वृद्धि के साथ पूरी क्षति अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का उत्पादन

बढ़ा है। कच्ची सामग्री की कमी के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पूरी तरह से जांच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित है।

टट. संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं। संबद्ध देश के बाजार में संबद्ध सामानों की मांग उस देश में सृजित उत्पादन क्षमताओं की तुलना में काफी कम है। इस प्रकार, देश में अतिरिक्त क्षमताएं बन रही हैं। संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के प्रमुख उत्पादकों के पास काफी अधिक उत्पादन क्षमता है, जो संबद्ध देश में मांग से अधिक है।

ठठ. याचिकाकर्ता यह नहीं समझ पाए कि हितबद्ध पक्षकार टीवीआर पाटनरोधी शुल्क के मामले में अंति जांच परिणाम से इस निष्कर्ष पर कैसे आए कि लगाए गए शुल्क क्षति मार्जिन पर आधारित थे।

डड. अनुरोध है कि हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत लाभ में गिरावट याचिकाकर्ता कंपनियों के तुलन पत्रों से देखी जा सकती है। यह देखा जाएगा कि (क) कंपनियों के लिए समग्र रूप से तथा जांच की अवधि के लिए लाभप्रदता में गिरावट आई है। (ख) विचाराधीन उत्पाद की लाभप्रदता में गिरावट गैर विचाराधीन उत्पाद की लाभप्रदता में गिरावट से अधिक है। (ग) यहां तक कि जब विचाराधीन उत्पाद का विक्री और नियोजित पूंजी में बराबर हिस्सा है तो उनसे अर्जित लाभ बहुत कम है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

396. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:-

क. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने भारी लाभ कमाए हैं क्योंकि उत्पाद की मांग और कंपनी का राजस्व बढ़ा है। अतः घरेलू उद्योग को सविडीयुक्त आयातों के कारण संबद्ध सामानों के तथाक्षित बढ़े हुए आयातों के कारण कोई क्षति नहीं है। बड़ी हुई मांग भी दर्शाती है कि चीन जन.गण. के मूल से शुरू होने वाले आयातों का घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है।

ख. घरेलू उद्योग को यदि कोई क्षति है तो वह स्वप्रभावित है क्योंकि पहले तो प्रैस रिपोर्टों के अनुसार भारत ने अपना जोर काफी देर तक टीवीवी पर दिया और चमकीलापन अपनाने में धीमा है तथा उपभोक्ता अपनी बेहतर शक्ति और टिकाऊपन के लिए रेडियल टायरों को बेहतर मानते हैं। दूसरे, चीनी निर्यातकों ने उस समय टीवीआर की अपनी कीमत कम कर दी जब कच्ची सामग्री की लागत नीचे चली गई जबकि घरेलू उद्योग का ध्यान भारी लाभ कमाने पर रहा। तीसरे, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में यदि कोई कमी है तो वह अन्य घरेलू प्रतिस्पर्द्धियों के आक्रामक कीमत व्यवहार के कारण है न कि चीन जन.गण. से आयातों के कारण।

ग. तुलन पत्रों तथा लाभ और हानि खातों की जांच करने पर और घरेलू टायर उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि एटीएमई के उल्लिखित सदस्यों को कोई वास्तविक क्षति नहीं है तथा जांच की अवधि के दौरान आयातों में और भी गिरावट है।

घ. रेडियल टायरों की मांग और उपयोग बढ़ रहा है तथा बायस टायरों के लिए प्राथमिकता में गिरावट आ रही है जिसके कारण बायस टायरों का घरेलू उद्योग निष्पादन में गिरावट दर्शा रहा है। इस गिरावट के प्रभाव याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना में शामिल किए गए हैं।

ड. घरेलू स्तर पर कच्ची सामग्री व्यस्ततम अगस्त, 2008 और फिर अगस्त, 2013 से कम पर विद्यमान है। इसके बावजूद टायरों की कीमतें पिछली तीन तिमाहियों के दौरान नियमित अंतराल पर बढ़ाई गई हैं और परिणामस्वरूप उद्योग ने भारी लाभ कमाया है जिसे विशेष रूप से जांच की अवधि के पिछले 10 वर्षों के तुलनपत्रों का मूल्यांकन कर देखा जा सकता है।

च. टायर विनिर्माण भारी रूप से कच्ची सामग्री आधारित उद्योग है और निवेश पर आय की दर सामान्यतः 10 प्रतिशत-12 प्रतिशत होती है। घरेलू टायर वाले अपने वास्तविक लाभ को छिपाते हुए अपना आनुपातिक उत्पादन और विक्री बढ़ाए बिना भी क्षमता का विस्तार करने का मार्ग अपनाते हैं। इसी प्रकार, नियमित टायर आयातों के बावजूद घरेलू टायर वालों ने आकार और लाभ के संदर्भ में तथा निवेश पर अत्यधिक आय के साथ काफी वृद्धि की है।

छ. वर्ष 2010 से आगे से रेडियल टायर आयातों से घरेलू उद्योग टक और बस टायरों के लिए अपने स्तर पर रेडियलीकरण को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर हुआ है क्योंकि घरेलू टायर वाले उन पुरानी प्रौद्योगिकी और अदक्ष बायस प्लाई नायलोन फैब्रिक टायरों की विक्री कर लाभ कमा रहे थे जो पाकिस्तान, श्रीलंका और बंगलादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी नहीं बेचे जा रहे हैं। यह इस कारण है कि घरेलू टायर विक्रेता को अनुचित प्रशुल्क तथा भारत सरकार द्वारा दिया गया गैर प्रशुल्क संरक्षण लेते हैं और कीमत समानांतरता तथा व्यवसायी समूहन में शामिल होकर घरेलू बाजार का उपयोग करते हैं।

ज. मै. अपोलो टायर तथा अन्य (उत्तरदाता) बनाम कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (सूचनादाता) में महानिदेशक, जांच, सी सी आई में घरेलू टायर विक्रेताओं को कीमत समानांतरता और व्यवसायी समूहन में लिप्त घोषित किया है। अतः प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की मांग करने वाले एटीएमए द्वारा वर्तमान याचिका टायर आयातों पर शुल्क की दीवार और बढ़ाने तथा भारत में प्रतिस्थापन बाजार में बाजार बलों के स्वच्छंद और उचित व्यापार का गला घोटने का केवल एक प्रयास है।

झ. चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयातों की गिरावट है।

- उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जांच की अवधि में चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के निर्यातों की मात्रा में गिरावट आई है और वह पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण तथा मूल सीमाशुल्क में वृद्धि के कारण जांच की अवधि के बाद की अवधि में और नीचे गई है।
- चीन जन. गण. में कई टायर कारखानों को प्रदूषण कम करने के सरकार के अभियान के परिणाम के रूप में बंद करने अथवा उत्पादन कम करने के आदेश दे दिए गए हैं। इससे भारत को पहले ही निर्यात कम हो गए हैं।
- अतः चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण क्षति का कोई खतरा नहीं है।

ठ. कच्ची सामग्री की कमी और उद्योग में परिवर्तन से घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हो रहा है।

- प्रमुख घटक, कार्बन ब्लैक और प्राकृतिक रबड़ की घरेलू आपूर्ति भारत में प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा बढ़ती हुई घरेलू मांग के अनुरूप बने रहने में असमर्थ है।
- इसके अतिरिक्त, अन्य कच्ची सामग्री पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से भारत में संबद्ध सामानों के विनिर्माण की लागत में और वृद्धि हुई है।

ठ. भारतीय बाजार में रेडियल टायरों की मांग और प्रयोग में वृद्धि है जबकि वायस टायरों की प्रथमिकता में गिरावट आ रही है। इससे रेडियल और वायस टायरों के लिए दोनों को साथ लेकर घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में गिरावट आई है।

ड. प्रतिकारी शुल्क नियमावली के नियम 13 में यह अपेक्षित है कि वास्तविक क्षति मूल्यांकन नियमावली के अनुबंध-1 में उल्लिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अनुबंध-1 के पैरा 1 उप पैरा (2) में प्राथिकारी के लिए अपेक्षित है कि वे इस पर विचार करें कि क्या सब्सिडीयुक्त आयातों में काफी वृद्धि हुई है। अनुबंध-1 के पैरा 1 उप पैरा (3) में प्राथिकारी के लिए अपेक्षित है कि वे कीमतों के संबंध में सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभाव पर विचार करें और क्या उनसे काफी कीमत कटौती हुई है।

ढ. चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों की मात्रा में जांच अवधि में गिरावट आई है और जांच की अवधि के बाद की अवधि में वे और काफी नीचे गई हैं।

वर्ष	पी ओ आई (अक्टू. 16-सितं. 17)	पश्चात - पी ओ आई (अक्टू. 17 - जून 18)	पश्च- पी ओ आई (ए)
मात्रा (मी.ट.)	65,386.93	15,183.53	20,244.71

ण. जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है घरेलू उद्योग द्वारा याचिका के अनुसार क्षति की अवधि के पिछले दो वर्षों में कीमत कटौती के स्तर में काफी गिरावट आई है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
चीन जन. गण. से आयातों की पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	169	161	169	168
घरेलू विक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	%	15-25	15-25	5-15	5-15

त. नए न्यूमेटिक रेडियल टायरों पर सीमाशुल्क की वृद्धि से जांच की अवधि के बाद की अवधि में चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप कीमत कटौती कम हुई है।

घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में बढ़ा है और आयातों का बाजार हिस्सा कम हुआ है।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	पीओआई(अक्टू. 2016-सितं. 2017)
घरेलू उद्योग	% सूचीबद्ध	101	100	102
चीन जन. गण. से आयात	%	17.5	21.2	16.5
अन्य देश	%	2.6	2.3	2.8
समग्र रूप से घरेलू उत्पादक	%	79.9	76.5	80.7

थ. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और वृद्धि दर्शाएगा यदि जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार किया जाए जहां जांच की अवधि की तुलना में आयातों में लगभग 70 प्रतिशत तक गिरावट आई है।

द. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, पी बी आई टी और नियोजित पूँजी पर आय में 2015-16 में वृद्धि हुई है परंतु 2016-17 में गिरावट आई। परंतु, यह 2016-17 और जांच की अवधि में कीमत कटौती में और आयातों की मात्रा में गिरावट के अनुरूप नहीं है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई(अक्टू. 2016-सितं. 2017)
लाभ – कुल	करोड़ रूपए/सूचीबद्ध	100	156	103	38
नकद लाभ	करोड़ रूपए/सूचीबद्ध	100	147	107	62
आर औ सी ई	% / सूचीबद्ध	100	116	74	33
संबद्ध देशों से आयात	मीट.	30,665	69,982	81,896	61,203
कीमत कटौती रेंज	%	15-25	15-25	5-15	5-15

ध. घरेलू उद्योग ने वर्तमान और प्रत्याशित मांग के मद्देनजर अपनी क्षमता में वृद्धि की है। क्षमता उपयोग जांच की अवधि में आंशिक रूप से कम हुआ है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई(अक्टू. 2016-सितं. 2017)
क्षमता	सूचीबद्ध	100	101	103	106
उत्पादन	सूचीबद्ध	100	102	103	102
क्षमता उपयोग	सूचीबद्ध	100	101	100	96

न. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग वर्ष 2014-15 में 86.42 प्रतिशत था। वर्तमान मामले में एमआरएफ को भी घरेलू उद्योग के रूप में शामिल किया गया है और घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग ने जांच की अवधि के दौरान आंशिक

गिरावट है। परंतु यह निश्चित है कि क्षमता उपयोग जांच की अवधि में अब भी 80 प्रतिशत से अधिक है। यह जांच की अवधि में क्षमता में वृद्धि तथा वायस टायरों को रेडियल टायरों के लिए क्षमता परिवर्तित करने में कठिनाई के कारण है। इसके अतिरिक्त, क्षमता उपयोग में गिरावट आई है क्योंकि वायस आयरों के विनिर्माता कम हो गए हैं।

यह वायस टायरों की अपेक्षा रेडियल टायरों की प्राथमिकता के कारण हो सकता है। जैसा कि पहले भी नोट किया गया है, वायस टायरों के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन को हुई वास्तविक क्षति को वास्तविक क्षति के मूल्यांकन के लिए अलग किए जाने की आवश्यकता है।

प. रेडियल टायरों की मांग और प्रयोग बढ़ रहा है तथा वायस टायरों के लिए प्राथमिकता में गिरावट आ रही है जिसके कारण वायस टायरों का घरेलू उद्योग निष्पादन में गिरावट दर्शा रहा है। इस गिरावट के प्रभाव याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना में शामिल किए गए हैं।

फ. घरेलू उद्योग को यदि कोई क्षति है तो वह कच्ची सामग्री की कमी के कारण है। विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त एक प्रमुख कच्ची सामग्री कार्बन ब्लैक है। विभिन्न कारणों से भारत में कार्बन ब्लैक के लिए घरेलू आपूर्ति घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं रही है। इसे चीन जन. गण. और रूस के कार्बन ब्लैक के आयातों पर 494 अमरीकी डॉलर/मी.ट. तक अधिक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से और भी खराब कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत में कार्बन ब्लैक की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध सामानों का उत्पादन प्रभावित हुआ तथा घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर भी भारी चोट आई। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि कार्बन ब्लैक की कमी से घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में काफी गिरावट आई है जैसाकि याचिकाकर्ता ने खुद स्वीकार किया है।

ब. विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त दूसरी प्राथमिक कच्ची सामग्री रबड़ है। भारत में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में काफी कमी है और इसीलिए मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतराल है। प्राकृतिक रबड़ जिस पर इस समय 25 प्रतिशत अधिक तक वी सी डी लग रहा है, आयात किया जाना होता है। साथ ही 13 जून, 2018 तक प्राकृतिक रबड़ के आयातों की देश में प्राकृतिक रबड़ की लागतों को जोड़कर भारत में चेन्नई और नाहावा शेवा पतनों से होकर आने की ही अनुमति थी। अन्यथा प्राकृतिक रबड़ की घरेलू कीमतें कम से कम 20 प्रतिशत तक अंतरराष्ट्रीय कीमतों से अधिक हैं। इनका प्रभाव अपोलो द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त, टायर उद्योग अर्थात् एस बी आर, एन बी आर, 6 पी पी डी और नायलोन टायर कोर्ड फैब्रिक द्वारा प्रयुक्त अन्य प्रमुख कच्ची सामग्री भी पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हैं।

भ. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है। वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित कानूनी प्रावधान प्रतिकारी शुल्क नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा- 3 में निहित हैं जिनमें यह उल्लेख है कि “वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा न कि केवल आरोप, अवधारणा अथवा सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन, जो ऐसी स्थिति बनाएंगे जिनमें सब्सिडी से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से पूर्वानुमानित और आसन्न होनी चाहिए।” इसके लिए, माने जाने वाले कारक उसमें सूचीबद्ध हैं। तथापि, चीन सरकार इंकार करती है कि निम्नलिखित कारणों से संबद्ध आयातों के कारण वास्तविक क्षति का खतरा है।

- वास्तविक क्षति के खतरे के अंतर्गत पहला मानदंड “प्रश्नगत सब्सिडी की प्रकृति तथा उससे उत्पन्न होने के लिए संभावित व्यापार प्रभावों” से संबंधित है। तथापि इस शीर्ष अंतर्गत याचिकाकर्ता के तर्क सिद्ध नहीं हैं। दूसरे, विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद की अवधि में काफी गिरावट आई है।
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं जबकि उनकी मांग काफी कम है, जिससे अधिक क्षमताएं हो रही हैं। तथापि, जिन आंकड़ों पर विश्वास किया गया है, वे चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण की क्षमता से संबंधित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त चीन सरकार ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. में कई टायर कारखानों को प्रदूषण कम करने के सरकार के अभियान के परिणाम के रूप में बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं अथवा उत्पादन कम करने के लिए कहा गया है।

म. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की घरेलू विक्री कीमत से कम है। तथापि, यह सिद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने तथा बढ़े हुए वी सी डी लगाए जाने को किसी कीमत आकर्षकता, जो बन सकती है, नकारा गया है।

य. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि टीबीबी और टीबीआर दो अलग-अलग उत्पाद हैं जिनका प्रयोग बाजार में परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जाता है। याचिका से और यहां तक कि लिखित अनुरोध से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता उद्योग ने दोनों टायरों के लिए अलग-अलग क्षति संबंधी सूचना नहीं दी है। आयातों, पहुंच मूल्य, बाजार हिस्सा, उत्पादन बिक्री, क्षमता, क्षमता उपयोग, निर्माण एवं बिक्री की लागत, लाभप्रदता, मालसूची की स्थिति के संबंध में दोनों प्रकार के टायरों के लिए अलग-अलग सूचना के बिना, यदि याचिकाकर्ता उद्योग को कोई क्षति हुई है, तो उसके संबंध में कोई सार्थक टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं। अतः यह हमारा अधिकार है कि हम वांछित सूचना हमें उपलब्ध कराए जाने पर क्षति मानदंडों के संबंध में टिप्पणी करें।

र. क्षति के खतरे के संबंध में यह अनुरोध है कि उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता उद्योग द्वारा दर्शायी गई क्षति पर बहुत गंभीर संदेह हैं। किसी भी दशा में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद याचिकाकर्ता उद्योग के लिए वास्तविक क्षति के खतरे का दावा करने का भी कोई अवसर नहीं है।

कक. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का मूल्यांकन घरेलू बाजार में उपभोक्ताओं की विशेष श्रेणी की तुलना में नहीं किया जा सकता। ओईएम बाजार के संबंध में बिक्री, बाजार हिस्सा आदि को अलग करने की कोई संभावना नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अकेले प्रतिस्थापन बाजार की तुलना में अनिवार्य क्षति मानदंडों के संबंध में मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। यह दावा करने के लिए कोई कानूनी अथवा वास्तविक आधार नहीं है कि प्रतिस्थापन बाजार में घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसे पर्याप्त माना जाना चाहिए।

खख. मूल सीमाशुल्क में वृद्धि तथा रेडियल टायरों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में जांच की अवधि के बाद की अवधि में वृद्धि हुई है। इस प्रकार यदि जांच की अवधि सितंबर, 2017 से आगे बढ़ाई जाती है तो संबद्ध आयातों से कोई कीमत कटौती नहीं होगी।

गग. चीन जन गण से आयातों के कारण जांच की अवधि में कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण तथा घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट के बीच कोई सह संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, पी बी आई टी और नियोजित पूँजी पर आय में जांच की अवधि में गिरावट आई है। तथापि, आयातों में भी जांच की अवधि में गिरावट आई है और जांच की अवधि में कीमत कटौती में भी गिरावट आई है।

घघ. रेडियल टायरों पर पाटनरोधी शुल्क और वढ़े हुए मूल सीमाशुल्क के सुधारात्मक प्रभाव जांच की अवधि के बाद की अवधि में सिद्ध है। उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि भारत में टायर उद्योग सकारात्मक रूप से निष्पादन कर रहा है और वर्ष 2018-19 में बिक्री की मात्रा में 8 प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड करने के लिए निर्धारित है जोकि मांग में वृद्धि के अनुरूप है। उत्तरदाता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें।

ड.ड. संबद्ध आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद की अवधि में काफी गिरावट आई है। इस प्रकार, इस संबंध में वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

397. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देश से समिडीयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की है।

398. समिडी नियमावली का नियम 13 क्षति के निर्धारित को शासित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं।

13. क्षति मार्जिन का निर्धारण

(1) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अगला जांच परिणाम देंगे कि भारत में ऐसे आयात के कारण भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा होता है अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी होती है।

(2) शिवाय इसके कि जब क्षति का जांच परिणाम उप नियम (3) के तहत किया जाता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ नियमावली के अनुबंध-1 में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए किसी उद्योग की स्थापना को क्षति, क्षति का खतरा, वास्तविक मंदी और समिडीयुक्त आयात तथा क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क निर्धारित करेंगे।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी वहां भी क्षति की मौजूदगी के संबंध में जांच परिणाम दे सकते हैं जहां घरेलू उद्योग का काफी भाग क्षतिग्रस्त नहीं है यदि-

(i) यदि अलग-थलग बाजार में सब्सिडीयुक्त आयातों का संकेन्द्रण है, और

(ii) सब्सिडी आयातों से उस बाजार के अंतर्गत लगभग पूरे उत्पादन के उत्पादकों को क्षति हो रही है।

अ. **सब्सिडीयुक्त आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव**

(i) **मांग का मूल्यांकन**

399. भारत में संबंधित उत्पाद की मांग और स्पष्ट खपत भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्री की मात्रा तथा अन्य सभी देशों से आयातों के रूप में परिभाषित की जाती है। यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में आंशिक गिरावट के साथ क्षति की अवधि में मांग बढ़ी है। इस प्रकार निर्धारित मांग निम्नलिखित है:

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	अक्टू. '16-सितं. '17
चीन	मी.ट.	30,665	69,982	81,896	61,203
अन्य देश	मी.ट.	14,564	10,402	9,666	11,145
डी.आई. विक्री	मी.ट.	295,488	347,554	356,128	360,178
अन्य उत्पादक	मी.ट.	54,081	43,631	44,143	21,240
कुल मांग	मी.ट.	394,798	471,569	491,833	453,766

(ii) **आयात**

400. संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है।

401. क्षति की अवधि के लिए पूर्ण दृष्टि से आयातों की मात्रा निम्नलिखित है: प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा 2016-17 तक बढ़ी है परंतु जांच की अवधि के दौरान कम हुई है।

विवरण	यू.ओ.एम	2014-15	2015-16	2016-17	अक्टू. '16-सितं. '17
आयात मात्रा					
चीन	मी.ट.	30,665	69,982	81,896	61,203
अन्य देश	मी.ट.	14,564	10,402	9,666	11,145
कुल	मी.ट.	45,229	80,384	91,562	72,348
आयातों में हिस्सा					
चीन	%	68%	87%	89%	85%
अन्य देश	%	32%	13%	11%	15%
कुल	%	100%	100%	100%	100%

402. क्षति की अवधि के दौरान भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात की मात्रा निम्नलिखित है: प्राधिकारी यह देखते हैं कि भारत में उत्पादन तथा खपत के संबंध में आयात की प्रवृत्ति पूर्ण दृष्टि से आयातों की तरह वही प्रवृत्ति अपनाती है। भारत में उत्पादन तथा खपत के संबंध में आयातों में 2016-17 तक वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

विवरण	यू.ओ.एम	2014-15	2015-16	2016-17	अक्टू. '16-सितं. '17
के संबंध में संबद्ध देश के आयात					
भारतीय उत्पादन	%	8%	16%	18%	14%
खपत	%	8%	15%	17%	13%
डी आई विक्री	%	68%	87%	89%	85%

(iii) **बाजार हिस्सा**

विवरण	यू.ओ.एम	2014-15	2015-16	2016-17	अक्टू. '16-सितं. '17
मांग में बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश	%	8%	15%	17%	13%
अन्य देश	%	4%	2%	2%	2%
डी आई घरेलू विक्री	%	75%	74%	72%	79%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	14%	9%	9%	5%
कुल	%	100%	100%	100%	100%

403. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश का बाजार हिस्सा 2016-17 तक बढ़ा है और जांच की अवधि के दौरान कम हुआ है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि के दौरान बढ़ा है। तथापि, पी ओ आई के दौरान आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में काफी अधिक रहा था।

II. संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव और उनका घरेलू उद्योग पर प्रभाव

404. कीमतों पर सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना करके सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण काफी कीमत कटौती हुई है अथवा इन सब्सिडीयुक्त आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमत का न्यूनीकरण करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए अन्यथा है जोकि अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत (सीओपी), भारित औसत निवल विक्री वसूली की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

(i) **कीमत कटौती**

405. कीमत कटौती आयातों की पहुंच कीमत की तुलना जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से करके निकाली गई है। निवल विक्री वसूली बाहरी भाड़े और करों को घटाने के बाद निकाली गई है। आयातों का पहुंच मूल्य संबद्ध आयातों के सीआईएफ मूल्य पर लागू उपकर सहित लागू मूल सीमाशुल्क और सार संभाल प्रभार जोड़कर परिकलित की गई है।

विवरण	यू.ओ.एम	2014-15	2015-16	2016-17	पी.ओ.आई
आयात मात्रा	मी.ट.	30,665	69,982	81,896	61,203
आयातों की पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	169	161	169	168
निवल विक्री वसूली	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***

कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	%	20-30	20-30	10-20	10-20

406. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की विक्री कीमत के स्तर के काफी नीचे है और इस प्रकार उनसे घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है। कीमत कटौती क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक है।

(ii) **कम कीमत पर विक्री**

407. प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की क्षतिरहित कीमतें निकाली हैं और उनकी तुलना कम कीमत पर विक्री की मात्रा तक पहुंचने के लिए आयातित सामानों के पहुंच मूल्य से की है। जांच की अवधि के दौरान कम कीमत पर विक्री सकारात्मक है।

उत्पादक/निर्यातक का नाम	पहुंच मूल्य (अम.डॉ./किग्रा.)	क्षति रहित कीमत (अम.डॉ./किग्रा.)	क्षति मार्जिन (अम.डॉ./किग्रा.)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज
झोंगसे रबड़ ग्रुप कं. लि.	****	****	****	****	30-40%
शानडोंग वांडा बोटो टायर कं. लि.	****	****	****	****	20-30%
शानडोंग योंगफेंग टायर्स कं. लि.	****	****	****	****	20-30%
ट्रिंगले टायर कं. लि.	****	****	****	****	20-30%
एयोलस टायर कं. लि.	****	****	****	****	30-40%
यलो सी रबड़ कं. लि.	****	****	****	****	20-30%
एयूलस टायर कंपनी लि. और किंगडाओ यलो सी रबड़ कं. लि. के लिए भारित औसत					30-40%
अन्य सभी	****	****	****	****	40-50%

(iii) **कीमत ह्रास और न्यूनीकरण**

408. घरेलू उद्योग (डी आई) की विक्री लागत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 4 सूचकांक तक कम हुई है और घरेलू उद्योग की विक्री कीमत उसी अवधि के दौरान 7 सूचकांक तक कम हुई है। संबद्ध देश से आयातों का पहुंच मूल्य आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उसी स्तर पर रहा है।

उत्पादक	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	अक्टू. '16-सितं. '17
विक्री की लागत	रु./किग्रा.	****	****	****	****

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	90	96
विक्री कीमत	रु./किग्रा.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	92	93
पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	100	100

III. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

409. नियमावली में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभावों की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर समिस्डीयुक्त आयातों के प्रभाव की जांच में विक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारक और तत्व; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग के निष्पादन की क्षति की अवधि में जांच की गई है।

(i) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और विक्री

410. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और विक्री के संबंध में क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की विक्री निम्नलिखित थी :

उत्पादक	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	अक्टू. '16-सितं. '17
क्षमता	मी.ट.	429,841	458,974	474,863	496,900
उत्पादन	मी.ट.	343,654	387,508	405,626	418,847
क्षमता उपयोग	%	80%	84%	85%	84%
विक्री मात्रा कुल		342,310	387,511	405,446	422,026

411. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- घरेलू ने उद्योग निरंतर अपनी क्षमता बढ़ाई है।
- घरेलू उद्योग का उत्पादन पूरी क्षति अवधि में और जांच की अवधि में निरंतर बढ़ा है।
- इसी प्रकार घरेलू उद्योग की विक्री पूरी क्षति की अवधि और जांच की अवधि में निरंतर बढ़ी है।
- घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में आधार वर्ष के बाद सुधार हुआ है और फिर उसके बाद लगभग समान रहा है।

(ii) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

412. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नलिखित है :

उत्पादक	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	अक्टू. '16-सितं. '17
विक्री की लागत	रु./किग्रा.	****	****	****	****

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	90	96
विक्री कीमत	रु./किग्रा.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	92	93
लाभ	रु./किग्रा.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	157	113	52
नकद लाभ	लाख रु.	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	157	132	93
पीबीआईटी	लाख रु.	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	185	136	64
निवेश पर आय	%	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	120	80	45

413. उपरोक्त सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

(क) घरेलू उद्योग का लाभ (रु./किग्रा.) जांच की अवधि के दौरान कम हुआ है।
 (ख) इसी प्रकार, घरेलू उद्योग का नकद लाभ, व्याज पूर्व लाभ और निवेश पर आय भी जांच की अवधि के दौरान कम हुआ है।
 (iii) बाजार हिस्सा

414. मांग में बाजार हिस्से के संबंध में क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नलिखित है :

उत्पादक	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	अक्टू. '16-सितं. '17
मांग में बाजार हिस्सा					
संबद्ध दो	%	8%	15%	17%	13%
अन्य दो	%	4%	2%	2%	2%
डी आई घरेलू विक्री	%	75%	74%	72%	79%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	14%	9%	9%	5%
कुल	%	100%	100%	100%	100%

415. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

(iv) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

उत्पादक	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	अक्टू. '16-सितं. '17
कर्मचारियों की संख्या	सं.	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	100	105	104

वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	115	132	145
वेतन एवं प्रति इकाई मजदूरी	रु./किंगा.	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	102	112	119
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./सं.	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	112	113	117
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.ट./दिवस	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	113	118	122

416. जांच अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या, प्रति युनिट वेतन और मजदूरी तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई है। जांच अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में आंशिक गिरावट आई है।

(v) मालसूची

417. घरेलू उद्योग में मालसूची में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

उत्पादक	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	अक्टू. '16-सितं. '17
मालसूची	मी.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	103	132

(vi) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

418. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि नए निवेश जुटाने की क्षमता उत्पाद के सब्सिडीकरण से प्रभावित नहीं है क्योंकि निवेश संबंधी निर्णय दीर्घावधि निर्णय होते हैं और विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्तमान एवं संभावित मांग पर विचार करते हुए लिए जाते हैं। तथापि, विचाराधीन उत्पाद की दीर्घावधि अर्थक्षमता सशक्त लाभदायी व्यापार पर निर्भर करती है।

सब्सिडी प्राप्त आयातों और वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

419. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से सब्सिडी प्राप्त आयातों और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बीच निम्नलिखित के कारण कारणात्मक संबंध सिद्ध होता है।

- (क) भारत में चीन जन. गण. से सब्सिडी प्राप्त आयात काफी अधिक मात्रा में आ रहे हैं।
- (ख) चीन जन. गण. से सब्सिडी प्राप्त आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
- (ग) चीन जन. गण. से सब्सिडी प्राप्त आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और ऐसी कीमत वृद्धि को रोक रहे हैं जो पाटन की अनुपस्थिति में हो गई होती।
- (घ) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय की दृष्टि से विकृति आई है।

iv. वास्तविक क्षति का खतरा

420. वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित प्रावधान सब्सिडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 3 में दिए गए हैं जिनमें निम्नलिखित प्रावधान है :

3. आर्थिक क्षति के खतरे से संबंधित प्रावधान निम्नानुसार है:-

"(3) वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों के आधार पर होगा और न कि मात्र आरोप, अनुमानों अथवा सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन को, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें सब्सिडी के कारण क्षति होती है, स्पष्टतया प्रत्याशित और

आसन्न माना जाना चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे के विद्यमान होने का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे :

- (i) प्रश्नगत सब्सिडी अथवा सब्सिडियों की प्रकृति तथा उनसे उत्पन्न होने वाले संभावित व्यापार प्रभाव;
- (ii) पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए घरेलू बाजार में सब्सिडीयुक्त आयातों की काफी वृद्धि दर।
- (iii) किसी अतिरिक्त निर्यात को लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए सब्सिडीयुक्त नियर्यातों की संभावना दर्शाने वाले नियर्यातिक की, क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य अथवा आसन्न और वृद्धि,
- (iv) क्या आयात इन कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण अथवा ह्लासमान प्रभाव होगा और आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और
- (v) जांच किए जा रहे उत्पाद की मालसूची।

421. वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं :

- क. ऐसी प्रतिकार योग्य सब्सिडियां हैं जो चीन जन गण में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को दी जा रही हैं। चीन जन गण के कुछ सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।
- ख. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की घटती हुई प्रवृत्ति है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के आयात संबद्ध देश के संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण और संबद्ध सामानों पर भारत सरकार द्वारा मूल सीमाशुल्क की दरों में वृद्धि के कारण जांच की अवधि के बाद की अवधि में और कम हुए हैं।
- ग. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमता के ब्यौरों की जांच की है और यह नोट किया जाता है कि किसी भी सहयोगी उत्पादक/निर्यातिक द्वारा कोई पर्याप्त क्षमता नहीं जोड़ी गई है।
- घ. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की मालसूची की बात की है और यह नोट किया जाता है कि उनकी किसी की भी संबद्ध सामानों की काफी मालसूची नहीं है।

422. क्षति के खतरे से संबंधित दावे के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पहले ही यह निष्कर्ष हो चुका है कि घरेलू उद्योग को सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और इसलिए प्राधिकारी के लिए क्षति के खतरे संबंधी निष्कर्ष निकालना अपेक्षित नहीं है।

हितबद्ध प्रक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियां

423. हितबद्ध प्रक्षकारों से प्रकटन पश्चात् किए गए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उनमें उठाये गये मुद्दों को जांच की प्रक्रिया के दौरान पहले ही उठाया गया है और उनका समाधान उपयुक्त रूप से कर दिया गया है। हालांकि, स्पष्टता के वास्ते, हितबद्ध प्रक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच नीचे दिए गए अनुसार उस सीमा तक की जा रही है जिस सीमा तक उसे संगत माना गया है :

ज्ञ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

- 424. प्रति उत्तर के रूप में अनुरोधों, सत्यापन रिपोर्ट, पूरक प्रश्नावली का उत्तर और सभी योजनाओं के लिए सब्सिडी मार्जिन की गणना की कार्यपद्धति की प्रति प्रकट नहीं की जानी चाहिए।
- 425. निर्धारित सब्सिडी मार्जिन टायर की जांचों के लिए अन्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सब्सिडी मार्जिन की तुलना में बहुत कम है।
- 426. यूरोपीय संघ ने एओलस के लिए 32.85 प्रतिशत की सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया है जबकि भारतीय प्राधिकारी ने एओलस के लिए 0-10 प्रतिशत का सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है यद्यपि जांच की अवधि इन दोनों जांचों के बीच परस्पर व्याप्त हो रही है।
- 427. प्राधिकारी ने सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए लाभ तथा सब्सिडी मार्जिन के प्रतिशत का निर्धारण करने के लिए विभाजक हेतु उपयोग में लाए गए बैंच मार्क को प्रकट नहीं किया है।
- 428. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण करते समय संबद्ध कंपनियों द्वारा प्राप्त सब्सिडी की जांच नहीं की है।

429. वर्तमान मामले में सब्सिडी की मात्रा के निर्धारण के लिए लागू की गई कार्य पद्धति (क) पूर्व की दो जांचों में लागू की गई कार्यपद्धति और (ख) अन्य प्राधिकारियों द्वारा लागू की गई कार्य पद्धति से वास्तविक रूप से अलग है। चीन के बैच मार्कों पर विचार अंतर्राष्ट्रीय बैच मार्क के बजाय लाभ का निर्धारण करने के लिए किया गया है।

430. निर्दिष्ट प्राधिकारी पूर्व की जांच में पाटनरोधी शुल्क में कटौती करने के बाद सब्सिडी मार्जिन की मात्रा के रूप में प्रतिकारी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की थी क्योंकि पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क मार्जिन दोनों गैर-चीनी बैच मार्कों के आधार पर थे। हालांकि, वर्तमान मामले में अपनाए गए बैच मार्क कच्चे मालों के प्रावधान के लिए घरेलू बैच मार्क हैं और इस कारण से पूर्व के दो मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क तथा प्रतिकारी शुल्क जिसका निर्धारण घरेलू सब्सिडी के लिए किया गया है, का हकदार है यदि इस प्रकार की शुल्क राशि घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन की तुलना में कम हो।

431. जांच की अवधि इस प्रतिकारी शुल्क जांच और पाटनरोधी जांच में अलग अलग है और इस कारण से यह सिद्ध नहीं किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क पाटन और सब्सिडी की उसी स्थिति के लिए है।

432. जब इस कार्यक्रम को जांच की अवधि के बाद समाप्त कर दिया गया हो, तब इस जांच को उसके संबंध में समाप्त नहीं किया जा सकता है (उदाहरण के लिए कार्यक्रम सं. 1)। जब इस कार्यक्रम को जांच की अवधि के दौरान अथवा उसके पूर्व समाप्त कर दिया गया हो तब इस जांच को उस स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक यह दर्शाया नहीं गया हो कि उसके संबंध में जांच की अवधि के दौरान कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था (उदाहरण के लिए कार्यक्रम सं. 3 और 4)। जब इस कार्यक्रम को जांच की अवधि के दौरान या उससे पूर्व समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन वही लाभ प्रदान करते हुए एक नई अधिसूचना लागू हो तब इस जांच को समाप्त नहीं किया जा सकता है (उदाहरण के लिए कार्यक्रम सं. 28, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50)।

433. प्राधिकारी से न केवल यह अपेक्षित है कि वे संबद्ध वस्तुओं के संबंध में प्राप्त अनुदानों पर प्रतिकारी शुल्क लगायें बल्कि कंपनी द्वारा प्राप्त सामान्य प्रकृति के सभी अनुदानों पर प्रतिकारी शुल्क लगायें।

434. अन्य जांच प्राधिकारी प्रतिकारी शुल्क योग्य राशि के रूप में कार्यक्रम 4, 17, 18, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 64 और 72 आयोजित करना जारी रख रहे हैं और अनेक संघ्या में इन कार्यक्रमों में सब्सिडी का निर्धारण करना जारी रख रहे हैं।

435. इस निर्धारण के संबंध में की पी-17, 17, 18, 19 और 20 स्थानों में आधारित टायर का कोई निर्माता नहीं है, याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को दर्शाते हुए कि उस क्षेत्र में इसके संयंत्र स्थित हैं एक विस्तृत निर्यातकावार अनुरोध उपलब्ध कराये हैं।

436. इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि कंपनी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, निर्यातक द्वारा केवल एक व्यान दिया गया है और उसे प्रकटन विवरण में स्वीकार किया गया है।

437. यूरोपीय संघ की जांच की अवधि 1 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2017 तक है जो वर्तमान जांच की जांच अवधि अर्थात अक्टूबर, 2016 से – सितंबर, 2017 में परस्पर व्याप्त हैं। टायर के संबंध में यूरोपीय संघ और विभिन्न जांचों में अन्य प्राधिकारियों द्वारा निकाले गये सी वी डी मार्जिन उस मार्जिन से काफी हृद तक अधिक है जिसका निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है। यू एस के प्राधिकारियों ने 38 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक सी वी डी मार्जिन का निर्धारण किया है।

438. प्रकटन विवरण ऐसी किसी योजना को नहीं दर्शाता है जिस पर दोहरे निदान सिद्धांतों का समाधान करने के उद्देश्य से "निर्यात सब्सिडी" के रूप में विचार किया जा सकता है। इस कारण से, निर्दिष्ट प्राधिकारी विचार की गई योजनाओं की संपूर्णता पर पाटनरोधी शुल्कों के लिए समायोजन किए विना सी वी डी शुल्क लगाये जाने के उद्देश्य से विचार किया जाना अपेक्षित है। उत्तर देने वाले चीन के निर्यातकों और जी ओ सी पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि वे निर्यात सब्सिडी को शामिल करें।

439. एओलस टायर कंपनी लिमि. और टाइएंगल टायर कं. लिमि. की वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण यह दर्शाता है कि उत्तर देने वाले दोनों निर्यातकों ने 'सरकारी अनुदानों' के मद के अंतर्गत विभिन्न लाभ प्राप्त किए हैं जो उन अनुदानों के अलावा हैं जिसकी मात्रा का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है, जिसकी सूचना निर्यातकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है और इस प्रकार से उसकी जांच नहीं की गई है। टाइएंगल टायर कं. लिमि. की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कंपनी को वर्ष 2017 में पूर्णस्थापन के लिए सब्सिडी के रूप में बहुत अधिक मात्रा में राशि प्राप्त हुई है।

440. गैर आवृत्ति सब्सिडी जिसे निर्धारित परिसंपत्तियों को अर्जित किए जाने से जोड़ा जा सकता है के लिए, सब्सिडी का कुल मूल्य इन परिसंपत्तियों के सामान्य जीवन काल तक बढ़ाया जाना होगा जिसका अर्थ यह है कि जांच की अवधि के अनेक वर्ष पूर्व दी गई गैर आवृत्ति सब्सिडी पर अभी भी प्रतिकारी शुल्क लगाया जा सकता है और उसकी मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है यदि उसे जांच की अवधि और इस जांच की अवधि के पूर्व भी प्राप्त किया गया हो। उत्तर देने वाले निर्यातकों ने अपने संबद्ध पक्षकारों और मूल कंपनी द्वारा प्राप्त लाभों को उपलब्ध नहीं कराया है।

441. कार्यक्रम सं. 22 से 26 के अंतर्गत, डबल क्वाइन होल्डिंग्स और जी आई टी आई ग्रुप की 2013 के लिए वार्षिक रिपोर्ट याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये थे और सब्सिडी के मार्जिन की मात्रा का निर्धारण किया गया था।

442. पूर्व की जांच की तुलना में मौजूदा जांच की अवधि में क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई। उत्पादन और विक्री में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग के लाभ में अचानक तेजी से गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 और जांच की अवधि के दौरान लाभ और उसके परिणामस्वरूप निवेश पर लाभ में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग स्थिर रहा है। जांच की अवधि की तुलना में माल भंडार में लगभग 32 प्रतिशत वृद्धि हुई।

443. चीन से टी बी आर टायरों के आयातों की पहुंच कीमत टी बी बी टायरों के लिए घरेलू उद्योग की विक्री कीमत की तुलना में बहुत अधिक कम है। इस प्रकार से, इन वस्तुओं का आयात इस देश में उस कीमत से भी कम कीमत पर किया जा रहा है जो भारत में टी बी बी टायर की कीमत है। वर्तमान कीमतों पर घरेलू उद्योग इस उत्पाद की विक्री उस कीमत पर कर रहा है जो क्षति रहित कीमत से कम है और इस कारण से भारतीय उत्पादक इस स्थिति में नहीं हैं कि वे अपनी कीमतों को आयात की कीमतों की सीमा तक कटौती कर सकें। यदि घरेलू उद्योग इस उत्पाद की विक्री उस कीमत पर करे जो आयात की कीमतों के अनुरूप हो, तब इसे वित्तीय हानि उठानी पड़ेगी।

444. वास्तविक क्षति के खतरे की जांच करने में कोई दम नहीं है, प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे वास्तविक क्षति के खतरे की जांच करें। किसी भी मामले में, प्राधिकारी द्वारा किए गए खतरे का विश्लेषण सही नहीं है।

445. स्वतंत्र रूप से विक्री योग्य क्षमता को केवल सहयोगी उत्पादकों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। मौजूदा स्वतंत्र रूप से विक्री योग्य क्षमताओं और उन क्षमताओं में वृद्धि दो अलग और स्पष्ट अपेक्षाएं हैं और उन्हें मिलाया नहीं जा सकता है। चीन से तीसरे देश में निर्यात, निर्यातों की बहुत अधिक मात्रा उस कीमत पर किए जाने का दर्शाता है जो भारत में निर्यात किए गए कीमतों की तुलना में कम है। इस प्रकार से, इस मात्रा को भारत में परिवर्तित होने की भी संभावना है।

ज्ञ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

446. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के उत्तर में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए 5 कार्य दिवस दिए हैं जो व्याप्त नहीं है और इस कारण से आगे टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।

447. प्राधिकारी ने सब्सिडी कार्यक्रमों जिनका निर्धारण प्रतिकारी शुल्क के रूप में किया जाता है, के लिए किसी विशिष्टता का निर्धारण नहीं किया है। इस तथ्य का निर्धारण किए बिना कि यह कार्यक्रम विशिष्ट है कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

448. याचिकाकर्ता द्वारा 9 और 13 के लिए कोई कानूनी आधार नहीं दिया गया है और इस कारण से कार्यक्रम सं. 9 और 13 के लिए किसी प्रतिकारी शुल्क की सिफारिश नहीं की जा सकती है।

449. कार्यक्रम सं. 5, 13, 14, और 15 अनहुई राज्य के लिए विशेष रूप से है। कार्यक्रम 20 विशेष रूप से गुआंगडॉग राज्य के लिए है। कार्यक्रमों के ये दो समुच्चय परस्पर रूप से विशिष्ट हैं। चीन जन. गण. जिसमें संबद्ध इस्पात का निर्यात भारत में किया है, में टायर के उत्पादक कार्यक्रमों के इन दो समुच्चय में से केवल एक का उपयोग कर सकते हैं। इस कारण से प्राधिकारी को सभी अन्य श्रेणियों के लिए सब्सिडी की दर का निर्धारण करते समय कार्यक्रम के इन दोनों समुच्चयों पर विचार नहीं करना चाहिए।

450. राज्य के स्वामित्व वाले वैंकों को सार्वजनिक निकाय के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि वे सरकारी कार्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और वे सरकारी प्राधिकार का उपयोग नहीं कर रहे थे। किसी निर्धारित व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक वैंक का निर्णय सब्सिडी नहीं है। वाणिज्यिक वैंक कानून अनुसार और किसी प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति से बिना किसी हस्तक्षेप के अपने व्यापार संबंधी कार्यचालनों के संबंध में स्वयं के आधार पर निर्णय लेते हैं।

451. प्राधिकारी को भूमि के उपयोग के अधिकारों के प्रावधान और विजली कार्यक्रमों के प्रावधान पर प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाना चाहिए। औद्योगिक भूमि का हक केवल राज्य से औद्योगिक उपकरणों को बोली लगाने के माध्यम से अथवा वैसी ही किसी सार्वजनिक पेशकश करने की प्रक्रिया से दिया जा सकता है। ग्रिड से विजली की खरीद की कीमत औद्योगिक ग्राहकों के लिए

प्रांतीय आधार पर तय की गई सरकारी तरीके से स्थापित कीमत स्तरों का पालन किया। टायर उद्योग के लिए विजली की कोई अधिमान्य दरें नहीं हैं और इस कारण से कीमत के इन स्तरों से टायर उद्योगों को कोई लाभ नहीं मिलता है।

452. किसी प्रतिकारी शुल्क की सिफारिश भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए विजली के प्रावधान और भूमि के उपयोग के अधिकारों का प्रावधान करने के लिए सिफारिश नहीं की जा सकती है क्योंकि समुचित प्रतिफल से कम पर भूमि के उपयोग के अधिकारों का प्रावधान और समुचित प्रतिफल से कम पर विजली के प्रावधान के लिए कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। भूमि के उपयोग के अधिकारों के संबंध में अनुदानों को पहले ही प्राधिकारी द्वारा अनुदान कार्यक्रमों के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते समय शामिल किया गया है।

453. विजली का प्रावधान और भूमि के उपयोग के अधिकारों के प्रावधान के संबंध में अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा अपनाए गए सब्सिडी मार्जिन को इस मामले में इस जांच प्राधिकारी द्वारा अपनाया नहीं जा सकता है।

454. मैसर्स शानडॉग हाओहुआ टायर कं. लिमि., मैसर्स गुआंजाऊ एक्सिड इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी कं. लिमि. और मैसर्स एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लिमि. ने अनुरोध किया है कि उनके लिए अलग अलग सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया जाए यद्यपि उन्होंने संबद्ध वस्तु का निर्यात भारत में नहीं किया है क्योंकि प्रतिकारी शुल्क नियमावली में न्यू शिपर समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।

455. चीन जन. गण. से आयात किया गया रेडियल टायर उन टायरों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता का है जिनकी विक्री घरेलू उद्योग द्वारा की जाती है। शुल्क को लगाना अंतिम उपभोक्ताओं के हित में नहीं है।

456. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में अधिकांश आर्थिक मानदंडों के संबंध में सुधार हुआ है। यदि घरेलू उद्योग को क्षति भी हुई है तब वास्तविक क्षति और सब्सिडी के आधार पर किए गए आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

457. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है क्योंकि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की प्रवृत्ति में गिरावट देखी जा रही है, संबद्ध वस्तुओं के आयातों में जांच की अवधि के बाद की अवधि में कमी आई है, क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि नहीं की गई है और किसी भी सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के पास बहुत अधिक माल भंडार नहीं है।

ज्ञ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

458. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये सभी मुद्रों का उस सीमा तक समाधान किया है जिस सीमा तक उसे संगत पाया गया।

459. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध, प्रश्नावली का उत्तर और उपलब्ध कराई गई प्रकटन से संबंधित टिप्पणियां के अगोपनीय पाठ को सार्वजनिक फाइल में रखा गया है। प्राधिकारी की यह सतत प्रथा है कि हितबद्ध पक्षकारों के प्रति उत्तर के रूप में अनुरोधों को सार्वजनिक फाइल में नहीं रखा जाता है। वर्तमान जांच में भी उसी प्रक्रिया का पालन किया गया है।

460. विगत में प्राधिकारी की एक हितबद्ध पक्षकार की सत्यापन रिपोर्ट को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट करने की कोई प्रथा नहीं है। इसके अलावा, यह सूचना गोपनीय प्रकृति की है और यह सारांश किए जाने के अधीन नहीं है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग की सत्यापन रिपोर्टों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को और अन्य हितबद्ध पक्षकारों की सत्यापन रिपोर्टों को घरेलू उद्योग को प्रकट नहीं करते हैं।

461. टायर की जांचों के लिए अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई अपेक्षाकृत अधिक सब्सिडी मार्जिन के संबंध में दावे के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह दावा सही नहीं है। चीन जन. गण. से कुछ यात्री वाहन और हल्के ट्रक के टायरों के मामले में संयुक्त राज्य द्वारा निर्धारित किया गया सब्सिडी मार्जिन संगत नहीं है क्योंकि इसका संबंध जांच की अलग अवधियों और अलग अलग विचाराधीन उत्पाद से है। कुछ हवा से भरे हुए टायरों, नए अथवा वापस लिये गये जो रबड़ का बना होता है और वह एक तरह का टायर है जिसका उपयोग यूरोपीय संघ द्वारा वसों और लोरियों में, चीन जन. गण. से भाग लेने वाले नमूने लिये गये उत्पादक/ निर्यातक के लिए निर्धारित की गई निम्नतम सब्सिडी मार्जिन 2.06 प्रतिशत था। वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया न्यूनतम सब्सिडी मार्जिन *** है जो यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित किए गए निम्नतम

सब्सिडी मार्जिन की तुलना में बहुत अधिक है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य और जांच की प्रक्रिया के दौरान हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सत्यापन योग्य सूचना के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सब्सिडी का मार्जिन का निर्धारण चीन जन. गण. में टायर के उत्पादकों जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया, के लिए किया जाना अपेक्षित है। उत्पादक/निर्यातक जिन्होंने संबद्ध उत्पादक का निर्यात यूरोपीय संघ में किया और जिनकी जांच यूरोपीय संघ द्वारा की गई थी उन उत्पादकों/निर्यातकों से भिन्न थे जिन्होंने संबद्ध उत्पाद का निर्यात भारत में किया और इस कारण से सब्सिडी का मार्जिन दोनों जांचों में अलग अलग है।

462. इस दावे के संबंध में की संयुक्त राज्य द्वारा ट्रक और बस के टायरों में सब्सिडी का मार्जिन 20.68 प्रतिशत से 63.34 प्रतिशत के बीच है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य के निर्णय और वर्तमान जांच के बीच तुलना उचित नहीं है। 20.68 प्रतिशत से 63.34 प्रतिशत का सब्सिडी मार्जिन चीन जन. गण. के अलग अलग टायर उत्पादकों अर्थात् गुईज्जाऊ टायर ग्रुप, डबल क्वाइन ग्रुप और कुनलुन टायर के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण संयुक्त राज्य द्वारा किया गया था और यह जांच की एक अलग अवधि अर्थात् जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 के लिए था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य 20.68 प्रतिशत से 63.34 प्रतिशत के सब्सिडी के मार्जिन की गणना करने के लिए निर्णय अनुदान संबंधी कार्यक्रमों, अधिमान्य ऋण कार्यक्रमों के लिए और विजली, कच्चे माल (कार्बन ब्लैक, नाइलॉन कार्ड, सिंथेटिक रबड़ और दुटाडाइन, प्राकृतिक रबड़) और भूमि के उपयोग के अधिकारों के लिए उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों को लागू करने के आधार पर था।

463. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी विशेष उत्पाद पर प्रतिकारी शुल्क की जांच के लिए अलग अलग जांच प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किये गये सब्सिडी के मार्जिन एक ही होने चाहिए। सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण भाग लेने वाले उत्पादकों और निर्यातकों, चीन की सरकार और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य और रिकार्ड पर उपलब्ध अन्य तथ्यों पर भी, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर है। ट्रक और बस के टायरों के लिए यू.एस और ई.यू. द्वारा निर्धारण किये गये अलग अलग सब्सिडी का मार्जिन अपने आप यह दर्शाता है कि विचाराधीन उसी उत्पाद के लिए अलग अलग प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया सब्सिडी मार्जिन, सामान्य रूप से अलग अलग है।

464. इस दावे के संबंध में की यूरोपीय संघ द्वारा एओलस के लिए निर्धारित किया गया सब्सिडी मार्जिन 32.85 प्रतिशत है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 32.85 प्रतिशत के सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण यूरोपीय संघ द्वारा अनेक कंपनियों से बने चीन नेशनल टायर ग्रुप के लिए पूर्ण रूप से किया गया था। एओलस टायर कं. लिमि. नेशनल टायर ग्रुप ने कंपनियों में से एक कंपनी है। वर्तमान जांच में, एओलस टायर कं. लिमि. और इसकी संबंधित क्वार्ंगडाओ येलो सी रबड़ कं. लिमि. ने भाग लिया है क्योंकि केवल उन्होंने ही जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उनके दोनों द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी की विधिवत जांच की है और दोनों के लिए उपयुक्त सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नेशनल टायर ग्रुप के लिए अधिमान्य वित्त पोषण के संबंध में सब्सिडी का मार्जिन यूरोपीय संघ द्वारा उपलब्ध तथ्यों पर आंशिक रूप से विश्वास करते हुए किया गया था जबकि भारतीय प्राधिकारी ने एओलस टायर कं. लिमि. और क्वार्ंगडाओ येलो सी रबड़ कं. लिमि. द्वारा आपूर्ति की गई सत्यापित सूचना के आधार पर अधिमान्य ऋण के संबंध में सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा उचित प्रतिफल से कम के लिए विजली का प्रावधान, उचित प्रतिफल से कम भूमि के उपयोग के अधिकारों के प्रावधान और एओलस टायर कं. लिमि. के लिए आयकर में छूट के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई सब्सिडी का मार्जिन इन सब्सिडियों के लिए यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित किए गए सब्सिडी मार्जिन की तुलना में अधिक है।

465. प्राधिकारी ने जहां भी लागू हुआ सब्सिडी कार्यक्रमों के अपने विश्लेषण में सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए अपनाये गये बैंच मार्क के प्रकार को प्रकट नहीं किया है। इस दावे के संबंध में की प्राधिकारी ने उस आधार को प्रकट नहीं किया है जिस पर सब्सिडी के मार्जिन का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण सी आई एफ कीमत का प्रतिशत के रूप किया जाता है।

466. इस दावे के संबंध में की प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण करते समय संबद्ध कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी की जांच नहीं की है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी पर वर्तमान जांच में उस सीमा तक विधिवत विचार किया गया है जिस सीमा तक इसे संगत माना गया। उदाहरण के लिए, ज्ञोंगसी रबड़ ग्रुप कं. लिमि. के लिए सब्सिडी का मार्जिन, इसकी तीन सहायक कंपनियों जो जॉब कार्य के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगा हुआ था, द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी का निर्धारण करते समय इस पर विधिवत विचार किया गया था। एओलस टायर कंपनी लिमि. की सभी संबंधित कंपनियों में से, केवल क्वींगडाओ येलो सी रबड़ कं. लिमि. जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में लगा हुआ था। तदनुसार, प्राधिकारी ने एओलस टायर कं. लिमि. और क्वींगडाओ येलो सी रबड़ कं. लिमि. के लिए सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और इस प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किये गये अनुसार सूचना के आधार पर किया है।

467. इस दावे के संबंध में की भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा प्राप्त की गई पुनर्स्थापन से संबंधित राशि पर विचार अनुदान के रूप में किया जाना चाहिए और इस पर प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा प्राप्त की गई पुनर्स्थापन संबंधी मुआवजा पर विचार अनुदान के रूप में किया गया है और इस प्रकार के अनुदान कार्यक्रम के लिए सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण किया गया है।

468. इस दावे के संबंध में की जांच की अवधि के पूर्व और ए यू एल की अवधि के दौरान पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबद्ध गैर आवृत्ति सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए प्राप्त किये गये लाभ पर भी प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जहां भी ये अनुदान परिसंपत्तियों से संबंधित हैं, भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों ने उन्हें आस्थगित आय, संबंधित परिसंपत्ति का औसत उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि एक प्रतिशेधित और जहां ये अनुदान आय से संबंधित हैं, भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों ने उसकी पहचान उस विशिष्ट वर्ष जिसमें इसे प्राप्त किया गया था, के लिए लाभ और हानि में 'अन्य आय' अथवा 'गैर-प्रचालन संबंधी आय' के रूप में उन्हें तत्काल पहचाना है। किसी भी प्रकार से इस राशि को उस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है जिसमें यह प्राप्त हुआ है। संपूर्ण अनुदान राशियों को उस वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया जाता है जहां यह उस परिसंपत्ति के औसत उपयोगी जीवन के प्रत्येक वर्ष जहां यह सम्पत्ति से संबंधित हो, की वार्षिक रिपोर्ट में एक परिशेषित राशि के रूप में आय से संबंधित अथवा उसे दर्शाया गया हो। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में आय से संबंधित अनुदानों तथा परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों दोनों पर प्रतिकारी शुल्क लगाया है।

469. इस दावे के संबंध में की भाग लेने वाले उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्टों में रिपोर्ट किए गए सभी अनुदानों पर अनुदान कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाना अपेक्षित है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसने भाग लेने वाले सभी उत्पादकों/ निर्यातकों की वार्षिक रिपोर्टों की जांच की है और अनुदान कार्यक्रमों के लिए कुल सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण करने के वास्ते अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्ट किये गये सभी अनुदानों पर विचार किया है।

470. इस दावे के संबंध में की वर्तमान जांच में सब्सिडी की मात्रा का निर्धारण करने के लिए लागू की गई कार्य पद्धति पूर्व की दो जांचों में लागू की गई कार्य पद्धति और उस कार्य पद्धति जिसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा लागू किया गया है, से अलग है और यह कि अंतर्राष्ट्रीय बैंच मार्कों का उपयोग वर्तमान जांच में कच्चे माल के प्रावधान के लिए लाभ का निर्धारण करने हेतु नहीं किया गया है, प्राधिकारी नीचे दिए गए अनुसार नोट करते हैं:

- i. प्राधिकारी ने विश्व व्यापार संगठन के एस सी एम करार के प्रावधानों के संबंध में, प्रतिकारी शुल्क नियमावली और अपनी सतत प्रथा के अनुसार वर्तमान जांच में में सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण किया है।
- ii. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुचित प्रतिफल से कम पर भूमि के उपयोग के अधिकारों के प्रावधान के लिए सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण किया है।

iii. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुचित प्रतिफल से कम पर विजली के प्रावधान के लिए सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण किया है जो बाद में हैंट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील फ्लैट उत्पादों के संबंध पूर्व के प्रतिकारी शुल्क से संबंधित जांच में भारतीय प्राधिकारी के निर्णय पर आधारित है।

iv. समुचित लाभप्रद से कम के लिए कच्चे मालों के प्रावधान के संबंध में सबसे प्राधिकारी ने इस तथ्य के बारे में एक विस्तृत जांच की कि कौन से कच्चे मालों को राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों से भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा खरीद की गई है। उसके बाद प्राधिकारी ने राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों से खरीद की कीमत की तुलना निजी उपक्रमों से खरीद की कीमत के साथ और आयात की कीमत/ अंतर्राष्ट्रीय बैंच मार्क से की, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली प्रतिष्ठानों से खरीदे गए तीन प्राथमिक कच्चे माल प्राकृतिक रबड़, सिंथेटिक रबड़ और कार्बन ब्लैक हैं।

v. जहां तक प्राकृतिक रबड़ का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राथमिक रूप से इसका आयात चीन में किया जाता है और राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों से घेरेलू विक्री बहुत कम होती है। राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम से खरीद कीमत भी आयात किये गये उत्पाद की कीमत से तुलनीय है।

vi. जहां तक सिंथेटिक रबड़ का प्रश्न प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों ने राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों तथा निजी उपक्रमों से सिंथेटिक रबड़ की खरीद की है और इसके साथ ही उसका आयात किया है। प्राधिकारी ने राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों से खरीद की कीमत की तुलना निजी प्रतिष्ठानों से खरीद की कीमत तथा आयात किये गये उत्पाद की कीमत से की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम से खरीद की कीमत निजी प्रतिष्ठानों से खरीद की कीमत तथा आयात किये गये उत्पाद की कीमत से तुलनीय है।

vii. जहां तक कार्बन ब्लैक का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों ने राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों तथा निजी प्रतिष्ठानों से कार्बन ब्लैक की खरीद की है। भाग लेने वाले किसी भी उत्पादकों/ निर्यातकों ने कार्बन ब्लैक का आयात नहीं किया है। तुलना के उद्देश्य से प्राधिकारी ने कोरिया जन. गण. से भारत में कार्बन ब्लैक की आयात कीमत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बैंच मार्क पर विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ट्राइएंगल टायर कं. लिमि. और जॉनसनी रबड़ ग्रुप लिमि. को छोड़कर भाग लेने वाले सभी उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम से खरीद की कीमत निजी प्रतिष्ठानों से खरीद की कीमत और प्राधिकारी द्वारा अपनाये गये अंतर्राष्ट्रीय मानदंड से की जा सकती है। तदनुसार, प्राधिकारी ने राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम को भुगतान की गई कीमत और अंतर्राष्ट्रीय बैंच मार्क के बीच अंतर के आधार पर ट्राइएंगल टायर कं. लिमि. और जॉनसनी रबड़ ग्रुप लिमि. के लिए लाभ का निर्धारण किया है।

viii. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य द्वारा चीन जन. गण. से ट्रक और बस के टायरों के संबंध में प्रतिकारी शुल्क की जांच में, संयुक्त राज्य ने राज्य के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों द्वारा वसूली गई कीमत और भाग लेने वाले चीन की कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई वास्तविक आयात खरीद कीमत के बीच अंतर की तुलना कर चीन जन. गण. से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण किया।

ix. एस सी एम करार के अंतर नियम 14(घ) में यह प्रावधान है कि वस्तुओं के प्रावधान के मामले में, प्रतिफल की पर्याप्तता का निर्धारण प्रावधान के देश में प्रश्नगत वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए प्रचलित बाजार स्थितियों (कीमत, गुणवत्ता, उपलब्धता, विपणन की क्षमता, दुलाई और खरीद अथवा विक्री की अन्य शर्तों) की तुलना में की जाएगी। प्रतिकारी शुल्क नियमावली के अनुबंध IV, पैरा ख(घ)(i) में यह प्रावधान है कि समुचित प्रतिफल का निर्धारण सामान्य रूप से निर्यातक देश के घेरेलू बाजार पर प्रचलित बाजार स्थितियों के आलोक में किया जाना चाहिए। पैरा ख(घ) (ii) में यह प्रावधान है कि सब्सिडी की राशि वह अंतर होनी चाहिए जो निजी आपूर्तिकर्ताओं से उपलब्ध निम्नतम कीमत और सरकारी कीमत के बीच हो।

x. वसों अथवा लोसियों के लिए उपयोग किए गए एक प्रकार के रबड़ के कुछ हवा से भरे हुए टायरों चाहे वे नए हों अथवा उसे वापस लिया गया हो, के संबंध में प्रतिकारी शुल्क की जांच में, यूरोपीय संघ ने यह निर्धारित किया कि कच्चे मालों अर्थात् कार्बन ब्लैक, नाइलॉन कार्ड, सिंथेटिक रबड़ एवं प्राकृतिक रबड़ के प्रावधान के संबंध में चीन जन. गण. से उत्पादकों/ निर्यातकों को कोई लाभ नहीं दिया गया है।

xi. चीन जन. गण. के उत्पादकों/ निर्यातकों और चीन की सरकार से हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील फ्लैट उत्पादों के संबंध में भारतीय प्रतिकारी शुल्क की जांच में कोई सहयोग नहीं मिला था और हवा से प्रचालित विद्युत जनरेटरों के कॉस्टिंग के संबंध में भारतीय प्रतिकारी शुल्क जांच में चीन की सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला था। इस कारण से इन दोनों प्रतिकारी शुल्क जांचों में, प्राधिकारी ने अनेक सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए तथ्यों पर विश्वास किया था। दूसरी ओर, वर्तमान जांच में चीन की सरकार और चीन जन. गण. से उत्पादकों/ निर्यातकों दोनों ने भाग लिया है और संगत सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध कराई है।

xii. एस सी एम करार में अथवा प्रतिकारी शुल्क नियमावली में गैर बाजार अर्थव्यवस्था की विवेचना के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

471. इस याचिका में कथित सब्सिडी कार्यक्रमों की प्रतिकारनीयता के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रत्येक सब्सिडी कार्यक्रम के लिए विस्तृत विश्लेषण के उल्लेख वाले भाग में प्राधिकारी द्वारा सभी दावों का उत्तर दिया गया है।

472. इस दावे के संबंध में की पाटनरोधी शुल्क के अलावा प्रतिकारी शुल्क की पूरी राशि लगाई जानी चाहिए क्योंकि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में कच्चे मालों के प्रावधान के लिए घरेलू बैंच मार्क अपनाया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के अनुरोध का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह जांच की प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा दिए गए अपने तर्क और किये गये अनुरोध के विपरीत है। घरेलू उद्योग ने सुनवाई के बाद के अपने अनुरोधों में यह कहा था कि यदि पहले से लगाये गये पाटनरोधी शुल्क वर्तमान जांच में निर्धारित किये गये प्रतिकारी शुल्क की तुलना में अधिक है तब किसी भी प्रतिकारी शुल्क की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए, उसे नहीं लगाया जाना चाहिए और उसकी वसूली नहीं की जानी चाहिए। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का यह दावा सही नहीं है कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में कच्चे मालों के प्रावधान के लिए घरेलू बैंच मार्क अपनाया है जिसे पूर्व के भागों में देखा जा सकता है।

473. पाटनरोधी शुल्क उस विचाराधीन उत्पाद पर पहले से ही लागू है जिसका आयात चीन जन. गण. से किया गया है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई कुल सब्सिडी के मार्जिन में निर्यात सब्सिडी और घरेलू सब्सिडी होती है। निर्यात सब्सिडी के संबंध में, सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ब(1)(क) में यह प्रावधान है कि कोई उत्पाद पाटन और निर्यात की सब्सिडी की उसी स्थिति के लिए मुआवजा देने हेतु पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क दोनों के अध्यधीन नहीं होगी। इस प्रकार से, लागू पाटनरोधी शुल्क को कुल प्रतिकारी शुल्क से कम किया जाना अपेक्षित है ताकि सब्सिडी की दोहरी गिनती से बचा जा सके और केवल यदि प्रतिकारी शुल्क लागू पाटनरोधी शुल्क की तुलना में अधिक हो तब अंतर संबंधी राशि की वसूली प्रतिकारी शुल्क के रूप में की जानी अपेक्षित है। यदि प्रतिकारी शुल्क पाटनरोधी शुल्क के अलावा लगाया जाता है तब यह दोहरा निदान होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब्सिडी का निदान दो बार नहीं किया जाता हो अर्थात् 'दोहरा निदान' नहीं हो, तब प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि प्रतिकारी शुल्क पाटनरोधी शुल्क की तुलना में अधिक हो तब अंतर संबंधी राशि की वसूली पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क के अलावा प्रतिकारी शुल्क के रूप में वसूली जाएगी। यह पूर्ण रूप से चीन जन. गण. के विरुद्ध पूर्व के सभी पाटनरोधी जांचों में भारतीय प्राधिकारी द्वारा सतत रूप अपनाई गई विगत प्रथा के अनुरूप है।

474. इसके अलावा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी की सतत प्रथा के अनुरूप दोहरी गिनती से बचने के लिए कुल प्रतिकारी शुल्क से लागू पाटनरोधी शुल्क को कम करने के लिए प्राधिकारी का निर्णय, सनसिटी शीट्स बनाम भारतीय संघ में माननीय सेस्टेट का निर्णय, एस सी एम करार और यू एस – में अपीलीय निकाय का निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क और सी वी डी (चीन) के निर्णय के अनुरूप है।

475. इस दावे के संबंध में की वर्तमान मामले में कोई निर्यात विशिष्ट सब्सिडी नहीं है और तदनुसार, लागू पाटनरोधी शुल्क को कम करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अनेक निर्यात विशिष्ट सब्सिडी हैं जिन पर प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच में प्रतिकारी शुल्क लगाया गया है और तदनुसार प्रतिकारी शुल्क की सिफारिश करते समय लागू पाटनरोधी शुल्क को कम किये जाने की आवश्यकता है।

476. क्षति के खतरे के संबंध में किये गये इस दावे के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह निष्कर्ष पहले ही निकाला जा चुका है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और इस कारण से प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे क्षति के खतरे के लिए निष्कर्ष उपलब्ध करायें।

477. इस दावे के संबंध में की प्रतिकारी शुल्क नियमावली में नई शिप्पर की समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है और इस कारण से अलग अलग सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण उन उत्पादकों के लिए किया जाना चाहिए जिन्होंने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जिस व्यापार संगठन के एस सी एम करार के अनुच्छेद 19.3 में निर्यातकों के लिए जिनकी वास्तव में सहयोग करने से इनकार करने के अलावा किन्हीं अन्य कारणों से जांच नहीं की गई थी, के लिए 'तेजी से की गई समीक्षा' का प्रावधान है। इस कारण से चीन जन. गण. के नए उत्पादकों/ निर्यातकों अर्थात् वे जिन्होंने जांच की अवधि में भारत में संबद्ध उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, उस स्थिति में न्यू शिपर समीक्षा आरंभ करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं यदि उन्होंने जांच की अवधि के बाद संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है।

478. अतिरिक्त समय के संबंध में दावे के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसने पहले ही इन हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त समय दिया है और आगे कोई समय इन हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए नहीं दी जा सकती हैं क्योंकि यह जांच समयबद्ध है। यह प्राधिकारी की सतत् प्रथा है कि प्रकटन के संबंध में इन टिप्पणियों के अनुसरण में आगे कोई अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाए।

479. सब्सिडी कार्यक्रमों की प्रतिकारनीयता के संबंध में प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि जब वित्तीय अंशदान, लाभ और विशिष्टता हो तब सब्सिडी कार्यक्रम प्रतिकारनीय है। प्राधिकारी इस जांच परिणाम में प्रत्येक सब्सिडी कार्यक्रम के लिए दी गई व्याख्या का संदर्भ लेते हैं। प्राधिकारी ने प्रत्येक मामले में सब्सिडी के मार्जिन के निर्धारण के लिए कार्य पद्धति का खुलासा नहीं किया है और इन सब्सिडी कार्यक्रमों में से प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अपने विश्लेषण में इस प्रकार की कार्य पद्धति के लिए व्याख्या उपलब्ध कराई है।

480. इस दावे के संबंध में की किसी प्रतिकारी शुल्क की सिफारिश उन कार्यक्रमों के लिए नहीं की जा सकती है जिनके लिए कोई कानूनी आधार नहीं दिया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा सूचना के आधार पर अथवा प्राधिकारी के पास रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर अंतिम अंशदान, लाभ और विशिष्टता के मौजूद होने के बारे में पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी इस प्रकार के सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश कर सकते हैं।

481. इस दावे के संबंध में की कार्यक्रम सं. 5, 13, 14 और 15 और कार्यक्रम सं. 20 आपसी आधार पर अलग अलग हैं और कार्यक्रमों के दोनों समुच्चय पर 'अन्य सभी' दर का निर्धारण करते समय प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 'अन्य सभी' श्रेणी के लिए प्रतिकारी शुल्क की सिफारिश कार्यक्रम के केवल एक समुच्चय के विरुद्ध की गई है।

482. इस दावे के संबंध में की राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और प्रतिष्ठानों जो विजली उपलब्ध करा रहे हैं पर विचार सार्वजनिक निकायों के रूप में नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे सरकारी कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा सरकार के अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन की सरकार द्वारा अथवा इस प्रकार के राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और प्रतिष्ठानों द्वारा चीन की सरकार के माध्यम से यह दर्शनी के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि वे सरकारी कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा सरकारी प्राधिकारी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। प्राधिकारी ने रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर यह निर्धारित किया है कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंक और प्रतिष्ठान जो विजली उपलब्ध करा रहे हैं, सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(1)(क) के अभिप्राय से सार्वजनिक निकाय हैं। इसके अलावा यदि विजली उपलब्ध कराने वाले राज्य के स्वामित्व

वाले वित्तीय संस्थाओं और प्रतिष्ठानों पर सार्वजनिक निकायों के रूप में विचार नहीं किया जाना था तब प्राधिकारी ने यह पाया कि उन्हें सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(1)(क)(iv) के आशय से सरकार में सामान्य रूप से निहित कार्यों को करने के लिए चीन की सरकार द्वारा सौंपे गए अथवा निदेशित माना जायेगा।

483. इस अनुरोध के संबंध में की चीन में वाणिज्यिक बैंक किसी अन्य प्रतिष्ठान से किसी हस्तक्षेप के बिना उनके अपने निर्णय के आधार पर ऋण उपलब्ध करते हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना ने यह दर्शाया कि कुछ मामलों में राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से प्राप्त किया गया ऋण पीपल्स बैंक औफ चाईना द्वारा अधिसूचित व्याज दर की तुलना में निम्नतर व्याज दर पर था। इस कारण से प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा अधिमान्य ऋण कार्यक्रम के रूप में टायर के उत्पादकों/ निर्यातिकों को लाभ प्रदान किया गया है।

अ. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

484. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने का उद्देश्य सामान्य तौर पर सब्सिडी की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। प्रतिकारी शुल्क लगाये जाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

485. प्रतिकारी शुल्कों को लगाये जाने से सब्सिडी के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभों को समाप्त किया जायेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जायेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्ध बनाये रखने में मदद मिलेगी।

ट. सिफारिशें

486. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोधी जांच को आरंभ किया गया था और चीन जन. गण. की सरकार सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंधों के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। निर्धारित नियमावली के संबंध में सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंधों की जांच आरंभ किए जाने और पूरा कर लिये जाने तथा इस प्रकार के सब्सिडीयुक्त आयातों से हुई घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति तथा सकारात्मक सब्सिडी मार्जिन को सिद्ध किए जाने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि निश्चयात्मक प्रतिकारी शुल्क लगाना सब्सिडी और क्षति को प्रति संतुलित करने के लिए अपेक्षित है। इस कारण से प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं कि नीचे दिए गए रूप में और निर्धारित तरीके से चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिकारी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की जाए।

487. प्राधिकारी द्वारा अपनाये गये कमतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से सब्सिडी के मार्जिन और क्षति का मार्जिन नीचे कमतर के बराबर निश्चयात्मक प्रतिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त की जा सके। चूंकि, विचाराधीन उत्पाद पर चीन जन. गण. के पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लग रहा है अतः लगाई जाने वाली प्रतिकारी शुल्क की मात्रा और भुगतान किये जाने वाले पाटनरोधी, यदि कोई हो, के बीच हो। यदि प्रतिकारी शुल्क भुगतान किये जाने वाले पाटनरोधी शुल्क से कम हो तब अंतर संबंधी राशि ऋणात्मक होगी और कोई भी प्रतिकारी शुल्क ऐसे मामले में नहीं वसूला जायेगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्षक/ उप-शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	उत्पत्ति के देश	निर्यातिक देश	उत्पादक	सी आई एफ मूल्य के % के रूप में शुल्क की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1.	40112010	बसों और लॉरियों / ट्रकों में उपयोग किए जाने वाले "नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर के ट्यूब सहित या रहित और /या रबड़ के फ्लैप (ट्यूबलेस टायर सहित) जिनका 16 से नाममात्र अधिक रिम व्यास कोड हो	चीन गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	झाँगसी रबड़ ग्रुप कं. लिमि.	9.55%
2.	- उपरोक्त -	- उपरोक्त -	चीन गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	शानडॉग वंडा बोटो टायर कं. लिमि.	9.18%
3.	- उपरोक्त -	- उपरोक्त -	चीन गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	ट्राइएंगल टायर कं. लिमि.	12.23%
4.	- उपरोक्त -	- उपरोक्त -	चीन गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	शानडॉग योरफेंग टायर्स कं. लिमि.	9.12%
5.	- उपरोक्त -	- उपरोक्त -	चीन गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	एयोलस टायर कं. लिमि.	9.66%
6.	- उपरोक्त -	- उपरोक्त -	चीन गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	किंगडाओ येलो सी रबड़ कं. लिमि.	9.66%
7.	- उपरोक्त -	- उपरोक्त -	चीन गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	क्र. सं. 1 से 6 को छोड़कर कोई भी अन्य उत्पादक	17.57%
8.	- उपरोक्त -	- उपरोक्त -	चीन गण. को छोड़कर कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई भी	17.57%

488. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।

489. इस अंतिम जांच परिणाम के फलस्वरूप निकलने वाले केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जायेगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2019

FINAL FINDINGS

Subject: Countervailing Duty/Anti-subsidy investigation concerning imports of “New Pneumatic Tyres for Buses and Lorries” from People’s Republic of China.

F. No.6/8/2018 DGAD—A. BACKGROUND OF THE CASE

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the “Rules”) thereof:

1. Whereas, Automotive Tyre Manufacturer’s Association (hereinafter also referred to as the “Petitioner/Petitioner Association” or “ATMA”) have filed a petition on behalf of domestic producers, namely, Apollo Tyres Ltd., J.K. Tyre Industries Ltd., MRF Ltd. and Ceat Ltd. (collectively referred as “Domestic Industry”), before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for imposition of Countervailing Duty on imports of “New Pneumatic Tyres for Buses and Lorries” from People’s Republic of China (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. And, whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Petitioners, issued a public notice vide Notification No. 6/8/2018 - DGAD dated 27th March, 2018, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 6 to determine existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

- a) The Authority notified the Embassy of People’s Republic of China in India about the receipt of the present anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 6 supra.
- b) The Authority invited the Government of China PR for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on subsidies and countervailing measures. The consultation was held on 20th March, 2018 in New Delhi, which was attended by the following representatives of the Government of China PR (hereinafter also referred to as GOC):
 - (i) Mr. Liang Hao, Counsellor
 - (ii) Mr. Guo Fang, Deputy Director, Ministry of Commerce, China PR
 - (iii) Mr. Ma Xin, Ministry of Commerce, China PR

c) The Authority issued a public notice dated 27th March, 2018 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating countervailing duty/anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods.

d) The Authority sent a copy of the initiation notification dated 27th March, 2018 to the Embassy of People's Republic of China, known producers/exporters from People's Republic of China, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Petitioner and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

e) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the People's Republic of China in India in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra.

f) The Embassy of People's Republic of China in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the People's Republic of China.

g) The Authority sent questionnaires to the GOC (Govt. of China) in order to seek relevant facts/information with regard to various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred by the GOC. The GOC filed a questionnaire response, which has also been taken into account.

h) The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in People's Republic of China, in accordance with Rule 7(4) of the Rules:

S.No.	Name of Exporter	S.No.	Name of Exporter
1.	Shandong Yinbao Tire Group Co. Ltd., Taitou Industrial Zone, Shouguang City, Shandong Province, China - 262735	2.	Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co Ltd. Dawang Economic Zone Guangrao County Shandong China- 257335
3.	Aeolus Tyre Co. Ltd. No. 48, Jiaodong South Road, Jiaozuo, Henan, China- 454003	4.	Zhaoyuan Liao Rubber Products Co., Ltd. No. 777, Jinlong Road, Zhaoyuan, Yantai, Shandong, China-265400
5.	Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. 95 Qingdao Road, Jiaonan Development Zone, Qingdao, China- 266400	6.	Hangzhou ZhongCe Rubber Co., Ltd., No. 2 the 10 th Ave., Economic Development Area, Zhejiang Province, China-310008
7.	Haoyou Tyre Co., Ltd Middle Section Of Fengxu Rd., Industrial Park, Bo'ai, Jiaozuo Henan Province, China-454450	8.	Triangle Tyre Co. Ltd. 56 Middle Qingdao Road, Weihai, Shandong Province, China-264200
9.	Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd. 68 Yongshen Road, Dongying City, Shandong Province, China-257506	10.	Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd. Shanghai Municipality No. 63, Sichuan Central Rd., Shanghai, Shanghai, China-200002
11.	Jiangsu General Science Technology Co., Ltd.	12.	Doublestar-Dongfeng Tyre Co., Ltd. No. 221, Hanjiang Road,

	Hongdou Industrial Zone, Gangxia Town, Wuxi City, Jiangsu Prov. China-214199		Shiyan, Hubei, China-442053
13.	Giti Radial Tire(Anhui) Company Ltd. No. 18, Shixin Road, Hefei EcotechDevelopment Zone, Hefei Anhui, China- 230601	14.	Shenzhen Yuanyunxiang Trading Co., Ltd. 2702 Haitiange, Hailonghuayuan, Fenghuang Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong Province, China-518002
15.	Qingdao Yellow Sea Rubber Company Limited No. 1 Cangan Road, Qingdao, Shandong Province, China-266041	16.	Kenda Rubber (China) Co., Ltd. No.2, Kunjia Rd., Penlang Town, Kunshan, Suzhou, Jiangsu, Jiangsu Province, China 215333
17.	Shengtai Group Co., Ltd. Xishui Industrial Park of Guangrao Country Shandong Province, China-257336	18.	Pirelli Tyre Co., Ltd. Yinhe Industrial Park, Yanzhou, Jining,Shandong Province, China- 272100
19.	Guang Rao Economic & Technology Development Zone, Dongying, Shandong Province, China-257300	20.	Dingying ZhongYi Rubber Co., Ltd. Dawang Economic Developing Zone, Guangrao Dongying Shandong Province, China-257335
21.	Kupo Chengshan (Shandong) Tyre Co., Ltd. No. 98, Nanshan N. Rd., Rongcheng, Weihai,	22.	Shen Zhen City Hong Yun Cai Trade Co., Ltd. No. 12 H Yinboge, Haihui Mansion, Nanyou Avenue, Shenzhen, Guangdong Province, China – 518000
23.	Shenzhen Diruolan Trade Co., Ltd. No. 4, Lane 5, Xinsanqu, Zhenpuling Road, Nanlian Xiang, Longgang Town, Longgang District, Shenzhen Guangdong Province, China- 518116	24.	Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd. Tanbu Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China-510828
25.	Micheling (Sheyang) Tyre Co., Ltd. No. 15 Shenxin Rd. Economic- Technologic Development Zone, Shenyang Liaoning Province, China-110141	26.	Pirelli Tyre Co., Ltd. Yinhe Industrial Park, Yanzhou, Jining, Shandong Province, China-272100
27.	Qingdao Duoublestar Tire Industrial Co., Ltd. 95 Quingdao Road, Jiaonan Development Zone Qingdao, China – 266400	28.	Qingdao Yellow Sea Rubber Company Limited, No. 1 Cangan Road, Qingdao, Shandong Province, China-266041
29	Shandong Xingyuan International Trading Xishui Industrial Zone, Guangrao County Dongying City, Shandong Province China-257336		

i) In response, the following exporters/producers from the subject country filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:

- i.M/s. Shandong Haohua Tire Co. Ltd.
- ii.M/s. Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd.
- iii.M/s. HK Trade Wind Trading Ltd.
- iv.M/s. Aeolus Tyre Co. Ltd.
- v.M/s. Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd.
- vi.M/s. Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd.
- vii.M/s. Zhongce Rubber Group Co. Ltd.
- viii.M/s. Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.
- ix.M/s. Triangle Tyre Co. Ltd.

j) Pursuant to the initiation notification, apart from the above producers/ exporters from the subject country, Government of China PR also filed the questionnaire response.

k) The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:

S.No.	Name of Importer	S.No.	Name of Importer
1.	A.G. Industries Near Petrol Pump, Opp. Bus Stand, Sirsa Road, Hisar/Haryana Pin-110065	2.	A.S. & Company 2343, Tilak Bazar Khari Baoli, Delhi Pin-110006
3.	Aditya Sales Corporation, 333, Sant Nagar, East Of Kailash, New Delhi – 110065	4.	Agk Digital Private Limited, 703 Krishna Apra Business Square, Plot No. D-4/5/6, Netaji Subhash Place, Delhi-110034
5.	Adkhil Impex Building R.K.Associates, Sehdev Market Jalandhar, Pin-144001	6.	Alliance Traders, 2 nd Floor, T-770 Dcm Road Kishan Ganj Delhi
7.	Amitt Enterprises, Near Perfect Marriage Palace, Ambala Bye Pass Road, Near Samrala Chowk, Ludhiana- 141009	8.	Arora Enterprises, 51/45 Bajoria Market, Nayaganj Kanpur, Uttar Pradesh, Pin-208001
9.	Asis Enterprises 2, Gurunanak Niwas, Dongri Pada, King Kong Nagar, G.B.Road, Thane West, Thane, Maharashtra	10.	Bhagwatee Impex Cabin No.-6, 294, Basement, Sant Nagar, East Of Kailash, New Delhi- 110065
11.	Captown Overseas C 244, Minto Road Complex, New Delhi	12.	Celite Tyre Corporatin B/16, Bihari Apartments, Nr. Welcome Hotel, R.C.Dutt Road, Baroda-390007
13.	Chadha Tyre Traders 69, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035	14.	Chhabra Sales Corporation 122/235, Sarojini Nagar, New Delhi
15.	Dashmesh Trading Co. 804/B, Odesscy Bhakti Park, Wadala Nr. Imax Cinema, Mumbai Maharashtra-400037	16.	Deep Enterprises Laladiggi Ganaesh Ganj, Mirzapur, UP-231001

17.	Delhi Tyre Shoppe F-7, East Of Kailash, New Delhi-110065	18.	Eknoor Tyres Private Limited. M.H Building No. 1 R.C. Marg, Chembur, Mumbai
19.	Electro Link 5/356 B,C & D, Eswaramangalam, Ponnani, Malapurram, Kerala, India Pin-679573	20.	Ess Infraproject Private Limited William Compound, Off. Marve Road, Mith Chowli, Malad (W) Mumbai
21.	Fine Traders G-12/334, Gali No. -12 Block-G Sangam, Vihar, Delhi	22.	Fish Aquarium Home H-16, Vikas Marg Laxmi Nagar, Delhi
23.	Ganpati Overseas RZA-72, A Block Dwarka, New Delhi	24.	Genetic Sales Corporation 7A/28, 1 st Floor W.E.A. Karol Bagh New Delhi, Pin-110005
25.	Globus Corporation A-301, Prime Apts. P.P. Marg, Virat Nagar, Virar, West, Mumbai	26.	Gupta Tyre House 328, Auto Market, Hisar/Haryana
27.	H.D.International S Ghee Mandi Amritsar Punjab	28.	H.S.Arora & Co., F-5/1A, Bhagat Singh Market, Sahid Bhagat Singh Marg, New Delhi-110015
29.	H.S.International C-192, Basement, Shop No-2, Pushpanjali Enclave, Pitampura Delhi-110034	30.	Harpreet International B-5 Karampura, Shivaji Marg, New Delhi Pin-110015
31.	Hayer Trading Co Shop No. 2, The Hayer Premium Opp Shishu Vihar, Marathi School, Rambaug Lane No.6, Kalyan-West-421301	32.	Hind Traders, C Wing No. 234, Steel Chamber, Plot No. 514, Kalamboli Steel Market, Navi Mumbai, Maharashtra
33.	Hind Traders Khasra No.9 Sangam Vihar Gali No. 10, Village Wazirabad, Delhi	34.	Indian Rubber Manufacturers Research Association, Plot No. 254/1b, Road No. 16V, Wagle Indl. Estate, Thane West, Mumbai. (M.S.) Pin-400604
35.	Indo China Impex 149-Transport Centre Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi Pin-110035	36.	Indo Silicon Electronics P. Ltd. 3/7, Block-C, Ashok Vihar, Phase.II New Delhi, Pin-110052
37.	International Business Group 1238/5 Nandadeep, 1 st Floor, Apte Road, Decan Gymkhana, Pune/Maharashtra	38.	J.M.Shama Designs 494, Melegrina, Linking Road, Off Bandra West, Mumbai, Maharashtra Pin-400050
39.	Jaipex 1-15, Samhita Indl. Estate, Behind Orkay Mills, Sakinaka Andheri (E) Mumbai, Maharashtra Pin- 400059	40.	Jitender Overseas D-149 G. Floor,Nr. Milan Cinema Karampura New Delhi Pin-1 10015
41.	Juneja Agencies 267, Transport Nagar, Opp. Sarb Multiplex, Jalandhar, Punjab	42.	K.C. Impex C-64, Ground Floor, Mansa Ram park, Uttam Nagar, New Delhi Pin-110059
43.	Kabeer Components Pvt. Ltd.	44.	Kaks And Bills Pvt Ltd.

	C-208 Mayapuri Industrial Area Phase-II, New Delhi Pin-110064		N-5 Kailash Colony New Delhi Pin-110048
45.	Kingston Enterprises 7/8, Ganesh Nagar Pandav Nagar Complex, Gali No 1B, Delhi	46.	Lokesh Impex Plot No. 3 Nawalgarh House S C Road, Jalupura, Jaipur, Rajasthan
47.	M S International H. No.-174, Near Swama Apptt. Vill. Pitampura, Delhi	48.	Maankesh Trading Company U-74 Top Floor Tirupati Complex, Shakarpur Delhi
49.	Meenakshi Importers 2 Amrit Bhavan 65D Linking Road, Santa Cruz Bombay, Maharashtra Pin-400054	50.	Mohan Enterprises D-262 Karampura New Delhi
51.	Nand Rubber Pvt.Ltd. Dhani Pandit Kishan Dutt, XII Quarter Road, Hisar/Haryana Pin 125001	52.	National Trading Company 14, C-Block, DDA Market, Dilshad Garden, Delhi Pin-1 10095
53.	New Vikas Tyres 92, Mm Road, Bara Hindu Rao Delhi Pin-110006	54.	Pahwa Distributors 81/20-A, Shivpuri G.B.Road Lucknow, UP - 226018
55.	Paras Auto Parts Shop No.4, Plot No.70, Pjp Chamber, Sector-9c, Gandhidham (Kutch) Pin370201	56.	Pardeep Import Export Shop No.2/3, Sainath Building, Aziz Baug, Chembur, Mumbai, Maharashtra-400074
57.	Pioneer Trading Corporation 178 Chadha House, S.V.P.Nagar,Mhada Layout, Andheri (West) Mumbai, Maharashtra - 400053	58.	Prem Trading Company 57, Harsh Nagar, Subhash Nagar, Near Sanskar Secondary School, Jabalpur M.P. Pin-482002
59.	Pricon Engineering Services 90, National Park Lajpat Nagar- IV New Delhi Pin-110024	60.	R C International C-33, Maruti Dham, Anand Nagar, Vasai West, Thane. Maharashtra Pin-401202
61.	R S Enterprises 122/235,Sarojini Nagar A-2, Room No 61, Sec-20 Jurbhe, Navi Mumbai - 400705	62.	Radhey Kishan Enterprises 2263/68 Gf Shop No.3 Gali I-linga Beg Phatak Habs Khan Khari Baoli Delhi
63.	Rajpal Roadlines Pvt Ltd 23, Sewree Premises Society, 2nd Floor, Sewree Fort Road, Sewree (E), Mumbai, M.S.	64.	Rameshwar Dass & Co. B-584, Nehru Ground NIT Faridabad, Haryana
65.	Rangi Road Carrier Shop No. 3, Kawle Complex Datta Nagar, Hingoli Road, Near Railway Over Bridge, Nanded/Mah.	66.	Renu Raj Trading D-303, Mota Nagar, Chakala , Andheri- East, Mumbai, Maharashtra, Pin-400099
67.	Roadlion International Lane No.7, Burari Road Khasra No.5/5, 5/6, Swaroop Nagar Sameypur, Delhi Pin-110042	68.	Royal Traders Shop No.21, 1st Floor Maa Ghouri Complex, WZ-97 Punjabi Bagh, Delhi

			Pin110063
69.	Rynaa Overseas (India) 540/1, Gitanjali, 13 Th Road, Tps Iii,Khar (W), Mumbai	70.	S R Enterprises E-109, First Floor, Karampura,Delhi
71.	S. S. And Sons 2343, 1st Floor, Tiiak Bazar Chandni Chowk Delhi	72.	S.K. International B-3/13, Janakpuri, New Delhi Pin-110058
73.	Saarwan Enterprises 21 9, 11nd Floor Vishal Tower DistrictCentre, Janak Puri, New Delhi	74.	Sabharwal Trading Company 3099 , No. 36 Shop No.4,Beadonpura Karol Bagh Delhi
75.	Sachin Prasad Yadav, 20a/H/2,Pottery Road, Kolkata,W.B.Pin-700015	76.	Samar Traders 6528, Main Road Bara Hindu Rao Delhi Pin-110006
77.	Sanjog Impex 6/2, South Tukoganj, Madhumiani Square, Indore, M.P. Pin- 452001	78.	Sanmatl Portex Pvt Ltd. y-434/7 Adarsh Enclave Prem Nagar
79.	Sat Guru Traders 148 First Floor Civil Lines Sadar Azamgarh U.P. Pin-276001	80.	Saveer International 703, Krishna Apra Business Square Plot No.D-4/5/6, Netaji Subhash Place, Dist.Centre, Wazirpur,N.D. Pin-110034
81.	Shiv Shakti Enterprises 10 Rama Park, Kishan Ganj, Delhi	82.	Shivalik Exim, sco.21-25, Cabin No.20, Sector 70, Opp.Vivek High School Mohali.(Pb).
83.	Simran India Inc., D-139, Karampura, New Delhi Pin-110015	84.	Simran Traders House No 160 Ground Floor Chand Nagar,Vishnu Garden, New Delhi
85.	Som Projects & Associates Shop No.5, Plot No.1, A 2 Block, Kanwar Singh Nagar, Nangloi Delhi Pin-110041	86.	Sri & co, No. 16/2, L.B.F.Road, Bangalore, Karnataka
87.	Sri Kumaran Traders No.5, 6, 7, 4/1, Ground Floor, 2nd Cross, Rudrappa Compound, H.Siddajah Road, Bangalore	88.	Sri Tyres NO. 22/4 Karnataka Complex Lalbagh Fort Road Bangalore Pin-560004
89.	Sumant Bachhawat 189, Bangur Avenue, Block-B, Kolkata, W.B. Pin-700055	90.	Sun Traders 7A/28, W.E.A Karol Bagh, Delhi
91.	Supreme Trading Corporation 104 Shivlok House -I Karampura Co, New Delhi Pin-110015	92.	Surodhya Sales G-190, Pushkar Enclave Paschim Vihar, New Delhi Pin-1 10063
93.	Trans Tyres (India) Pvt.Ltd. 193, Chakala Street, Mumbai, Maharashtra Pin-400003	94.	Uniglory International K-1 1st Floor Kailash Colony New Delhi Pin-1 10048
95.	Vaan Sales India Pvt. Ltd. T-770, Dcm Road, Bara Hindu Road, Delhi - 110006	96.	Vikas Retail Private Limited Ag 103, Sanjay Gandhi Transport Nagar, New Delhi-110042
97.	Vortex Rubber Industries Pvt. Ltd. 98-A, Pocket D, Ground Floor Ashok	98.	Vrinda Overseas Flat No.127, F/F, Kondli Gharoli,

	Vihar,Phase-II Delhi-110052		Mayur Vihar, Pahse-III,New Delhi
99.	Zafco India Pvt. Ltd 1 A Vandhna, 11, Tolstoy Marg New Delhi-110001		

l) None of the importers/users have responded and filed importer's questionnaire response.

m) Apart from the respondent exporters and importers mentioned above, some legal submissions have been received on behalf of the following parties during the course of this investigation.

- (i) Embassy of China PR in India
- (ii) All India Tyre Dealers' Federation

n) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented / submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

o) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

p) The Non-Injurious Price (NIP) based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

q) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the applicant domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present final findings.

r) Verification of the information provided by the producers/exporters and Government of China, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and has been relied upon for the purpose of present final findings.

s) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-subsidy investigation is from October, 2016 to September, 2017 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI.

t) In accordance with Rule 7(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 28th August, 2018. All the parties who had attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were advised to offer their rebuttals.

u) The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered in the present final findings.

v) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final findings.

w) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

x) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.

y) In accordance with Rule 18 of the Rules supra, the Authority disclosed the essential facts of the present investigation to all interested parties vide a disclosure statement issued on 6th March, 2019, and advised them to file the comments on the disclosure statement by 13th March, 2019. The comments received from the domestic industry and other interested parties, have been addressed in the present findings to the extent considered relevant.

z) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹66.70.

aa) In this notification, *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration is defined as:

The product under consideration in the present investigation is “New Pneumatic Tyres for Buses and Lorries”, classifiable under Customs Subheading 4011.20.

5. The petitioner has claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject goods originating in or exported from People’s Republic of China. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the domestic industry and those exported from People’s Republic of China. The petitioner claims that the two are technically and commercially substitutable.

C.1. Submissions made by the Domestic Industry

6. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:

a) The product under consideration in the present investigation is “New Pneumatic tyres, of rubber of a kind used in buses or lorries, whether radial or bias with or without tubes and/or flap of rubber, classifiable under 4011.20”.

b) Tyres, Tubes and Flaps are produced separately. However, they are invariably used together in automotive applications. Product under consideration is classified in Chapter 40 under customs subheading no 4011.20 and tubes and flaps are classified under 4013.1010/4013.1020 and 4012.9049 respectively.

c) Even though the cost of production of radial tyres for buses and lorries is higher than the bias tyres for buses and lorries and even though the domestic industry is selling the bias tyres at a price marginally lower than radial one (on per kg basis), the landed price of imports

of radial tyres is materially below not only the radial tyres but also the bias tyres produced and sold by the domestic industry.

d) Subject goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods being imported into India from the subject country. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like articles' under the Rules.

e) The inclusion of TBB Tyres is essential in the present investigation as TBB and TBR are substitutable products out of two different technologies and are being interchangeably used. Moreover, the prices at which the imports of TBR are being made are even lower than that of domestic industry's TBB price. As regards the contention that TBB should be excluded as there are no imports, it is submitted that the CVD investigation is on the product under consideration which includes both, bias as well as radial tyres. Countervailing duty can be levied on all the types of the product under consideration, provided it is in commercial competition, with the like article, and can cause injury on its import. The petitioner would like to draw the attention of the authorities to *Huawei Technologies Co. Ltd v. Designated Authority* where CESTAT held the following:

As regards STM 256, it has been argued that this product was neither produced in India nor imported into India from the subject countries during the period of investigation. This in our view is not material as the investigation is qua the product, and not the types of the product. We agree with the counsel for the domestic industry that as long as the product is imported duty can be imposed on all types of such product provided such type is in commercial competition with the like article made in India and can cause injury on its import. STM 256 is a higher version of STM 64. STM 256 if offered at a lower price can substitute for STM 64 and cause injury to Tejas qua its market for STM 64 in India.

f) In the present case imports of TBR are being made at a price which is even lower than the price of TBB sold by domestic industry, it is more than likely that it will eat up the TBB market of the domestic industry, in addition to TBR market. It is interesting to note that in *Huawei* case, even when the domestic industry was not supplying a particular product type and there were zero imports of the product type such product type was included solely on the basis that the product type is substitutable with other product type and can cause injury to the product type produced by the domestic industry. In the present case, there is a significant TBB market in India, where many Indian producers are majorly supplying TBB, so the exclusion of TBB from product under consideration and domestic industry's performance will be unwarranted and detrimental to the investigation.

g) The fact of TBR tyres imported from China PR competing with the TBB tyres was acknowledged by the Authority in the final findings pertaining to anti-dumping investigation concerning imports of "New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having nominal rim dia code above 16 used in buses and lorries/trucks", originating in or exported from China PR. Relevant part is extracted below:

The domestic industry has however contended that imports of Chinese TBR are causing injury to the TBB and TBR produced by the domestic industry. The interested parties have also contended that there has been increasing radialisation in the tyre industry across the country. Radialisation means that the bias tyres are being increasingly substituted by radial tyres. While it may be true that TBR and TBB are

technically different products, there is no dispute that TBR is increasingly substituting TBB. In fact, the interested parties have themselves contended the same. The contention of the domestic industry that TBR and TBB are being used even in the same lorries has not been refuted by the interested parties, which implies that such substitution has not happened at the level of OEM (i.e., while selling a new truck/bus), but has happened when the tyres are being replaced by the consumers.

- h) In the case of *Kajaria Ceramics v. Designated Authority* it was held, it is not necessary that tiles of every size or dimension are imported into India for levy of duty. There may be many types/sizes/ dimensions, which may be manufactured in China and not exported to India. As long as such types, forming part of PUC, are in commercial competition with like article and can cause injury to the domestic producer they can be covered by the scope of levy.
- i) The fact of absence of imports of a particular type and inclusion of the same within the scope of the PUC was considered by the Designated Authority in the matter of NBR from Korea.
- j) The decision in the case of *Andhra Petrochemicals Ltd. v. Designated Authority* relied upon by the interested parties is totally different and not applicable to the present case. In that case, CESTAT found that the product under consideration or article had not been correctly defined, and that each Acyclic Oxo-alcohol was a separate article, for which separate dumping and injury was required to be examined. It is in that context that CESTAT held that an article, which has not been imported, cannot be subject to levy of duties. Further, the product sought to be included within the scope of the product under consideration was imported into India, but the domestic industry did not supply the like article and hence its inclusion was found inappropriate. In the present case, TBB is being produced in China and India. It has not been imported during the POI, but it continues to be produced in China and India, both.
- k) On the same principle the Honble CESTAT had distinguished the decision of *Andhra Petrochemicals Ltd. v. Designated Authority* in the matter of *Huawei Technologies Co. Ltd v. Designated Authority*.
- l) The CESTAT decision in the case of *Andhra Petrochemicals Ltd. v. Designated Authority* is not applicable here in the present case as TBB tyre is not a distinct or separate product but one type of New Pneumatic tyre for bus and lorries, that is PUC. Both bias and radial tyres are part of the product under consideration.
- m) The US Authority in its scope of investigation for the Certain Passenger Vehicle and Light Truck Tires from the People's Republic of China held that Passenger vehicle and light truck tires are new pneumatic tires, of rubber, with a passenger vehicle or light truck size designation. The tyres covered by that investigation included tube-type, tubeless, radial, or non-radial, intended for sale to original equipment manufacturers or the replacement market. Furthermore, the US Authority in its order for the Certain New Pneumatic Off-The-Road Tyres from the People's Republic of China held that the OTR tyres included in the scope may be either tube-type or tubeless, radial or non-radial, and intended for sale either to original equipment manufacturers or the replacement market.
- n) Thus, Bias tyres and Radial tyres have been considered as one product under consideration by the US authority in the matter of Certain Passenger Vehicle and Light Truck

Tyres from the People's Republic of China and Certain New Pneumatic Off-The-Road Tyres from the People's Republic of China.

C.2. Submissions made by the other interested parties

7. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:

- a) Product under consideration in the present investigation covers two types of tyres—Truck & Bus bias Tyres (TBB) and Truck and Bus Radial Tyres (TBR) and both the products were subjected to separate anti-dumping duties. Moreover, the Authority themselves admitted that both are technically different products and TBR is increasingly substituting TBB. In light of this, it is clear that both the products cannot be clubbed together as they cannot be said to be like articles under Rule 2(c).
- b) Furthermore, the authority did not extend the duties to TBB, as the domestic industry failed to prove that there was any injury or any likelihood of injury on account of TBB. Clubbing them is merely an attempt to get the duties imposed on TBB also. Therefore, it is requested that the TBB be excluded from the scope of this investigation.
- c) DGCI&S import data of new pneumatic tyres shows all imports during POI are of new pneumatic radial tyres.

Import China PR	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Radial Tyres	MT	30,665	69,982	81,896	61,203
Bias tyres	Pcs	0	0	0	1

d) Anti-dumping duty investigation cannot be initiated on the product when there are no imports of such product in the investigating country. This was held in Andhra Petrochemicals Vs. Designated Authority. Therefore, new pneumatic bias tyres for buses and lorries are required to be excluded from the scope of product under consideration.

e) Section 9B(1)(b)(ii) of the Customs Tariff Act read with Rule 2(b) of countervailing duty rules requires that imported product should cause material injury to the domestic industry engaged in the manufacture of like article. Like article is an article which is identical or alike in all respects to the product under investigation. Therefore, the domestic like product should be narrowed down to include only new pneumatic radial tyres for buses and lorries. This was observed in Anti-dumping investigation on New Pneumatic Radial Tyres from China PR.

f) The product under consideration ought to exclude Tyres having normal rim diameter of 17.5 inch tubeless used on light commercial vehicles and tyres having nominal rim diameter of 16 inch & below used on light commercial vehicles, because in India buses & lorries/trucks use tyres of rim diameter code 20 inch for tube type tyres & 22.5 for tubeless tyres only.

g) Domestic industry claims that imported new pneumatic radial tyres for buses and lorries are used interchangeably with domestically produced radial tyres as well as bias tyres. Consequently, the domestic industry submits that the two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Product under consideration (PUC) in the present case is new pneumatic tyres for buses and lorries. Thus, PUC includes both new pneumatic radial tyres and new pneumatic bias tyres. DGCI&S import data of new pneumatic tyres shows that there is no import of new pneumatic bias tyres from China PR in the injury investigation period. There is only one sample transaction of import of bias tyres. Anti-dumping/Countervailing duty investigation cannot be initiated on the product when there are no imports of such product in the investigating country. In the

case of *Andhra Petrochemicals Vs. Designated Authority*, 2006 (201) E.L.T. 481, the Hon'ble CESTAT held that:

"Furthermore, it is evident from the provisions of Section 9A(1) that not only the article should be identified for the purpose of the import, it should be an article that is exported from any country or territory to India. Therefore, export of the article identified from the country is the basis for the levy when it is exported at less than its normal value and becomes liable to imposition of anti-dumping duty not exceeding the margin of dumping upon the importation. An article which has not been exported to India cannot, therefore, be subjected to imposition of anti-dumping duty under Section 9A(1) of the Act which lays down the basis for the import. There is, therefore, no error in the final findings in so far as duty on articles not imported to India, has not been imposed. For the same reasons imposition of anti-dumping duty on the articles which were not imported, was not justified." (emphasis added)

- h) If new pneumatic bias tyres for buses and lorries are not imported into India, investigation cannot be initiated against such products by including it within the broad ambit of new pneumatic tyres for buses and lorries. New pneumatic bias tyres for buses and lorries are required to be excluded from the scope of product under consideration.
- i) Like article is an article which is identical or alike in all respects to the product under investigation. As stated, all imports into India from China PR are of new pneumatic radial tyres for buses and lorries. Accordingly, the domestic like product should also be narrowed down to include only new pneumatic radial tyres for buses and lorries. In the *Anti-dumping investigation on New Pneumatic Radial Tyres from China PR*, the Authority has already held that material injury is to be assessed for the domestic industry producing like article and domestic radial tyres is to be treated as like article to the imported radial tyres. The Authority observed that:

"The Truck and Bus Radial (TBR) Tyres produced by the domestic industry are technically and commercially substitutable to the imported TBR Tyres. TBR produced by the domestic industry are like article to the TBR imported from China."

- j) Thus, the domestic industry cannot re-agitate the issue again in the present investigation and claim that domestically produced bias tyres should be treated as like article to imported radial tyres.

C.3. Examination by the Authority

8. The Authority has noted submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the domestic industry. With respect to the product under consideration, the Authority notes as follows:

- a) The very first step in an investigation is to identify the product under consideration. The product under consideration is the imported product which is allegedly causing injury to the domestic industry. In the facts of the present case, it is clear that only new pneumatic radial tyres for buses and lorries are being imported into India and there are no imports of new pneumatic bias tyres for buses and lorries. The claim of the domestic industry also is that new pneumatic radial tyres for buses and lorries being imported into India are causing injury to the manufacturers of radial tyres as well as bias tyres manufactured by them. There is no claim

by the domestic industry that new pneumatic bias tyres for buses and lorries are being imported into India. Therefore, on the basis of submissions made by various interested parties and the examination of records of Domestic Industry, the Authority excludes new pneumatic bias tyres for buses and lorries from the scope of product under consideration. Accordingly, the product under consideration in the present investigation is "New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks". The scope of the product under consideration includes both tube type and tubeless tyres. In tube type tyre, tyre is used along with one tube and one flap in a vehicle. One tyre, one tube and one flap are together sold as a "tyre set" and described as "TTF". The term "TTF" is prevalent in the industry, to denote a "tyre set". Tyre, tube and flap jointly render the function of "tyre" in a vehicle. Sale of tyre, tube and flap are primarily on "TTF" or "tyre set" basis. Tubeless radial tyres, where tube and flap are not required, are also within the scope of this investigation.

b) The scope of the imported product includes only Radial tyres used in buses and lorries / trucks. Tyres are generally used in various kinds of vehicles such as trucks, buses, lorries, light commercial vehicles, passenger car, jeep, tractor, two-wheeler, three-wheeler, animal pulled vehicles, earthmover, industrial tyres, aircrafts etc. However, the product under consideration is only that type of tyre that is used in buses & lorries / trucks. All other types of tyres are beyond the scope of the product under consideration in the present investigation.

c) Product under consideration is classified under chapter 40 of the Customs Tariff Act, 1975, Tyres are classified under customs sub-heading 40112010 whereas tubes and flaps are under 40131020 and 40129049 respectively. The customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.

d) New/Unused pneumatic radial tyres produced by the domestic industry are like article to the New/Unused pneumatic radial tyres imported from China PR. The Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic Industry and that exported from China PR. Subject goods produced by the Petitioners and imported from China PR are comparable, collectively and cumulatively, in terms of product characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The Authority holds that product under consideration produced by the applicant domestic industry is like article to the subject product under consideration imported from subject country in accordance with the Anti-Subsidy Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the Domestic Industry

9. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:

a) Application was filed by Automotive Tyre Manufacturer's Association for imposition of anti-subsidy/countervailing duty on subsidized imports of subject goods from China. Four ATMA members, viz. Apollo Tyres Ltd., M/s Ceat Ltd. M/s J. K. Tyre Industries Ltd. and MRF Ltd., have participated in the present investigation by providing all the relevant information. The production of the petitioner companies constitutes a major proportion of total Indian production. Petitioner companies are not related to any producer-exporter of the

subject product outside India. The petitioner companies, therefore, constitutes domestic industry within the stipulated criteria provided under the Anti-Subsidy Rules and satisfies the requirement of standing.

D.2. Submission of other interested parties

10. The submissions made by interested parties with regard to the scope and standing of the domestic industry are as follows:

- i. As stated, the domestic like product should be narrowed down to include only new pneumatic radial tyres for buses and lorries. The Respondent requests the Authority re-examine the standing of the domestic industry and also the claim of the domestic industry that it constitutes 'major proportion' of total production after excluding new pneumatic bias tyres from the scope of like article.

D.3. Examination by the Authority

11. Rule 2(b) of the Rules provides as follows:

"domestic industry means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry".

12. The petition was filed by Automotive Tyre Manufacturer's Association on behalf of domestic producers namely Apollo Tyres Ltd., J.K. Tyre Industries Ltd., MRF Ltd. and Ceat Ltd. The Authority notes that petitioner companies have neither imported the subject goods, nor are related to any importer or exporter of the subject goods. The Authority further holds that the Petitioner companies command a major proportion of the production of the subject goods in India. Accordingly, for the purpose of this investigation, the Petitioner Companies satisfy the standing requirement and constitute the domestic industry in terms of Rule 2(b) and Rule 6(3) of the Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by domestic industry

13. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:

- a) Responding exporters have resorted to excessive confidentiality in the questionnaire filed by them. The exporters have claimed most of the information as confidential, without providing for proper non-confidential summarization. Further, the exporters have responded to limited number of schemes, which is a grossly inadequate response. These actions are in contravention of Rule 8 of the CVD Rules, as well as the trade notice illustrating the nature of information to be disclosed.

- b) The exporters have also suppressed vital facts in relation to information pertaining to

-
- Relationship with other related and affiliated enterprises
- Capacity, production, stocks and sales
- Sample export sales documents
- Sample domestic sales documents

- Information relating to exports to India
- Additional Grants

c) Art 12.4 of Agreement on Subsidies and Countervailing Measures also clarifies the contours of confidentiality in such investigations.

d) In *Guatemala – Cement II*, the panel examined the claim that the Guatemalan authority violated Articles 6.5, 6.5.1 and 6.5.2 by granting a submission from the domestic producer confidential treatment on its own initiative, without good cause having been shown by the producer. Mexico claimed that the authority violated 6.5.2 by failing to require that the domestic producer provide reasons as to why certain information could not be made public.

e) In *Argentina – Ceramic Tiles*, the Panel while examining whether the authorities were allowed to base themselves on confidential information in their determination considered that the purpose of the NCV summaries is to inform the interested parties so as to enable them to defend their interests.

f) In India, the decisions in *Essar Steel v UoI & HR Johnson v DA* by the CESTAT highlights that the DA is not required to mechanically treat information provided by a party as confidential merely on the request of the party for the same. Further the rules also confer discretion upon the Designated Authority to consider the request for confidentiality made by a party and if it is satisfied that the same is not warranted or that the supplier of the information is unwilling to make information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

g) The claim of excessive confidentiality by Domestic industry is unwarranted as the Domestic industry has supplied all the relevant data in indexed version, as disclosure of actual data, which is business sensitive information, will be detrimental to the domestic industry.

h) Moreover, the claim of excessive confidentiality from the interested parties is surprising as the interested parties have not only claimed their data confidential, they have also claimed schemes and the documents showing existence or closure of such schemes as confidential. A government policy for the benefit of a certain sections of society would be available in public domain and to claim such information as confidential is blatant misuse of the confidentiality law.

E.2. Submissions by other interested parties

14. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:

a) The applicant industry has kept several key economic parameters confidential without giving adequate reasoning for having done so. This has prevented the respondents from undertaking a meaningful examination of injury parameters of the applicant industry and defend their own interests. They have not even provided a proper non-confidential version of the said parameters for a reasonable understanding of the substance of the petition, as is required under Rule 8 of the Anti-Subsidy Rules. The confidentiality maintained by the applicants is excessive in respect to the following factors:

- Basic information relating to capacity, production, sales.
- Demand figures have not been provided. Without them the respondents are unable to comment on the critical issue of market share.

- Facts regarding whether the applicant has dedicated capacity or common capacity.
- Other key factors, apart from the above, have also been kept confidential.

b) Moreover, having themselves disclosed volume related information as non-confidential in the final findings of the TBR anti-dumping case, the Authority should not let the applicants keep such information confidential in the present case. Doing so is just an attempt by the applicants to deprive interested parties from making effective comments on the petition filed by them. It is requested that the Designated Authority should not let the applicants keep such information confidential without a proper examination. To this end, the Supreme Court, in *Sterile Industries Ltd. v. Designated Authority*, has opined that confidentiality should not be granted automatically and should be based on thorough scrutiny.

c) If the party providing information on a confidential basis is acting under the belief that the given information cannot be summarised, then Rule 8 of the Anti-subsidy Rules requires that the reason for having such an opinion needs to be submitted. In the present matter, the claim for confidentiality has been granted without a thorough evaluation of the relevant information, which is against the established legal standards.

d) The Hon'ble CESTAT has clarified in the case of *H&R Johnson Ltd. v. Designated Authority* that Authority does not have to mechanically treat the information provided by a party as confidential merely because the party desires so. They have to be satisfied on the confidentiality on the basis of various factors like nature of information and if any such information is by law or custom or usage treated as confidential. Any claim to treat the information as confidential must be bona fide and germane to the rights and legitimate interests of the party coming up with the claim.

e) Furthermore, the Appellate Body has opined in *European Communities- Fasteners* that it is for the party claiming confidentiality to show good cause and the Authority needs to objectively assess the same. It needs to determine whether the claim was sufficiently substantiated. This has to be balanced with the prejudicial effect the non-disclosure might have on the transparency and due process interests of the other parties involved. In light of the above, it is imperative that the applicant industry discloses all the volume related information and proper non-confidential version of their parameters in accordance with the provisions of the law.

f) The Petitioner has claimed confidentiality over actual figures of sales volume, consumption, Indian production, capacity, production of domestic industry, capacity utilization, market share, and demand. The information pertaining to these parameters are not of a commercially sensitive nature and wouldn't give the Petitioner's competitors any competitive advantage whatsoever.

g) Furthermore, the information on these parameters have been disclosed by the Authority in the Final Findings dated 1st August 2017 and therefore, there is no reason for the domestic industry to claim confidentiality. The Govt. of China PR requests the Authority to direct the Petitioner to furnish the actual data of the said parameters to the interested parties.

E.3. Examination by the Authority

15. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-Subsidy Rules provides as follows:

“Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and

no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

16. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection.

17. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions made by other interested parties

18. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- Anti-dumping duty was imposed on New Pneumatic radial tyres imported from China PR vide Customs Notification dated 18th September 2017 and will remain in force for five years i.e. till 17th September 2022.
- Domestic industry has conflated two separate legal requirements against the imposition of double remedy on imports under the Countervailing Duty Rules and the SCM Agreement. Domestic industry does not deny that if export subsidization is established, it cannot be countervailed owing to the express prohibition under Section 9B(1)(a) of the Customs Tariff Act.
- Export subsidization and dumping results in lower export price of product concerned. Therefore, Article VI:5 of GATT 1994 and Section 9B(1)(a) of the Customs Tariff Act provides that a product shall not be subject to both anti-dumping and countervailing duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidization.
- The Appellate Body in *United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing*

Duties on Certain Products from China observed that application of double remedies is contrary to Article 19.3 of the SCM Agreement, which provides for imposition of countervailing duty in the appropriate amount.

e) According to Article VI:5 of GATT 1994 and section 9B (1)(a) of the Customs Tariff Act both anti-dumping and countervailing duty cannot be imposed to remedy the same situation of dumping and export subsidization. Therefore, further imposition of countervailing duty on the imports which are already subjected to the anti-dumping duty would provide additional duties to offset the export subsidies and directly contravene the said provisions.

f) In the present case, under the anti-dumping investigation, China PR was treated as a non-market economy where the normal value was constructed for China PR and normal value was not based on the actual cost of Chinese companies. Therefore, any distortion, including distortion caused by the benefit of any subsidy received by such producers/ exporters, in the cost of production of the producers/ exporters were remedied by the imposition of anti-dumping duty. Also, the imposition of countervailing duty to offset other domestic subsidization would amount to double remedy.

g) In the *US- Definitive AD and CVD (China) (DS 379)* dispute, the Appellate Body held that offsetting the same subsidisation twice by the concurrent imposition of both the duties, is inconsistent with Article 19.3 of the SCM agreement.

h) In *J.K. Industries Ltd. v Union of India*, it was stated that the reason behind not imposing both duties simultaneously because it is matter of choice for the central government to opt either of the measures, keeping in mind considerations apart from mere quantity of export and its effect on home product.

i) Hon'ble CESTAT decision in case of *Suncity Sheets vs. Union of India* was based on a different fact situation: injury margin was lower than the dumping margin in the anti-dumping investigations concerning imports from China PR, and not to the full extent of dumping margin. Thus, there was further scope for remedying the subsidization because it was probable that not all the subsidization was offset by way of imposition of anti-dumping duty Hon'ble CESTAT observed that there was no infirmity in the imposition of both countervailing duty and anti-dumping duty in such a case.

j) Any imposition of countervailing duty to offset so called domestic subsidisation in China PR would amount to double remedy as there is already existing anti-dumping duty and it has been imposed to its fullest margin of dumping based on the treatment of application of non-market economy of China PR. Section 9B(1)(a) of the Custom Tariff Act and Article VI:5 of GATT 1994 specifically state that both anti-dumping and countervailing duty cannot be imposed to offset the same ground of dumping and export subsidization.

k) Export subsidization, even if determined to exist pursuant to these alleged programs in the present investigation, cannot be countervailed due to already existing anti-dumping duty on the product as it would be inconsistent of Article VI:5 of the GATT.

l) Imposition of countervailing duty would result in offsetting it a second time and would be inconsistent with Article 19.3 of the SCM Agreement. Therefore, we request the Authority to ensure that there is no double remedy in the present matter.

m) There is already an existing anti-dumping duty levied on subject goods exported

from China, the petition violates paragraph 5 of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994 principles as both anti-dumping duty and anti-subsidy countervailing duty cannot be simultaneously levied by a contracting party. It is clear that this article prevents a situation of double remedy or compensation for same situation. Dumping margin already accounts for export subsidy and concurrent duties will lead to double jeopardy and section 9B(1)(a) of Custom Tariff Act in India prohibit double jeopardy. As it was laid down in the case of *J.K. Industries Ltd. v Union of India*, the authority is at liberty to recommend imposition of either anti-dumping duty or countervailing/ anti-subsidy duty on the product under consideration but is not at liberty to impose both duties. Moreover, China PR has been considered as a non-economic market and computed on normal value, due to which, if any advantage gained by the Chinese manufactures on account of alleged subsidies has already been countered by imposition of anti-dumping duty. This determination was done on the basis of Injury Margin by applying the lesser duty rule, and therefore, if any injury is caused to the domestic industry by the imports has already been considered and addressed by the authority whilst imposing anti-dumping duty on imports.

n) The Petitioner has alleged export subsidization in the present investigation and have claimed the following programs as constituting export subsidies provided by the Chinese Government to its tyre producers/exporters:

- i. Program 11: Export Assistance Grant
- ii. Program 15: Hefei Municipal Export Promotion Policies
- iii. Program 19: Export Interest Subsidy Funds for Enterprises Located in Guangdong and Zhejiang Provinces
- iv. Program 55: Export seller's credit
- v. Program 56: Export buyer's credit
- vi. Program 57: Other export financing from State-Owned Banks
- vii. Program 58: Export credit insurance subsidies
- viii. Program 59: Export credit guarantees

It is therefore submitted that while calculating subsidy margins, the export subsidies should not be considered by the Authority.

o) The period of investigation is not representative of the actual situation regarding injury to the domestic industry.

- Anti-dumping duty on imports of new pneumatic radial tyres used on buses or lorries was increased to 15% from 10%, as a result, effective customs duty rate for China PR increased from 8.6% to 12.9%.
- Period of investigation in the present case is October 2016 to September 2017. Basic customs duty on the import of New pneumatic radial tyres used on buses or lorries falling under HS code 40112010 was increased to 15% from 10% by Government of India with effect from 2nd February 2018. As a result, effective customs duty rate for China increased from 8.6% to 12.9%. Anti-dumping duty was also imposed on new pneumatic radial tyres from China PR w.e.f 18 September 2017 ranging from 245 USD/MT to 452 USD/MT.

- The authority will not be able to assess the effect of anti-dumping duty and increase in customs duty on the import of subject goods and improvement in the situation of the domestic industry because these things have occurred after the end of the investigation period. Thus, assessment of material injury by the domestic industry will not be representative of the actual situation regarding imports and performance of the domestic industry.

p) Respondents object to the written submissions filed by the petitioner industry which run into more than 172 pages. The Annexures run into more than 700 pages. In this context, it is submitted that the written submissions are supposed to be a gist of what has been presented before the Hon'ble Authority. It may be mentioned that the written submissions made by the petitioner Industry have no connect with the submissions made during the oral hearing. The Authority is requested to look into this aspect and ignore all such written submissions which were not argued during the oral hearing.

q) It is submitted that petitioner industry has again tried to mislead the Hon'ble Authority with regard to dual remedy by placing reliance on Section 8(3) of Safeguards in CVD investigation. It is a known fact that Section 8 of Customs is applicable for safeguard investigations and not countervailing investigations. Further, petitioner industry has again tried to mislead the Authority by merely quoting Section 9B (1), which prohibits imposition of both ADD and CVD for same situation of dumping and export subsidization. In their complete written submission they have failed to justify why, in terms of Section 9B(1), both ADD and CVD duties are justified in present investigation.

F.2. Submissions made by domestic industry

19. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- a) It has been contended that for the purpose of calculating the normal value of the subject goods, China was treated as Non-Market Economy and lesser duty rule was applied by the Authority in that investigation. The WTO Appellate body in US-China held that double remedies are likely to occur in cases where NME methodology is employed. However, Petitioners contend that the WTO decision is inapplicable in the Indian context as, India applies the lesser duty rules and as the petitioner consents that subsidy duty may be charged only to the extent that the quantum of subsidy duty exceeds the quantum of ADD. In the WTO case, the US had applied subsidy duty and dumping duty without granting offset of one duty in other.
- b) Petitioner consents that (a) the authority may kindly determine the subsidy margin and injury margin, (b) determine the quantum of subsidy duty payable, (c) the authority may reduce the quantum of dumping duty in case the quantum of subsidy duty is higher than the quantum of dumping duty and recommend the differential as the amount of subsidy duty in respect of those product types which are already attracting ADD, (d) in case the quantum of existing dumping duty is higher than the quantum of subsidy duty, a Nil rate of duty may be specified in respect of those product types. Reference is made to the Final Findings concerning imports of Stainless Steel where the dual protection to the domestic industry had not been granted by the Designated Authority or the Ministry of Finance.
- c) Petitioners submit that the interested parties are misleading the Designated Authority in believing or considering that mere initiation of subsidy investigations in respect of a product that is already subject to anti-dumping duty is prohibited. Further, the interested parties are also misleading the Designated Authority in believing that the statute prohibits

imposition of subsidy duties on those products where ADD is already in place. It would be seen that the WTO has clearly held that the only bar is in imposing double duties – once as anti-dumping and once as anti-subsidy duty to account for same situation of dumping and an export subsidization. Whether or not the facts of the particular case fall into the meaning of same situation is a pertinent question of fact and is required to be established by interested parties before they can establish their contention.

d) The interested parties are being selective in their import trend analysis, it is unfair to compare import trends from 2016-17 to POI, ignoring the tremendous increase subject imports have seen since base year. Imports have almost doubled since base year to the POI. Further, decline in imports is partly because of decline in demand and partly because of initiation of antidumping investigation on imports of TBR in May 2016.

e) It is pertinent to note here that the POI of the anti-dumping investigation was July 2014- December 2015. The Authority had concluded increase in imports in that period and also concluded material injury when the price parameters were comparatively in a better position as prevailing in the present POI. It would be seen that though imports have declined import prices have further declined despite increases in costs. The profitability of the domestic industry has further declined thus evidencing continued material injury being suffered in terms of subsidized imports from China.

f) As regards the argument that there has been a significant decline in imports in the post-POI, it is a settled principle of dumping law that POI is the relevant period for purpose of injury analysis. Further, while it is appreciated that there has been a decline in imports post POI as a result of imposition of ADD, what is also pertinent to see is that import prices have declined significantly in comparison to POI even with the increase in custom duty and imposition of anti-dumping duty, which clearly indicates the propensity of the Chinese exporters to reduce the prices, thanks to numerous subsidies available to them. Past decision of the Designated Authority on information pertaining to post POI is referred to and relied upon in the matter of imports of NBA from Saudi Arabia.

g) As regards contentions raised by the opposing parties with regard to dual remedy, as anti-dumping duty has already been imposed on some types of the product under consideration, petitioner submit that only truck & bus radial tyres are attracting ADD on TBR. At the outset, there is nothing in law to bar the petitioner to seek both the remedies on the same products and at the same time. Petitioners rely upon Section 8(B)(3) of Custom tariff Act, 1975 which states as follows-

(3) The duty chargeable under this section shall be in addition to any other duty imposed under this Act or under any other law for the time being in force.

Further, Section 9 (5) of Custom Tariff Act, 1975 states as follows-

(5) The countervailing duty chargeable under this section shall be in addition to any other duty imposed under this Act or any other law for the time being in force.

Section 9B(1) of Custom tariff Act, 1975 states that-

9B. (1) Notwithstanding anything contained in section 9 or section 9A, -

*(a) no article shall be subjected to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the **same situation** of dumping or export subsidization;*

h) The interested parties' submission to the Authority that the initiation of countervailing duty investigation and imposition of countervailing duty on a product that is already subject to anti-dumping duty is prohibited under the statute, is misleading. As per the WTO Appellate Body's decision, the only bar on the Authority is in deciding the subsidy amount, and in doing so should consider the relief that has already been granted to the domestic industry by way of anti-dumping duty.

i) The existence of domestic subsidies even in NME countries does not imply that duties cannot be applied. There is no bar in imposing countervailing duty even when anti-dumping duty is in place. Since India follows the lesser duty rule, the Authority should compare the subsidy margin with injury margin to determine the countervailing duty. If the countervailing duty determined is higher than the existing quantum of anti-dumping duty, then there is no bar in imposing countervailing duty after adjusting for existing anti-dumping duty.

j) Petitioner submits that the CESTAT order and DGTR finding on – “*Certain Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products from China*”, clearly clarifies the situation of simultaneous imposition of duties.

k) As far as the WTO decision is concerned, petitioner submits that the same is entirely inapplicable in the Indian context considering that (a) India applies lesser duty rules and (b) the petitioner consents that the subsidy duty may be charged only to the extent that the quantum of subsidy duty exceeds the quantum of anti-dumping duty. In the case of WTO DS 379, the US has applied subsidy duty and dumping duty, without granting any offset of one duty in other.

l) Accordingly, Petitioner requests the authority to –

- Recommend that the quantum of subsidy duty that shall be determined after reducing the quantum of anti-dumping duty payable on the imports in order to address the dual remedy to the domestic industry. Only the differential amount shall be charged as subsidy duty. Further, if the differential amount is negative, no CVD shall be collected.
- In the alternative, the authority may kindly determine the quantum of subsidy duty payable after adding ADD payable to the landed price of imports and recommend the remaining amount as the quantum of subsidy duty payable.
- In the alternative, the authority may kindly determine the quantum of subsidy duty payable and recommend the differential between CVD margin and ADD as the quantum of subsidy duty payable.

F.3. Examination by the Authority

Various submissions made by the interested parties with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

20. As regards to the issue of dual remedy, because of AD duty already in force on subject goods, the Authority holds that the quantum of countervailing duty will be recommended after duly adjusting the quantum of anti-dumping duty payable on the imports of the subject goods. Only the differential amount would be charged as countervailing duty. Further, if the differential amount is negative, no Countervailing duty shall be collected.

21. This approach is in line with the consistent practice of the Authority followed in earlier investigations also, which has been ratified by the Hon'ble CESTAT as well.

G. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN

22. The petition filed by Domestic Industry provided *prima facie* evidence of existence of countervailable subsidies in the subject country to initiate the instant investigation prior to initiation of investigation. Government of China was invited for consultation, which was held on 20th March, 2018 in New Delhi. The producers and exporters from China PR were advised to file response to the questionnaire and were given adequate opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.

23. The following producers/exporters from China PR including Government of China have filed questionnaire responses.

- i. Shandong Haohua Tire Co. Ltd.
- ii. Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd.
- iii. HK Trade Wind Trading Ltd.
- iv. Aeolus Tyre Co. Ltd.
- v. Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd.
- vi. Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd.
- vii. Zhongce Rubber Group Co. Ltd.
- viii. Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.
- ix. Triangle Tyre Co. Ltd.

General overview of the alleged Subsidy Programs

G.1. Submissions made by domestic industry

24. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i. The domestic industry has contended that the Government of China PR ("GOC") is providing countervailable subsidies to its producers/exporters of the subject goods and has provided *prima facie* evidence of existence of such subsidy schemes in terms of legislation and policy documents. Accordingly, the domestic industry identified existence of certain numbers of countervailable subsidy schemes in China PR, within the meaning of ASCM and Indian Rules and have contended that the producers/exporters of subject goods in China PR have benefited from such subsidies.
- ii. The petitioner has submitted that the authority can rely on GOC and Exporter data, provided the information provided by the interested parties is complete, correct and sufficient. The questionnaire responses have been filed by the responding producers and exporters only to "pretend" that they have cooperated with the Designated Authority. The questionnaire response are grossly incomplete and inadequate. The GOC and the exporters should be treated as non-cooperative in this investigation. The very limited information filed by these exporters also shows contrary claims. The Government has denied existence of certain schemes. However, exporters have admitted availment of benefit under certain schemes. Further exporters have provided additional subsidy schemes availed by them which

have not been disclosed by the GOC. Thus, since the GOC and the exporters have not provided necessary information within a reasonable period, the Authority may proceed on the basis of facts available.

- iii. The Petitioner has submitted that the producers/exporters of subject goods have benefited from actionable subsidies. The Government of China has maintained various programs. Petitioners have considered documents such as relevant Chinese laws and regulations, WTO reports, media sources, government reports, independent reports analyses & studies, countervailing duty investigations analysis and findings of other authorities regarding subsidy programs in China PR. The petitioner has provided elaborate information regarding various subsidy programs
- iv. Petitioner has submitted that the Designated Authority may resort to sampling in the present case. There are a large number of exporters of subject goods in China PR, exporting subject goods to India. The petitioner requested the Designated Authority to kindly consider sampling of the Chinese producers and restrict the detailed examination to only the top three producers which are Shandong Yinbao Tyre Group Co. Ltd.; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd.; Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd., because detailed examination of all the responding producers shall be unduly burdensome. The volume of exports made by some of the responding producers is very low and does not justify elaborate examination.
- v. The programs of the GOC and other Public Bodies in China PR constitute a subsidy because of the following reasons:
 - There is a financial contribution by government or a public body, where the government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits), government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases goods;
 - Benefit is thereby conferred on the Chinese producers/ exporters of the PUC; and
 - The program is specific within the meaning of Indian Rules and ASCM.
- vi. Relevant Chinese laws and regulations, WTO reports, various Government reports, media reports and independent studies and analysis, findings of other investigating agencies in their ant-subsidy investigations clearly constitute sufficient evidence of the existence of countervailable subsidy programs in China PR. These evidences were made available by the petitioner to all interested parties, including the GOC and the known producers and exporters in China PR.
- vii. For the purpose of this investigation, the "Government of People's Republic of China" covers all levels of government, i.e. Federal, Central, 27 Provincial, Regional or Local Govt. such as Municipal or City or Township Govts. Village or Local legislative, administrative or judicial agencies/bodies; and State-owned enterprises, operating under the direct or indirect control or influence of the GOC which operate as 'public bodies' within the meaning of the term as defined in the ASCM.
- viii. As per the petition the Chinese producers/exporters of the subject goods have received countervailable subsidies under the following programs of various levels of Govts. and they have been classified under 6 broad categories. The various programs classified under these categories are listed below:

I. Grants

II. Tax Incentives
III. Preferential Lending
IV. Export Financing and Export Credit
V. Equity Support
VI. Provision of Goods and Services

G.2. Submissions made by other interested parties

25. The following submissions have been made by the other interested parties:

- i. There are no countervailable subsidy programs available to exporters. There are no preferential loan, equity infusion, and provision of any goods / services by government or public body for less than adequate remuneration, revenue forgone by government or tax incentives given by Chinese government. The amounts are negligible compared to investment required to produce and export subject goods to India.
- ii. If the investigation is continued, then determination of subsidization should be based on the response filed by the exporters and the Government of China PR. As the petition does not provide evidence of actual benefit to exporters/ producers of the subject goods from China PR, the authority is requested to determine the extent of subsidization for all exports from China PR based on the questionnaire response.
- iii. Out of the 72 subsidy programs identified by the petitioners, 22 have been terminated. Accordingly, the Designated Authority should terminate the investigation against the following programs:

S. No. (Petition)	Program
4	The State Key Technology Renovation Projects Fund
7	Grants for Encouraging the Establishment of Headquarters and Regional headquarters with Foreign Investment
17	Weihai Municipality Subsidies for the Automobile and Tyre Industries
18	Subsidies for Companies Located in the Rongcheng Economic Development Zone
19	Export Interest Subsidy Funds for Enterprises Located in Guangdong and Zhejiang Provinces
28	Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs
29	Tax Offsets for Research and Development by FIEs
30	Income tax credit for the purchase of domestically produced & manufactured production equipment
34	Income Tax credits for domestically owned companies purchasing Chinese made equipment
36	VAT Refunds for domestic Firms on Purchases of Chinese made Equipment
37	VAT Exemptions and Deductions for Central Regions
38	Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to Operate for a Period not Less Than 10 Years
39	Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises
40	Preferential Tax Policies for FIEs which are Technology Intensive and Knowledge Intensive
41	Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises Which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipment
42	Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors

44	Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area)
45	Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones
46	Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
47	Corporate Income Tax Exemption and /or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
52	Preferential Loans to SOE
65	Land Use Rights in Industrial and other Special Economic Zone

iv. The petitioners have alleged the existence of several subsidies without providing sufficient evidence in support of them or the benefits to the exporters/producers in China PR. Therefore, the Authority is requested to determine the extent of subsidization based on the questionnaire response filed by the GOC and producers/exporters from China PR.

v. In relation to subsidy associated with cost and production, it is submitted that the Authority while recommending the anti-dumping duty against subject goods from China PR has disregarded the normal value and cost in China PR. Further, the Authority has constructed normal value and while doing so, the Authority has followed the following methodology:

- International price of raw materials, namely, natural rubber, synthetic rubber, carbon black, nylon cord fabric, steel cord fabric and bead wire (Export/Import price from/into China PR as per World Trade Atlas has been adopted);
- Prices of chemicals and reclaimed rubber have been considered based on domestic industry's data;
- Consumption Norms of the most efficient constituent of domestic industry;
- Conversion costs based on the most efficient constituent of domestic industry;
- Selling, general and administrative expenses based on the most efficient constituent of domestic industry; and
- Notional Profit @ 5% has been considered.

From the above methodology, it is clear that while computing constructed normal value, the Authority has adopted all components of constructed normal value mainly, raw material, energy consumption, conversion factors, selling & general administrative expenses and even profit which was not even related to the Chinese companies. Therefore, it goes without saying that subsidy, if any, hidden or otherwise, has already been taken care of while computing constructed normal value for dumping determination.

vi. In relation to subsidies related to export performance, it is submitted that CIF price is lower due to export subsidy. Assuming, respondents are getting export subsidy (for example 10%), their net export price would be lower to the extent of 10%. This lower CIF/ export price is appropriately taken care of in anti-dumping duties.

vii. In relation to submission of the petitioner industry relating to sampling and restricting the investigation to top three producers / exporters, the respondents submit with all humility that the request of the petitioner industry cannot be accepted at this stage of the investigation. Sampling is permitted at the beginning of the investigation subject to the prescribed conditions. It would be a travesty of justice if the responses of the fully cooperating exporters are rejected by resorting to sampling at this stage of the investigation. The Authority needs to appreciate that the respondents have fully cooperated in the proceedings and filed their complete questionnaire response to the Authority in anticipation of individual margin based on their data and numbers. It is also submitted that any sampling at this stage would cause serious prejudice to the legal and commercial interest of the respondents. In any case, we are

surprised that the petitioner industry is attempting to advance a proposition on an issue which is the sole prerogative of the Hon'ble Authority.

viii. In relation to the identification of grants available for producers / exporters of subject goods in China PR, it is submitted that the respondents had already provided complete details of the schemes availed by them. The respondents also invite the Authority for complete verification of the data/information supplied by them. All other schemes are not applicable for respondents and therefore no response is made on such schemes.

ix. Reliance on the quantum of subsidy margins recommended by other Authorities, would be incorrect and lead to incorrect conclusions. Since subsidy margins are based on the subsidy received by specific exporter and quantum of exports made during the POI, any generic reliance on margins would not only be illogical but contrary to applicable law.

x. If the Authority decides to proceed with the investigation, determination of subsidization should be based on the response filed by the exporters and the Government of China PR as Petition does not provide evidence of actual benefit to exporters/producers of the subject goods from China PR.

xi. The claim of the domestic industry that response is required to be filed by all the related entities is incorrect, is contrary to the requirement under the SCM Agreement and Countervailing Duty Rules and is against the past practice of the Designated Authority. Related entities of Aeolus Tyre Co. Ltd. & Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd. are not required to file the exporters questionnaire response as they have not exported the product under consideration. The domestic industry has not identified the necessary information that will be unavailable if such related entities do not file questionnaire response. Questionnaire response filed by Yellow Sea and Aeolus provides all the information regarding benefits received by it under the subsidy programs alleged in the petition and also regarding the subsidy programs not alleged in the petition.

xii. Out of the 72 programs alleged in the petition, questionnaire response filed by exporters have clearly identified the programs for which benefit is received by them. Questionnaire response filed by exporters have also provided information about subsidy programs not alleged in the petition.

xiii. Difference in the program alleged by the petitioner and program identified by the responding exporter is clear from the difference in the legal basis for the benefit noted by the domestic industry in its petition and by the responding exporters in the questionnaire response. Thus, it is clear that the GOC has not provided any incorrect information and there is no contradiction in the response filed by the GOC and the exporter.

xiv. For the State Key Technology Renovation Projects Fund, GOC has noted that the program was rescinded in February 22, 2008. The domestic industry has claimed that this program may exist under different nomenclature but has not provided any evidence to substantiate such claim.

xv. Average useful life of assets is not 18 years as claimed by the domestic industry and therefore it is incorrect to say that the benefit received under this program is required to be examined for such period. The domestic industry has not provided any evidence to support such claim either. Information regarding annual depreciation rates, depreciation policy adopted by the exporter, average useful life of different assets is requested in the questionnaire response filed by the Authority. The Authority shall decide the appropriate average useful life period based on the information provided by the exporter concerned.

xvi. For Preferential income tax law for FIEs, the GOC's response is that such programs alleged by the domestic industry are rescinded.

xvii. GOC in its questionnaire response has itself acknowledged that new enterprise income tax law was enacted in the year 2008 upon the expiration of the previous law concerning income tax for Foreign Invested Enterprise. The GOC has also clarified in its questionnaire response that no grace period was applicable for the program alleged by the petitioners. GOC has also

provided evidence in the questionnaire response regarding the termination of the program and the inapplicability of the grace period. 'Notice by the PRC State Council on the Implementation of the Grandfathering Preferential Policies under the PRC Enterprise Income Tax Law Decree No. [2007] 39' demonstrates that only those programs that were clearly listed in this notice were granted grace period.

- xviii. For Direct government grants to specified companies, Petition filed by the domestic industry does not provide detailed description, legal basis, eligibility criteria, name of the granting authority etc, regarding the alleged programs. The petition filed by the domestic industry simply alleges existence of 'direct grant programs'. Therefore, GOC has clearly responded that there is no direct grant program of such nature.
- xix. If the domestic industry does not file any specific information or provide explanation and evidence regarding the alleged subsidy, it cannot simply claim existence of some grant programs by the Government of China PR.
- xx. There are no preferential loans by banks, Article 4 of the "Commercial Banking Law of China" requires the commercial banks to follow the principles of safety, liquidity and efficiency. Commercial banks make their own decisions regarding their business operations in accordance with the law and without any interference from any entity or individual. People's Bank of China (PBOC) does not interfere with the loan business of commercial banks. Following the restructuring, major state owned commercial banks (SOCBs) as well as private banks are now publicly listed companies operating solely on market principles. There is no specific lending policy designed and applied according to any specific industry sector.
- xxi. For provision of goods or services at less than adequate remuneration, GOC has provided complete information regarding the mechanism applicable in China PR for each of the alleged provision of goods in response to the questions noted by the Authority in the provision of Goods/Services Annexures.
- xxii. Domestic industry has relied on the finding of the United States, Department of Commerce in the case of Certain Passenger Vehicle and Light Truck Tires to claim that tyre producers in China PR may have received benefit under these programs. The GOC notes that there is no reason to resort to secondary information when the responding exporters have clearly provided the information regarding the use of programs availed by them. Subsidization is required to be determined for the responding exporters based on the facts and information provided by them in the questionnaire response.
- xxiii. In the countervailing duty investigation by the United States, the POI was fixed as January 1, 2013 to December 31, 2013. The POI in the present investigation is October 2016 to September, 2017. Subsidization determined for a stale POI for exporters in China PR who were exporting to the United States is unrepresentative for the present anti-subsidy investigation. Subsidization is required to be determined for the POI for producers of new pneumatic tyres for buses and lorries who have exported to India. Moreover, the product under consideration in the present investigation is "new pneumatic tyres for buses and lorries" which is different from the product under consideration in the countervailing investigation by United States i.e. "certain passenger vehicle and light truck tires".
- xxiv. Also, the determination relied upon by the domestic industry is of the year 2015, which is obsolete as there has been subsequent administrative review by the United States itself.
- xxv. Domestic industry has wrongly claimed that certain programs were countervailed by the United States. For example, the domestic industry alleges that US authority concluded that "Weihai Municipality Subsidies for the Automobile and Tyre Industries" is countervailable. However, in the administrative review, the United States has specifically concluded that "Weihai Municipality subsidies for the Automobile and Tyre Industries" was not used and was not conferring benefit during the period of review to the exporters from China PR. Similarly, the domestic industry has incorrectly noted that the US authority has determined that exporter Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd. has received benefit under the

"Income Tax Reduction for Advanced Technology". United States has specifically concluded in the administrative review that no benefit was conferred to the exporters for " Income Tax Reduction for Advanced Technology" program.

xxvi. If no information is provided regarding the alleged subsidy, the GOC cannot be put under an onerous burden to respond to the specific questions. Article 11.2 of the SCM Agreement and Rule 6 of the Anti-subsidy Rules clearly provides that the application filed by the domestic industry shall include sufficient evidence of the existence of a subsidy. Therefore, the application shall include sufficient evidence regarding (i) financial contribution (ii) specificity & (iii) benefit.

xxvii. Domestic industry has provided incorrect information regarding the countervailability of the programs by the Designated Authority in the previous CVD investigations. For example, following grant programs alleged by the domestic industry as being held countervailable in the case of *Castings for Wind Operated Electricity Generator* were not even investigated by the Designated Authority:

- Special Fund for energy saving technology reform
- The clean production technology fund
- Fixed Asset Investment Subsidies &
- Export assistance grant

xxviii. Similarly, following preferential tax programs alleged by the domestic industry as being held countervailable in the case of *Castings for Wind Operated Electricity Generator* were not even investigated by the Designated Authority in that case:

- Reduced Tax rate for productive FIEs scheduled to operate for a period not less than 10 years
- Preferential tax policies for foreign invested export enterprise
- Income tax refund for re-investment of FIE profits by foreign investors
- Income tax reduction for advanced technology FIEs
- Preferential tax policies for enterprise with foreign investment established in special economic zones
- Preferential tax policies for enterprise with foreign investment established in coastal economic open areas and in the economic and technological development areas
- Corporate income tax exemption and reduction in SEZs and other designated areas etc.

xxix. Domestic industry has also made similar incorrect claims regarding countervailability of the programs based on the previous finding of the Designated Authority in respect of other categories of subsidy programs.

xxx. In the case of *Certain Hot and Cold Stainless-Steel Products*, the Designated Authority considered the GOC as non-co-operating and consequently determined the countervailability of the alleged programs based on facts available. However, in the present case, the GOC has filed complete questionnaire response and has provided all the relevant information. The Designated Authority may request further information from GOC that it may require and should not rely on its previous finding in the case of stainless steel products to decide the countervailability of the programs.

xxxi. Reliance on the findings of the Authority in other countries in countervailing duty investigations concerning steel products is not justified. Article 12.8 of the SCM Agreement and Rule 7(8) of the Countervailing duty rule clearly provides that only when the interested party (i.e. the GOC or other exporters) refuses access to the information or does not provide necessary information that the Authority can resort to facts available. The product under

consideration in those cases were 'organic coated steel", "carbon & alloy steel", "non-oriented steel" "grain oriented electrical steel" etc. All the products under investigation in these cases concern steel sector. Benefit determined to have been received by steel producers in China PR bears no connection with the benefit that may have been received by producers of new pneumatic tyre for buses and lorries in China PR. The POI in those cases are stale and unrepresentative and the investigating authorities in those cases determined subsidization in respect of number of programs based on facts available and not based on positive evidence or based on the information provided by the GOC or exporters from China PR.

- xxxii. Rule 12 (1) of the Countervailing Duty Rules provides that the amount of countervailable duty shall be calculated in terms of the benefit conferred on the recipient which is found to exist during the investigation period for subsidization.
- xxxiii. GOC has provided information regarding the benefit received by the cooperating exporters for the alleged subsidy programs in its questionnaire response. There is no requirement of information regarding benefit received by producers of product under consideration who are either not exporting the product under consideration at all or did not export the product under consideration to India during the POI. Benefit received by producers who exported the product under consideration to third countries is not required to be analysed by the Authority in this countervailing duty investigation. Scope of the present investigation is restricted to the producers who have exported new pneumatic tyres for buses and lorries to India.
- xxxiv. Responding exporters have provided the information regarding the benefit received by them for recurring subsidies during the POI and for non-recurring subsidies for which the benefit is received in the POI.
- xxxv. Domestic industry has presumed that the AUL period is of 18 years. In fact, in the written submission, the domestic industry has also claimed that the AUL period is of 25 years in the present investigation. The domestic industry has not provided any basis for presuming such elongated AUL period. Authority is required to decide the appropriate AUL period for allocating the benefit in case of non-recurring subsidies based on the depreciation rates for different types of assets prevailing in the tyre sector in China PR. Exporters have provided information in their questionnaire response regarding such depreciation rates and the proposed AUL period based on such depreciation rates.
- xxxvi. Domestic industry has not provided any positive evidence showing that the exporter has received benefit for the alleged subsidy program during the POI. Exporters have provided detailed responses clearly identifying the following:
 - Recurring subsidy programs which are alleged in the petition and under which they have received benefit in the POI.
 - Non-recurring subsidy programs alleged in the petition under which they have received benefit in the POI..
 - Recurring subsidy programs which are not alleged in the petition but under which they have received benefit in the POI.
 - Non-recurring subsidy programs which are not alleged in the petition but under which they have received benefit in the POI.
- xxxvii. The claim of the domestic industry that responding exporters should demonstrate by way of positive evidence that they have not received the benefit under the alleged subsidy program is unreasonable.
- xxxviii. Exporters have provided positive evidence showing that the nature and amount of benefit received under these subsidy programs. The exporters cannot provide positive evidence showing that they have not received benefit under the alleged subsidy program. Non-receipt of benefit is a negative fact which cannot be established by way of positive evidence.

G.3. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioners

26. Six groups of tyre producers from China PR have filed questionnaire response. Out of these, 5 groups have exported the subject product to India during the POI. M/s. Shandong Haohua Tire Co. Ltd., M/s. Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd. and M/s. HK Trade Wind Trading Ltd. have not exported the subject product to India. Individual subsidy margin cannot be determined for tyre producers who have not exported the subject product to India during the POI. Accordingly, the Authority notes that separate countervailing duty rate cannot be determined for these producers from China PR.

I. Grants

(i) Program No. 1: Famous Brands Program

a. Submission by the Petitioners

27. The Petitioners submitted that enterprises whose products qualify for the title of 'China Worldwide Famous Brand' are eligible to get direct transfer of funds from the GOC. The program confers benefit to the recipient. The program is specific in nature because it is contingent on exports. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Order No. 124 – Measure for the Administration of Chinese Famous Brand Products (Dec 2009)
- ii. Measures for the Administration of Chinese Famous Brand Products (Dec 2006)
- iii. Notice Concerning the Promulgation and Circulation of "Measures for the Administration of National Key Technological Renovation Projects" (Para 4&7)
- iv. Measures for the Administration of Treasury Bond Special Fund for National Key Technological Renovation Projects at Para 6-9 Guo Jing Mao Tou Zi (1999) No. 886 (Sep 10, 1999)
- v. Guiding Opinion of the State Council on Promoting Enterprise Technological Renovation (Guo Fa (2012) No. 44)
- vi. Industrial Revitalization and Technological Renovation Special Work Plan for 2015
- vii. Decision Concerning Commending and/or Awarding to Enterprises of Guangdong Province Whose Products Qualify for the Title of "China Worldwide Famous Brand", "China Famous Brand", or "China Well-known Brand"
- viii. Notice of Shandong Province concerning the Special Award Fund Budget in 2008 for the Development of Self Exporting Brand (Lu Cai Qi Zhi (2008) No. 75)

b. Submissions by GOC / other interested parties-

28. The GOC stated that among all legal basis provided by the petitioners, legal text is provided only for Order No. 124 – Measure for the Administration of Chinese Famous Brand Products (Dec 2009). Order No. 124 – Measure for the Administration of Chinese Famous Brand Products (Dec 2009) was terminated on 6 March 2018. No legal text is attached for the remaining exhibits. The *China Famous Brand Strategy Development Report* provided by the petitioners is not legal text.

c. Examination by the Authority:

29. The Notice Concerning the Promulgation and Circulation of “Measures for the Administration of National Key Technological Renovation Projects” (Paras 4&7) and Measures for the Administration of Treasury Bond Special Fund for National Key Technological Renovation Projects at Para 6-9 Guo Jing Mao Tou Zi (1999) No. 886 (Sep 10, 1999) were referring to the State Key Technology Renovation Projects Fund and both were found invalid.

30. Guiding Opinion of the State Council on Promoting Enterprise Technological Renovation (Guo Fa (2012) No. 44) and Industrial Revitalization and Technological Renovation Special Work Plan for 2015 were found not relevant to famous brand program. The Authority was unable to identify the content of Notice of Shandong Province concerning the Special Award Fund Budget in 2008 for the Development of Self Exporting Brand (Lu Cai Qi Zhi (2008) No. 75) and evaluate whether the regulation is related to the program or not.

31. The Authority also noticed on the website of People’s Government of Guangdong Province, that it issued Decision Concerning Commending and/or Awarding to Enterprises of Guangdong Province Whose Products Qualify for the Title of “China Worldwide Famous Brand”, “China Famous Brand”, or “China Well-known Brand” in 2005, 2006 and 2007. However, it is unknown whether the programme is still active or not.

32. The Authority notes that the program was governed under Administrative Measures for China’s Brand Name Products (Order No. 12 of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) dated December 29, 2001. It was amended by the Decision of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine on Revising the “Administrative Measures for China’s Brand Name Products” on December 18, 2009 (Order No. 124 of 2009 of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine).

33. According to Decision of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine on Abolishing and Amending Some Regulations (2018) (Order No. 196 of 2018 of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine), the program was still valid during the POI.

34. The program provides financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred on the recipient. The program is specific because it is available only to certain enterprise who meets the product criteria for famous brands. None of the participating producers and exporters from China PR have received benefit under this program.

35. The petitioner has also not provided any evidence to show that this program was used by the tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI.

36. During the course of investigation, the Authority could also not find any evidence to show that tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI received benefit under this program. Moreover, the GOC has provided evidence to demonstrate that the program was terminated on 6 March 2018. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(ii) Program No. 2: Special Fund for Energy-Saving Technology Reform

a. Submission by the Petitioners

37. The Petitioners submitted that under the program, funds were arranged to support enterprises who are manufacturing high-efficiency and energy-consuming products in China. As evidence of

existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Circular of Ministry of Finance and National Development and Reform Commission on Printing and Distributing Interim Measures on Administration of Energy Saving Technology Reform Awards Fiscal Funds (Cai Jian (2007) No. 371)
- ii. Provisional Measures Special Fund for Energy Saving Technology under the Circular of the Shandong Finance Department and Shandong Economic and Trade Commission
- iii. Translated Notice of the Ministry of Industry and Information Technology on Issuing the Tire Industry Policy (Gong Chan Ye Zheng Ce (2010) No. 2 at Art.6

b. Submissions by GOC / other interested parties

38. The GOC stated that the petitioners did not provide legal text in respect of Provisional Measures Special Fund for Energy Saving Technology under the Circular of the Shandong Finance Department and Shandong Economic and Trade Commission.

c. Examination by the Authority

39. The Authority notes that the program was governed under Cai Jian (2007) No. 371. The Regulation was replaced with Notice of the Ministry of Finance and the National Development and Reform Commission on Issuing the Administrative Measures for the Financial Incentive Funds for Energy Conservation Technology Retrofits (Cai Jian (2011) No. 367) dated 21 June 2011. This Notice was further replaced with Notice of the Ministry of Finance on Issuing the Interim Measures for the Administration of Subsidy Funds for Energy Conservation and Emission Reduction (Cai Jian (2015) No. 161) dated 12 May, 2015. Cai Jian (2015) No. 161 and is in force till date.

40. With regard to Provisional Measures on Special Fund for Energy Saving Technology under the Circular of the Shandong Finance Department and Shandong Economic and Trade Commission (Lu Cai Jian (2006) No. 61), the Authority also noted that the regulation was replaced with Lu Cai Jian (2007) No. 14) dated 12 June, 2007 and then further replaced with Lu Cai Gong (2017) No.52 dated 27 December, 2017. Lu Cai Gong (2017) No. 52 and is in force till date.

41. The Authority notes that the program has been earlier examined by other investigating authorities in the past, which also proves its existence. For example, countervailability of this program has been established by the US authorities in *Non-Oriented Electrical Steel*.

42. The program provides financial contribution in the form of direct transfer of funds and thereby confers benefit to the recipient of such financial contribution. The program is specific because it is limited to enterprise that undertake energy saving technology reforms.

43. None of the participating producers/exporter from China PR however have received benefit under this subsidy program. Petitioners have also not provided any evidence to show that benefit was received under this program by any of the tyre producers in China PR who exported to India during the POI.

44. During the course of investigation, the Authority could also not find any evidence that tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI received benefit under this program.

45. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(iii) Program No. 3: The Clean Production Technology Fund

a. Submissions by the petitioners

46. The Petitioners submitted that under this program, subsidy fund was provided for the purpose of decreasing pollution through incentives including monetary rewards presented to producers and manufacturers that pass an environmental inspection. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- Provisional Measures on Clean Production Inspection, Decree No. 16 of the Ministry of Environmental Protection of the People's Republic of China (Aug.16, 2004), translated excerpts

b. Examination by the Authority

47. The Authority notes that the program was governed under 'The Interim Measures for Cleaner Production Review (Order No. 16 of the National Development and Reform Commission and the Former State Environmental Protection Administration)'. The regulation was replaced with Measures for Cleaner Production Review (2016 Revision) dated 16 May, 2016. This 2016 Revision is in force till now.

48. The Authority notes that the program has been examined by other investigating authorities in the past. For example, Existence of countervailability of this program has been established by the US authorities in *Non-Oriented Electrical Steel*.

49. The program provides financial contribution in the form of direct transfer of funds and thereby confers benefit to the recipient of such financial contribution. The program is specific because it is limited to enterprise that pass the environmental inspection.

50. None of the participating companies have received benefit under this subsidy program. Petitioner has also not provided any evidence to show that benefit was received under this program by any of the tyre producers in China PR who exported to India during the POI.

51. During the course of investigation, the Authority could also not find any evidence to show that tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI received benefit under this program.

52. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(iv) Program No. 4: The State Key Technology Renovation Projects Fund

a. Submissions by the petitioners

53. The eligible enterprises are provided grants for technical upgrades and renovation and is intended to *inter alia* promote technological renovation in key industries, enterprises and products. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Notice concerning the Promulgation and Circulation of "Measures for the Administration of National Key Technological Renovation Projects" and "Measures for the Administration of Treasury-bond Special Fund for National Key Technological Renovation Projects" (Guo Jing Mao Tou Zi [1999] No 886);
- ii. Guo Jing Mao Tou Zi No 122 of 1999;
- iii. Notice Concerning the Promulgation and Circulation of "Measures for the Supervision and Administration of National Key Technological Renovation Projects (for

Trail Implementation)" from the State Economics and Trade Commission (Guo Jing Mao Tou Zi [1999] No 1038);

iv. Notice of Amendments to the "Measures for the Administration of National Key Technological Renovation Projects" and "Measures for the Administration of Treasury-bond Special Fund for National Key Technological Renovation Projects" (Guo Jing Mao Tou Zi [2000] No 822).

v. Shandong Province's List of 2012-13 Shandong Province International Brands for Focused Fostering and Development includes 15 tire brands / producers

vi. Measures for the Administration of Chinese Famous-Brand Products, General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine, Order No. 124 (Dec 18, 2009)

vii. Notice of Shandong Province Department of Commerce on Announcing List of 2011-2013 Shandong Province International Brand Names for Focused Fostering and Development (Jan.7. 2012)

54. The program provides for direct transfer of funds in the form of cash grants and confers benefit on the recipient. This program has been held countervailable by other investigating authorities. The petitioners have further alleged that major tyre producers in China who are eligible for these programs are entities such as Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd (a predecessor to Double Coin), Guizhou Tyre Co., Ltd, Qingdao Doublestar.

b. Submissions by GOC / other interested parties

55. This program was terminated long time ago on February 22, 2008. There is no continuing existence of benefit under this program. There was no replacement and grace period granted for this program. So no producers / exporters could have applied for or received benefits under this program during the POI.

c. Examination by the Authority-

56. The Authority notes that the said program was introduced on 10 September 1999 through:

i. "Measures for the Administration of National Key Technological Renovation Projects" and

ii. "Measures for the Administration of Treasury-bond Special Fund for National Key Technological Renovation Projects" (Guo Jing Mao Tou Zi [1999] No 886), which was replaced on 28 August 2000 (Guo Jing Mao Tou Zi [2000] No 822).

iii. Further, "Measures for the Supervision and Administration of National Key Technological Renovation Projects (for Trail Implementation)" issued by the State Economics and Trade Commission (Guo Jing Mao Tou Zi [1999] No 1038) was the instrument providing for the supervision of the program.

57. On 22 February 2008, the National Development and Reform Commission ("NDRC") issued its Decree No. 59, by which the aforementioned instruments were rescinded.

58. The Authority examined the remaining three instruments forming the legal basis:

i. Shandong Province's List of 2012-13 Shandong Province International Brands for Focused Fostering and Development (which includes the names of 15 tyre brands/producers);

ii. Measures for the Administration of Chinese Famous-Brand Products, General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine, Order No. 124 (Dec 18, 2009); and

iii. Notice of Shandong Province Department of Commerce on Announcing List of 2011-2013 Shandong Province International Brand Names for Focused Fostering and Development (Jan.7. 2012)

The Authority however found that these instruments were not relevant for the legal basis of the said program.

59. In view of the above, the Authority notes that while some of the instruments were not relevant to the aforementioned program, the other instruments were no longer in force. Thus, no producers in China PR who exported the subject product to India could have received the benefit under this program during the POI. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(v) Program No. 5: Fixed asset investment subsidies

a. Submissions by the petitioners

60. The petitioners stated that under above program, a subsidy is provided by the Hefei Government. It is a subsidy that is provided under the report of 'the Hefei Municipal Economy and Information Commission' for export promotion. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Hefei Municipal Economy and Information Commission, Notice of Request for Comments: Several Policies for Receiving Transferred Industries and Accelerating New Industrialization (May 15, 2013)
- ii. GITI Fujian Initial Quarterly Reports (2014)

Petitioners also pointed out that only Giti Anhui Passenger Radial Tyre Co., Ltd, Giti Tyre (Anhui) Co., Ltd. were eligible for this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

61. Giti Fujian Initial Quarterly Reports is not the legal basis. Therefore, the Authority should disregard such information. There is only one producer of the subject goods based in Hefei City, i.e. Giti Tyre (Anhui) Co., Ltd.

c. Examination by the Authority

62. The Authority notes that under the regulation, Hefei Municipal Economy and Information Commission provides financial contribution equivalent to 5% of fixed assets investment value. The program provides financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred on the recipient. Subsidy is also specific because it is specific to enterprise having fixed assets investment and who qualify for such benefit.

63. None of the participating companies have received benefit under this subsidy program. Petitioner has also not provided any evidence to show that benefit was received under this program by any of the tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI.

64. The Authority notes that Giti Tyre (Anhui) Co. Ltd. based in Hefei City has exported the subject product to India during the POI and was eligible to receive benefit under this program. Giti

Tyre (Anhui) Co. Ltd. has not participated or filed questionnaire response and therefore the Authority cannot presume that Giti Tyre (Anhui) Co. Ltd. has not received benefit under this program. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(vi) Program No. 6: Venture Investment Fund of Hi-tech Industry

a. Submissions by the petitioners

65. The petitioners stated that under above program, enterprises producing “high-tech products” located in the high-tech zone or the high-tech park (Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Northern Districts of China) are eligible for financial grants. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

i. Circular of Chongqing People’s Government Office in Temporary Administration Measures on Venture Investment Fund of Hi-tech Industry in Chongqing 2005

66. The petitioner also pointed out only Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd, Shanghai Guang Zheng Rubber Co., Ltd, Shanghai International Trade Co., Ltd, Fitch Bamboo, China Shipbuilding Trading (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai Xingyu Trading Co., Ltd, Chongqing Aung Dove Trade Co., Ltd, Upload Ying Trade Co., Ltd, Chongqing Yan Import and Export Co., Ltd, Chongqing Xuannan Science & Technology Co., Ltd. were eligible for this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties

67. The GOC stated that the regulation was only applicable to Chongqing Municipality. There was no producer of subject product based in Chongqing.

c. Examination by the Authority:

68. The Authority notes that under the regulation, the Chongqing Municipal Government did provide subsidy to important high-tech industries in Chongqing.

69. The Authority notes that the program has been examined by some other investigating authorities, which also proves its existence. For example, countervailability of this program has been established by the Canadian investigating authorities in *Certain Aluminium Extrusions*.

70. The program provides financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred on the recipient. Subsidy is also specific because it is specific to high-tech industries.

71. However, the Authority notes that there were no tyre producers based in Chongqing. Therefore, none of the tyre producers who exported the subject product to India could have received benefit under this program. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(vii) Program No. 7: Grants for encouraging the establishment of headquarters and regional headquarters with foreign investment

a. Submissions by the petitioners

72. The petitioners state that the main object of the program was to attract investment. FIEs are provided grants in order to reduce investment costs. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Provision of Guangzhou Municipality on Encouraging Foreign Investors to Set up Headquarters and Regional Headquarters
- ii. Notice of the General Office of Guangzhou Municipal People's Government about Issuing the Provisions of Guangzhou Municipality on Encouraging Foreign Investors to Set up Headquarters and Regional Headquarters (No. 34 (2006))
- iii. Guangzhou Municipal People's Government to speed up the implementation of the views forwarded to notice the development of headquarters economy (Sui (2010) No. 2)

73. Petitioners pointed out that only Zhaoyuan Liao Rubber Products Co., Ltd, Hangzhou Zhongce Rubber Co., Ltd, Haoyou Tyre Co., Ltd, Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd, Michelin (Shenyang) Tyre Co., Ltd, Xiamen Zhengxin Rubber Industry Co., Ltd, Kenda Rubber (China) Co., Ltd. were eligible for this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties

74. Legal basis (i) and (ii) were same, which were terminated as per legal basis (iii). Legal basis (iii) was also terminated under Notice of the People's Government of Guangzhou Municipality on Accelerating the Development of Headquarter Economy (Sui Fu (2013) No. 14 dated 15 June 2013

c. Examination by the Authority

75. The Authority notes that Notice of the General Office of Guangzhou Municipal People's Government on Encouraging Foreign Investors to Set up Headquarters and Regional Headquarters (Sui Fu Ban (2006) No.34) was replaced with Guangzhou Municipal People's Government to speed up the implementation of the views forwarded to notice the development of headquarters economy (Sui Fu (2010) No. 2) on 16 January 2010. However, this legal basis was also terminated under Notice of the People's Government of Guangzhou Municipality on Accelerating the Development of Headquarter Economy (Sui Fu (2013) No. 14 dated 15 June 2013.

76. No tyre producers in China PR could have received benefit under the alleged subsidy programs because it was not in force.

77. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(viii) Program No. 8: Innovative Small and Medium Enterprise Grants

a. Submissions by the petitioners

78. Grants were provided to start-up capital, and subsidies for new product development for SMEs. The appropriation amount to each project will generally not exceed RMB 1 million with a maximum of RMB 2 million for key projects. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents.

- i. Article 12, 13, 36 of Law of PRC on promotion of SME;
- ii. Measures for Administration of International Market Developing Funds of Small and Medium Sized Enterprises
- iii. Detailed rules for the implementation of the measures for administration of international market developing funds for small and medium sized enterprises (July 1, 2001)
- iv. Circular cooperation issuing the measures for the administration of international market developing funds of small and medium sized enterprises (2010)

- v. Foreign trade development funds and management approach, Cai Qi (2014)
- vi. Notice of the ministry of finance and the ministry of industry and information technology on issuing the “Measures on Administration of Special Funds for Development of SMEs” (No. 96 (2012) of Ministry of Finance)
- vii. Ministry of industry and information technology, Ministry of science and technology, Ministry of commerce on the issuance of special funds interim measures for SMEs development (Cai Qi (2014) No.38)
- viii. Ministry of Finance on the issuance of “Interim Measures on Management of Special Funds for SMEs development (Cai Jian (2015) No.458

b. Submissions by GOC / other interested parties-

79. Participating producers/exporters from China PR did not receive any benefit under this program.

c. Examination by the Authority:

80. The Authority notes that the program was governed under the Measures for the Administration of Special Funds for the Development of Small and Medium Enterprises (Cai Qi (2004) No. 185). The regulation was replaced several times. It was eventually replaced by Cai Jian (2016) No.841, which is still in force.

81. Also, Law of the People's Republic of China on the Promotion of Small and Medium- sized Enterprises was revised on 1 September, 2017.

82. The Authority also notes that Detailed Rules for the Implementation of the Measures for Administration of International Market Developing Funds of Small-and Medium-Sized Enterprises was eventually replaced with Notice of the Ministry of Finance and the Ministry of Commerce on Issuing the Measures for the Administration of the Special Fund for Foreign Trade and Economic Development (2014 Revision) (Cai Qi (2014) No.36), which is still in force.

83. The program provided financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred on the recipient. Subsidy is also specific because it is available only to small and medium-term enterprise (SMEs).

84. None of the participating producers/exporters from China PR have received benefit under this program. Petitioners have also not provided any evidence to show that tyre producers in China PR have received benefit under the alleged subsidy program. During the course of investigation, the Authority could also not find any evidence to show that tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI received benefit under this program.

85. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(ix) Program No. 9: Reimbursement of Anti-dumping and / or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments

a. Submissions by the petitioners

86. The Petitioners claimed that the scheme is restricted to certain enterprises that are subject to foreign anti-dumping proceedings. Such companies are eligible for refund of 40% of legal fees incurred for participating in anti-dumping proceedings. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Rules for the Implementation of the Support Policy for the Antidumping, Anti-subsidy, Safeguard Investigation Respondent

It has also been submitted that this program has been held countervailable by other investigating authorities.

b. Examination by the Authority

87. The Authority notes that in the petition, the petitioners only provided a news article, which is not the legal basis. However, the Authority also notes that Zhejiang Province issued Countermeasures for Antidumping Regarding Export Products of Zhejiang Province (Order. 319 of the People's Government of Zhejiang Province) dated April 1, 2014 and it was found that Article 5.1 stated that the Financial Administrative Authorities shall provide the necessary financial support for antidumping defense.

88. The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established For example, the EU authorities in *organic coated steel products* and *coated fine paper* countervailing duty investigation and the United States authorities in *carbon and certain alloy steel wire rod*.

89. The program provided financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred on the recipient. Subsidy is also specific because it is specific to enterprise subjected to anti-dumping investigation.

90. The Authority noted that certain cooperative producers/exporters from China PR received benefit in the name of legal fee for fair trade fund during the POI instead legal fee for participating in the anti-dumping investigation initiated by other countries. The reimbursement of legal fee for fair trade thus availed by some exporters has been countervailed.

(x) Program No. 10: Superstar Enterprise Grant

a. Submissions by the petitioners

91. The Petitioners claimed that the scheme is restricted to certain enterprises that exceed the sales value during the year. Financial contribution in the form of grant is provided by the local government upon meeting the target of annual sales. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Measures for Assessment and Encouragement of Superstar Enterprises and Excellent Enterprises
- ii. Notice of Huzhou Government Office Concerning Announcement of Criteria for Superstar Enterprises, Excellent Enterprises and Backbone Enterprises

b. Submission by the GOC/other interested parties

92. The Program is Huzhou City specific. There are no tyre producers based in Huzhou City.

c. Examination by the Authority

93. The Authority notes that in the petition, the petitioners only provided findings by Authorities in other jurisdictions. No legal text was attached of the scheme documents noted in the petition. The Authority failed to identify the content of Measures for Assessment and Encouragement of Superstar Enterprises and Excellent Enterprises and evaluate the existence of the program based on such evaluation.

94. The Authority notes that Notice of Huzhou Government Office Concerning Announcement of Criteria for Superstar Enterprises, Excellent Enterprises and Backbone Enterprises (Hu Zheng Ban Fa (2008) No. 20) was replaced with the Opinions of the People's Government of Huzhou City on further Promoting Industrial Transformation and Upgrading (Hu Zheng Fa (2011) No. 6). Hu Zheng Fa (2011) No. 6 was also abolished under Notice of the People's Government of Huzhou City on Repealing Administrative Documents (Hu Zheng Fa (2014) No. 14). The program was in existence in Huzhou City.

95. The Authority notes that there was no tyre producer based in Huzhou City and so even if this program amounts to subsidy and was specific in nature, no tyre producer in China PR could have received benefit under this program. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(xi) Program No. 11: Export Assistance Grant

a. Submissions by the petitioners

96. Grants are provided to SMEs for (i) holding or participating in overseas exhibitions, (ii) for quality management system, environment management system, (iii) promotion in the international market, (iv) exploring a new market, (v) holding training seminars and symposiums, and (vi) overseas bidding. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following scheme document.

- i. Foreign Trade Department of Finance (2001) No. 270

b. Submissions by GOC / other interested parties

97. Neither GOC nor any of the responding exporters have provided any specific comments with regard to the alleged program. However, Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd and Shandong Haohua Tire Co, Ltd have accepted that they have availed benefit out of this program.

c. Examination by the Authority:

98. The Authority notes that the program was governed under Circular Cooperation Concerning Issuing the Measures for the Administration of International Market Developing Funds of Small-and Medium-Sized Enterprises (for Trial Implementation) (Cai Qi (2000) No. 467) and Detailed Rules for the Implementation of the Measures for Administration of International Market Developing Funds of Small-and Medium-Sized Enterprises (for provisional implementation) (Wai Jing Mao Ji Cai Fa (2001) No. 270). However, both regulations were replaced with Notice of the Ministry of Finance and the Ministry of Commerce on Issuing the Administrative Measures for International

Market Developing Funds of Small and Medium-Sized Enterprises (Cai Qi (2010) No. 87) dated May 24, 2010 and further replaced with 2014 Revision (Cai Qi (2014) No. 36 dated April 9, 2014. Cai Qi (2014) No. 36 was found in existence till now.

99. The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities and existence and countervailability of this program has been established (a) by the US authorities in *Circular Welded Carbon Quality Steel Pipe* as well as in *Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe*; and (2) by the Canadian authorities in *Certain Metal Bar Grating of Carbon, Alloy or Stainless Steel*.

100. Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd and Shandong Haohua Tire Co, Ltd, two of the responding exporters from China who have submitted questionnaire response, have stated that they availed this benefit and have provided information with regard to the amount of subsidy received by them during the POI.

101. Besides, the companies also provided relevant information with regard to operation of the scheme and benefit under the scheme, including the legal basis. The Authority notes that Department of Commerce of Shandong Province yearly issued the Notice on Hundred Exhibitions Market Exploring Plan, in which the Government of Shandong Province would provide grants to the companies for reducing their cost of participation in such exhibitions.

102. Program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. Program is also specific because it is limited to SMEs. The fact that Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd., benefited from the program shows that program was in fact used by the tyre producers in China that exported the subject product to India during the POI. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(xii) Program No. 12: Research & Development Assistance Grant

a. Submissions by the petitioners

103. The petitioners stated that the grant is limited to enterprises that undertake science and technology research and are selected by the local authorities. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents

- i. Implementation measure to support the acquisition of foreign science & technology type enterprises and the employment of foreign science & technology development team, issued by the Shenyang Economic & Technological Development Area Administration
- ii. Notice of the Office of People's Government of Wuxing District on Publishing and Issuing the Management Measures on three types of Science and Technology Expenses of Wuxing District
- iii. Circular of the office of the People's Government of Wuxing District Concerning Printing and Distributing the Administrative Measures of the use of Science & Technology Three type of funds of Wuxing District
- iv. Wuxi Municipal Bureau on S&T

v. Article 9, 34, 35, 37 Law of PRC on S&T, 2007

However, the petitioner also pointed out that only Hangzhou Zhongce Rubber Co., Ltd, Yiwu Jinyun Commodities Purchase Co., Ltd. were eligible for this program

b. Submissions by GOC / other interested parties-

104. The GOC stated that the petitioners failed to provide legal text of Implementation measure to support the acquisition of foreign science & technology type enterprises and the employment of foreign science & technology development team, issued by the Shenyang Economic & Technological Development Area Administration. Notices of the Office of People's Government of Wuxing District were only applicable to companies located in Wuxing District, Huzhou, Zhejiang Province. However, no producer of the PUC was located in the area.

c. Examination by the Authority:

105. The Authority notes that the program was regulated under the Law of the People's Republic of China on Scientific and Technological Progress and the regulation was still valid.

106. Notice of the Office of People's Government of Wuxing District on Publishing and Issuing the Management Measures on three types of Science and Technology Expenses of Wuxing District (Wu Zheng Ban Fa (2005) No. 78) was abolished on 22 September 2017 through Wuxing District People's Government Notice on Publishing Reviewing Results towards Administrative Rules and Regulations in 2017 (Wu Zheng Fa (2017) No.29) and was thus in existence during POI.

107. Petitioners did not provide legal text of Implementation measure to support the acquisition of foreign science & technology type enterprises and the employment of foreign science & technology development team, issued by the Shenyang Economic & Technological Development Area Administration.

108. The Authority notes that the program has been earlier examined by other investigating authorities in the past. For example, countervailability of this program has been established by the Canadian authorities in *Certain Stainless Steel Sinks* and *Certain Aluminium Extrusions*.

109. The program provides for financial contribution by way of direct transfer of funds by Wuxing District to enterprises that undertake science and technology research. However, there are no tyre manufacturers based in Wuxing district and therefore the Authority determines that no tyre manufacturer in China who exported the subject product to India could have benefitted from this program. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(xiii) Program No. 13: Subsidies for Companies Located in the Hefei Economic and Technology Development Zone

a. Submissions by the petitioners

110. Hefei government provided funds to support innovation and technology upgrades and matching funds for new upgrades, exemptions from government fees, grants and rebates, loan interest deductions and preferential VAT and income tax treatment for exports. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided annual report of the company as evidence of the existence of the program.

111. This program was only eligible for producers situated in certain designed areas. It has been shown that producers such as Giti Radial Tyre (Anhui) Co., Ltd might have availed the benefit out of this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

112. The GOC stated that there was only one tyre manufacturer based in the designated area. However, annual report is not the form of legal basis.

c. Examination by the Authority

113. The Authority noted that in the petition, the petitioners only provided Hefei Economic & Technological Development Area Investment Environment Study 2008 reported by KPMG and web introduction of Hefei Economic & Technological Development Area. Both documents were not legal basis of the program.

114. However, the Authority notes that the alleged program provided financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred on the recipient. Subsidy is also specific because it is specific to certain enterprise engaged in technology and innovation upgrade.

115. One tyre manufacturer GITI Radial Tyre (Anhui) Co. Ltd. was based in Hefei Economic and Technology Development Zone. GITI Radial Tyre (Anhui) Co. Ltd. has not participated in this investigation or filed questionnaire response. GITI Radial Tyre (Anhui) Co. Ltd was eligible to receive benefit under this program and the Authority cannot presume that the GITI Tyre (Anhui) Co. Ltd. has not received benefit under this program. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(xiv) Program No. 14: Anhui Province Subsidies for Foreign-Invested Enterprises

a. Submissions by the petitioners

116. The Petitioners claimed that FIEs which are located in Anhui Province are eligible for certain exemptions and deductions of VAT. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Preferential Tax Policies of Anhui Province for Foreign-invested Enterprises (May 13, 2011)
- ii. "Preferential Treatment for the Foreign-funded Enterprises in the Development Zones of Anhui Provinces" (May 13, 2011)

The petitioners also pointed out that PUC producers such as Giti Radial Tyre (Anhui) Co., Ltd might have availed the benefit out of this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

117. The GOC stated that there was only one FIE tyre manufacturer based in the designated area.

c. Examination by the Authority

118. In the petition, the petitioners only provided web news of Preferential Policies for Foreign Invested Enterprises in Anhui Province. However, both documents are not legal basis for the

existence of the program. Authority was unable to identify the scheme document governing the implementation of this program.

119. Giti Radial Tyre (Anhui) Co., Ltd is an FIE and was based in Anhui province. Giti Tyre (Anhui) Co. Ltd. is based in Anhui province and has exported the subject product to India during the POI and was eligible to receive benefit under this program.

120. Giti Tyre (Anhui) Co. Ltd. has not participated or filed questionnaire response and therefore the Authority cannot presume that Giti Tyre (Anhui) Co. Ltd. has not received benefit under this program.

121. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(xv) Program No. 15: Hefei Municipal Export Promotion Policies

a. Submissions by the petitioners

122. The Petitioners claimed that a grant equal to 1% or 1.5% of a company's trade value is awarded by the municipality of Hefei, if the company exports and imports above a certain amount. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Hefei introduced a number of policies to promote the development of foreign trade (May 23, 2012)
- ii. Notice of Hefei People's Government on the issuance of a number of policies to promote the development of foreign trade (September 30, 2013)

The petitioners also pointed out that producers such as Giti Radial Tyre (Anhui) Co., Ltd might have availed the benefit out of this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

123. The GOC stated that there was only one FIE tyre manufacturer based in the designed area.

c. Examination by the Authority

124. The Authority notes that the petitioners have provided Notice of Hefei People's Government on the issuance of a number of policies to promote the development of foreign trade (He Zheng Mi (2013) No. 115), in which it was clearly mentioned that when the enterprise achieves import and export volume of more than \$ 50 million and achieves steady growth, 1% of its total import and export trade value is provided as reward.

125. Regarding the claim that Hefei introduced a number of policies to promote the development of foreign trade (May 23, 2012), the Authority notes that the petition does not provide legal text of any of these policies. The Authority also identified that Hefei People's Government Office issued Notice (He Zheng Ban (2012) No. 25) but the same was repealed under the Decision on Revocation of Administrative Documents (He Zheng (2014) No. 46 dated April 8, 2014.

126. Giti Radial Tyre (Anhui) Co., Ltd is an FIE and was based in Hefei City. Giti Radial Tyre (Anhui) Co. Ltd. is based in Hefei City and has exported the subject product to India during the POI and was eligible to receive benefit under this program.

127. Giti Tyre (Anhui) Co. Ltd. has not participated or filed questionnaire response and therefore the Authority cannot presume that Giti Tyre (Anhui) Co. Ltd. has not received benefit under this program.

128. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(xvi) Program No. 16: Subsidies for Companies Located in the Kunshan Economic and Technological Development Zone.

a. Submissions by the petitioners

129. Various benefits like exemption from local income tax, exemption by half in income tax for export oriented enterprises, reduced income tax rates are available to FIEs located in the Kunshan Economic and Technological Development Zone. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents

- i. Kunshan Municipal Office of the State Administration of Taxation “Introduction of Tax Benefits for Foreign-invested Enterprises
- ii. Preferential Policies for Foreign-Invested Enterprises under the Old Income Tax Law.

The petitioners also pointed out that PUC producers such as Kenda Rubber (China) Co., Ltd might have availed the benefit out of this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties

130. The GOC stated that there was no tyre FIE manufacturer based in the designated area.

c. Examination by the Authority

131. The Authority notes that document referred to by the petitioners did not constitute legal basis. Petitioners claim that the subsidy program existed under the old income tax law. In this regard, the Authority notes the details regarding the tax reform that took place in China PR in 2008. Before 2008, China PR implemented Provisional Regulations of the People's Republic of China on Enterprises Income Tax, which was applicable to all enterprises other than foreign invested enterprises (“FIEs”) within China PR. China PR separately implemented Income Tax Law of the PRC for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises, in which there were lot of preferential tax policies applicable to FIEs. On 16th March 2007, the GOC issued Enterprise Income Tax Law (“EITL”) of the PRC, which is applicable to all enterprises in China PR including the FIEs. This law was implemented w.e.f 1 January 2008. There were two major changes in the new tax law: (1) preferential income tax policies for FIEs have been terminated, and a unified tax rate is made applicable for domestic enterprises and FIEs; (2) preferential income tax policies for local special economic zones have been terminated. Further, the State Council issued notice on the Implementation of the Transitional Preferential Policies in respect of Enterprise Income Tax,

stipulating that as of 1 January, 2008, enterprises that previously enjoyed the preferential policies of low tax rates shall be gradually transited to enjoy the statutory tax rate within 5 years after implementation of the EITL. Therefore, even enterprises which enjoyed preferential tax policies under old income tax law would no longer enjoy the same from the end of 2012.

132. The document annexed in the petition itself mentioned that new enterprise income tax law granted a five-year transitional period since January 1, 2008. This transition period ended before the POI i.e on 1 January 2013. Besides, it is found that there was no producer of the PUC located in Kunshan Economic and Technological Development Zone.

133. No tyre producers in China PR could have received benefit under the alleged subsidy program because it was not in force.

134. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(xvii) Program No. 17: Weihai Municipality Subsidies for the Automobile and Tyre Industries

a. Submissions by the petitioners

135. The Municipal Authority of Weihai provides funds for expansion of projects in form of credit support, exemption of tax for encouraging companies to take advantage of preferential policy. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents

- i. Weihai Economic and Information Technology Committee, “Weihai Municipal 12th Five Year Development Plan for the Automobile and Automobile Parts Industry” (April 3, 2013)
- ii. Weihai Bureau of Finance, “Shandong Province Competitive Allocation Plan of Self Dependant Innovation Specialty Fund” (August 6, 2012)

It has been claimed that producers such as Kupo Chengshan (Shandong) Tyre Co., Ltd. and Triangle Tyre Co., Ltd might have availed the benefit out of this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

136. The GOC stated that 12th Five Year Plan referred to the Year 2011-2015 and that since the period has elapsed, the program was invalid since 2015.

c. Examination by the Authority:

137. The Authority notes that Shandong Province did provide financial assistance in the form of grants, loan interest subsidies, equity investment, incentives and other means to support rubber tyre industry through Notice of the General Office of the Provincial Government on the Competitive Distribution of Special Funds for Independent Innovation (Lu Zheng Ban Fa [2012] No. 49). Benefit was thereby conferred on the recipient of these financial contribution. However, the same notice clearly mentioned that provincial government would arrange 1 billion RMB each year in 2012-2015 to support the projects development. However, the period of benefit expired before the beginning of the POI. The program was terminated as well. The Authority also notes that the grants from the

above program were not tied to capital assets and were recurring in nature.

138. In view of the above, the Authority notes that while some of the instruments were not relevant to the aforementioned program, the other instruments were no longer in force. Thus, no tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI could have received the benefit under this program during the POI.

139. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(xviii) Program No. 18: Subsidies for Companies Located in the Rongcheng Economic Development Zone

a. Submissions by the petitioners

140. The Rongcheng Municipal Government provided funds for providing support to CCT Companies situated in Rongcheng EDZ. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents

- i. Certain Rules on Encouraging Companies to Transform and Develop by Rongcheng Municipal People's Government (February 28, 2012)

It has been claimed that tyre producers such as Kupo Chengshan (Shandong) Tyre Co., Ltd. and Rongcheng Yuke Trading Co., Ltd might have availed the benefit out of this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties

141. The GOC stated that the Petitioner provided legal basis but attached wrong legal text. The GOC stated that this program has been terminated.

c. Examination by the Authority:

142. The Authority notes that the program was governed under Regulations on the encouragement and transformation of enterprises by the government of Rongcheng City (Rong Zheng Fa (2012) No. 7). But it was terminated under Notice of the public government of Rongcheng City on the publication of the cleanup results of the municipal government's regulatory documents (Rong Zheng Fa (2016) No.16).

143. In view of the above, the Authority notes that relevant instrument was no longer in force during POI. No tire producers in China PR who exported the PUC to India during POI could have received benefit under the alleged subsidy programme because it was not in force.

144. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(xix) Program No. 19: Export Interest Subsidy Funds for Enterprises Located in Guangdong and Zhejiang Provinces

a. Submissions by the petitioners

145. Funds were provided to exporters located in Guandong Province and Zhejiang Province. For evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents.

- i. Transitional Review Mechanism Pursuant to Section 18 of the Protocol on the Accession of the people's Republic of China, Questions from the European Communities to China with Regard to China's Transitional Review Mechanism on Subsidy Practices, G/SCM/Q2/CHN/24, at 2,3 (Oct. 20, 2006)
- ii. Export Interest Subsidy for Shenzhen Enterprises Raised, TDC Trade (May 1,2004)

146. It has been claimed that producers such as Zhongce, Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd, Kenda Tyre (Shenzhen) Co., Ltd and South China Tyre & Rubber might have availed the benefit out of this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

147. The GOC stated that the Petitioner provided two legal basis but both were not legal basis regarding the existence of the program.

c. Examination by the Authority:

148. The Authority notes that the petitioners merely provided evidence showing that exporters in Zhejiang Province and Shenzhen might get export interest subsidy funds in 2004. Authority also notes that question from the EU to China PR in the WTO is not the legal basis and does not establish the existence of the program. Transitional Review Mechanism Pursuant to Section 18 of the Protocol on the Accession of the People's Republic of China has expired.

149. The Authority notes that, no tyre producer in China PR who exported the PUC to India during the POI could have received benefit under the alleged subsidy program because it was not in force. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed

(xx) Program No. 20 Funds for “Outward Expansion” of Industries in Guangdong Province

a. Submissions by the petitioners

150. Funds were provided to enterprises for international market exploration, export credit insurance assistance, the development of trade through science and technology, export product research and development, support for defense expenses in antidumping duty cases, interest grants for various export-related loans and development of outward-looking enterprises. The petitioner claims that subsidy is regional specific and contingent on export performance. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents.

- i. Implementing Measures of Guangdong Province on the Supporting the Development of Outward-Oriented Private Enterprises (Yue Ban Fa (2003) No. 17)
- ii. Guangdong Supports Private Enterprise Outwards, TDC Trade, Mar. 1, 2004.

However, the petitioner also pointed out that only Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Co., Ltd., Kenda Tyre (Shenzhen) Co., Ltd, South China Tyre & Rubber were eligible for this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

151. The GOC stated that the regulation Yue Ban Fa (2003) No. 17 is valid but was only applicable to Guangdong Province. Besides, there was only one producer of the PUC based in Guangdong Province. Further, the second document ‘Guangdong Supports Private Enterprise Outwards’ does not constitute valid legal basis.

c. Examination by the Authority:

152. The Authority notes that Yue Ban Fa (2003) No. 17 was valid. Pursuant to this regulation, Guangdong province provided grants to companies through the program.

153. The program provided financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred on the recipient. Subsidy is also specific because it is contingent on export performance. The Authority notes that the program has been earlier examined by other investigating authorities in the past, which establishes its existence as a subsidy. For example, countervailability of this program has been established by the US authorities in *Lightweight Thermal Paper*.

154. Out of the tyre producers who have exported to India during POI, Guangzhou Pearl River is located in this place. Guangzhou Pearl River has not participated in the investigation or filed questionnaire response. Guangzhou Pearl River was eligible to receive benefit under this program. In absence of any information or participation from Guangzhou Pearl River, the Authority cannot presume that Guangzhou Pearl River has not received benefit under this program.

155. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(xxi) Program No. 21: Direct Government Grants to Aeolus

a. Submissions by the petitioners

156. The Petitioners claimed that various grants for export promotion are provided by the GOC to the tyre industry. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents.

i. Annual Report of Aeolus

The petitioners also pointed out this program was only eligible to Aeolus.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

157. The GOC stated that an annual report does not form the legal basis. The Authority may verify from the Exporter’s Questionnaire Response filed by Aeolus Tire Co., Ltd., as to whether it has received any such subsidies from the GOC.

c. Examination by the Authority

158. The Authority notes that the petitioners have provided a news report which was not legal basis to establish the existence of the program.

159. The Authority has verified the existence of all government grants received by Aeolus and it was found that all data reported were reconciled with its annual report and audited accounts. The

subsidy margin for grants received by Aeolus has been determined separately based on the information provided in the questionnaire response. There is no program by the description of direct grants from the GOC to Aeolus.

160. The Authority notes that no other tyre producer(s) in China PR who exported the subject product to India could have received benefit under the alleged program which was allegedly only available to Aeolus.

161. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(xxii) Programs No. 22 to 26: Direct Government Grants to Double Coin, GITI, Guizhou Tire, Qingdao Double Star, Sailun Group

a. Submissions by the petitioners

162. The Petitioners claimed that various grants were mentioned in the annual reports such as innovation and industry upgrading special guiding funds to specific tyre producers. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents.

- i. Annual Report 2013 of Double Coin Holdings
- ii. Annual Report 2016 of GITI
- iii. Annual Report of Guizhou Tyre
- iv. Annual Report of Qingdao Double Star
- v. Annual Report of Sailun Group

b. Submissions by GOC / other interested parties-

163. The GOC states that the annual reports do not constitute the legal basis. Besides, the petitioners have only provided Annual Reports of Double Coin Holdings and GITI for the year 2013.

c. Examination by the Authority

164. The Authority noted that the petitioners did not provide any legal basis concerning the above programs. Moreover, evidence provided in the form of annual report of two companies is for the year 2013 and therefore not relevant to determine that grants were received by these tyre producers during the POI.

165. In any case, the Authority notes after reviewing all the information that no subsidy programs by the name 'direct grants' were in existence.

166. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against these programs.

I.A Grant programs received by participating producers/exporters from China PR

167. Six groups of tyre producers from China PR have filed questionnaire response. Out of these, 5 groups have exported the subject product to India during the POI. M/s. Shandong Haohua Tire Co.

Ltd., M/s. Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd. and M/s. HK Trade Wind Trading Ltd. have not exported the subject product to India. Individual subsidy margin cannot be determined for tyre producers who have not exported the subject product to India during the POI. Accordingly, the Authority holds that separate countervailing duty rate cannot be determined for these producers from China PR.

(i) Zhongce Rubber Group Co. Ltd

168. Zhongce Rubber Group Co. Ltd., (Zhongce Rubber) filed questionnaire response and provided information regarding the grant programs availed by them.

169. Zhongce has three factories involved in the production of the subject goods. The three factories namely, (i) Zhongce Rubber (Jiande) Co., Ltd. (ii) Zhongce Chaoyang Rubber Co., Ltd. (iii) Zhongce Rubber (Fuyang) Co., Ltd. are subsidiaries 100% owned by Zhongce Rubber. Zhongce Rubber has provided information regarding grant programs availed by these subsidiaries as well.

170. Authority has verified the information provided by Zhongce Rubber Group Co. Ltd. and determined subsidy margin for grant programs for which benefit was received or accrued during the POI. Authority determined that all the grant programs resulted in the provision of financial contribution in the form of direct transfer of funds. As a result, benefit was conferred to Zhongce Rubber as a recipient of this grant. Subsidy programs were also specific because they were limited to certain enterprise including Zhongce Rubber.

171. The table below provides for the name of the grant programs, and the corresponding subsidy margin:

Name of the grant program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
2014 Special Funds for Promotion of Foreign Economic and Trade Development in Hangzhou Economic and Technology Development Area (HEDA)	To support the following five main projects: (1)Exhibition Subsidies; (2) Export Brand Names; (3) Export Credit Insurance; (4) Import Advanced Equipment; (5) Participating of Anti-dumping investigation (6) Service outsourcing industry related activities (7) Setting up foriegn trade operation survey mornitoring points	***	0-1%
2013 Export Credit Insurance Subvention for Enterprises located in HEDA	Reimbursement of the Export Credit Insurance cost incurred by the company in previous years	***	0-1%
2016 Special Funds for Foreign Economic and Trade Development (HEDA)	To support enterprises investment in overseas region - Zhongce received the grant for its investment activities in Thailand.	***	0-1%

Coal-fired Boiler Clean Renovation 1st Phase Special Grants (HEDA)	To reform thermoelectric coal-fired boilers and industrial coal-fired boilers for environment protection purpose in order to decrease the emission of dust, sulfur dioxide and nitrogen oxide.	***	0-1%
2016 Air Pollution Prevention Special Grants	To reform thermoelectric coal-fired boilers for environment protection purpose	***	0-1%
2016 Hangzhou Pollution Source Monitoring Equipment Funds (1st batch)	To reform thermoelectric coal-fired boilers for environment protection purpose	***	0-1%
2016 Hangzhou Pollution Source Monitoring Equipment Funds (2nd batch)	To reform thermoelectric coal-fired boilers for environment protection purpose	***	0-1%
2014 Zhejiang Province and Hangzhou City "Export Famous Brand" Award	The program is provided for enterprises whose product brand is recognized as "Hangzhou Export Famous Brand" or "Zhejiang Export Famous Brand"	***	0-1%
Grants for Employment Stabilization of Hangzhou City	The employment stabilization subsidy is provided to the enterprises that takes effective measures to reduce layoffs and keep stable employment.	***	0-1%
2016 Hangzhou Internet of Things and Industrial Internet Pilot Project Funding	Support enterprises trial projects on applying internet of things into production and management	***	0-1%
Financial subsidy (HEDA)	General financial assistance	***	0-1%
2015 RD Investment Funding for Enterprises located in HEDA	For R&D purposes	***	0-1%
2016 Technology Standard Funding (HEDA)	For technology advancement	***	0-1%
2013 Import and Export Trade Fair Funding	For marketing assistance	***	0-1%
Postdoctoral researchers funding	For R&D purposes	***	0-1%
Postdoctoral researchers one-time R&D funding	For R&D purposes	***	0-1%
Government subsidy deferred income transfer into non-operational income	For acquisition of assets	***	0-1%
Relocation compensation	Relocation compensation	***	0-1%

Jiande			
2016 Hangzhou Pollution Source Monitoring Equipment Funds (1st batch and 2nd batch)	To reform thermoelectric coal-fired boilers for environment protection purpose	***	0-1%
2016 Jiande Pollution Source Monitoring Equipment Funds (1st batch)	To reform thermoelectric coal-fired boilers for environment protection purpose	***	0-1%
2015 "115" Introduction Investment Subsidy	To reward company for introducing investment	***	0-1%
Chaoyang			
2016 Zhejiang Province Advanced Industrial New Product (Technology) List - All steel Industrial Radial Tires	To encourage new industrial technology and product	***	0-1%
2016 Hangzhou Subsidy to Online Technology Transaction Achievement Conversion Project (2nd Batch)	To encourage the conversion of technology transaction achievement	***	0-1%
2016 Hangzhou Subsidy to Online Technology Transaction Achievement Conversion Project (2nd Batch)	To encourage the conversion of technology transaction achievement	***	0-1%
2015 Hangzhou Internet of Things and Industrial Internet Pilot Project Funding-All-steel Off-Road Radial Tyre Craft	Support enterprises trial projects on applying internet of things into production and management	***	0-1%
2015 Hangzhou Internet of Things and Industrial Internet Pilot Project Funding	Support enterprises trial projects on applying internet of things into production and management	***	0-1%
2015 RD Investment Funding for Enterprises located in HEDA	For R&D purposes	***	0-1%
2016 Provincial and City Industry and Information Development Financial Special Fund - mixing A area central air-conditionedtechnology renovation	Support enterprises trial projects on applying internet of things into production and management	***	0-1%
2016 Provincial and City Industry and Information Development Financial Special Fund - Chaoyang All-steel Radial Tyre Industrial	Support enterprises trial projects on applying internet of things into production and management	***	0-1%

Design			
2015 Hangzhou Development Zone Graduates Training and Employment Grants	To provide training to graduates	***	0-1%
2016 Hangzhou Pollution Source Monitoring Equipment Funds (1st batch)	To reform thermoelectric coal-fired boilers for environment protection purpose	***	0-1%
2016 Hangzhou Pollution Source Monitoring Equipment Funds (2nd batch)	To reform thermoelectric coal-fired boilers for environment protection purpose	***	0-1%
Grants to “Mayoral Cup”	To encourage intellectual property creation	***	0-1%
2015 Hangzhou Urban Ecological Civilization Demonstration Project Subsidy	To improve urban ecological environment	***	0-1%
Grants for Employment Stabilization of Hangzhou City	The employment stabilization subsidy is provided to the enterprises that takes effective measures to reduce layoffs and keep stable employment.	***	0-1%
Miscellaneous Government subsidies related to assets received in previous years and amortized in this year	Miscellaneous Government subsidies related to assets received in previous years and amortized in this year	***	0-1%
Fuyang			
Relocation Compensation	Relocation Compensation	***	0-1%
Total		***	0-5%

(ii)Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.

172. Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd. (“Wanda Boto”) filed questionnaire response and provided information regarding the grant programs availed by them. Authority has verified the information provided by Wanda Boto and determined subsidy margin for grant programs for which benefit was received or accrued during the POI. Authority determined that all the grant programs resulted in the provision of financial contribution in the form of direct transfer of funds. As a result, benefit was conferred to Wanda Boto as a recipient of this grant. Subsidy programs were also specific because they were specific to certain enterprise including Wanda Boto.

173. The table below provides for the grant programs, and the corresponding subsidy margin:

Name of the grant	Brief	Subsidy margin%	Subsidy margin range
Foreign trade development fund	Special fund for foreign trade development of Dongying City Finance	***	0-5%

	Bureau		
Export Assistance Grant - the grants for participating in overseas exhibitions.	2016 Frankfurt Middle East (Dubai) international auto parts exhibition special fund	***	0-1%
Export Assistance Grant - the grants for participating in overseas exhibitions.	2016 Germany Essen international tire booth subsidy	***	0-1%
Export Assistance Grant - the grants for participating in overseas exhibitions.	Subsidies for Exhibitions	***	0-1%
Talent introduction fund	Funding of Dongying Human Resources and Social Security Bureau	***	0-1%
Foreign trade development fund	Special fund for foreign trade development of Dongying City Finance Bureau	***	0-5%
Research report writing expenditure	Research report writing expenditure	***	0-1%
Development fund	Supporting Subsidies of Shengtuo Town Government	***	0-1%
Service industry development fund	Special funds for service industry development of Kenli County Finance Bureau in 2016	***	0-1%
Export Assistance Grant - the grants for participating in overseas exhibitions.	Subsidies for Exhibitions	***	0-1%
Total		***	0-5%

(iii) Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd.

174. Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd. ("Shandong Yongfeng") filed questionnaire response and provided information regarding the grant programs availed by them. Authority has verified the information provided by Shandong Yongfeng and determined subsidy margin for grant programs for which benefit was received or accrued during the POI. Authority determined that all the grant programs resulted in the provision of financial contribution in the form of direct transfer of funds. As a result, benefit was conferred to Shandong Yongfeng as a recipient to this grant. Subsidy programs were also specific because they were specific to certain enterprises including Shandong Yongfeng.

175. The table below provides for the name of the grant programs, and the corresponding subsidy margin:

Name of the grant program	Brief Description/Comment	Subsidy margin%	Subsidy margin range%
Gas Anti-pollution Special Fund	To reform thermoelectric coal-fired boilers for environment protection purpose	***	0-1%
Provincial Key Self-owned Brand Subsidy	To promote the creation of international self-owned brands in Shandong province	***	0-1%
Self-owned Brand Development Registration Fee	To promote the creation of international self-owned brands in Shandong province	***	0-1%
Import Equipment interest subsidy 2015	To give support for the import of encouraged equipments	***	0-1%
Import Equipment interest subsidy	To give support for the import of encouraged equipments	***	0-1%
Export Reward	To reward enterprises who achieves the goal of export value	***	0-1%
Special Fund for Foreign Trade and Economic Development (import equipment)	To give support for the import of encouraged equipments	***	0-1%
Total		***	0-5%

(iv) Triangle Tyre Co. Ltd.

176. Triangle Tyre Co. Ltd. (“Triangle Tyre”) filed questionnaire response and provided information regarding the grant programs availed by them. Authority has verified the information provided by Triangle Tyre and determined subsidy margin for grant programs for which benefit was received or accrued during the POI. Authority determined that all the grant programs resulted in the provision of financial contribution in the form of direct transfer of funds. As a result, benefit was conferred to Triangle Tyre as a recipient of this grant. Subsidy programs were also specific because they were specific to certain enterprise including Triangle Tyre.

177. The table below provides for the grant programs and the corresponding subsidy margin:

Name of the grant	Brief	Subsidy margin%	Subsidy margin range%
Patent Creation Support Fund	It is a subsidy for patents already obtained by the company before the end of 2015.	***	0-1%
Technology Award	Provided to Entities for Upgradation of Technology	***	0-1%
Patent Creation Support Fund	It is a subsidy for patents already obtained by the company before the end of 2015.	***	0-1%
Industrial Design Award	Provided to Entities for Upgradation of Technology	***	0-1%
export credit insurance premium subsidy	Export credit insurance premium subsidy	***	0-1%
Listing Fee Grant	Granted to Stock Listed Companies	***	0-1%
Patent Support Fund	It is a subsidy for patents already obtained by the company before the end of 2015. This is not a subsidy for new patents. It is a subsidy for patents already obtained by the company before the end of 2015.	***	0-1%
export credit insurance premium subsidy	export credit insurance premium subsidy	***	0-1%
export credit insurance premium subsidy	export credit insurance premium subsidy	***	0-1%
Grant for Bringing in Foreign Intellectuals	Provided against employment of Expert Foreign National to subsidise their salary element	***	0-1%
2016 City Science and Technology Plan "In-house self-repair and anti-puncture" research funding	Provided to Entities for Upgradation of Technology	***	0-1%
Patent Award Fund	Patent Award Fund	***	0-1%
Environmental Monitoring System Monitoring Equipment Operation and Maintenance Subsidy	The government (Environmental Protection Agency) has set up an environmental monitoring equipment in the company, which helps to maintain and incur costs. That part of the cost paid by the government.	***	0-1%

2016 Technology Innovation Enterprise Support Award	Provided to Entities for Upgradation of Technology	***	0-1%
Export Credits in 2016	Export Credits in 2016	***	0-1%
Listed company listed company subsidies for 2016	Granted to Stock Listed Companies (Balance 50%)	***	0-1%
2017 Weihai Patent Creation Funding Fund	It is a subsidy for patents already obtained by the company before the end of 2015...	***	0-1%
2017 Weihai Patent Creation Support Fund	It is a subsidy for patents already obtained by the company before the end of 2015.	***	0-1%
R & D Center Industrial Park infrastructure construction special funds	The factory was originally located in the urban area (where the land price is very high), the new location of the factory relocation is located in the suburbs, and the economy is underdeveloped (where the land price is very low). Government compensation is provided.	***	0-1%
Infrastructure spending	The factory was originally located in the urban area (where the land price is very high), the new location of the factory relocation is located in the suburbs, and the economy is underdeveloped (where the land price is very low). Government compensation is provided.	***	0-1%
Development and Application Projects of Low Temperature Primary Rubber Refining Technology (related To Rubber refining Technology)	Grant for Technological Upgradation	***	0-1%
R & D Center Industrial Park infrastructure construction special funds	The factory was originally located in the urban area (where the land price is very high), the new location of the factory relocation is located in the suburbs, and the economy is underdeveloped (where the land price is very low). Government compensation is provided.	***	0-1%
Funds for land acquisition and relocation compensation expenses	The factory was originally located in the urban area (where the land price is very high), the new location of the factory relocation is located in the suburbs, and the economy is underdeveloped (where the land price is very low). Government compensation is provided	***	0-1%

Industrial Park Phase II construction on the south side of the land base of special funds	The factory was originally located in the urban area (where the land price is very high), the new location of the factory relocation is located in the suburbs, and the economy is underdeveloped (where the land price is very low). Government compensation is provided.	***	0-1%
R & D Center Industrial Park infrastructure construction special funds	The factory was originally located in the urban area (where the land price is very high), the new location of the factory relocation is located in the suburbs, and the economy is underdeveloped (where the land price is very low). Government compensation is provided.	***	0-1%
Construction of industrial park land base of special funds	The factory was originally located in the urban area (where the land price is very high), the new location of the factory relocation is located in the suburbs, and the economy is underdeveloped (where the land price is very low). Government compensation is provided.	***	0-1%
Key technological transformation projects industry loans financial discount funds for Year 2015	Grant for Technological Upgradation	***	0-1%
Infrastructure construction expenditure	The factory was originally located in the urban area (where the land price is very high), the new location of the factory relocation is located in the suburbs, and the economy is underdeveloped (where the land price is very low). Government compensation is provided.	***	0-1%
Development and Application Projects of Low Temperature Primary Rubber Refining Technology (related To Rubber refining Technology)	Grant for Technological Upgradation	***	0-1%
Land acquisition and demolition compensation expenditure funds	The factory was originally located in the urban area (where the land price is very high), the new location of the factory relocation is located in the suburbs, and the economy is underdeveloped (where the land price is very low). Government compensation is provided.	***	0-1%

Special fund for land foundation construction on the south side of the second phase of Industrial Park	The factory was originally located in the urban area (where the land price is very high), the new location of the factory relocation is located in the suburbs, and the economy is underdeveloped (where the land price is very low). Government compensation is provided.	***	0-1%
Industrial Park R&D Center Fundamental Construction Special Fund	The factory was originally located in the urban area (where the land price is very high), the new location of the factory relocation is located in the suburbs, and the economy is underdeveloped (where the land price is very low). Government compensation is provided.	***	0-1%
Industrial Park Land Foundation Special Fund	The factory was originally located in the urban area (where the land price is very high), the new location of the factory relocation is located in the suburbs, and the economy is underdeveloped (where the land price is very low). Government compensation is provided.	***	0-1%
Shandong Province Key Industry Technical Reform Project Loan Financial Discount Interest Fund	Grant for Technological Upgradation	***	0-1%
Nanhai New District Industrial Park Land Special Fund	The factory was originally located in the urban area (where the land price is very high), the new location of the factory relocation is located in the suburbs, and the economy is underdeveloped (where the land price is very low). Government compensation is provided.	***	0-1%
Boiler desulfurization, denitrification and dust removal technology transformation funds	Grant for Technological Upgradation	***	0-1%
Total		***	0-5%

(v) Aeolus Tyre Co. Ltd.

178. Aeolus Tyre Co. Ltd. filed questionnaire response and provided information regarding the grant programs availed by them. Authority has verified the information provided by Aeolus Tyre and determined subsidy margin for grant programs for which benefit was received or accrued during the POI. Authority determined that all the grant programs resulted in the provision of financial contribution in the form of direct transfer of funds. As a result, benefit was conferred to Aeolus Tyre as a recipient of this grant. Subsidy programs were also specific because they were specific to certain enterprise including Aeolus Tyre.

The table below provides for the grant programs and the corresponding subsidy margin

Name of the grant	Brief	Subsidy margin %	Subsidy margin range %
Jiaozuo 2015 Science and Technology Award	To award the Company for its technological achievement	***	0-1%
2017 Special Fund Plan for Environmental Protection - 5# Rubber Mixing Center 1# Gk400 Production Line Odor Management Project	To cover the expense of environmental management projects	***	0-1%
Subsidy for Stabilization of Employment	To stabilize employment of the Company	***	0-1%
Second Batch of Municipal Science and Technology Funds in 2016	To award the Company for its authorization of patent	***	0-1%
2016 Henan Province Science and Technology Reward Funds	To award the Company for its technological achievement	***	0-1%
Subsidy for Processing Trade Project	To subsidize the Company to conduct processing trade	***	0-1%
2016 Annual Subsidy for Export Credit Insurance	To cover expense of export credit insurance	***	0-1%
Jiaozuo City Entrepreneurial Innovation Leading Talent Award	To courage innovation	***	0-1%
2017 Industrial Restructuring and Upgrading Funds	To cover the expense of Industrial Restructuring and Upgrading	***	0-1%
Boiler Low Emission Renovation Funds	To cover the treatment cost for environment protection purpose	***	0-1%
Total		***	0-5%

(vi) Yellow Sea Rubber Co. Ltd.

179. Yellow Sea Rubber Co. Ltd. (“Yellow Sea”) filed questionnaire response and provided information regarding the grant programs availed by them. Authority has verified the information provided by Yellow Sea and determined subsidy margin for grant programs for which benefit was received or accrued during the POI. Authority determined that all the grant programs resulted in the provision of financial contribution in the form of direct transfer of funds. As a result, benefit was conferred to Yellow Sea as a recipient of this grant. Subsidy programs were also specific because they were specific to certain enterprise including Yellow Sea. The table below provides for the grant programs and the corresponding subsidy margin for Yellow Sea:

Name of the grant	Brief	Subsidy margin%	Subsidy margin range%
Postdoctoral Grant	For R&D purposes	***	0-1%
Special Subsidy for High-tech Enterprises of Year 2015	To cover R&D expense	***	0-1%
Subsidy for Export Credit Insurance of Year 2015	Reimbursement of the Export Credit Insurance cost incurred by the company in previous years	***	0-1%
Subsidy for Export Credit Insurance	Reimbursement of the Export Credit Insurance cost incurred by the company in previous years	***	0-1%
Coal-fired boiler air-pollution control funds	To cover the treatment cost	***	0-1%
Total		***	0-5%

I.B. Summary of Grant Programs

180. The Authority has determined the all others rate based on the highest of the subsidy margins for the cooperating parties. In addition, subsidy margin for program nos. 5, 13, 14 and 15 has also been added while determining the all others rate.

Name of the Company	Subsidy Margin for grants%	Range%
Zhongce Rubber Group Co. Ltd.	***	0-5%

Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.	***	0-5%
Triangle Tyre Co. Ltd	***	0-5%
Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd	***	0-5%
Aeolus Tyre Co. Ltd.	***	0-5%
Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd.	***	0-5%
All Others	***	5-15%

II. Programs Identified in the Form of Tax Incentives

(i) Program No. 27: Tax Policies for the Deduction of Research and Development Expenses

a. Submissions by the petitioners

181. Companies which introduce new technologies, products or techniques in their production can decrease corporate income tax by 50%. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents

- i. China State Administration of Taxation (SAT) Guo Shui Fa (2008) No. 116
- ii. Notice of MOF and SAT on policy issues concerning Free Tax Super Deduction of R&D Expenses (Circular 70, 2013)
- iii. Article 3 of Notice of SAT on issuing the Administrative Measures for the Pre tax deductions of Enterprise Research and Development Expenses, 2008
- iv. Corporate Income Tax Law of the PRC (Article 30.1)
- v. Article 95 of the Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC (Decree No. 512 of the State Council of the PRC) and the Guide to Key Fields (Notification No. 6 2007)

b. Submissions by GOC / other interested parties-

182. Neither GOC nor any of the responding exporters have provided any specific comments with regard to the alleged program. However, Zhongce Rubber Group Co, Ltd has admitted that it has availed benefit out of this program.

c. Examination by the Authority:

183. The Authority notes that the program was governed under Article 30.1 of the Corporate Income Tax Law of the PRC and Article 95 of the Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC. Further, the SAT issued Notice on Issuing the Administrative

Measures for the Pre-tax Deduction of Enterprise Research and Development Expenses (for Trial Implementation) (Guo Shui Fa (2008) No. 116) to clarify R&D expense allowed to be deducted on a weighted basis.

184. The above instrument also stipulates that where the R&D expenses actually incurred by an enterprise have not been included in the current loss and profit as intangible assets, 50% of the amount of R&D expenses actually incurred during year shall be deducted from the amount of taxable income in addition to the deduction based on actual expenses. Where any intangible assets are formed, 150% of the costs of the intangible assets shall be amortized before tax payment.

185. The Authority notes that Guo Shui Fa (2008) No. 116 was replaced with Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Issues concerning the Policies for the Weighted Pre-tax Deduction of Research and Development Costs (Cai Shui (2013) No. 70) dated January 1, 2013 and then further replaced with Notice of the Ministry of Finance, the State Administration of Taxation and the Ministry of Science and Technology on Improving the Policies for the Weighted Pre-tax Deduction of Research and Development Expenses (Cai Shui (2015) No. 119) dated January 1, 2016. The same is still in effect.

186. The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past, which establishes its existence. For example, countervailability of this program has been established by the EU authorities in *Organic Coated Steel Products*.

187. Zhongce Rubber Group Co, Ltd, one of the responding exporters from China PR has submitted in its questionnaire response that it availed this subsidy and has provided information with regard to the amount of subsidy during the POI.

188. Program provides for a financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to enterprise which are engaged in research and developmental activities. The fact that Zhongce Rubber benefitted from the program shows that program was in fact used by the tyre producers in China PR that exported the subject product to India during the POI. Therefore, Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(ii) Programs No. 28 and 29: Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs & Tax Offsets for Research and Development by FIEs

189. Legal basis of alleged financial contribution and benefit for programs 28 and 29 is the same. These two programs have been examined together.

a. Submissions by the petitioners

190. GOC maintains preferential tax policies for research and development. Specifically, when research and development expenses increase by more than ten percent from the previous year, the producing companies are allowed to offset such expenses by 50 percent from the taxable income of that year. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents.

- i. Guo Shui Han (2001) No. 405
- ii. SAT Circular Guo Shui Fa No. 173 of 1999

191. Petitioners allege that producers such as Zhaoyan Liao Rubber Products Co., Ltd., Haoyou Tyre Co., Ltd., Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd. Giti Radial Tire (Anhui) Co., Ltd., Michelin (Shenyang) Tyre Co., Ltd., Xiamen Zhengxin Rubber Industry Co., Ltd., Kenda Rubber (China) Co., Ltd. might have availed benefit from these programs.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

192. It was submitted by the GOC that both programs were terminated way back on January 4, 2011 and there was no replacement and grace period granted for this program. Thus, there is no continuing existence of a benefit. So no PUC producers / exporters could apply for or receive benefits under this program during the POI.

c. Examination by the Authority:

193. The Authority notes that the alleged programs were governed by:

- i. "Circular on the Issues Related with the Offset Taxable Income on Technology Development Fee of Foreign Investment Enterprises" (Guo Shui Fa No. 173 of 1999) dated 19 September 1999 and
- ii. Supplementary Circular (Guo Shui Han (2001) No. 405) dated June 8, 2001.

However, both regulations were abolished by Announcement No. 2 [2011] of the State Administration of Taxation dated January 4, 2011.

194. In view of the above, the Authority holds that these programs were no longer in force and tyre producers in China PR who exported the subject product to India during POI could not have received benefits under these two programs.

195. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be determined against these programs.

(iii) Program No. 30: Income tax credit for the purchase of domestically Produced & manufactured production equipment

(iv) Program No. 34: Income Tax credits for domestically owned Companies Purchasing Chinese made Equipment

196. The above mentioned programs allegedly provide tax exemption/reduction/remission to enterprises for the purchase of domestically produced and manufactured production equipment as per the income tax law of China PR. Therefore, both these programs have been examined together.

a. Submissions by the petitioners

197. It is the submission of the Petitioners that the GOC provides a tax credit of up to 40% of the purchase price of domestic equipment which may be considered as a tax saving for eligible enterprises. As evidence of existence of the programs, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents.

- i. Provisional measures on enterprise income tax credit for investment in domestically produced equipment for technology renovation projects of 1 July 1999
- ii. Notice of the State Administration of Taxation on Stopping the Implementation of the Equipment Income Tax Deduction and Exemption Policy of the Investment of an Enterprise in Purchasing Home-made Equipment, No. 52 [2008] of the Statement Administration of Taxation, effective 1 January 2008
- iii. Article 28 of the PRC Law on Enterprise Income Tax (No 63 promulgated on 16 March 2007) along with the Administrative Measures for the Determination of High and New Technology Enterprises
- iv. Circular of the State Council on the issues concerning carrying out the transitional preferential policies on enterprise income tax, Guo Fa (2007) No. 39
- v. Circular of the state administration of taxation on the issues concerning implementation of preferential income tax for Hi-tech enterprises, Guo Shui Han (2009) No. 203
- vi. Circular of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Enterprise Income Tax Credits for Purchase of Domestic Equipment by Foreign Invested Enterprises and Foreign Enterprises (Cai Shui Zi (2000) No.49)
- vii. Administrative Measures on Enterprise Income Tax Credits for Purchase of Domestic Equipment by FIEs and Foreign Enterprises (Guo Shui Fa (2000) No.90)
- viii. The Circular of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation of the People's Republic of China on Distribution of Interim Measures Concerning the Reduction and Exemption of Enterprise Income Tax for Technological Renovation (Cai Shui Zi (1999) No.209)

198. Petitioners mention that producers such as Zhaoyan Liao Rubber Products Co., Ltd., Haoyou Tyre Co., Ltd., Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd. Giti Radial Tire (Anhui) Co., Ltd., Michelin (Shenyang) Tyre Co., Ltd., Xiamen Zhengxin Rubber Industry Co., Ltd., Kenda Rubber (China) Co., Ltd. might have availed the benefit out of these programs.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

199. Article 28 of the PRC Law on Enterprise Income Tax (No 63 promulgated on 16 March 2007), Administrative Measures for the Determination of High and New Technology Enterprises and Circular of the state administration of taxation on the issues concerning implementation of preferential income tax for Hi-tech enterprises, Guo Shui Han (2009) No. 203 were not relevant to abovementioned programs, but instead related to high technology enterprises.

200. Both programs were terminated long back on May 16, 2008. There was no replacement or grace period granted. Thus, there is no continuing existence of a benefit. Hence, none of the producers / exporters could have applied for or received benefits under this program during the POI.

c. Examination by the Authority:

201. The Authority notes that the said programs were introduced in 1999 through “Provisional Measures on Enterprise Income Tax Credit for Investment in Domestically Produced Equipment for Technology Renovation Projects” (Cai Shui Zi (1999) No. 290).

202. On 14 January 2000, the GOC issued the Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation concerning the Issue of Tax Credit for Enterprise Income Tax for Domestic Equipment Purchased by Foreign-funded Enterprises (Cai Shui Zi (2000) No.49), which allowed FIEs falling under the Encouraged Category and Restricted B Category listed in the Directive Category of the Industries of Foreign-funded Enterprises to deduct 40 percent of the investment for the domestic equipment purchases from the increased part of their enterprise income taxes of the purchasing year over those of the year before.

203. However, both regulations were abolished through Decision of the Ministry of Finance on Announcement of the List of Abolished and Invalidated Finance Provisions and Regulatory Documents (11th Set) dated 21 February 2011.

204. The Authority also notes that the State Administration of Taxation also issued Notice of the State Administration of Taxation on Prohibiting and Distributing the Measures Concerning Industrial Income Tax Credit on the Investment of Foreign-funded Enterprises and Foreign Enterprises by Way of Purchasing Home Products (Guo Shui Fa (2000) No. 90). But the regulation was also abolished through Announcement No. 2 [2011] of the State Administration of Taxation dated January 4, 2011.

205. Regarding Notice of the State Administration of Taxation on Stopping the Implementation of the Enterprise Income Tax Deduction and Exemption Policy of the Investments of an Enterprise in Purchasing Home-made Equipment, No. 52 [2008] of the State Administration of Taxation, it was clearly mentioned that commencing from 1 January 2008, the implementation of the policy of offsetting the enterprise income tax by purchasing domestically manufactured equipment would be terminated. Therefore, both programs were terminated after implementing new Enterprise Income Tax Law of the PRC.

206. The Circular of the state council on the issues carrying out the transitional preferential policies on enterprise income tax, Guo Fa (2007) No.39 provides for transitional period under the old law but no relation could be found with Programs 30 & 34.

207. The Authority also examined Article 28 of the PRC Law on Enterprise Income Tax (No 63 promulgated on 16 March 2007) and the Administrative Measures for the Determination of High and New Technology Enterprises and Circular of the state administration of taxation on the issues concerning implementation of preferential income tax for Hi-tech enterprises (Guo Shui Han (2009) No. 203) but found that these regulations pertain to Program 31 and not Programs 30 and 34.

208. In view of the above, the Authority notes that while some of the instruments were not relevant to the aforementioned programs, other instruments were no longer in force. Thus, no tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI received benefit under these programs during the POI.

209. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against these programs.

(v) Program No. 31: Preferential Tax Policies / Income Tax Reductions for Companies that are Recognized as High and New Technology Companies

a. Submissions by the petitioners

210. Enterprises applying for a certificate of high and new technology enterprise are eligible for a benefit of a reduced income tax rate of 15% as compared to the ordinarily applicable rate of 25%. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them:

- i. Article 28 of the Corporate Income Tax Law of the PRC (No. 63 promulgated on 16 March 2007)
- ii. Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC (Decree No. 512 of the State Council of the PRC)
- iii. Administrative Measures for the Determination of High and New Technology Enterprises
- iv. Notice of the State Administration of Taxation on the issues concerning Enterprises Income Tax Payment of High and New Technology Enterprises (Guo Shui Han (2008) No. 985)
- v. Circular Guo Shui Fa No. 135 of 2003
- vi. Circular Cai Shui (2014) No. 59 & Cai Shui (2010) No. 65
- vii. SAT circular Guo Shui Fa No. 139 of 1995

b. Submissions by GOC / other interested parties-

211. Neither GOC nor any of the responding exporters have provided any specific comments with regard to the alleged program. However, Aeolus Tyre Co, Ltd and Triangle Tyre Co, Ltd have stated that they have received subsidy under this program and the same has been disclosed in their Questionnaire Response.

c. Examination by the Authority:

212. The program was governed under Article 28 of the Corporate Income Tax Law of the PRC and Article 93 of the Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC. Further, the Ministry of Science and Technology, Ministry of Finance, and SAT jointly issued Administrative Measures for the Determination of High and New Technology Enterprises (Guo Ke Fa Huo [2008] No. 172) as well as Circular of the Ministry of Science and Technology, Ministry of Finance and State Administration of Taxation on Printing and Issuing of the Guidelines for the Administration of the Recognition of Hi-tech Enterprises (Guo Ke Fa Huo [2008] No. 362) to clarify the identification of high and new technology enterprises. The SAT issued Circular on the Issues Concerning Implementation of the Preferential Income Tax for Hi-Tech Enterprises (Guo Shui Han (2009) No. 203), which was in force till now.

213. However, Guo Ke Fa Huo (2008) No. 172 and Guo Ke Fa Huo (2008) No. 362 were replaced by Notice of the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Finance and the SAT on Revising and Issuing the Measures for the Administration of the Certification of High-tech Enterprises (2016) (Guo Ke Fa Huo (2016) No. 32) and Notice of the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Finance, and the SAT on Revising and Issuing the Guidelines for the Administration of the Certification of High-Tech Enterprises (2016) (Guo Ke Fa Huo (2016) No. 195. The SAT issued Announcement on Issues concerning the Implementation of the Preferential Income Tax Policies regarding High-Tech Enterprises (Announcement No. 24 [2017] of the State Administration of Taxation).

214. The Authority also noticed that Notice of the SAT on the issues concerning Enterprises Income Tax Payment of High and New Technology Enterprises (Guo Shui Han (2008) No. 985) was

just related to the financial year of 2008 and it was repealed by Announcement on Issuing the Catalogue of Tax Regulatory Documents to be Invalidated and Entirely or Partially Repealed (Announcement No. 34 [2016] of the State Administration of Taxation) dated May 29, 2016.

215. In addition, Cai Shui (2010) No. 65 and Cai Shui (2014) No. 59 were related to advanced technology service enterprises. Guo Shui Fa No. 135 of 2003 and Guo Shui Fa No. 139 of 1995 were repealed by Announcement No. 2 [2011] of the SAT.

216. The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established. For example, (a) by the EU authorities in *organic coated steel products* as well as *coated fine paper*.

217. Aeolus Tyre Co, Ltd and Triangle Tyre Co, Ltd, two of the responding exporters from China PR who have submitted questionnaire response and have stated that they availed this benefit and have provided information with regard to the amount of subsidy received by them during the POI.

218. Program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. Program is also specific because it is limited to certain enterprises. The fact that Aeolus Tyre Co. Ltd. and Triangle Tyre Co. Ltd., benefited from the program shows that program was in fact used by the tyre producers in China PR that exported the subject product to India during the POI. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(vi) Program No. 32: Income Tax Concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilization (special raw materials)

a. Submissions by the petitioners

219. The Petitioners submitted that under the program, companies that use materials and manufacturing products listed in the *Catalogue of Income Tax Concessions for Enterprises engaged in Comprehensive Resource Utilization* are eligible for a 10% exemption on income tax for 5 years. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Article 33 of the PRC Law on Enterprise Income Tax, Order 63, 2007
- ii. Article 99 of Regulations on Implementation of the PRC Law on Enterprises Income Tax by the State Council, Order 115, 2008
- iii. Catalogue of Income Tax Concession for Enterprises engaged in Comprehensive Resource Utilization (Cai Shui (2008) No. 117)
- iv. EU-Certain organic steel products – 2013
- v. EU-Coated fine paper, 2011

b. Submissions by GOC / other interested parties-

220. The GOC stated that the program name determined by the petitioners was wrong, and the inclusion of the phrase "special raw materials" was erroneous. Besides, the program was not relevant to tyre industry.

c. Examination by the Authority:

221. The Authority notes that the program was governed under the EITL and Article 99 of Order 115, 2008 also stipulated that an enterprise that uses any of the materials as listed in the Catalogue of Resources for Comprehensive Utilization by Enterprises Entitled to Preferential Income Tax Treatment as its major raw materials, the income obtained from producing products which are not restricted or prohibited by the state and which meet the relevant standards of the state or the industry concerned shall be eligible for a 10% exemption from taxability.

222. The Authority also notes that only using junked tyre to make retread tyre was listed in the catalogue. Therefore, it is not relevant to the production of subject goods. Also, none of the responding producers/exporters have benefited from the program. Petitioner has not provided any evidence to show that any tyre producers in China PR who exported the subject product to India received benefit under the program. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(vii) Program No. 33: Tax Credit Concerning the Purchase of Special Equipment**a. Submissions by the petitioners**

223. An offset of 10% is granted on purchase cost of special equipment used for environmental protection, energy and water saving and production safety against the corporate income tax payable in the year of purchase, which can be carried forward for 5 years.

As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents

- i. Enterprise Income Tax Law of the PRC, Order of the President of the People's Republic of China No. 63
- ii. Article 100 of the Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC (Decree No. 512 of the State Council of the PRC)

b. Submissions by GOC / other interested parties-

224. Neither GOC nor any of the responding exporters have provided any specific comments with regard to the alleged program. However, Shandong Yongfeng Tire Co, Ltd has accepted that it has availed benefit out of this program.

c. Examination by the Authority:

225. The Authority notes that the program was governed under Article 34 of the Enterprise Income Tax Law of the PRC and Article 100 of the Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC. Further, the Ministry of Finance, the State Administration of Taxation, the National Development and Reform Commission and Other Departments issued the Catalogues of the Special Equipment for Energy and Water Conservation and Environmental Protection Eligible for Enterprise Income Tax Preferences (Cai Shui (2008) No. 115), which was replaced by 2017 Version (Cai Shui (2017) No. 71).

226. The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established. For example, by the EU authorities in *organic coated steel products*.

227. Shandong Yongfeng Tire Co. Ltd, one of the responding exporters from China PR who has submitted questionnaire response has stated that it availed this benefit and has provided information with regard to the amount of subsidy received by the company during the POI.

228. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred on the recipient. The program is also specific because it is limited to certain enterprises that purchases special equipment. The fact that Shandong Yongfeng benefited from the program shows that program was in fact used by the tyre producers in China PR that exported the subject product to India during the POI. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against this program.

(vii) Program No. 35: Tariff and VAT exemptions for imported technologies and equipment

a. Submissions by the petitioners

229. If an FIE falls in the 'encouraged' or 'restricted' categories in the Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment (2004) or the Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment (2007), it is eligible for the exemption from tariff and import VAT for equipment. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them:

- i. Article 1 and 2 of the Notice of the State Council Concerning the Adjustment of Taxation Policies for Imported Equipment (Guo Fa (1997) No. 37)
- ii. Announcement of the Ministry of Finance, the General Administration of Customs and the State Administration of Taxation (2008) No. 43
- iii. Notice of the NDRC on the relevant issues concerning the handling of confirmation letter on domestic or foreign-funded projects encouraged to develop by the State, No. 316 2006 of 22 February 2006
- iv. Catalogue on Non-duty-exemptible Articles of importation for either FIEs or domestic enterprises 2008
- v. Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment
- vi. Catalogue of Industry, Product and Technology Key Supported by the State at Present (2004)
- vii. State Council's Import Goods Not Exempted from Taxation for Foreign Investment Projects Catalogue
- viii. Import Goods Not Exempted from Taxation for Domestic Investment Projects Catalogue

230. The petitioners have further alleged that major tyre producers in China PR who might have benefited under this scheme are entities such as Zhaoyuan Liao Rubber Products Co., Ltd, Haoyou

Tyre Co., Ltd, Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd, Giti Radial Tyre (Anhui) Co., Ltd, Michelin (Shenyang) Tyre Co., Ltd, Xiamen Zhengxin Rubber Industry Co., Ltd, Kenda Rubber (China) Co., Ltd.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

231. This program was terminated way back on February 22, 2008 and there was no replacement and grace period granted for this program. Thus, there is no continuing existence of a benefit. So, no PUC producers / exporters could apply for or receive benefits under this program during the POI.

c. Examination by the Authority-

232. The Authority noted that the petitioner provided (i) Cai Shui (2007) No. 75, (ii) Cai Shui (2008) No. 170 (iii) Cai Shui (2014) No. 36, (iv) Cai Shui (2014) No. 38, (v) Cai Shui (2014) No.37, (vi) Cai Quan Shui (2014) No. 24, (v) Fa Gai Ban Wai Zi (2014) No. 1329, (vi) Fa Gai Ban Wai Zi (2014) No.1454, (vii) Fa Gai Ban Wai Zi (2014) No. 1386, (viii) PBOC Order (2014) No. 2, (ix) the State Council (1993) No. 134, (x) Cai Fa (1993) No.38, (xi) Guo Shui Fa (2000) No.84. However, these 11 legal texts were not related to the program at all.

233. The Authority notes that Program 35 was actually governed under Circular of the State Council on Adjustment of Imported Equipment Taxation Policies (Guo Fa (1997) No. 37). The General Administration of Customs further issued Notice of the General Administration of Customs on Import Taxation Policies Related to Further Encouraging Foreign Investment (Shui Shui (1999) No. 791) to clarify which articles imported by FIEs were exempted from VAT and Customs duties.

234. Meanwhile, Guo Fa (1997) No. 37 also clarifies that, equipment:

- a. imported for own use within the total amount of investment of foreign investment projects which involve technology transfer and
- b. which are in the encouraged category or Group B of the restricted category of the Industrial Guidance Catalogue for Foreign Investment and
- c. such equipment is not among commodities listed in the Catalogue of Imported Commodities not Entitled for Tariff Exemption for Projects with Foreign Investment.

shall enjoy exemption from tariff and import-stage value- added tax, provided that

"High performance radial tyre" was listed in the encourage category of Catalogue for Guiding Industry Restructuring (2011 Version) (2013 Amendment).

235. The Authority notes that this program has been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established. For example, by the EU authorities in *solar glass, organic coated steel products and coated fine paper*.

236. Program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. Program is also specific because it is limited to foreign invested enterprise. None of the participating tyre producers has received benefit under this program during the POI. Petitioner has not provided any evidence to show that tyre producers in China PR who exported the subject

product to India during the POI benefited from this program. During the course of investigation, the Authority could also not identify evidence to support that tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI benefited from this program.

237. Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(viii) Program No. 36 VAT refunds for domestic firms on purchases of Chinese made equipment

(ix) Program No. 41: Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises Which Have Establishments in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipments

238. Programs No. 36 & 41, allege same VAT benefits to enterprises for the purchase of domestically produced & manufactured production equipment. Therefore, these programs have been examined together.

a. Submissions by the petitioners

239. VAT is refunded on the purchase of domestic equipment for the enterprises, including FIEs. As evidence of existence of the programs, petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Article 3 & 27 of the “Interim Regulations of the People’s Republic of China on Value-Added Tax” (Decree (1993) No. 134 of State Council)
- ii. “Directive Category of Foreign Funded Industries stipulated in the Circular of the State Council concerning the Adjustment of the Taxation Policies of Imported Equipments”
- iii. Circular of State Administrating of Taxation Concerning Transmitting the Interim Measures for Administration of Tax Refund to Enterprise with FIEs. (Guo Shui Fa (1997) No. 171, September 20, 1999)
- iv. Circular of State Council on Adjustment of Tax Policies of Imported Equipment (Guo Fa (1997) No. 37)
- v. Catalogue of major industries, products and technologies encouraged for development in China (1998)
- vi. EU-Coated Fine Paper
- vii. EU-Organic Coated Steel Products
- viii. Notice regarding the adjustment of import-level tax policies related to key technological equipment and machinery (Cai Guan Shui (2014) No.2)

240. Tyre producers such as Zhaoyan Liao Rubber Products Co., Ltd., Haoyou Tyre Co., Ltd., Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd. Giti Radial Tire (Anhui) Co., Ltd., Michelin (Shenyang) Tyre Co., Ltd., Xiamen Zhengxin Rubber Industry Co., Ltd., Kenda Rubber (China) Co., Ltd. might have availed the benefit out of these programs.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

241. Articles 3 & 27 of the “Interim Regulations of the People’s Republic of China on Value-Added Tax” (Decree (1993) No. 134 of State Council) is invalid as it was replaced with “Interim Regulations of the People’s Republic of China on Value-Added Tax” (2008 Revision).

242. Further, the CVD findings of the European Commission in *EU-Coated Fine Paper* and *EU-Organic Coated Steel* do not form the legal basis.

243. Circular of State Council on Adjustment of Tax Policies of Imported Equipment (Guo Fa (1997) No. 37) and Notice regarding the adjustment of import-level tax policies related to key technological equipment and machinery (Cai Guan Shui (2014) No.2) are the regulations related to Program 35 but not Program 36 or Program 41.

c. Examination by the Authority:

244. The Authority notes that:

i. The said programs were mainly governed under Notice of the State Administration of Taxation concerning the Proposed Management Methods for Tax Refund (Guo Shui Fa (1997) No. 171).

ii. On May 10, 2006, the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation jointly issued Notice on Adjusting the Scope of Tax Refund Policies for the Purchase of Home-made Equipment for Foreign-funded Projects (Cai Shui (2006) No.61).

iii. The State Administration of Taxation and the NDRC also jointly issued the “Trial Implementation Measures on Tax Refunded Administration for the Purchase of Home-made Equipment for Foreign-funded Projects” (Guo Shui Fa (2006) No.111) on July 1, 2006.

245. However, all above regulations were abolished under the Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Stopping the Implementation of the Policy of Refunding Tax to Foreign-funded Enterprises for Their Purchase of Home-made Equipment (Cai Shui (2008) No. 176). As per this instrument, it is clearly mentioned that from January 1, 2009, the policy that refunds VAT to foreign-funded enterprises that purchase home-made equipment within the total amount of investment shall not be implemented any more.

246. Authority also notes that “Directive Category of Foreign Funded Industries stipulated in the Circular of the State Council concerning the Adjustment of the Taxation Policies of Imported Equipments” and “Catalogue of Major Industries, Products and Technologies Encouraged for Development in China” have no direct link with the said programs.

247. In view of the above, Authority notes that while some of the instruments were not relevant to the aforementioned program, the other instruments were no longer in force. No tyre producer in China PR who exported the subject product to India during the POI could have benefitted from the program.

248. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against these programs.

(x) Program No. 37: VAT Exemptions and Deductions for Central Regions

a. Submissions by the petitioners

249. The petitioners stated that under above program, VAT payers located in 26 cities of the old industrial bases of the central region, that make investments in certain fixed assets can deduct the

amount of VAT paid on the fixed assets from its total VAT liability. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents.

- i. SAT-Provisional Regulation on VAT of China PR-Order No.134 (1993)
- ii. SAT-Rules for implementation of provisional Regulation on VAT of China PR -order No. 38 (1993)
- iii. SAT-Measures for pre-Tax Deductions from China PR-Guo Shui Fa (2000)-Order -No.84
- iv. Interim Measures for expanding the scope of offset for VAT in central region No. 75 (2007)
- v. Notice of the Ministry of Finance and the SAT on several issues concerning the National implementation of VAT tax reforms No. 170 (2008) of the Ministry of Finance
- vi. Notice regarding issues related to the simplification and unification of Value-Added Tax (VAT) collection rates (SAT Announcement [2014] No. 36)
- vii. Web Research – China Business Hand Book
- viii. Web Research – Investment in China PR
- ix. Web Research – China's VAT experience – By Xu Yan

However, the petitioners also pointed out that this program was only eligible to producers who were situated in certain designated areas. It has been claimed that producers such as Kenda Rubber (China) Co., Ltd, Giti Radial Tyre (Anhui) Co., Ltd and Xiamen Zhengxin Rubber Industry Co., Ltd. might have availed the benefit out of these programs.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

250. No legal text was provided by the petitioner of the notification noted in the petition. Web research and case findings are not the legal basis under the Article 11.2 of the SCM. In order to co-operate fully, the GOC has provided the legal text and also the termination notification.

c. Examination by the Authority:

251. Based on the information provided by the GOC, the Authority could identify relevant regulations. The said program was governed under Interim Measures for expanding the scope of offset for VAT in central region (Cai Shui (2007) No. 75). However, the regulation was terminated under Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Several Issues concerning the National Implementation of Value-added Tax Reform (Cai Shui [2008] No. 170). However, Cai Shui (2008) No. 170 was still in force and VAT rate was simplified under Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on the Policy of Streamlining and Combination of Value-Added Tax Levy Rates (Cai Shui (2014) No. 57). Both regulations are just general provisions of VAT in China PR. And there is no relation with Program 37.

252. The Authority notes that Interim Regulations of the People's Republic of China on Value-added Tax (No. 134 of the State Council), was revised in 2008, 2016 and 2017. Detailed Rules for the Implementation of the Interim Regulations of the People's Republic of China on Value-Added Tax dated December 25, 1993, were revised in 2008 and 2011 as well. However, both regulations are just general provisions of VAT in China PR and there is no relation with Program 37.

253. The instrument Measures for Pre-tax Deductions from Income Tax for Enterprises (Guo Shui Fa (2000) No.84) was related to the deduction of Enterprise Income Tax and the same was

terminated by Catalogue of Currently Effective, Invalidated and Repealed Rules of Taxation Departments dated November 29, 2010.

254. The instrument Notice regarding issues related to the simplification and unification of Value-Added Tax (VAT) collection rates (SAT Announcement [2014] No. 36) was the clarification of VAT to be collected by simplified method. This instrument was not relevant to program 37.

255. In view of the above, the Authority notes that while some of the instruments were not relevant to the aforementioned program, the other instruments were no longer in force. No tyre producer in China PR who exported the subject product could have received benefit under this alleged program. The Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program alleged in the petition.

(xi) Program No. 38: Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to operate for a period not Less Than 10 Years

(xii) Program No. 39: Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises

(xiii) Program No. 40: Preferential Tax Policies for FIEs which are Technology Intensive and Knowledge Intensive

(xiv) Program No. 42: Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors

(xv) Program No. 44: Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area)

(xvi) Program No. 45: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones

(xvii) Program No. 46: Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas

(xviii) Program No. 47: Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas

256. Petitioners have alleged existence of series of tax programs, which provide income tax exemption/reduction/remission to certain categories of enterprises based on their location or nature of the enterprises or technological innovation. It is noted that the Program Nos. 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46 & 47, as listed above alleges existence of similar income tax benefits to FIEs enterprises. Therefore, all these programs have been examined together.

a. Submissions by the petitioners

257. Program No. 38 is administered by MOF, MOFCOM, SAT and its local tax bureaus. From the year an FIE makes profits, it enjoys full income tax exemption for first two years and 50% exemption in the next three years. To be eligible, the enterprise must be an FIE which is product oriented, with an anticipated operation of at least 10 years and that has had a financial year in which it made a profit.

258. Under Program 39, export-oriented enterprises invested in and operated by foreign businesses for which in any year the output value of all export products amounts to 70% or more than for that

particular year may pay half or fifteen per cent that qualify under the above-mentioned conditions or shall pay enterprise income tax at the tax rate of 10%.

259. Under Program 40, FIEs that qualify as technology-intensive or knowledge-intensive and have major products listed in the Catalogue of High and New Technology Products of China are eligible for the said program.

260. Under Program 42, FIEs are entitled to receive a 40% (if profits are re-invested) or 100% (if profits are re-invested in an export-oriented or technologically advanced enterprise) refund on the income tax that was paid on the re-invested amounts.

261. Under Program 44, the foreign invested productive enterprises established in Pudong area (Shanghai) are subject to income tax at the reduced rate of 15 percent.

262. Under Program 45, FIEs located in economic and technological development zones or coastal economic open areas are eligible to a reduced income tax rate of 15% or 24% based on location.

263. Under Program 46, both domestic enterprises and FIEs are eligible to income tax at lower rates of 15% or 24% or an exemption of 3% under "Regulations on Special Economic Zones in Guangdong Province" and "Provisions of the State Council Concerning the Encouragement of Investment in Developing Hainan Island".

264. Under Program 47, FIEs that are established in the Economic and Technological Development Zones are subject to the reduced corporate income tax rate of 15%.

265. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents

Program 39- Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises

- i. Income Tax Law of the People's Republic of China for Enterprises with foreign Investment and Foreign Enterprises
- ii. Rules for the implementation of the Income Tax Law of the People's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises
- iii. Circular of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Enterprise income Tax Preferential Policies- Cai Shui [2009] No.69
- iv. Circular 115-Oct 2009
- v. SAT Circular Guo Shui Fa No. 139 of 1995
- vi. SAT Circular Guo Shui Fa No. 1 of 2003
- vii. Circular Cai Shui (2014) No.59 & 65

Program 40- Preferential Tax Policies for FIEs which are Technology intensive and Knowledge intensive

- viii. Notification of the State Council on carrying out the transitional preferential policies concerning Enterprise Income Tax (Guo Fa 2007 No. 39)

- ix. Notice of the State Administration of Taxation on Issues regarding pre tax deduction from enterprise Income Tax on interests expenditure for enterprise borrowing money from natural person. (Letter No. 777, 2009)
- x. Article 73 of. the Implementation Rules of the Income Tax Law of the People's Republic of China of Foreign Investment Enterprises
- xi. Catalogue of High and New Technology Products of China promulgated by the Ministry of Science and Technology ("MOST")

Program 42- Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors

- xii. Article 10 of the Foreign Invested Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax law 1991 (the FIE income Tax Law)
- xiii. Article 80 of Implementing Rules of the Foreign Investment Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax Law (the FIE Tax Regulations).
- xiv. Circular of the State Administration. of Taxation on Some Issues Concerning Tax Re-imbursment for Re-investment Made by Foreign Investors of Enterprise with Foreign Investment (Guo Shui Fa [1993] No 9) Cai Shui [2009] No. 69
- xv. Catalogue-Circular of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Enterprise Income Tax Preferential Policies-2015

Program 44- Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investments (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area)

- xvi. Decree [1991] No. 85 of the State Council [30 June 1991]
- xvii. Order [1991] No. 45 of the President of the People's Republic of China [9 April-91]
- xviii. State Council Circular Guo Fa No. 37 of 2000
- xix. Notification of the State Council on Carrying out theTransition Preferential Policies Concerning Enterprise Income Tax, Guo Fa No. 39 of 2007
- xx. Article 19 of Tax Law of the People's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises 1991
- xxi. Article 4, 28 and 36 of Enterprises Income Tax Caw of the People's Republic of China 2008;
- xxii. Article 91 of Regulations of People's Republic of China on the Implementation of the Enterprise Income Tax, 2008

Program 45- Preferential Tax Policies for (FIEs) Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones

- xxiii. Income Tax Law of the People's Republic of China forEnterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises (the Tax Law);
- xxiv. Enterprises Income Tax Law 2008
- xxv. Rules for the Implementation of the Income Tax Law of the People 's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprise

Program 46- Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas-

- xxvi. Article 81 of Decree 85, 1991
- xxvii. Income Tax Law of the People's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises (the Tax Law)
- xxviii. Article 5, Regulation on the Implementation of the Income Tax Law of the People's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprise
- xxix. Regulations on Special Economic Zones in Guangdong Province
- xxx. Provisions of the State Council Concerning the Encouragement of Investment in Developing Hainan Island

Program 47- Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas-

- xxxi. Article 28.2 of the Enterprises Income Tax Law of the People's Republic of China, 2008
- xxxii. Article 93 of Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the People's Republic of China by the State Council
- xxxiii. Ministry of Finance, State Administration of Taxation, the State Development and Reform Commission on Comprehensive Utilization of Resources announced the Corporate Income Tax Catalogue (2008 edition) Notice (Cai Shui [2008] No. 116) and (Cai Shui [2008] No. 117) (2008).
- xxxiv. Income Tax Law of the People's Republic of China for Enterprises, with Foreign Investment and Foreign Enterprises (the Tax Law);
- xxxv. State Council Issue Circular Guofa (2014) No. 14-(2014)
- xxxvi. State Council Notice 40-Article 57 of Corporate Income Tax
- xxxvii. Decree No-63 of Chairman of China PR -2007
- xxxviii. Decree No-516 State Council of China PR-2007
- xxxix. State Council Issue Circular Guofa (2014) No.14-(2014)

b. Submissions by GOC / other interested parties-

- 266. The instruments - G/SCM/N/235/CAN-2012, US-Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod, US-Initiation Check List in Sodium Nitrate China PR and G/SCM/N/123/CHn-2006 did not form the legal basis.
- 267. Secondly, the GOC introduced tax reform that took place in China PR in 2008. Before 2008, China PR law provided a lot of preferential tax policies applicable to FIEs.
- 268. On 16th March 2007, the GOC issued Enterprise Income Tax Law ("EITL") of the PRC, which is applicable to all enterprises in China PR including the FIEs. This law was implemented with effect from 1 January 2008.
- 269. There were two major changes in the new tax law: (1) preferential income tax policies for FIEs were terminated, and a unified tax rate was applicable for domestic enterprises and FIEs; (2) preferential income tax policies for local special economic zones have been terminated. Further, the State Council issued notice on the Implementation of the Transitional Preferential Policies in respect of Enterprise Income Tax, stipulating that as of 1 January, 2008, enterprises that previously enjoyed

the preferential policies of low tax rates shall be gradually transited to become subject to enjoy the statutory tax rate within 5 years after implementation of the EITL. Therefore, even enterprises which enjoyed preferential tax policies under the previous income tax law would no longer enjoy the same from the end of 2012.

c.Examination by the Authority:

270. The Authority notes that President Order No. 45, dated 9 April 1991 was terminated under Enterprise Income Tax Law of the People's Republic of China (President Order No. 63, dated 16 March, 2007) since 1 January 2008. The Authority also notes State Council Order No.85, dated 30 June, 1991 was terminated under Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the People's Republic of China by the State Council (State Council Order No. 512).

271. Meanwhile, the State Council also issued “Notice of the State Council on the Implementation of the Transitional Preferential Policies in respect of Enterprise Income Tax (Guo Fa (2007) No. 39” which provides a grace period to enterprises enjoying the preferential policies in respect of enterprise income tax under the former tax law, administrative regulations and documents. Program 47 (Sr.1), 45 (Sr.2 &14), 40 (Sr.3), 44 (Sr.5), 46 (Sr. 11 & 13), 38 (Sr.19) were listed in the table for implementation of transitional preferential policy on enterprise income tax.

272. The Circular of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Enterprise Income Tax Preferential Policies (Cai Shui (2009) No. 69) further clarifies several issues related to Guo Fa (2007) No. 39. However, no issue was related to mentioned programs.

273. Guo Shui Fa (1995) No. 139 was replaced with Circular of the State Administration of Taxation concerning the Tax Preferential Policy Applicable to Enterprises with Foreign Investment with Regard to Technology-Intensive and Knowledge-Intensive Projects (Guo Shui Fa (2003) No. 135) dated November 7, 2003. This in turn was repealed by Announcement No. 2 [2011] of the State Administration of Taxation.

274. Similarly, Guo Shui Fa (1993) No. 9 and Guo Fa (2000) No. 37 implemented provisions of President Order No. 45 and the State Council Order No.85. However, since President Order No. 45 and State Council Order No.85 were terminated on 1 January 2008, Guo Shui Fa (1993) No.9 and Guo Fa (2000) No. 37 stood invalidated.

275. In its examination, the Authority found that Cai Shui (2010) No. 65 and Cai Shui (2014) No. 59 did not relate to the aforementioned programs.

276. The Authority also noted that the petitioner did not provide legal text of legal basis Circular 115 – Oct 2009. Therefore, the Authority is not in a position to make the determination regarding this instrument.

277. Authority also notes that before 2008, China PR implemented Provisional Regulations of the People's Republic of China on Enterprises Income Tax, which was applicable to all enterprises other than foreign invested enterprises (“FIEs”) within China PR. China PR separately implemented Income Tax Law of the PRC for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises, in which there were lot of preferential tax policies applicable to FIEs. On 16th March 2007, the GOC issued Enterprise Income Tax Law (“EITL”) of the PRC, which is applicable to all enterprises in China PR including the FIEs. This law was implemented w.e.f 1 January 2008. There were two major changes in the new tax law: (1) preferential income tax policies for FIEs have been terminated,

and a unified tax rate is made applicable for domestic enterprises and FIEs; (2) preferential income tax policies for local special economic zones have been terminated. Further, the State Council issued notice on the Implementation of the Transitional Preferential Policies in respect of Enterprise Income Tax, stipulating that as of 1 January, 2008, enterprises that previously enjoyed the preferential policies of low tax rates shall be gradually transited to enjoy the statutory tax rate within 5 years after implementation of the EITL. Therefore, even enterprises which enjoyed preferential tax policies under old income tax law would no longer enjoy the same from the end of 2012.

278. In view of the above, the Authority notes that while some of the instruments were not relevant to the aforementioned program, the other instruments were no longer in force. Thus, no tyre producers/exporters who had exported the subject product to India during the POI received benefit under this program.

279. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be determined against these programs.

(xix) Program No. 43: Income Tax Reduction for Advanced Technology FIEs

a. Submissions by the petitioners

280. FIEs of advanced technology may continue to enjoy 50% income tax exemption after period of reduction and exemption has expired. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents.

- i. Circular of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Enterprise Income Tax Preferential Policies (Cai Shui (2009) No. 69)
- ii. Cai Shui (2015) No. 37
- iii. Catalogue – Circular of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Enterprise Income Tax Preferential Policies 2015

The petitioner also pointed out that PUC producers such as Kenda Rubber (China) Co., Ltd might have availed the benefit out of this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

281. Petitioner has not provided legal text of the notification mentioned in the petition.

c. Examination by the Authority

282. The Authority notes that legal basis of Cai Shui (2009) No. 69 is not relevant to this Program.

283. Cai Shui (2015) No. 37 was related to Deed Tax Policy for Further Supporting the Transformation and Restructuring of Enterprises and Public Institutions and not to the Program 43. Petitioners did not provide legal text of Circular of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Enterprise Income Tax Preferential Policies 2015. During the course of investigation, the Authority also failed to identify relevant legal basis for the alleged program.

284. None of the participating producers from China PR has received benefit under this program. Petitioner has also not provided evidence to show that tyre producers in China PR who exported the subject product to India received benefit under this program.

285. Therefore, there is no evidence to establish that the alleged program exists.

286. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against the alleged subsidy program.

(xx) Program No. 48: Tariff and Value-added tax exemptions on imported materials and equipment in SEZs and other designated areas

a. Submissions by the petitioners

287. Both FIEs and certain domestic enterprises are exempted from the VAT and tariffs on imported equipment used in their production so long as the equipment does not fall into prescribed lists of non-eligible items. Provincial branch provides a certificate to enterprises that receive the exemption. The program encourages foreign investment and aims to introduce foreign advanced technology equipment and industry technology upgrades. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents.

i. Circular of the State Council on Adjusting Tax Policies on Import Equipment (Guo Fa No. 37)

ii. Web research – tax exemption and reduction

iii. Web research – trade regulations, customs and standards

iv. China PR Tax Laws

b. Submissions by GOC / other interested parties-

288. The GOC stated that except Guo Fa No. 37, the remaining documents did not constitute the legal basis.

c. Examination by the Authority:

289. The Authority notes that Guo Fa (1997) No. 37 pertains to exemption from tariff and import-stage value- added tax for imported materials and equipment. Tax benefit of imported material is already evaluated in Program 35.

290. In absence of any other legal basis, the Authority is unable to evaluate if the program provides for financial contribution in the form of revenue foregone. Moreover, none of the participating tyre producers have received benefit under this program during the POI. Petitioners have not provided any evidence to show that tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI benefitted from this program. During the course of investigation, the Authority could also not identify evidence to support that tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI benefitted from the program.

291. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(xxi) Program No. 49 Preferential Income Tax Policy for the Enterprises in the Northeast Region

a. Submissions by the petitioners

292. The petitioners stated that under above program, enterprises located in the Northeast region of China PR are eligible for deduction of accelerated depreciation and amortization expenses linked

to the purchase of fixed assets. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents :

- i. Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on the Assets Depreciation and the Implementation Calibre of Amortization Policy in the Northeast Old Industrial Base (Cai Shui (2005) No. 17)
- ii. Opinions of the General Office of the State Council on Implementing the Promoting of Further Opening-up of the Old Industrial Bases in Northeast China (Guo Ban Fa (2005) No.36)
- iii. Opinions of the State Council on Further Implementing the Strategy of Revitalizing the Old Industrial Bases including Northeast China (Guo Fa (2009) No.33)
- iv. Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Exempting the Tax Arrears of the enterprises in the old industrial bases of northeast China (Cai Shui (2006) No. 167)

However, the petitioners also pointed out that only tyre companies located in Northeast region were eligible for this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

293. The GOC clarified that item (1) was abolished under Decision of the Ministry of Finance on Announcement of the List of Abolished and Invalidated Finance Provisions and Regulatory Documents (11th Set) dated 21 January 2011. Item (2) and (3) were not relevant to the program. Also, no legal text was attached in the petition. In order to cooperate fully, the GOC identified the legal text for this program and provided the same to the verification team and the same was made part of the verification exhibits.

c. Examination by the Authority:

294. The Authority notes that Cai Shui (2005) No.17 was terminated by Decision of the Ministry of Finance on Announcement of the List of Abolished and Invalidated Finance Provisions and Regulatory Documents (11th Set) on 21 February 2011. Moreover, Guo Ban Fa (2005) No. 36, Cai Shui (2006) No. 167 and Guo Fa (2009) No. 33 was not related to the program at all.

295. The Authority also noted that the program actually was governed under Notice of the State Administration of Taxation about Scope of Application of the Enterprise Income Tax Preferential Policies for Revitalizing the Old Industrial Base in Northeast China (Guo Shui Han (2005) No. 823). However, the regulation was terminated under Announcement No. 2 [2011] of the State Administration of Taxation dated 4 January 2011. Authority is unable to identify any other legal basis which provides for the existence of this program and which is still in force.

296. Moreover, none of the participating tyre producers have received benefit under this alleged program during the POI. Petitioners have not provided any evidence to show that tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI benefited from this program. During the course of investigation, the Authority could also not identify evidence to support that tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI benefited from this program.

297. Therefore, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(xxii) Program No. 50: Tax Concessions for Central and Western Regions**a. Submissions by the petitioners**

298. A preferential income tax rate of 15% over the ordinarily applicable 25% was available to companies in the Central and Western regions of China PR. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Guo Fa (2000) No.33
- ii. Cai Shui (2001) No. 202
- i. Cai Shui (2011) No. 58
- ii. SAT – in depth implementation of the Western Development, Strategy on CIT
- iii. China approves for the 12th Five Year Plan for Western Region – 2012
- iv. Foreign Investment Guidelines for Central & Western Region
- v. Investing in Central & Western Region, 2000
- vi. State Administration of Taxation – 2012
- vii. Western China Development Strategy, 2013
- viii. China extends tax incentives in western regions
- ix. State Administration of Taxation – 2015. Announcement on Issues concerning Enterprise Income Tax in Implementing the “Catalogue of Industries Encouraged to Develop in the Western Region” (Cai Shui (2015) No. 14)

299. Petitioners provided the following names as eligible entities: Aeolus Tyre Co. Ltd., Haoyou Tyre Co., Ltd., Doublestar-Dongfeng Tyre Co. Ltd., Enshi Geelong Trading Co. Ltd. Tyre Producers in Western China- Chongqing Qingsu Science & Technology Co. Ltd., Chongqing Lianpo Science & Technology Co. Ltd., Chongqing Zhundong Trade Co. Ltd, Chongqing Duhao Trade Co. Ltd, Chongqing Xuannan Science & Technology Co. Ltd, Chongqing Wei Sha Trading Co. Ltd., Chengdu Gao Wei Neng Trading Co. Ltd, Chengdu Fengsheng Trade Co. Ltd., Chengdu Shengdafei Commerce and Trade Co. Ltd., Chengdu Baoling Technology Co. Ltd., Kunming Sangduo Trade Co. Ltd, Kunming Mingwen Trading Co. Ltd., Baiyinmeixuan Trading Co. Ltd, Kashi Jin Sheng Sanli International Trade Co., Ltd.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

300. In the petition, Indian domestic industry noted 12 legal basis towards this program. The GOC clarified that 3 legal basis were terminated, 5 legal basis have no text or relevant documents. Remaining 4 legal basis have relevant legal text but all of them are related to western region. There are totally 12 provinces included in western region, i.e. Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xizang, Xinjiang, Inner Mongolia and Chongqing. It was clarified that there are no tyre manufacturers located in these places.

c. Examination by the Authority:

301. The Authority notes that the program actually was governed under Guo Fa (2000) No.33, which is still valid. The areas in which policies on the development of the Western Region are

applicable include Chongqing Municipality, Sichuan Province, Guizhou Province, Yunnan Province, Tibet Autonomous Region, Shangxi Province, Gansu Province, Ningxia Hui Autonomous Region, Qinghai Province, Xinjiang Uygur Autonomous Region, Inner Mongolian Autonomous Region and Guangxi Chuang Autonomous Region.

302. Cai Shui (2015) No. 14 further regulated corporate income tax towards encouraged industries in western region and provided that they would continue preferential income tax rate of 15%.

303. The Authority notes that the program has been earlier examined by other investigating authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established. For example, by the EU authorities in *Organic Coated Paper*.

304. The Authority however notes that no tyre manufacturer who exported the subject product to India during the POI was based in the western region. During the course of investigation, the Authority could also not identify that any tyre producers who exported the subject product to India during the POI received benefit under this program.

305. Therefore, the Authority holds that countervailing duty should not be imposed against this program.

II.A Tax programs received by participating producers/exporters from China PR

(i) Zhongce Rubber Group Co Ltd.

306. Authority has verified the information provided by Zhongce Rubber Group Co. Ltd. and determined subsidy margin for tax programs for which benefit was received or accrued during the POI. Authority determined that all the tax programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone. As a result, benefit was conferred to Zhongce Rubber as a recipient of foregone revenue. Subsidy programs were also specific because they provided benefit to certain enterprise including Zhongce Rubber.

307. The table below provides for the name of the tax programs, and the corresponding subsidy margin:

Name of the grant program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program 27: as per the petition: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses	Where an enterprise has incurred research and development expense in the development of new technologies, new products and new processes but intangible assets are yet to be formed and included in the profit and loss for the current period, 50% of the research and development expenses shall be deducted on the basis of actual deduction; where intangible assets are formed, 150% of the cost of intangible assets shall be amortised.	***	0-5%

(ii) Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.

308. Wanda Boto did not receive any benefit under tax program during the POI.

(iii) Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd.

309. Tax programs received by Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd. are noted in the table below:

Name of the grant program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program 33: Tax credit concerning the purchase of special equipment	Article 34 of EITL stipulates that the amount of an enterprise's investment in the purchase of special equipment for environmental protection, energy and water saving, work safety, etc. may be deducted from the tax amount at a certain rate.	***	0-5%

(iv) Triangle Tyre Co. Ltd.

310. Tax programs received by Triangle Tyre are noted in the table below:

Name of the grant program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program 31: Preferential income tax rate	Preferential income tax rate for high and new technology enterprise	***	0-5%

(v) Aeolus Tyre Co. Ltd.

311. The table below provides for the tax programs and the corresponding subsidy margin.

Name of the Program	Brief Facts	Subsidy Margin	Subsidy Margin Range %
Program 31: Preferential tax policies/ Income Tax Reductions for companies that are recognized as high and new technology companies	The Company is officially recognized as a new high-tech enterprise.	***	0-5%

(vi) Yellow Sea Rubber Co. Ltd.

312. Yellow Sea Rubber Co. Ltd. did not receive any benefit under the tax programs during the POI.

II.B. Summary of Tax Programs

313. The Authority has determined the all others rate based on the highest of the subsidy margins for the cooperating parties.

Name of the Company	Subsidy Margin for grants %	Range %
Zhongce Rubber Group Co. Ltd.	***	0-5%
Triangle Tyre Co. Ltd	***	0-5%
Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd	***	0-5%
Aeolus Tyre Co. Ltd.	***	0-5%
All Others	***	0-5%

III. Programs Identified in the Form of Preferential Lending

(i) Program No. 51 Government Policy Lending

a. Submissions by the petitioners

314. Steel producers benefit from low (subsidized) interest rates from state owned commercial banks and government banks in accordance with the GOC policy to support and develop the expansion of the Chinese steel industry. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Decision of the State Council on Promulgating and Implementing the “Temporary Provisions on Promoting Industrial Structure Adjustment” (Guo Fa (2005) No. 40)
- ii. Article 34 and Article 38 of the Commercial Banking Law
- iii. Articles 16,24 and 25 of Order No. 35 – Policies for the development of Iron and Steel Industry
- iv. The Ministry of Industry and Information Technology’s 2012 Industry Transfer Guidance Catalog supports key and advantaged industries, such as the steel industry through preferential lending
- v. Directory Catalog on Readjustment of Industrial Structure (Directory Catalogue) – 2005 & 2011
- vi. Guidelines for the Eleventh Five-Year Plan for National Economic and Social Development (2006-2010) (11th Five-year Plan)
- vii. Yin Fa [2003] No. 50
- viii. Yinfia (2004) No. 251
- ix. Blueprint for implementing the adjustment and revitalisation program for the steel industry [2009] provides for “increasing the financial support for key backbone enterprises”

Tyre producers such as Aeolus, Double Coin, Sailun and Guizhou Tire might have availed the benefit out of this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

315. The GOC stated that the petitioners only provided legal text of Guo Fa (2005) No. 40. Other legal basis had no legal text. Besides, the article *MITT to publish Tire Industry Access Conditions* and the annual reports did not constitute legal basis.

316. Based on the list of legal basis provided in the petition, it is clear that the program is applicable only to the steel industry. Petition itself notes that steel industry benefits from this program.

c. Examination by the Authority

317. Authority notes that all the legal basis provided in the petition relates to steel industry. Therefore, Authority determines that no countervailing duty shall be imposed against this program.

318. However, during the course of investigation, the Authority determined that certain participating exporters from China PR have received benefit in the form of preferential lending from state owned banks. Authority has determined that such preferential lending has resulted in financial contribution in the form of direct transfer of funds. Authority has determined countervailing duty against such preferential lending by comparing the interest rate charged by the state owned bank from the exporter receiving loan with the commercial benchmark interest rate prescribed on the long term and short term borrowing by the People's Bank of China (Central Bank of China). Benefit was calculated based on the difference between these two amounts.

(ii) Program No. 52: Preferential Loans to SOE**a. Submissions by the petitioners**

319. It was claimed that under this Program, the SOEs receive preferential loans through state-owned commercial or policy banks. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents.

i. Circular of the China PR Bank of China, the State Administration of Foreign Exchange, the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation and the state Administration of Taxation Concerning Printing and distributing detailed Rules on rewarding and punishment concerning provisional regulations over examination of export collections of foreign exchange - Yin Fa (2000) No. 58

320. It has been shown that PUC producers such as Xiamen Penavico Logistics Co., Ltd; Doublestar Dongfeng Tyre Co., Ltd; Xuzhou Xugong Tyres Co., Ltd; Aeolus Tyre Co., Ltd; Qingdao Doublestar Tyre Industrial Co., Ltd; Triangle Tyre Co., Ltd; Shifeng Double-star Tyre Co., Ltd; Shandong Taishan Tyre Co., Ltd; China Shipbuilding Trading (Shanghai) Co., Ltd; Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd might have availed the benefit under this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

321. The GOC has stated that the program was terminated.

c. Examination by the Authority:

322. The Authority notes that the program was governed under Detailed Rules on Rewarding and Punishment Concerning Provisional Regulations over Examination of Export Collections of Foreign

Exchange (Yin Fa [2000] No. 58) but the same was terminated through Announcement No. 7 [2007] of the People's Bank of China, State Administration of Foreign Exchange, Ministry of Commerce and State Administration of Taxation -- annulling the Circular of Distributing the Detailed Rules on Reward and Punishments of Provisional Regulations on Examination of Foreign Exchange Collection.

323. In view of the above, the Authority notes that the relevant instrument was no longer in force. However, during the course of investigation, the Authority determined that certain participating exporters from China PR have received benefit in the form of preferential lending from state owned banks. Authority has determined that such preferential lending has resulted in financial contribution in the form of direct transfer of funds. Authority has determined countervailing duty against such preferential lending by comparing the interest rate charged by the state owned bank from the exporter receiving loan with the commercial benchmark interest rate prescribed on the long term and short term borrowing by the People's Bank of China (Central Bank of China). Benefit was calculated based on the difference between these two amounts.

(iii) Program No. 53 Discounted Loans for Export-oriented Enterprises and Export Loan Interest Subsidies

(iv) Program No. 54: Preferential Loans and Interest Rate to the Tyre Industry

a. Submissions by the petitioners

324. The Petitioners claimed that state-owned commercial banks provide preferential loans for exports. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents:

- i. Fujian Province iron and steel industry and non-ferrous metals industry adjustment and revitalization implementation plan (2009-2011)
- ii. 2012 Annual Report of Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd
- iii. 2013 Recruitment Notice Of The Export Import Bank Of China Ningbo Branch
- iv. Circular of the ministry of industry and information technology on printing and distributing the iron and steel industry 12th five-year development plan (Gong Xin Gui (2011) No.480)
- v. Circular of the ministry of science and technology on printing and distributing the high quality specialty steel science and technology development 12th five-year special plan (2012)
- vi. Order 47 – Article 34 of Law of the China PR on Commercial Banks (2003) with respect to the fulfilment of the government industrial policies
- vii. Circulars of the People's Bank of China (PBOC) concerning expansion of financial institutions' loan interest rate policy (Yin Fa (2003) No. 250)
- viii. The annual reports of Chinese banks that were either submitted from GOC or publicly available, information retrieved from the 2006 Deutsche Bank research on China's banking sector, WTO Policy review on China (2010 and 2012), China 2030 World Bank Report
- ix. PBOC's circular on the issues about the adjusting interest rates on deposits and loans – Yin Fa (2004) No. 251
- x. NDRC order No. 35 – Policies for the Development of Iron and Steel Industry,

xi. OECD 2010 economic survey of China, February 2010 (see chapter 3, pages 71, 73-81, 97)

xii. OECD China's financial sector reforms, economic department working paper No. 747, ECO/WKP (2010) 3, 1 February 2010, (see pages 2, 8-15, 36)

325. The petitioners also pointed out that producers such as Xiamen Penavico Logistics Co. Ltd; Fujian Province, Doublestar -Dongfeng Tyre Co. Ltd. Hubei Province, Xuzhou Xugong Tyres Co., Ltd. Jiangsu Province, Aeolus Tyre Co. Ltd. Henan Province, Qingdao Doublestar Tyre Industrial Co., Ltd. Shandong Province, Triangle Tyre Co. Ltd Shandong Province, Shifeng Double-Star Tyre Co., Ltd, Shandong Province, Shandong Taishan Tyre Co., Ltd, Shandong Province, China Shipbuilding Trading (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai Municipality, Shanghai Type & Rubber Co., Ltd. Shanghai Municipality, Sichuan Tyre And Rubber Co., Ltd, Sichuan Province might have availed the benefit out of this program.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

326. The GOC stated that the annual reports, 2013 recruitment notice of the export import bank of china Ningbo branch, and OECD reports did not constitute the legal basis.

327. Fujian Province Iron And Steel Industry And Non-Ferrous Metals Industry Adjustment And Revitalization Implementation Plan (2009-2011), Circular of the ministry of industry and information technology on printing and distributing the iron and steel industry 12th five-year development plan (Gong Xin Gui (2011) No.480), Circular of the ministry of science and technology on printing and distributing the high quality specialty steel science and technology development 12th five-year special plan (2012) were related to steel industry only.

c. Examination by the Authority

328. The Authority notes that most of the legal instruments provided by the petitioners in program 53 were related to the steel industry only. While Yin Fa (2003) No. 250 was the regulation determining the floating scope applicable to the commercial banks. Yin Fa (2004) No. 251 stipulated benchmark loan interest rate published by the PBOC. However, both these were not relevant to the program. Decree No. 40 did not mention that tyre industry shall be provided preferential loans and interest rates.

329. However, during the course of investigation, the Authority determined that certain participating exporters from China PR have received benefit in the form of preferential lending from state owned banks. Authority has determined that such preferential lending has resulted in financial contribution in the form of direct transfer of funds. Authority has determined countervailing duty against such preferential lending by comparing the interest rate charged by the state owned bank from the exporter receiving loan with the commercial benchmark interest rate prescribed on the long term and short term borrowing by the People's Bank of China (Central Bank of China). Benefit was calculated based on the difference between these two amounts.

IV. Programs Identified in the Form of Export Financing and Export Credit

- (i) Program No. 55: Export Seller's Credit**
- (ii) Program No. 56: Export Buyer's Credit**

(iii) Program No. 57: Other Export financing from State-owned Banks

a. Submissions by the petitioners

330. Domestic companies are eligible for getting financing from government banks for export of certain products according to their export performance. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them:

- i. Circular of Import & Export Bank of China on supporting the exports of high and new technologic products, 1999 No. 210
- ii. The Export-Import Bank of China, export sellers credit, 2012 Annual Report
- iii. Export Buyer's Credit, website excerpts
- iv. The Export-Import Bank of China website
- v. China's Compliance with WTO & International Trade Rules, 2014
- vi. Export Financing Activities by the Chinese Government 2011

It has also been submitted that this program has been held countervailable by other investigating authorities.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

331. The GOC stated that annual report of the Export-Import Bank of China, weblink of brief introduction of the Export-Import Bank of China, Giti's Annual Report and all other documents furnished by the petitioner did not constitute the legal basis.

c. Examination by the Authority

332. The Authority notes that the Import and Export Bank of China issued Circular on Supporting the Export of High-New Technologic Products (Jin Chu Yin Ji Fa [1999] No. 210), which is still in effect. Besides, Article 1 stated that the scope of the high and new technology products that need support shall be decided according to the List of Exports and Imports of High and New technology Product of China. The Authority also noted that radial tyre was listed as a high and new technology product of China.

333. The Authority notes that program 55 & 56 have been earlier examined by some other investigating Authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established by the US authorities in certain passenger vehicle and light truck tyres and utility scale wind towers.

334. During the course of investigation, the Authority noted that certain participating exporters from China PR have received benefit in the form of preferential lending from state owned banks. Authority has determined that such preferential lending has resulted in financial contribution in the form of direct transfer of funds. Authority has determined countervailing duty against such preferential lending by comparing the interest rate charged by the state owned bank from the exporter receiving loan with the commercial benchmark interest rate prescribed for the long term and short term borrowing by the People's Bank of China (Central Bank of China). Benefit was calculated

based on the difference between these two rates. The Authority has not separately identified whether the loan granted by state owned banks were for exports or for other reasons.

(iv) Program No. 58: Export Credit Insurance Subsidies

(v) Program No. 59: Export Credit Guarantees

a. Submissions by the petitioners

335. The Petitioners mentioned that under the program, the GOC directed the China Export & Credit Insurance Corporation, or Sinosure to increase its support for export of products listed in the catalogue of Chinese high-tech products for export. Tyre producers are eligible for export credit guarantees As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents:.

- i. Strategy of promoting trade through science and technology by utilizing export credit insurance
- ii. Catalogue of Chinese High-Technology Products for Export (2006) and translated excerpts
- iii. Ministry of Commerce of China PR, Department of Mechanic, Electronic and Hi-tech Industry (national Mechanic and Electronic Import and Export Office) Webpage and translated excerpt.
- iv. Notice of the Ministry of industry and information technology on issuing the tyre industry policy (Gong Chan Ye Zheng Ce (2010) No.2) and translated excerpts
- v. Order of the NDRC and Reform Commission of China PR on revising certain provisions of guidance catalogue for the industrial structure adjustment (2011) No. 21 (Feb 2013)
- vi. Ministry of Commerce and China Export & Credit Insurance, Shang Ji Fa (2004) No. 368

b. Submissions by GOC / other interested parties-

336. The GOC stated that strategy of promoting trade and webpage were not legal basis.

c. Examination by the Authority:

337. The Authority notes that the Ministry of Commerce and China Export & Credit Insurance Notice on utilizing export credit insurance to implement the strategy of encouraging trade through science and technology (Shang Ji Fa (2004) No. 368) was still in force.

338. Import and Export Bank of China issued Circular on Supporting the Export of High-New Technologic Products (Jin Chu Yin Ji Fa [1999] No. 210), which is still in effect. Besides, Article 1 stated that the scope of the high and new technology product that need support shall be decided according to the List of Exports and Imports of High and New technology Product of China. The Authority also noted that radial tyre was listed as the high and new technology product of China PR.

339. Authority notes that the program provides for provision of export guarantee by state funded insurance company Sinosure. The program provides for financial contribution in the form of potential direct transfer of funds. Program is also specific because it is contingent on export performance. The program can be said to provide benefit and is thus countervailable subsidy if it is determined that export guarantee is provided by Sinosure at less than comparable commercial charges i.e. the fees charges by other domestic private insurance company on comparable commercial export guarantee provision. No evidence is provided in the petition in this regard.

340. In any case, petition has not provided any evidence to show that tyre producers in China PR who exported the subject product to India received benefit under this program. None of the participating exporters from China PR have received benefit under this program. During the course of investigation, the Authority could also not identify that tyre producers in China PR who have exported the subject product to India have received benefit under this program.

341. Thus, the Authority holds that no countervailing duty can be imposed against these alleged programs.

342. The Authority also notes that some of the participating producers have reported benefit received in the form of export credit insurance premium subsidy as grants (other than the benefit under this program) and the same has already been countervailed by the Authority.

III/IV.A Summary for preferential lending/Export Financing and Export Credit received by responding producers/exporter

343. Authority has verified the information provided by participating producers/exporters from China PR. Subsidy margin for preferential loans for which benefit was received during the POI is noted in the table below.

344. The Authority has determined the all others rate based on the highest of the subsidy margins for the cooperating parties.

Name of the participating producer/exporters	Subsidy margin %	Subsidy margin range %
Zhongce Rubber Group Co. Ltd.	***	0-5%
Triangle Tyre Co. Ltd.	***	0-5%
Aeolus Tyre Co. Ltd.	***	0-5%
All others	***	0-5%

V. Programs Identified in the Form of Equity

(i) Program No. 60: Equity infusions

a. Submissions by the petitioners

345. The Petitioners claimed that the GOC acquires additional ownership shares in steel companies and at the same time provides cash subsidies. GOC owns majority stake in almost all steel

producers in China PR as economic policy goal. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents:

- i. China International Capital Corporation Ltd. ("CICC")'s web page

It has also been submitted that this program has been held countervailable by other investigating authorities.

b. Submissions by GOC / other interested parties-

346. The GOC stated that document cited by the Petitioners did not constitute the legal basis. Besides, CICC is not the shareholder of any tyre company.

c. Examination by the Authority

347. The Authority notes that the petition itself alleges that equity infusion is made in Steel industries. Unlike other alleged programs, petition has also not provided list of eligible tyre producer in China PR who may have received benefit under this program.

348. Authority also notes that none of the responding exporters have availed benefit under this program. Petition has not provided any information to demonstrate that tyre producers who exported the subject product to India received benefit under this program. During the course of investigation, the Authority also could not identify that exporters in China PR who exported the subject product to India received benefit under this program.

349. Therefore, Authority determines that no countervailing duty can be imposed against this program.

(ii) Program No. 61: Unpaid dividends

a. Submissions by the petitioners

350. Government acquires additional ownership shares in tyre companies. However, the GOC foregoes or does not collect the dividends from these companies, some of whom are producers of the PUC. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them:

- i. Ministry of Finance, State Administration of Taxation and China Securities Regulatory Commission jointly published Cai Shui (2014) No.79

b. Submission by Government of China

351. The document relied upon as evidence by the petitioner was not provided as exhibits.

c. Examination by the Authority

352. The Authority notes that the legal instrument noted by the petitioners determined that income derived by qualified foreign institutional investors ("QFII") and RMB qualified foreign institutional investors ("RQFII") from the transfer of stock or any other equity investment asset in China shall be temporarily exempt from enterprise income tax. This is however not relevant to this program. The Authority notes that Petition did not provide any evidence to show that tyre companies in China PR who exported the subject product received benefit under this program.

353. None of the participating producers/exporters from China PR received benefit in the form of unpaid dividends. Petitioner also did not provide any evidence to show that tyre producers in China PR who exported the subject product to India received benefit under this program. During the course

of investigation, the Authority also could not identify that tyre producers in China PR who exported the subject product to India received benefit under this program.

354. Therefore, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

(iii) Program No. 62 Dividend exemption between qualified resident enterprises

a. Submissions by the petitioners

355. Preferential tax treatment is provided in form of tax reduction on certain dividends, bonus and other equity benefits to the enterprises. Chinese enterprises who are shareholders in other Chinese resident enterprises are eligible for the said benefit. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. Article 26, Enterprise Income Tax Law
- ii. Article 83, Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law, Decree No. 512 of the State Council

b. Examination by the Authority:

356. The Authority notes that the program was governed under Article 26 of Enterprise Income Tax Law as well as Article 83 of Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law.

357. The Authority notes that the program has been earlier examined by some other investigating authorities in the past and existence and countervailability of this program has been established by the EU authorities in (a) *coated fine paper* and (b) *certain organic coated steel products*.

358. None of the responding producers/exporters from China PR received benefit under this program. Petition does not provide any evidence to show that tyre producers in China PR who exported the subject product to India received benefit under this program. During the course of investigation, the Authority could also not identify that tyre producers in China PR who exported the subject product to India received benefit under this program.

359. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this program.

VI. Programs Identified in the Form of Provision of Goods and Services

- (i) **Program No. 63: Provision of Electricity for Less Than Adequate Remuneration**
- (ii) **Program No. 64: Provision of Water for Less Than Adequate Remuneration**

a. Submissions by the petitioners

360. The Petitioners claimed that tyre manufacturers are eligible for receiving electricity or water for less than adequate remuneration. Petitioners relied on the following legal basis:

- i. Gua Fa 2004 No. 20
- ii. Catalog – Decision No. 40 (2005)-(NDRC)
- iii. Order 35 of the NDRC – Policies for development of Iron and Steel Industry – 2005
- iv. Articles 3,6,35,37,38,39,41 & 42 of Electricity Laws – 1995

- v. Water Laws in China PR-2002
- vi. Web Research—Preferential treatment for FIEs in Jiangsu Qidong Lusio Development Zone

b. Submission by Government of China

361. Petitioners have not provided legal text for any of the legal basis noted in the petition.

c. Examination by the Authority

362. Petitioners have alleged that GOC provides electricity and water at preferential rates and at basic price respectively.

363. The Authority notes that there is not sufficient evidence to conclusively prove that Government of China is providing water to certain enterprises at less than adequate remuneration.

364. However, the Authority notes that Government of China is providing electricity to certain enterprises at less than adequate remuneration. Provision of electricity at less than adequate remuneration amounts to financial contribution in the form of provision of services. Authority observes that electricity at less than market rates amounts to conferring of benefit. This subsidy program is also specific because it is limited to certain type of enterprises in China PR. Therefore, the Authority notes that the provision of electricity by the GOC is a countervailable subsidy program.

365. The Government of China and the participating exporters/respondents have not provided adequate information for quantification of benefit availed. The authority has therefore determined countervailing duty against provision of electricity for less than adequate remuneration based on facts available.

(iii) Program No. 65: Land Use Rights in Industrial and Other Special Economic Zone

(iv) Program No. 66: Land Use Rights for SOEs

a. Submissions by the petitioners

366. The land use right provisions in China are dealt with Land Administration Law of China PR. Land provision and acquisition in China is unclear and non-transparent and the prices are often arbitrarily set up by the authorities. The authorities set the prices according to the Urban Land Evaluation System which instruct them, among other criteria, to consider and set prices of industrial land. The land in China PR is provided far below the normal market rates.

367. According to Article 2 of the Land Administration Law, all land is government owned since, according to the Chinese constitution and relevant legal provisions, land belongs collectively to the People of China. No land can be sold but land use rights may be assigned according to the law. The State authorities can assign it through public bidding, quotation or auction.

368. The petitioners have noted that benefit is available to high and new technologically advanced SOEs. Following notifications or scheme documents have been furnished by them as evidence :

- i. General Office of the People's Government of Henan Province Notice Regarding Dissemination of Henan Province Industrial Transformation and Upgrading 12th Five-Year Plan, Yu Zheng Ban (2012) No.22 (Feb. 25, 2012)

- ii. Land Administration Law of the People's Republic of China 2004
- iii. Real Right Law of the People's Republic of China

b. Submissions by GOC / other interested parties-

369. The GOC stated that 12th Five Year Plan referred to Year 2011-2015. Since the 12th plan period expired, the program was invalid since 2015. Remaining exhibits provided by the petitioner do not constitute as legal basis.

c. Examination by the Authority:

370. The Authority notes that the legal basis provided by the petitioner was for the Year 2011-2015 and that period has expired.

371. However, Authority notes that Government of China is providing land use rights to certain enterprises at less than adequate remuneration. Provision of land use rights at less than adequate remuneration amounts to financial contribution in the form of provision of services. Authority observes that land use rights provided at less than market rates amounts to conferring of benefit. This subsidy program is also specific because it is limited to certain type of enterprises in China PR. Therefore, the Authority notes that the provision of land use rights by the GOC is a countervailable subsidy program.

372. The Government of China and the participating exporters/respondents have not provided adequate information for quantification of benefit availed under land use rights. The authority has therefore determined countervailing duty against provision of land use rights at less than adequate remuneration based on facts available.

(v) Program No. 67: Land use right for FIEs

a. Submissions by the petitioners

373. China has a policy of providing land-use rights to certain foreign-invested enterprises (FIEs) on a preferential basis in addition to SOEs. Enterprises with foreign investment could qualify either as an export enterprise. Also, technologically advanced enterprise can avail the benefit on land use fees, and local governments are authorized for such payment for limited periods of time. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents:

- i. Provisions of the State Council on the Encouragement of Foreign Investment, Guo Fa (1986) No. 95, at art.4 (Oct.11.1986)
- ii. Notice of the Ministry of Industry and Information Technology on Issuing the Tyre Industry Policy (Gong Chan Ye Zheng Ce (2010) No.2)
- iii. Provisions of Fuzhou Economic and Technological Development Zone (Dec.12, 1986) at art.23
- iv. Implementing Provisions for Encouraging Foreign Investment in Guangdong Province (Apr. 26, 1987) at art.20

- v. Provincial Provisions for Encouraging Foreign Investment in Heilongjiang Province (Dec.18, 1986) at Arts.2 4(1)-(2)
- vi. Regulations of the Jiangsu Provincial People's Government for the Encouragement of Foreign Investment (Nov.11, 1986) at art.2

b. Submissions by GOC / other interested parties-

374. The GOC stated that the petitioners did not provide legal text of Implementing Provisions for Encouraging Foreign Investment in Guangdong Province (Apr. 26, 1987) and Several Regulations of the Jiangsu Provincial People's Government for the Encouragement of Foreign Investment (Nov.11, 1986).

c. Examination by the Authority:

375. The Authority notes that the program was governed under Guo Fa (1986) No.95, which was still in force.

376. The Authority also noted that Regulations of Fuzhou Economic and Technological Development Zone was replaced with 1993 revision and 2002 revision. The 2002 revision was still in force. However, there was no tyre producer based in Fuzhou Economic and Technological Development Zone.

377. Implementing Provisions for Encouraging Foreign Investment in Guangdong Province (Apr. 26, 1987) was also repealed on 14 April 1998. Provincial Provisions for Encouraging Foreign Investment in Heilongjiang Province (Dec.18, 1986) was terminated on 5 January 2011. Regulations of the Jiangsu Provincial People's Government for the Encouragement of Foreign Investment (Nov.11, 1986) was terminated on 24 June 2002.

378. However, Authority notes that Government of China is providing land use rights to certain enterprises at less than adequate remuneration. Such provision of land use rights at less than adequate remuneration amounts to financial contribution in the form of provision of services. Authority observes that land use rights provided at less than market rates amounts to conferring of benefit. This subsidy program is also specific because it is limited to certain type of enterprises in China PR. Therefore, the Authority notes that the provision of land use rights by the GOC is a countervailable subsidy program.

379. The Government of China and the participating exporters/respondents have not provided adequate information for quantification of benefit availed under land use rights. The authority has therefore determined countervailing duty against provision of land use rights for less than adequate remuneration based on facts available.

(vi) Program No. 68: Provision of Carbon Black for Less than Adequate Remuneration

(vii) Program No. 69: Provision of Nylon Cord for Less than Adequate Remuneration

(viii) Program No. 70: Provision of Synthetic Rubber and Butadiene for Less than Adequate Remuneration

(ix) Program No. 71: Provision of Natural Rubber for Less than Adequate Remuneration.

a. Submissions by the petitioners

380. The Petitioners claimed that tyre industry is the predominant user of raw materials like carbon black, nylon cord, synthetic rubber and natural rubber. GOC through SOEs is providing these raw materials at less than adequate remuneration. As evidence of existence of the program, the petitioners have not provided the following notifications or scheme documents:

- i. Notice of the Ministry of Industry and Information Technology on Issuing the Tyre Industry Policy (Gong Chan Ye Zheng Ce (2010) No. 2) at arts.16-19
- ii. Form 20-F of Annual Report of Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd, filed with the United States Securities and Exchange Commission on Apr. 30, 2014
- iii. Ministry of Commerce, People's Republic of China, Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2011)
- iv. The Dalian High-Tech Industrial Zone lists "synthetic rubber" among its "encouraged foreign investment industries." Dalian High-Tech Industrial Zone, "Encouraged Foreign Investment Industries" (Mar. 16, 2006)
- v. The Guangzhou Development District lists "butadiene" and "synthetic rubber" as "encouraged industries", Guangzhou Development District, "Investment – encouraged industries" (2003)
- vi. The Guangzhou "State Industrial Catalog Guiding Foreign Investment" lists synthetic rubber among "The Encouraged Industries for Foreign Investment."
- vii. "The Encouraged Industries for Foreign Investment" the State Industrial Catalogue Guiding Foreign Investment.
- viii. Order of National Development and Reform Commission of China PR on revising certain provisions of "Guidance Catalogue for the Industrial Structure Adjustment (2011)

b. Submissions by GOC / other interested parties-

381. The GOC stated that Form 20-F Annual Report, the Dalian High-Tech Industrial Zone List, the Guangzhou Development District Lists did not constitute the legal basis and thus the Petitioner has not provided the legal basis/legal text for the alleged program.

c. Examination by the Authority

382. The Authority notes that the Notice of the Ministry of Industry and Information Technology on Issuing the Tyre Industry Policy (Gong Chan Ye Zheng Ce (2010) No. 2) was the major industrial policy regulating development of tyre industry. Articles 16 to 19 also stated that in order to update tyre quality, the State encouraged the development of natural rubber, certain synthetic rubber, structural steel cord and specialty carbon black.

383. Authority notes that financial contribution arises if the provision is made for raw materials at less than adequate remuneration by the government or public body. In such a situation, benefit is conferred on the recipient of goods. Such subsidy is also specific because it is limited to the enterprise which uses such raw material/goods.

384. Authority verified the information provided by participating exporters from China PR. Authority first did a detailed examination as to which raw materials have been procured by

participating producers/exporters from state owned enterprises. Thereafter, the Authority compared the purchase price from state owned enterprises with the purchase price from private enterprises as well as import price/international benchmark. The Authority notes that the three primary raw materials purchased by participating producers/exporters from state owned entities are natural rubber, synthetic rubber and carbon black.

385. In so far as natural rubber is concerned, the Authority notes that it is primarily imported into China and domestic purchases from state owned enterprises are negligible. Even the purchase price from state owned enterprise is comparable with the price of imported product.

386. In so far as synthetic rubber is concerned, the Authority notes that the participating producers/exporters have purchased synthetic rubber from state owned enterprises as well as private entities and also imported the same. The Authority has compared the purchase price from state owned enterprises with purchase price from private entity as well as the price of the imported product. The Authority notes that the purchase price from state owned enterprise is comparable with the purchase price from private entities as well as the price of the imported product.

387. In so far as carbon black is concerned, the Authority notes that participating producers/exporters have purchased carbon black from state owned enterprises as well as private entities. None of the participating producers/exporters have imported carbon black. For comparison purposes, the Authority has considered the international benchmark as the import price of carbon black into India from Korea RP. The Authority notes that the purchase price from state owned enterprise is comparable with the purchase price from private entities as well as the international benchmark adopted by the Authority except in case of Triangle Tyre Co. Ltd. and Zhongce Rubber group company Ltd. Accordingly, the Authority has determined the benefit for Triangle Tyre Co. Ltd. and Zhongce Rubber group company Ltd. based on the difference between the price paid to state owned enterprise and the international benchmark.

388. Thus, the Authority holds that no benefit has been received by the participating producers/exporters from China PR in the form of provision of raw materials for less than adequate remuneration except in the case of provision of carbon black for Triangle Tyre Co. Ltd. and Zhongce Rubber Group co. Ltd.

VI.A. Summary of provision of Goods and Services at less than adequate remuneration.

The Authority has determined the all others rate based on the highest of the subsidy margins for the cooperating parties.

Name of the Company	Subsidy Margin for provision of electricity at less than adequate remuneration %	Subsidy Margin for provision of land use rights at less than adequate remuneration %	Subsidy Margin for provision of carbon black at less than adequate remuneration	Total	Total range

Zhongce Rubber Group Co. Ltd.	***	***	***	***	5-15%
Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.	***	***	***	***	5-15%
Triangle Tyre Co. Ltd	***	***	***	***	5-15%
Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd	***	***	***	***	5-15%
Aeolus Tyre Co. Ltd.	***	***	***	***	5-15%
Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd.	***	***	***	***	5-15%
All Others	***	***	***	***	5-15%

(x) Program No. 72: Purchase of goods by the Government for higher than Adequate Remuneration

a. Submissions by the petitioners

389. Government purchases goods from the producers at higher prices. As evidence of existence of the program, the petitioners have provided the following notifications or scheme documents as was reasonably available to them.

- i. WTO challenges China's export restraints on raw material inputs
- ii. Chen Aizhu, as opposition grows, China defends plans for petrochemical plants
- iii. Sinopec Corp. Chemical, website excerpt
- iv. Synthetic Rubber Industry Assessments (China), China Synthetic Rubber Markets (Sep. 1998)
- v. China announces first cuts in gasoline, diesel prices in 16 months. Enlgish.new.cn, Oct. 8, 2011, attached at Exhibit M-74; China: Sinopec Confirms Receipt of US\$ 1.7 bn subsidy, Petrol World, March 24, 2008
- vi. World Energy: local player – Sinopec, economist intelligence unit, Aug. 13, 2007
- vii. Certain Crystalline Silicon Photovoltaic Products from China PR

b. Submissions by GOC / other interested parties-

390. The GOC stated that none of the documents identified by the Petitioners constitute legal basis at all. Besides, the GOC does not purchase PUC.

c. Examination by the Authority

391. The Authority notes that the Petitioners did not provide any legal basis and evidence in respect of the abovementioned program. In any case, the Authority observes that the Government of China does not purchase tyres/subject product and therefore question of financial contribution because of purchase of goods at more than adequate remuneration does not arise in this case.

392. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty can be determined against this subsidy program.

SUMMARY OF SUBSIDY MARGIN FOR PARTICIPATING PRODUCERS/EXPORTERS FROM CHINA PR

393. The details of the total subsidy margin for the participating producers/exporters from China PR and all others rate is given below:

Name of the Company	Subsidy Margin %	Range%
Zhongce Rubber Group Co. Ltd.	***	5-15%
Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.	***	5-15%
Triangle Tyre Co. Ltd	***	5-15%
Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd	***	5-15%
Aeolus Tyre Co. Ltd.	***	5-15%
Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd.	***	5-15%
Weighted average for Aeolus Tyre Co. Ltd. and Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd.	***	5-15%
All Others	***	10-20%

394. The Authority notes that subsidy margin for all the participating producers/exporters from China PR is above *de-minimis*.

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

H.1. Submission made by the Domestic Industry

395. The submissions made by domestic industry are as follows:

- Demand/apparent consumption of the PUC is defined as the sum of domestic sales of

Indian producers and imports from all other countries. Demand has increased over the injury period, with some decline in the POI.

b) Volume of subsidized imports from the subject country has doubled in comparison to the base year. Since the imports are de-facto only in the replacement market, the injury to the domestic industry is also prominent in the replacement market. Imports of PUC increased significantly in absolute terms in 2016-17, even as demand had marginally declined. Imports have thereafter declined in the POI, partly due to the decline in demand, as well as due to the initiation of ADD investigation on imports of subject goods (only TBR) in May 2016. There has been a significant decline in imports of TBB, the primary reason for which is the fact that the Chinese TBR is available in the market at a price below TBB. In fact, the present situation is such that one truck can be seen with TBB and TBR on different axle or even same axles. Evidence to this effect is enclosed with these submissions. TBB, however, still constitutes more than TBR in the Indian market. Chinese imports constitute 85% of all imports into India. There are no known imports of the product under consideration in the OEM segments and since the imports are de-facto only in replacement market, the injury will also be visible to the domestic industry in the replacement market.

c) Import prices from subject country is significantly low, and has declined in the POI, despite the costs of production having increased.

d) The DA is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the subsidised imports when compared with the price of like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In the present case, the landed price of imports from subject country is significantly below the domestic industry's selling price, thus undercutting the prices of the domestic industry.

e) The comparison of cost of production and selling prices show that both declined. However, the decline in prices was less compared to the decline in costs, allowing the domestic industry to improve its profitability in 2015-16. However, costs of sales declined thereafter in 2016-17 and increased in the present POI. Selling price declined further than the decline in costs in 2016-17, and thereafter the increase in selling price in the POI was also less as compared to the corresponding increase in costs. Landed price of imports have declined in the POI despite the costs having increased. The landed price is also below the level of both sale price and cost of sales of the domestic industry. Thus, imports have suppressed the prices of the domestic industry as the increase in selling price is less than increase in costs and subsidized imports are further preventing the domestic industry from increasing its selling price.

f) The fact that TBR imports are at a price materially lower than the TBB price implies that cost per kg to the consumer is significantly lower for imported TBR as compared to TBB tyres supplied by the domestic industry. This shows the suppressing and depressing behaviour of Chinese exporters.

g) Domestic Industry enhanced capacity in view of present & potential demand. However, despite this increase, the production that increased till 2016-17 fell in the POI, along with sales. Consequently, the capacity utilization has also fallen in the POI. The adverse effect of subsidised goods is more visible on the volume parameters in the replacement market.

Whether input prices rise/fall, the industry does not realign its prices along with the same.

h) The market share of imports from subject country has increased throughout the injury period and market share of the domestic industry also increased. However, market share of Indian industry as a whole has declined.

i) Suppressing effect of imports have caused decline in the profits of the domestic industry. Profit before interest, cash profits and return on capital employed, also showed the same trend as that of profits. The ROI of the domestic industry is even less than the bank rates prevailing in India. The profitability has declined for the companies as a whole as well as for PUC. The decline in PUC profitability is greater than that of non-PUC, and even if PUC commands equal share of sales and capital employed, the profits earned are meagre.

j) Inventories of the PUC with domestic industry have increased significantly in the POI.

k) Wages have shown improvement in the injury period while number of employees have remained the same. However, these are not solely dependent on the subject goods performance, as they are governed by several legislative requirements in the country, and other business compulsions.

l) The only factor responsible for the domestic industry prices are the import prices of the product and the cost of production of the domestic industry. On import price of the product, it is only the Chinese imports which concerns the domestic industry. Import price from rest of the world does not concern the domestic industry, as, either these are too high prices, or these imports are being made by one of the tyre companies and then being resold in the market at much higher prices. Thus, the principal factors responsible for the domestic industry prices are the cost of production and landed prices of the subject goods.

m) The ability to raise fresh investment has not been impacted by subsidization of the product as investment decisions are taken on a long-term basis. However, long term viability of the PUC is dependent upon strong profitable business.

n) The growth of the domestic industry during the injury period was negative in the presence of subsidized imports in the domestic market, based on production, sales, market share, profits, PBIT, cash profits and ROI parameters.

o) Imports from subject country have increased in absolute as well as relative terms over the injury period. While there was some decline in the imports in the POI as compared to preceding year, it does not mean that the imports have not increased over the injury period, considering that the imports in POI were still double the volumes in base year. The import price declined very steeply over the injury period. Imports are undercutting the prices of the Domestic Industry to a significant extent. Imports are suppressing the prices of the Domestic Industry and preventing the price increases that would have occurred in the absence of dumping. Performance of the domestic industry deteriorated in terms of production, domestic sales, capacity utilization, inventory, market share, profits, cash flow and ROI. Consequent impact of subsidized imports on the domestic industry has been significantly adverse.

p) Chinese subsidies to its producers allows them to produce at significantly low cost, giving them a competitive advantage over other producers of subject goods across the globe. This subsidisation has led to significant exports by China to other countries. The scheme of subsidies available are clearly geared towards increase in production and exports. Furthermore, the US has initiated ADD and Anti-subsidy investigation on the export of subject goods by China.

q) Imports from subject country have grown 100% in the POI as compared to the base year, despite the Domestic Industry having sufficient capacity to cater to domestic demand.

r) Producers of the PUC in the subject country have high capacities, despite demand for the subject goods being low in the subject country market in comparison, thus leading to excess capacities.

s) Landed value of imports are priced lower than the selling price as well as cost of production of the Domestic Industry. The domestic market is attractive to producers of the subject country. Imports are entering the market with suppressive/depressive effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports. There is a high likelihood that Chinese exporters would aggressively target the domestic market.

t) The import price of subject goods from China has declined significantly in the POI as compared to previous year despite the cost of production of subject goods increasing in the same period.

u) China is the world's largest producer and exporter of tyres, accounting for a quarter of global production. Exports from subject country to the world as well to India have been on the rise since 2005. Chinese exporters thus have high exports to world as well as India, showing them to be highly export oriented. The present price difference between the domestic product and the imported product is extremely significant, thus likely to increase demand for imported products. Furthermore, capacities are being expanded by producers. Despite trade barriers working against the Chinese tyre industry, it shows no signs of tiring out.

v) Number of other countries, such as Brazil, Turkey, Colombia, Egypt, US and EU, have either imposed ADD against the subject goods from subject country or have initiated the AD investigation.

w) China consumed 38% of the Natural Rubber used in tires globally in 2014. In 2015-16 China imported 2,220,373 MT of Natural Rubber. Out of total NR imports 2,63,123 MT were in form of RSS and 19,57,250 MT in form of Block Rubber (Technically Specified Natural Rubber). Thus around 88% of NR imported is in form of Block Rubber. Investments in major rubber producing countries has given significant cost advantages to Chinese Producers vis- a- vis India as import Price of Block rubber into China is consistently lower than import price in India.

x) Level of inventories present with producers of subject country are unknown to the domestic industry. However, in view of the fact of significant capacity available with them, it is evident that foreign producers can scale up their production in a short period.

y) India has become one of the top 10 export destinations for Chinese tyre producers. From being the 43rd ranked export destination in 2012, India is ranked 6th in 2016. Thus, subsidized Chinese exports are posing serious threat of material injury to the Indian domestic industry.

z) Thus, in the instant case, there is a substantial increase in subsidized PUC, projecting an increasing trend. Furthermore, these imports are only somewhat contained due to the initiation of ADD investigation as well as uncertainty over the quantum of the same in the mind of the importers. The price difference between the two products is significant, and may lead to increased demand for imports. Finally, not only are there freely disposable capacities available with the subject country, but the producers in the subject country can scale up production in a short period.

aa) The claimed injury to the Domestic Industry is solely on account of domestic operations. No significant advances in production technology have been made in the industry at a global level. Performance of other products being produced and sold by petitioner companies is not a possible cause of injury to the domestic industry. There are no trade restrictive practices, which could have contributed to the injury to the domestic industry and there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration. In light of this, the Petitioners submit that the following parameters can be used to establish the existence of a causal link –

- Imports are undercutting the prices of the Domestic Industry. Resultantly, the volume of imports has increased.
- Price undercutting is caused by the subsidized imports, resulting in increase of market share of imports and corresponding decline in market share of the Domestic Industry. Further, in the replacement segment, market share of the Domestic Industry has steeply declined.
- Landed price of imports of TBR is much below the prices of even TBB. Imports are significantly suppressing the domestic industry.
- Production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry has declined in the POI. Profits, profit before interest, cash profits and ROI employed have declined in the POI.
- Inventories with domestic industry have increased significantly.
- Consequent impact of subsidized imports on the domestic industry have been significantly adverse.

bb) The various parameters collectively and cumulatively establish that the Domestic Injury has suffered Material injury. Further increase in Chinese imports, excess capacity with Chinese producers coupled with their high export orientation and the price attractiveness of the Indian Market evidences that there is further threat of material injury to the Domestic Industry.

cc) The fact is that the producers in China are still left with significant capacity much more than their demand and are highly export oriented as evidenced from their ever rising exports to global market.

dd) Furthermore, the claim that the there is a further decline in price undercutting in the post-POI period because of increase in custom duty and imposition of anti-dumping duty is hypothetical conjecture devoid of any relation with reality. The price undercutting in the post-POI has increased as the price of imports has declined significantly in the post- POI period.

ee) As has been stated earlier the decline in imports is partly because of decline in demand and partly because of initiation of antidumping investigation on imports of subject goods (only TBR) in May 2016. Further, the relevant period for a countervailing investigation is the period of investigation. Volume of subsidized imports from the subject country has doubled in comparison to the base year. It may be noted that since the imports are de-facto only in replacement market, the injury to the domestic industry is also prominent in the replacement market. Notwithstanding above, though it is true that the volume of imports has fallen from subject country, but the price at which such imports are coming has also declined significantly in the post-POI period.

ff) It may be seen that the domestic industry was able to increase its profits in 2015-16. However, the same declined subsequently in 2016-17 with significant increase in imports at low prices. Import price have further declined in the POI when the costs have actually increased. Thus, the suppressing effect of imports have caused further decline in the profits of the domestic industry.

gg) It is also relevant to note that it is not possible for the industry to keep realigning its prices with every change in the inputs. It is submitted that whether the input prices increases or reduces, the industry does not realign its prices immediately with the changes in the input costs. In fact, the industry had in past taken 2-4 price changes in one year when the inputs such as natural rubber had undergone changes almost every day.

hh) The presumption of the interested parties is misplaced, as can be perused from the data submitted with the petition, which shows that the production of the domestic industry has increased. It is not possible for any business to increase production when it is facing shortage of raw materials. The evidence submitted by the interested parties in relation to shortage of raw material is all related to post-POI period and is an information accessible to the counsels by virtue of their assisting the consumers of these inputs. It is quite inappropriate for these parties to represent ATMA or other consumers on these raw materials, get briefings on these aspects and now present to the Designated Authority such claims which even do not pertain to the POI of the present case.

ii) The presumption of the interested parties is misplaced, as can be perused from the data submitted with the petition. The cost of sales have declined throughout the injury period with slight increase in POI. The production of the domestic industry has increased. The evidence submitted by the interested parties in relation to shortage of raw materials is all related to post-POI period.

jj) The producers of the product under consideration in the subject country have high capacities. The demand for subject goods in subject country market is significantly low as

compared to the production capacities created in such country, thus leading to excess capacities in the subject country. Major producers of subject goods in subject country have significantly high production capacity which is way beyond the demand in the subject country.

kk) The petitioner fails to understand how the interested parties have come to a conclusion from the final finding in the TBR ADD case that the duties imposed were based on injury margin.

ll) It is submitted that contrary to the claims of the interested parties, decline in profits is visible from the balance sheets of the petitioner companies. It would be seen that (a) the profitability has declined for the companies as a whole as well as for PUC (b) decline in profitability of PUC is higher than the decline in profitability of NPUC (d) even when PUC commands equal share of sales and capital employed, the profits earned from them is meagre.

H.2. Submission by other interested parties

396. The submissions made by other interested parties with regard to injury and causal link, are as follows:

a) During the period of investigation, the domestic industry has made huge profits, as the product demand and revenues of the company have increased. Therefore, there is no injury to the domestic industry due to alleged increased imports of subject goods caused by subsidized imports. The increased demand also indicates that imports originating in China PR do not have a negative impact on the domestic industry.

b) Injury, if any, to the domestic industry is self-inflicted, because firstly, according to press reports India kept its focus on TBB till late and is slow to adopt radialisation and consumers preferred radial tyres for its better strength and durability. Secondly, Chinese exporters lowered their price of TBR when cost of raw material went down, while the domestic industry focused on making huge profits. Thirdly, the decrease in market share of the domestic industry, if any, is caused by the aggressive pricing behaviour of other domestic competitors and not imports from China PR.

c) On the scrutiny of the balance sheets and profit and loss accounts and based on the various economic parameters of domestic tyre industry, it can be seen that there is no material injury to the stated members of ATMA and there is further decline in the imports during the POI.

d) Demand and use of radial tyres is increasing and preference for bias tyres is declining due to which domestic industry of bias tyres is demonstrating decline in performance. Effects of such decline has been included in the information given by the petitioners.

e) At home, the raw material are prevailing below the peak August 2008 and again in August 2013. Despite this, the tyre prices have been hiked at regular intervals during last three quarters and consequently, the industry had made huge profits, which can be seen by

evaluating the balance sheets of last 10 years particularly of POI.

f) Tyre manufacturing is a hugely raw material-based industry and rate of return on investment is normally 10%-12%. The domestic tyre majors use the route of expanding capacity even without expanding their proportionate production and sales, camouflaging their real profits. Similarly, despite regular tyre imports, the domestic tyre majors have grown exponentially in terms of size and profits and with high rate of return on investment.

g) Radial tyre imports from the year 2010 onwards have forced the domestic industry to give priority to radialisation at home for truck and bus tyres as domestic tyre majors were making profit by selling outdated technology and inefficient bias ply Nylon fabric tyres, which are not being sold even in neighbouring countries like Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. This is because the domestic tyre majors enjoy undue tariff and non-tariff protection granted by Government of India and exploit the domestic market by indulging in price parallelism and cartelisation.

h) In *M/s. Apollo Tyres & Ors. (Respondents) v Ministry of Corporate Affairs (informants)*, the DG investigation, CCI has declared domestic tyre majors indulging in price parallelism and cartelization. Hence the present petition by ATMA seeking imposition of countervailing duty is only an attempt to further raise the wall of tariff on tyre imports and strangulate the free and fair play of market forces in the replacement market in India.

i) There is decline of imports of subject goods from China PR.

- As per available data, there has been decline in volume of exports of the subject goods from China PR in the POI and the same has further gone down in the post POI period on account of the imposition of anti-dumping duty and the increase in basic custom duty.
- Many tyre factories in China PR have been ordered to shut down or reduce production, as an outcome of the government's drive to cut down pollution. This has already reduced exports to India.
- Therefore, there is no threat of injury due to imports of subject goods from China PR.

j) Shortage of raw material and shift in industry are affecting the performance of the domestic industry.

- The domestic supply of key ingredient, carbon black and natural rubber is unable to keep up with the increasing domestic demand by the user industries in India.
- Further anti-dumping duty imposed on other raw material caused further increase in the cost of manufacturing the subject goods in India.

k) There is increase in demand and use of radial tyres in the Indian market while preference for bias tyres is declining. This may have contributed to a decline in economic parameters of the domestic industry for both radial and bias tyres taken together.

l) Rule 13 of the Countervailing Duty Rules require that material injury assessment should be made taking in to account the principles laid down in Annexure I of the Rules.

Para 1 sub-para (2) of Annexure I requires the authority to consider whether there has been significant increase in subsidized imports. Para 1 sub-para (3) of Annexure I requires the Authority to consider the effect of subsidized imports on prices and whether there has been a significant price undercutting by them.

m) The volume of subject imports from China PR has declined in the POI and has further gone down substantially in the post-POI period.

Year	POI (Oct 16-Sep 17)	Post-POI (Oct 17 – June 18)	Post-POI(A)
Volume (in MT)	65,386.93	15,183.53	20,244.71

n) As can be seen from the table below, as per the petition by the domestic industry, there has been a substantial decline in the level of price undercutting in the last two years of the injury period.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Landed price of imports from China PR	Rs./kg	169	161	169	168
Domestic selling prices	Rs./kg	***	***	***	***
Price undercutting range	%	15-25	15-25	5-15	5-15

o) Increase of customs duty on new pneumatic radial tyres has increased the landed price of the subject imports from China PR in the post POI period resulting in reduced price undercutting.

The domestic industry's market share has increased in the POI and market share of imports have declined.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	POI (Oct 2016-Sep 2017)
Domestic industry	%Indexed	101	100	102
Imports from China PR	%	17.5	21.2	16.5
Other countries	%	2.6	2.3	2.8
Domestic producers as a whole	%	79.9	76.5	80.7

p) Market share of domestic industry would show further increase if the post POI data is considered where imports have declined by approximately 70% as compared to the POI.

q) The domestic industry's profits, cash profits, PBIT, and ROCE have increased in 2015-16, but declined in 2016-17 but this is inconsistent with the decline in the volume of imports and in price undercutting in 2016-17 and the POI.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI (Oct 16-Sep 17)
Profits-total	Rs. crore/Indexed	100	156	103	38
Cash Profits	Rs. crore/Indexed	100	147	107	62
RoCE	% /Indexed	100	116	74	33
Imports from subject country	MT	30,665	69,982	81,896	61,203
Price undercutting range	%	15-25	15-25	5-15	5-15

r) The domestic industry has increased its capacity in view of the present and expected demand. Capacity utilization has declined marginally in the POI.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI (Oct 16-Sep 17)
Capacity	Index	100	101	103	106
Production	Index	100	102	103	102
Capacity utilization	Index	100	101	100	96

s) Capacity utilization of the domestic industry was 86.42% in the year 2014-15. In the present case, MRF is also included as domestic industry and there is marginal decline during POI in the capacity utilization of domestic industry, but it is certain that capacity utilization is still above 80% in the POI. This is due to the increase in capacity in the POI and the difficulty in converting the capacity for Bias tyres to radial tyres. Moreover, capacity utilization has declined because the manufacture of bias tyres has declined. This can be due to preference for radial tyres over bias tyres. As already noted, the material injury caused to performance of the domestic industry for bias tyres is required to be excluded for assessment of material injury.

t) Demand and use of radial tyres is increasing and preference for bias tyres is declining due to which domestic industry of bias tyres is demonstrating decline in performance. Effects of such decline has been included in the information given by the petitioners.

u) Injury, if any, to the Domestic Industry is due to shortage of raw material. One of the primary raw materials used in the manufacture of the PUC is carbon black. For various reasons, the domestic supply for carbon black in India has not been able to meet the domestic demand. This is made worse by the imposition of anti-dumping duties as high as US\$ 494/MT on the imports of carbon black from China PR and Russia. This has resulted in a sharp increase in prices of carbon black in India and affected the production of the subject goods by the domestic industry and also severely dented the domestic industry's profitability. Publicly available information shows that shortage of carbon black has led to a significant decline in the domestic industry's capacity utilization, as admitted by the

Petitioner itself.

v) Another primary raw material used in the manufacture of the PUC is rubber. There is a significant shortage in production of natural rubber in India and therefore a huge gap between supply and demand. Natural rubber, which is currently attracting BCD as high as 25 per cent, has to be imported. Also, till 13 June 2018, imports of natural rubber were allowed only via Chennai and Nhava Sheva ports in India, adding to the costs of natural rubber in the country. Even otherwise, the domestic prices of natural rubber are higher than the international prices by at least 20%. The impact of these have been admitted to by Apollo in its annual report. Moreover, other key raw materials used by the tyre industry namely SBR, NBR, 6PPD & Nylon Tyre Cord Fabric are also subject to anti-dumping duty.

w) There is no threat of material injury to the domestic industry. The legal provisions concerning threat of material injury are contained in paragraph 3 of Annexure I to the Countervailing Duty Rules, which states that “A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the subsidy would cause injury must be clearly foreseen and imminent.” Factors to be considered for the same are listed therein. The GOC however denies that there is a threat of material injury on account of the subject imports for the following reasons.

- The first parameter under threat of material injury pertains to “the nature of the subsidies in question and the trade effects that are likely to arise therefrom”. The Petitioner’s contentions under this heading however are unsubstantiated. Secondly, volume of imports of the PUC has substantially declined in the POI and in the post-POI period.

- The Petitioner has contended that producers of the PUC in China PR have excess capacities while their demand there is significantly low, leading to excess capacities. However, the figures relied upon do not pertain to capacity to manufacture the PUC in China PR. Moreover, the GOC states that many tyre factories in China PR have been ordered to be shut-down or asked to reduce production, as an outcome of the government’s drive to cut down pollution.

x) The Petitioner has alleged that the landed value of the subject imports is lower than the domestic selling price of the domestic industry. However, this is unsubstantiated. Moreover, imposition of anti-dumping duty and the increased BCD on imports has negated any price attractiveness that may have existed.

y) It is an admitted position that TBB and TBR are two different products, which are used interchangeably in the market. It is also apparent from the petition and even written submission that petitioner industry has not provided segregated injury information for both types of tyres separately. Without having separate information for both types of tyres, in relation to imports, landed value, market share, production, sales, capacity, capacity utilization, cost to make and sell, profitability, inventory position, we are handicapped to offer any meaningful comments on the injury (if any) suffered by the petitioner industry. We

therefore, reserve our right to comment on the injury parameters once the desired information is provided to us.

z) In relation to threat of injury, it is submitted that respondents have very serious doubts over the injury shown by the petitioner industry. In any case, post imposition of anti-dumping duties, there is no occasion for petitioner industry to even claim for threat of material injury.

aa) Material injury to the domestic industry cannot be assessed vis-a-vis the particular category of consumers in the domestic market. There is no possibility of excluding the sales, market share, etc. with respect to OEM market. It is also not clear how the assessment regarding mandatory injury parameters can be made vis-à-vis replacement market alone. There is no legal or factual basis to claim that material injury caused to the domestic industry in the replacement market should be assessed and should be considered as sufficient.

bb) Due to increase in basic customs duty and imposition of anti-dumping duty on radial tyres, landed price of the subject imports has increased in the post POI period. Thus, there would be no price undercutting by subject imports if the POI is extended beyond September 2017.

cc) There is no correlation between price undercutting and price suppression in the POI due to imports from China PR and the decline in financial performance of the domestic industry. The domestic industry's profits, cash profits, PBIT, and ROCE have declined in the POI. However, imports has also declined in the POI and price undercutting have also declined in the POI.

dd) Remedial effects of the increased basic customs duty and anti-dumping duty on radial tyres are evident in the post-POI period. Available information indicates that tyre industry in India is performing positively and is set to record 8% growth in sales volume in the year 2018-19 which is commensurate with increase in demand. The Respondents request the Authority to assess the present situation of the domestic industry.

ee) The volume of subject imports has substantially declined in the POI and in the post-POI period. There is thus no threat of material injury in this regard.

H.3. Examination by the Authority

397. In consideration of the various submissions made by the interested parties and the domestic industry in this regard, the Authority has examined injury to the domestic industry on account of subsidized imports from the subject country.

398. Rule 13 of the Subsidy Rules deals with the principles governing the determination of injury which provide as follows:

13. Determination of injury.-

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to

any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.

(2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the causal link between the subsidized import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to the rule.

(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if—

(i) there is a concentration of subsidized imports into an isolated market, and

(ii) the subsidized imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such market.

I. Volume Effect of subsidized imports and Impact on domestic Industry

(i) Assessment of Demand

399. Demand or apparent consumption of the product concerned in India is defined as the sum of domestic sales of Indian producers and imports from all other countries. It is seen that demand has increased over the injury period with marginal decline in POI. The demand so assessed is as follows

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	Oct'16-Sep'17
China	MT	30,665	69,982	81,896	61,203
Other Countries	MT	14,564	10,402	9,666	11,145
D. I. Sales	MT	295,488	347,554	356,128	360,178
Other producers	MT	54,081	43,631	44,143	21,240
Total Demand	MT	394,798	471,569	491,833	453,766

(ii) Imports

400. With regard to volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

401. The volume of import in absolute term for the injury period is as under: The Authority notes that the volume of subject imports from the subject country has increased till 2016-17 but has reduced during POI. However, the imports during POI were much higher than the base year.

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	Oct'16-Sep'17
Import Volume					
China	MT	30,665	69,982	81,896	61,203
Other Countries	MT	14,564	10,402	9,666	11,145
Total	MT	45,229	80,384	91,562	72,348
Share in Imports					
China	%	68%	87%	89%	85%
Other Countries	%	32%	13%	11%	15%
Total	%	100%	100%	100%	100%

402. The volume of import in relation to production and consumption in India during the injury period is as under: The Authority observed that the trend of import in relation to production and consumption in India follows the same trend as imports in absolute terms. The imports in relation to production and consumption in India increased till 2016-17 and declined during POI. However, the imports during POI were much higher than the base year.

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	Oct'16-Sep'17
Subject Country Imports in relation to					
Indian Production	%	8%	16%	18%	14%
Consumption	%	8%	15%	17%	13%
Total Imports	%	68%	87%	89%	85%

(iii) Market Share-

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	Oct'16-Sep'17
Share in Demand					
Subject Country	%	8%	15%	17%	13%
Other Countries	%	4%	2%	2%	2%
DI domestic Sales	%	75%	74%	72%	79%
Other Indian Producers	%	13%	9%	9%	5%
Total	%	100%	100%	100%	100%

403. It is seen that the market share of subject country has increased till 2016-17 and declined during POI. The market share of domestic industry has increased during POI. However, the market share of imports during POI was much higher than the base year.

II. Price effect of subject imports and impact on domestic industry

404. With regard to the effect of subsidized imports on prices, the Authority has considered whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such subsidized imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production (COP), weighted average Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from the subject country.

(i) Price Undercutting

405. Price undercutting has been worked out by comparing the landed price of imports with the selling price of the domestic industry for the investigation period. The net sales realization has been arrived after deducting outward freight and taxes. Landed value of imports has been calculated by adding handling charge and applicable basic customs duty including applicable cess to the CIF value of subject imports.

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Import Volume	MT	30,665	69,982	81,896	61,203
Landed price of imports	Rs/Kg	169	161	169	168
Net Sales Realization	Rs/Kg	***	***	***	***

Price undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting Range	%	20-30	20-30	10-20	10-20

406. It can be seen that landed price of imports from subject country is significantly below the level of selling price of the domestic industry and are thus undercutting the prices of the domestic industry. Price undercutting is positive during the injury period and POI.

(ii) Price Underselling

407. The Authority has worked out non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the landed values of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. The price underselling during the POI is positive.

Name of the producer/exporter	Landed Value (USD/KG)	Non-Injurious Price (USD/KG)	Injury Margin USD/KG	Injury Margin %	Injury Margin Range
Zhongce Rubber Group Co. Ltd.	***	***	***	***	30-40%
Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30%
Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30%
Triangle Tyre Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30%
Aeolus Tyre Co. Ltd	***	***	***	***	30-40%
Yellow Sea Rubber Co. Ltd.	***	***	***	***	30-40%
Weighted average for Aeolus Tyre Co. Ltd and Yellow Sea Rubber Co. Ltd.	***	***	***	***	30-40%
All Others	***	***	***	***	40-50%

(iii) Price Suppression and Depression

408. The cost of sales of Domestic Industry (DI) has reduced by four indexed points in POI as compared to the base year and the selling price of the DI has reduced by seven indexed points during the same period. The landed value of imports from subject country has remained at the same level during POI as compared to the base year.

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	Oct'16-Sep'17
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	92	90	96
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	92	93
Landed Price	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	100	100

III. Economic Parameters relating to the Domestic Industry

409. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

(i) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

410. Position of the domestic industry over the injury period with regard to Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales was as follows:

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	Oct'16-Sep'17
Capacity	MT	429,841	458,974	474,863	496,900
Production	MT	343,654	387,508	405,626	418,847
Capacity Utilization	%	80%	84%	85%	84%
Sales Volume total		342,310	387,511	405,446	422,026

411. Authority notes that-

- The domestic industry has consistently enhanced its capacity.
- The production of the domestic industry has increased constantly throughout the injury period and POI.
- Similarly, sales of the domestic industry has also increased constantly throughout the injury period and POI.
- The capacity utilization of the DI has improved after base year and then almost remained same thereafter.

(ii) Profitability, return on investment and cash profits

412. Position of the domestic industry over the injury period with regard to profitability, ROI and cash profit are as follows:

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	Oct'16-Sep'17
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	92	90	96
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	92	93
Profit	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	157	113	52
Cash Profits	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend		100	157	132	93
PBIT	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend		100	185	136	64
Return on Investment	%	***	***	***	***
Trend		100	120	80	45

413. From the above information, the Authority notes that:

- The profit (Rs/kg) of the DI has reduced during POI.
- Similarly, cash profits, profit before interest and return of investment of the DI has also reduced during POI.

(iii) Market share

414. Position of the domestic industry over the injury period with regard to market share in demand are as follows:

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	Oct'16-Sep'17
Market Share in Demand					
Subject Countries	%	8%	15%	17%	13%
Other Countries	%	4%	2%	2%	2%
DI domestic Sales	%	75%	74%	72%	79%
Other Indian Producers	%	14%	9%	9%	5%
Total	%	100%	100%	100%	100%

415. The market share of the domestic industry has improved during the POI as compared to the earlier years.

(iv) Employment, Wages and Productivity

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	Oct'16-Sep'17
No of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend		100	100	105	104
Salaries & Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend		100	115	132	145
Salaries & Wages per Unit	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend		100	102	112	119
Productivity Per Employee	MT/No	***	***	***	***

Trend		100	112	113	117
Productivity Per Day	MT/Day	***	***	***	***
Trend		100	113	118	122

416. Number of employees, salaries and wages per unit and productivity per employee has increased during the POI. Number of employee has marginally declined during POI.

(v) Inventories

417. Inventories with the domestic industry have increased in the POI.

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	Oct'16-Sep'17
Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	103	103	132

(vi) Ability to raise capital investment

418. The Petitioner has submitted that ability to raise fresh investment is not impacted by subsidization of the product as investment decisions are long term decisions and are taken considering present and potential demand for the product under consideration. However, long term viability of the product under consideration is dependent upon strong profitable business.

Causal link between subsidized imports & material injury

419. The Authority notes that the causal link between subsidized imports from China PR and material injury to the domestic industry is established because of the following:

- Subsidized imports from China PR are coming into India in substantial volumes.
- Subsidized imports from China PR are undercutting the prices of the Domestic Industry.
- Subsidized imports from China PR are suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increases that would have occurred in the absence of dumping.
- Performance of the domestic industry has deteriorated during POI in terms of profits, cash flow and ROI.

IV. Threat of Material Injury

420. The provisions relating to threat of material injury are provided in para 3 of Annexure I of Subsidy Rules which provide as follows:

3. A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the subsidy would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of a material injury, the designated authority shall consider, inter alia, such factors as :

- the nature of the subsidy or subsidies in question and the trade effects likely to arise therefrom;*
- a significant rate of increase of subsidized imports into the domestic market indicating the likelihood of substantially increased importation;*

- iii. sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased subsidized exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- iv. whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further Imports; and
- v. inventories of the product being investigated.

421. With respect to threat of material injury, the Authority notes as under:

- a) There are countervailable subsidies which are being provided to the producers of the product under consideration in China PR. The subsidy margins for all of the co-operating producers/exporters from China PR are above de-minimis.
- b) There is a declining trend of imports of the subject goods from the subject country during the period of investigation. The Authority notes that the imports of the subject goods have further reduced during the post POI period due to the imposition of Anti-Dumping Duty on the subject goods from the subject country and increase in the rates of the basic customs duty by Government of India on the subject goods.
- c) The Authority has examined the capacity details of the co-operative producers/exporters from the subject country and it is noted that no significant capacity has been added by any of the co-operative producers/exporters.
- d) Authority has examined the inventory of the co-operative producers/exporters from the subject country and it is noted that none of them hold any significant inventory of the subject goods.

422. As regards the claim concerning threat of injury, the Authority notes that it has already concluded that the domestic industry is suffering material injury due to subsidized imports and therefore the Authority is not required to provide conclusion for threat of injury.

I. POST-DISCLOSURE COMMENTS BY INTERESTED PARTIES

423. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the course of the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity, the submissions by the interested parties to the extent deemed relevant are being examined as below:

I.1. Submissions by Domestic Industry

424. Copy of the rejoinder submission, verification report, supplementary Questionnaire response and Methodology of calculation of subsidy Margins for all schemes should be disclosed.

425. The subsidy margins determined are very low as compared to the subsidy margins determined by other authorities for tyre investigations.

426. The EU has determined a subsidy margin of 32.85% for Aeolus whereas the Indian Authority has determined subsidy margin of 0-10% for Aeolus even though the POI is overlapping between these two investigations.

427. The Authority has not disclosed the benchmark used for determining benefit for subsidy programs and the denominator for determining the % of subsidy margin.

428. The Authority has not examined subsidies received by affiliated companies while determining subsidy margins in the present investigation.

429. The methodology applied for determination of quantum of subsidy in the present case is materially different from the methodology applied (a) in previous two investigations and (b) applied by other authorities. Chinese benchmarks have been considered for determining benefit instead of international benchmark.

430. The Designated Authority had recommended Countervailing duty as the quantum of subsidy margins after reducing anti-dumping duty in the previous investigation because both anti-dumping and countervailing duty margins were based on non-Chinese benchmarks. However, in the instant case, the benchmarks adopted are domestic benchmarks for provision of raw materials and therefore the decision of the Designated Authority in the previous two cases cannot be applied. The domestic industry is entitled to a total duty of anti-dumping plus countervailing duty determined for domestic subsidies if such duty amount is lesser than the injury margin determined for the domestic industry.

431. POI is different in this countervailing duty investigation and the anti-dumping investigation and therefore it is not established that anti-dumping duty and countervailing duty are for the same situation of dumping and subsidisation.

432. When the program has been terminated after the POI, the investigation cannot be terminated in respect of the same (for instance, program number 1). When the program has been terminated during or before the POI, the investigation cannot be terminated unless it is shown that no benefit was received during the POI in respect of the same (for instance, program numbers 3 & 4). When the program has been terminated during or before the POI, but a new notification conferring the same benefit exists, the investigation cannot be terminated (for instance, program numbers 28, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 & 50).

433. The authority is not only required to countervailing the grants received with respect to subject goods but all grants of general nature received by the company.

434. Other investigating authorities are continuing to hold the programs 4, 17, 18, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 64, and 72 as countervailable and continuing to determine subsidies in a large number of these programs.

435. As regards the determination that there are no tyre manufacturers based in P-16, 17, 18, 19 & 20 locations, petitioners provided a detailed exporter wise submission showing whose plants are located in that region.

436. While stating that no benefit has been received by the company, a mere statement has been made by the exporter and has been accepted in the disclosure statement.

437. POI in EU investigation is from 1 July 2016 to 30 June 2017 which overlaps the POI of the present investigation i.e October 2016-September, 2017. CVD Margin derived by EU and other Authorities in various investigations with regard to tyre is significantly higher than the ones determined by the Authority. The US authorities determined CVD margins ranging 38%-65%.

438. The disclosure statement does not show any scheme which can be considered as “export subsidies” for the purpose of addressing dual remedy principles. Therefore, entirety of the schemes considered by the Designated Authority are required to be considered for the purpose of imposing CVD duty without adjusting for the anti-dumping duties. The GOC and the responding Chinese exporters hold the obligation to establish that these include export subsidies.

439. Analysis of annual reports of Aeolus tyre Co Ltd and Triangle Tire Co., Ltd reveals that both the responding exporters have availed various benefits under the head ‘government grants’ which are over and above grants quantified by the Authority, information of which has not been provided by the exporters and thus not been examined. Annual report of Triangle Tire Co., Ltd. shows that the company has received huge amounts towards relocation subsidy in the year 2017.

440. For non-recurring subsidies, which can be linked to the acquisition of fixed assets, the total value of the subsidy has to be spread over the normal life of the assets which means that nonrecurring subsidies granted several years before the investigation period can still be countervailed and quantified even if the same has been received before the POI and the investigation period. The responding exporters have not provided the benefits received by their affiliated parties and the parent company.

441. Under Program number 22 to 26, annual reports of Double Coin Holdings and GITI Group for 2013 were provided by the petitioner and the subsidy margin were quantified.

442. Injury margin increased in the current POI as compared to previous investigation. Despite increase in production and sales, the profits of the domestic industry have steeply declined. The profits and consequently ROI has declined during 2015-16 and the POI. Capacity utilization of the domestic industry has stagnated. There is almost 32% increase in inventories over the injury period.

443. The landed price of imports of TBR tyres from China is materially lower than the selling price of the domestic industry for TBB tyres. Thus, the goods are being imported into the Country at a price even below TBB tyre price in India. At current prices, the domestic industry is selling the product at a price below NIP and therefore the Indian producers are not in a position to reduce their prices to the extent of import prices. Should the domestic industry sell the product at a price matching the import prices, it would suffer financial losses

444. There is no merit in examining threat of material injury, the Authority is not required to examine threat of material injury. In any case, the threat analysis carried out by the Authority is incorrect.

445. Freely disposable capacity cannot be restricted to the cooperating producers alone. Existing freely disposable and increase in capacities are two separate and distinct requirements and cannot be

mixed. Third country exports from China, show significant volume of exports, at a price lower than at the prices exported to India. Thus, this volume is also likely to get diverted to India

I.2. Submission of other interested parties

446. The Authority provided 5 working days to file comments in response to the disclosure statement, which is not sufficient and therefore additional time should be provided to file further comments.

447. Authority has not determined specificity for the subsidy programs that are determined to be countervailed. No countervailing duty can be imposed without determining that the program is specific.

448. No legal basis is provided for 9 & 13 by the petitioner and therefore no countervailing duty can be recommended for program no. 9 & 13.

449. Program nos. 5, 13, 14 & 15 are specific to Anhui Province. Program 20 is specific to Guangdong province. These two sets of programs are mutually exclusive. Tyre producers in China PR who exported the subject product to India can only use one of these two sets of programs. Therefore, the Authority should not consider both these set of programs while determining the subsidy rate for all others category.

450. State owned banks cannot be considered as public bodies because they are not performing governmental function and were not exercising governmental authority. The decision of the commercial bank to provide loans at certain interest rate is not a subsidy. Commercial banks make their own decisions regarding their business operations in accordance with the law and without any interference from any entity or individual.

451. Authority should not countervail provision of land use rights and provision of electricity programs. Title to industrial land can only be granted from the State to industrial enterprises through bidding or a similar public offering process. Purchase prices of power from the grid followed the officially established price levels set at provincial level for industrial clients. There are no preferential electricity rates for tyre industry and therefore these price levels do not confer any benefit to tyre industries.

452. No countervailing duty can be recommended for provision of electricity and provision of land use rights for participating producers/exporters because no benefit has been received for provision of electricity at less than adequate remuneration and provision of land use rights at less than adequate remuneration. Grants concerning land use rights are already included by the Authority while recommending countervailing duty for grant programs.

453. Subsidy margin adopted by other investigating authorities concerning provision of electricity and provision of land use rights cannot be adopted by the investigating authority in this case.

454. M/s. Shandong Haohua Tire Co. Ltd., M/s. Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd.&M/s. HK Trade Wind Trading Ltd have requested that individual subsidy margin should be

determined for them even though they have not exported the subject product to India because there is no provision of new shipper review in the countervailing duty rules.

455. Radial tyres imported from China PR are of better quality than the tyres sold by the domestic industry. Imposition of duty is not in the interest of end users.

456. There is no injury to the domestic industry because the performance of the domestic industry has improved with regard to most of the economic parameters. Even if there is injury to the domestic industry, there is no causal link between the material injury and subsidized imports.

457. There is no threat of material injury to the domestic industry as there is declining trend of imports of the subject goods the import from China PR, imports of subject goods has reduced in the post POI period, no significant capacity has been added and none of the co-operative producers/exporters hold any significant inventory.

I.3. Examination by the Authority

458. The Authority has addressed all the issues raised by the domestic industry and other interested parties to the extent deemed relevant.

459. The Authority notes that non-confidential version of the submission, questionnaire response and disclosure comments provided by the interested parties are kept in the public file. It is the consistent practice of the Authority that rejoinder submissions of interested parties are not kept in the public file. The same procedure has been followed in the present investigation as well.

460. There is no past practice of the Authority to disclose verification report of one interested party to the other interested party. Further, this information is confidential in nature and not amenable to summarization. The Authority does not disclose the verification reports of domestic industry to other interested parties and *vice-versa*.

461. As regards the claim concerning higher subsidy margin determined by other investigating Authorities for tyre investigations, the Authority notes that the claim is not correct. Subsidy margin determined by the United States in the case of *Certain Passenger Vehicle and Light Truck Tires* from China PR is not relevant because it concerns different period of investigation as well as different product under consideration. In *Certain Pneumatic tyres, new or retreaded, of rubber, of a kind used for buses or lorries* by the European Union, lowest subsidy margin determined for the participating sampled producer/exporter from China PR was 2.06%. The lowest subsidy margin determined by the Authority in the present investigation is *** which is significantly higher than the lowest subsidy margin determined by the EU. The Authority notes that the subsidy margin is determined by the Authority based on the evidence and verifiable information presented by interested parties during the course of investigation. The Authority further notes that subsidy margin is required to be determined for tyre producers in China PR who exported the subject product to India during the POI. The producers/exporters who exported the subject product to the EU and who were investigated by the EU were different from the producers/exporters who exported the subject product to India and therefore subsidy margins are different in both investigations.

462. As regards the claim that subsidy margin in *Truck and Bus Tires* by the United States is between 20.68% to 63.34%, the Authority notes that the comparison between the United States decision and the present case is inappropriate. Subsidy margin of 20.68% to 63.34% is determined for different tyre producers in China PR i.e. Guizhou Tyre Group, Double Coin Group and Kunlun Tyre. The Authority further notes that the subsidy margin was determined by the United States was for a different POI i.e. January 2015 to December 2015. The Authority also notes that the decision of the United States to calculate subsidy margin of 20.68% to 63.34% was based on the application of adverse facts available for grant programs, preferential lending programs, and for provision of electricity, raw materials (carbon black, nylon cord, synthetic rubber and butadiene, natural rubber) and land use rights.

463. The Authority also notes that there is no requirement that subsidy margin determined by different investigating authorities for the countervailing duty investigation on a particular product should be same. Subsidy margin determination is based on the information provided by the participating producers and exporters, the GOC and also the evidence submitted by the domestic industry and other facts available on record. Different subsidy margin determined by the US and the EU for *truck and bus tyres* itself shows that subsidy margin determined by different authorities for the same product under consideration are normally different.

464. As regards the claim that subsidy margin determined for Aeolus is 32.85% by the EU, the Authority notes that subsidy margin of 32.85% was determined by the EU for the China National Tyre Group as a whole consisting of several companies. Aeolus Tyre Co. Ltd. is one of the companies in National Tyre Group. In the present investigation, Aeolus Tyre Co. Ltd. and its related company Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd have participated as only they have exported the PUC to India during the POI. The Authority has duly examined subsidies availed by both of them and determined suitable subsidy margin for both of them. The Authority also notes that the subsidy margin with respect to preferential financing for National Tyre Group was determined by the EU relying partially on facts available whereas the Indian Authority has determined subsidy margin with respect to preferential lending based on the verified information supplied by Aeolus Tyre Co. Ltd. and Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd. The Authority further notes that subsidy margin determined by the Authority with respect to provision of electricity for less than adequate remuneration, provision of land use rights for less than adequate remuneration, and income tax exemption for Aeolus Tyre Co. Ltd. are higher than the subsidy margins determined by the EU for these subsidies.

465. The Authority has disclosed the type of benchmark adopted for subsidy programs wherever applicable in its analysis of subsidy programs. As regards the claim that the Authority has not disclosed the basis on which % of subsidy margin is determined, the Authority notes that the subsidy margin is determined as a % of CIF price.

466. With regard to the claim that the Authority has not examined subsidies received by affiliated companies while determining subsidy margins in the present investigation, the Authority notes that the subsidies received by affiliated companies have been duly considered in the present investigation to the extent deemed relevant. For example, while determining subsidy margin for Zhongce Rubber Group Co. Ltd., subsidies received by its three subsidiaries who were engaged in production of

subject goods on job work basis were duly taken into account. Out of all the related companies of Aeolus Tyre Co. Ltd., only Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd. was engaged in production and exports of the subject goods to India during the POI. Accordingly, the Authority has determined subsidy margin for Aeolus Tyre Co. Ltd. and Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd based on the information provided by them and as verified by the Authority.

467. As regards the claim that relocation amount received by participating producers should be considered as grant and should be countervailed, the Authority notes that relocation compensation received by participating producers has been considered as grant and subsidy margin has been determined for such grant program.

468. As regards the claim that the benefit received for non-recurring subsidy programs tied to capital assets before the POI and during the AUL period should also be countervailed, the Authority notes that where the grants are related to assets, participating producers/exporters have recognized them as deferred income, amortized to profit and loss over the average useful life of the related asset and where the grants are related to income, participating producers/exporters have recognized them as 'other income' or 'non-operational income' immediately in the profit and loss for the specific year in which it was received. Either way, the amount is clearly shown in the annual report of the year in which it is received. The entire grant amounts is reflected in the annual report where it is income-linked or reflected as an amortized amount in the annual report of every year of the average useful life of the asset where it is asset-linked. The Authority has countervailed both grants related to income as well as grants related to assets in the present investigation.

469. As regards the claim that all grants reported in the Annual Reports of the participating producers are required to be considered for determining the subsidy margin for grant programs, the Authority notes that it has examined the Annual Reports of all participating producers/exporters and has considered all the grants reported in their Annual Report for determining the total subsidy margin for grant programs.

470. As regards the claim that methodology applied for determining quantum of subsidy in the present case is different form the methodology applied in previous two investigations and that applied by other Authorities and that international benchmarks have not been used for determining the benefit for provision of raw materials in the present investigation, the Authority notes as follows:

- i. The Authority has determined subsidy margin in the present case in terms of the provisions of WTO SCM Agreement, Countervailing Duty Rules and as per its consistent practice.
- ii. The Authority has determined subsidy margin for provision of land use rights at less than adequate remuneration based on facts available.
- iii. The Authority has determined subsidy margin for provision of electricity at less than adequate remuneration based on facts available, which is in turn based on the decision of the Indian Authority in the previous countervailing duty investigation concerning *Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products*.

iv. As regards provision of raw materials for less than adequate remuneration, Authority first did a detailed examination as to which raw materials have been procured by participating producers/exporters from state owned enterprises. Thereafter, the Authority compared the purchase price from state owned enterprises with the purchase price from private enterprises as well as import price/international benchmark. The Authority notes that the three primary raw materials purchased by participating producers/exporters from state owned entities are natural rubber, synthetic rubber and carbon black.

v. In so far as natural rubber is concerned, the Authority notes that it is primarily imported into China and domestic purchases from state owned enterprises are negligible. Even the purchase price from state owned enterprise is comparable with the price of imported product.

vi. In so far as synthetic rubber is concerned, the Authority notes that the participating producers/exporters have purchased synthetic rubber from state owned enterprises as well as private entities and also imported the same. The Authority has compared the purchase price from state owned enterprises with purchase price from private entity as well as the price of the imported product. The Authority notes that the purchase price from state owned enterprise is comparable with the purchase price from private entities as well as the price of the imported product.

vii. In so far as carbon black is concerned, the Authority notes that participating producers/exporters have purchased carbon black from state owned enterprises as well as private entities. None of the participating producers/exporters have imported carbon black. For comparison purposes, the Authority has considered the international benchmark as the import price of carbon black into India from Korea RP. The Authority notes that the purchase price from state owned enterprise by all participating producers/exporters except Triangle Tyre Co. Ltd. and Zhongce rubber group Ltd. is comparable with the purchase price from private entities as well as the international benchmark adopted by the Authority. Accordingly, the Authority has determined the benefit for Triangle Tyre Co. Ltd. and Zhongce rubber group Ltd. based on the difference between the price paid to state owned enterprise and the international benchmark.

viii. The Authority also notes that in countervailing duty investigation concerning *Truck and Bus Tyres* from China PR by the United States, the United States also determined the subsidy margin for producers/exporters from China PR by comparing the difference between the price charged by state owned entities and the actual import purchase price provided by participating Chinese companies.

ix. Article 14(d) of the SCM Agreement provides that in case of provision of goods, the adequacy of remuneration shall be determined in relation to prevailing market conditions for the goods or services in question in the country of provision (including price, quality, availability, marketability, transportation, and other

conditions of purchase or sale). Annexure IV, para B(d)(i) of Countervailing Duty Rules provides that adequate remuneration should normally be determined in light of prevailing market conditions on the domestic market of the exporting country. Para. B(d)(ii) provides that the amount subsidy should be difference between lowest price available from private suppliers and the government price.

- x. In countervailing duty investigation concerning *Certain Pneumatic tyres, new or retreaded, of rubber, of a kind used for buses or lorries*, the EU determined that no benefit has been conferred on the producers/exporters from China PR concerning provision of raw materials namely, carbon black, nylon cord, synthetic rubber & natural rubber.
- xi. There was no co-operation from the producers/exporters from China PR and the Government of China in the Indian countervailing duty investigation concerning *Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products* and there was no cooperation from Government of China in the Indian countervailing duty investigation on *castings for wind operated electricity generators*. Therefore, in both these countervailing duty investigations, the Authority had relied on facts available for a number of subsidy programs. On the other hand, in the present investigation both Government of China and producers/exporters from China PR have participated and provided relevant verifiable information.
- xii. There is no provision regarding non-market economy treatment in SCM Agreement or in the Countervailing Duty Rules.

471. Regarding the countervailability of alleged subsidy programs in the petition, the Authority notes that all the claims are responded by the Authority in the section containing detailed analysis for each subsidy program.

472. Regarding the claim that full amount of countervailing duty should be imposed in addition to the anti-dumping duty because the Authority has adopted domestic benchmark for provision of raw materials in the present investigation, the Authority notes that the submission of the domestic industry does not have any legal basis and is contrary to their own argument and submission made during the course of investigation. The domestic industry in its post hearing submissions had submitted that if anti-dumping duty already imposed is higher than the countervailing duty determined in the present investigation, then no countervailing duty shall be recommended, imposed and collected. The Authority also notes that the claim of the domestic industry is incorrect that the Authority has adopted domestic benchmark for provision of raw materials in the present investigation as can be seen in the previous sections.

473. Anti-dumping duty is already in force on the product under consideration imported from China PR. The total subsidy margin determined by the Authority consists of export subsidies and domestic subsidies. As regards the export subsidies, Section 9B(1)(a) of the Customs Tariff Act provides that a product shall not be subject to both anti-dumping and countervailing duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidization. Thus, the anti-dumping duty in force is required to be deducted from the total countervailing duty to avoid double counting of

subsidisation and only if countervailing duty is more than the anti-dumping duty in force, the differential amount is required to be collected as countervailing duty. If countervailing duty is imposed in addition to the anti-dumping duty, it would amount to double remedy. To ensure that subsidization is not remedied twice i.e. there is no 'double remedy', the Authority concludes that only if the countervailing duty is more than the anti-dumping duty, the differential amount would be charged as countervailing duty over and above the anti-dumping duty already in existence. This is completely in line with the past practice followed consistently by Indian Authority in all previous anti-subsidy investigations against China PR.

474. The Authority further notes that the decision of the Authority to reduce anti-dumping duty in force from the total countervailing duty to avoid double counting in line with the consistent practice of the Authority, the decision of the Hon'ble CESTAT in *Suncity Sheets vs. Union of India*, SCM Agreement and the decision of the Appellate Body in *US- Definitive AD and CVD (China)*.

475. As regards the claim that there are no export specific subsidies in the present case and accordingly no adjustment should be made to reduce the anti-dumping duty in force, the Authority notes that there are a number of export specific subsidies countervailed by the Authority in the present investigation and accordingly there is a need to reduce the anti-dumping duty in force at the time of recommending the countervailing duty.

476. As regards the claim concerning threat of injury, the Authority notes that it has already concluded that the domestic industry is suffering material injury due to subsidized imports of subject goods and therefore the Authority is not required to provide conclusion for threat of injury.

477. As regards the claim that there is no provision of new shipper review in the countervailing duty rules and therefore individual subsidy margin should be determined for producers who have not exported the subject product, the Authority notes that Article 19.3 of WTO SCM Agreement provides for 'expedited review' for exporters who were not actually investigated for reasons other than a refusal to co-operate. Therefore, new producer/exporters from China PR i.e. those who have not exported the subject product to India in the POI can request for initiation of new shipper review, if they have exported the subject product after the POI.

478. With regard to the claim concerning additional time, the Authority notes that it has already provided sufficient time to the interested parties and no further time can be provided to the interested parties to file comments because the investigation is time bound. It is the consistent practice of the Authority to not allow any further submission pursuant to the comments on disclosure.

479. As regards the countervailability of subsidy programs, the Authority has determined that subsidy programs are countervailable when there is a financial contribution, benefit and specificity. The Authority refers to the explanation provided for each subsidy program in this finding. The Authority has disclosed the methodology for determination of subsidy margin in each case and has provided explanation for such methodology in its analysis for each of the subsidy programs.

480. As regards the claim that no countervailing duty can be recommended for programs for which no legal basis is provided, the Authority notes that when there is sufficient evidence regarding the

existence of final contribution, benefit and specificity based on the information provided by the petitioner or based on the information available on record with the Authority, the Authority can recommend countervailing duty against such subsidy program.

481. As regards the claim that program nos. 5, 13, 14 & 15 and Program No. 20 are mutually exclusive and both sets of programs cannot be countervailed while determining 'all others' rate, the Authority notes that the countervailing duty for 'all others' category has been recommended against only one set of programs.

482. As regards the claim that state owned banks and entities providing electricity cannot be considered as public bodies because they are not performing governmental function or exercising governmental authority, the Authority notes that no information has been provided by the GOC or by such state-owned banks and entities through GOC to show that they are not performing governmental function or exercising governmental authority. The Authority has determined based on the information available on record that state-owned banks and entities providing electricity are public bodies within the meaning of Section 9(1)(a) of the Customs Tariff Act. In addition, even if the state-owned financial institutions and entities providing electricity were not to be considered as public bodies, the Authority found that they would be considered entrusted and directed by the GOC to carry out functions normally vested in the government, within the meaning of Section 9(1)(a)(iv) of Customs Tariff Act.

483. As regards the submission that commercial banks in China provide loans based on their own decision without any interference from any entity, the Authority notes that the information provided by the participating producers/exporters from China PR showed that loans obtained from state owned banks in certain cases were at a lower interest rate than the interest rate notified by the People's Bank of China. Therefore, the Authority determined that benefit has been conferred to the tyre producers/exporters by way of preferential lending program by state owned banks.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

484. The Authority notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of countervailing duty would not prohibit imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

485. Imposition of countervailing measures would remove the unfair advantages gained by subsidization, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

K. RECOMMENDATION

486. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including the Government of China PR and adequate opportunity was given to provide positive information on the aspect of subsidization, injury and causal links. Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal links in terms of the Rules laid down and

having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from China PR in the form and manner described hereunder.

487. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Since, product under consideration is already attracting anti-dumping duty from China PR, the amount of countervailing duty to be imposed is equivalent to the difference between the quantum of countervailing duty mentioned in Col No.7 below and antidumping duty payable, if any. If the countervailing duty is less than the anti-dumping duty payable, the differential amount would be in the negative and no countervailing duty shall be collected in such case.

DUTY TABLE

S. No.	Heading/ Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty amount as % of CIF value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	40112010	New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks	China PR	Any other country including China PR	Zhongce Rubber Group Co. Ltd.	9.55%
2.	-do-	-do-	China PR	Any other country including China PR	Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.	9.18%
3.	-do-	-do-	China PR	Any other country including China PR	Triangle Tyre Co. Ltd	12.23%
4.	-do-	-do-	China PR	Any other	Shandong	9.12%

				country including China PR	Yongfeng Tyres Co. Ltd	
5.	-do-	-do-	China PR	Any other country including China PR	Aeolus Tyre Co. Ltd.	9.66%
6.	-do-	-do-	China PR	Any other country including China PR	Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd.	9.66%
7.	-do-	-do-	China PR	Any other country including China PR	Any producer other than S. No. 1 to 6	17.57%
8.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	17.57%

488. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

489. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.& Designated Authority